ISSN : (P) 0976-5255
(e) 2454-339X
Impact Factor : 8.354 (SJIF)

शोध मंथन

हिन्दी शोध पत्रिका

A PEER REVIEWED & REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL IN HINDI

VOL - XII | SPECIAL ISSUE | APRIL 2021

कोविड 19 महामारी से संघर्षरत विश्व एवं भारत–एक परिदृश्य

मुख्य संपादक
डॉ० अभय कुमार मीतल

संपादक
डॉ० संजय कुमार बंसल
डॉ० मनीष कुमार गुप्ता

ANU BOOKS

मुख्य संपादक

डॉ0 अभय कुमार मीतल

प्राचार्य

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश

संपादक

डॉ0 संजय कुमार बंसल

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा (बुलंदशहर), उत्तर प्रदेश।

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर), उत्तर प्रदेश।

सहकर्मी समीक्षा मंडल

(Peer Review Board)

वाणिज्य और प्रबंधन

- डॉ. आर. के. गुप्ता, कुलपति, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
- डॉ. एन. एल. शर्मा, पूर्व प्राचार्य, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश।
- डॉ. एन. एल. गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष, डी. ए. वी. कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड
- डॉ. के. के. बंसल, पूर्व विभागाध्यक्ष, श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- प्रो0 सुबोध कुमार, कैंपस बादशाही थोल, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड।
- प्रोफेसर एन. सी. पांडे, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड।
- डॉ. जे. के. शर्मा, जी. जी. डी. एस. डी. कॉलेज, पलवल, हरियाणा
- डॉ. वी. एन. गुप्ता, राजकीय कॉलेज, टिहरी, उत्तराखंड।

विज्ञान

- प्रो. पी. पी. सिंह, पूर्व प्राचार्य, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी। (रसायन विज्ञान)
- डॉ. वीना गर्ग, पूर्व विभागाध्यक्ष, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान। (जैव रसायन)
- डॉ. ओमवीर सिंह, विभागाध्यक्ष, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (जंतु विज्ञान)

कला

- डॉ. सुशीला रानी गर्ग, पूर्व डीन, बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान। (हिंदी)
- डॉ. डी. सी. मीतल, पूर्व प्राचार्य, एस. डी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर, यू.पी.। (अंग्रेजी)
- डॉ. मुकेश बंसल, पूर्व विभागाध्यक्ष, एस. डी. कॉलेज, मुजफ्फरनगर, यू.पी.। (इतिहास)
- डॉ. बलराम सिंह, विभागाध्यक्ष, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, यू.पी.। (समाजशास्त्र)

Managing Editor - Vishal Mithal

शोध मंथन त्रि–मासिक जर्नल है।

शोध मंथन में पूर्व प्रकाशित लेख व पत्र प्रकाशित नहीं किये जाते।

शोध मंथन के प्रबन्ध सम्पादक पूर्व निर्धारित हैं। यथा समय अतिथि सम्पादक चयनित किये जाते हैं।

प्रकाशित सामग्री का कॉपी राइट जर्नल अनु बुक्स, मेरठ का है।

अपना शोध पत्र प्रकाशित करवाने के लिये ई मेल के द्वारा अपने पूर्ण पते के साथ भेजें। सम्पादकीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

Authors are solely responsible for the any case of plagiarism.

Published by ANU BOOKS in support of

KAILBRI INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRUST

Printed by D.K. Fine Art Press Pvt. Ltd., New Delhi.

प्राक्कथन

कोरोना त्रासदी से सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। कोरोना की प्रथम लहर ने विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को ही सर्वाधिक त्रस्त नहीं किया, वरन् जर्मनी, ब्राजील, भारत, इटली, चाइना समेत विश्व के 220 देश इसकी चपेट में आ गए। प्रथम लहर के दुष्परिणामों से जूझता विश्व वैक्सीन के आने से प्रसन्न भी नहीं हो पाया था कि भयानकतम दूसरी लहर ने सम्पूर्ण विश्व में महामारी को चरम पर पहुंचा दिया। सारी सुरक्षा, सावधानियों के बाद भी हर देश में मानव जाति और अर्थव्यवस्थाएं दोनों ही इससे त्रस्त हैं। आंकड़े अत्यन्त भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। विश्व में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक कोरोना महामारी से प्रताड़ित हुआ है। अमेरिका में अब तक लगभग 3.39 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुये हैं तथा 6.05 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। सम्पूर्ण विश्व के संदर्भ में अद्यतन कुल लगभग 16.88 करोड़ लोग कोरोना प्रभावित हुये हैं जबकि लगभग 15.05 करोड लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की और पुनः स्वस्थ हो गए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर अद्यतन लगभग 35.06 लाख लोग काल के गाल में समा गए हैं व सम्पूर्ण विश्व में सक्रिय कोरोना प्रभावितों की संख्या लगभग 1.48 करोड है। कोरोना संक्रमण के संदर्भ में विश्व के शीर्ष तीन देश क्रमशः अमेरिका, भारत एवं ब्राजील हैं।

भारत और संपूर्ण विश्व में इस समय कोरोना से त्राहि–त्राहि मची हुई है। ऐसी स्थिति में भी भारत अपने सीमित संसाधनों से संपूर्ण विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। समय रहते ही भारत ने कोरोना संक्रमितों के लिए दो प्रकार की स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर ली है– 'कोवैक्सीन' एवं 'कोविडशील्ड'। साथ ही अन्य स्वदेशी वैक्सीनों जैसे जाइडस, बायोलॉजिकल ई, नोवावैक्स, जिनोवा एमआरएनए; को भी जल्द ही सरकार से अनुमति मिलने वाली है। भारत बायोटेक का नाक से दिया जाने वाला टीका भी वर्ष के अंत तक विकसित हो जाएगा। रूसी वैक्सीन स्पूतनिक–V को भी भारत ने मंजूरी दे दी है। इसकी पहली खेप भारत को मई में प्राप्त होने की संभावना है। भारत में टीकों की कमी की पूर्ति हेतु सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विदेशी कंपनियों जैसे फाइजर, मॉडर्ना तथा जॉनसन एंड जॉनसन से भी निरंतर संपर्क में है। भारत ने 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे वृहद एवं विस्तृत कोविड़ टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है।

कोरोना की इस वर्तमान स्थिति में भारत समेत समस्त विश्व किसी भी प्रकार से अपने नागरिकों को एवं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के तरह–तरह के प्रयास कर रहा है चाहे वह वैक्सीन एवं दवाइयों का निरंतर व अधिकतम प्रयोग हो, चिकित्सकीय ढांचे को और अधिक विकसित व मजबूत बनाना हो या अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करने के लिए, नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए तरह–तरह के राहत पैकेज की घोषणा करना हो। भारत में भी इस संबंध में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह कहते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी भारत विश्व बंधुत्व की भावना से पीछे नहीं हटा है। स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के तुरन्त बाद भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत एवं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की कानूनी अनिवार्यताओं के अंतर्गत विश्व के 90 से ज्यादा विभिन्न देशों को कुल 6.64 करोड़ वैक्सीन की खुराक भेजी हैं।

यद्यपि भारत में कोरोना से युद्ध के लिए पर्याप्त आर्थिक एवं चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन कोरोना की यह दूसरी लहर हमारे भारत के लिए इतनी तीव्र है कि भारत के आर्थिक संसाधन एवं चिकित्सकीय संसाधन कम पड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में संसाधन कम नहीं हैं। सरकार, समाज, विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र एवं विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं में आपसी समन्वय एवं संतुलन की कमी है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम, संतुलित एवं मितव्ययी प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ समस्याएं भी हैं जैसे ऑक्सीजन बनाने की क्षमता तो है लेकिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर उपलब्ध नहीं हैं। वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में तो हैं लेकिन अस्पतालों में उनका समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है। साथ ही सरकार के विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयासों के बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में गिरावट हो रही है। 2020 के विस्तृत लॉकडाउन तथा 2021 के कोरोना कर्फ्यू व कुछ जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन भी भारत की जीडीपी दर को नीचे घसीट रहा है।

भारत की उदारवादी विदेश नीति, वैक्सीन मैत्री अभियान एवं संपूर्ण संसार के विभिन्न देशों से मधुर संबंधों के कारण संसार के तमाम देश इस मुश्किल परिस्थिति में भारत की विभिन्न प्रकार से सहायता कर रहे हैं। सरकार ने भी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से एवं बजट आवंटन से भारत में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धि, कोरोना संक्रमण से मुक्ति हेतु दवाइयां, ऑक्सीजन, वैक्सीन इत्यादि की समुचित उपलब्धता हेतु भरसक प्रयास किये हैं तथा कर रही है। साथ ही साथ सरकार निजी क्षेत्र को भी इस बात के लिए निरंतर अभिप्रेरित कर रही है कि वो मजदूरों के पलायन को कम से कम करें, जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, मजदूरों को सेवा सुरक्षा की गारंटी दें इत्यादि। शिक्षा जगत प्रभावित ना हो इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। किसानों को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। भले ही कोरोना अपने भयावह रूप में भारत के सामने है लेकिन इस दशा में भी भारत एकजुट होकर इस स्थिति का सामना कर रहा है और भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को; देश के नागरिकों को तथा वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा को साथ लेकर चलते हुए इस त्रासदी से बचाने का संतुलित एवं संयमित प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा विश्व के बड़े एवं शक्तिशाली देश भी भारत के विभिन्न प्रयासों की सराहना कर रहें हैं।

दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से संपूर्ण विश्व अद्यतन अंतहीन लड़ाई में जुटा हुआ है। यह संतोषजनक तथ्य है कि विश्व के लगभग 16 देश इस महामारी पर पूर्ण रूप से काबू पा चुके हैं। वहीं 4 देश ऐसे हैं जहॉ पर कोरोना संक्रमण पर पर्याप्त रूप से काबू पाया जा चुका है और ये देश मास्क मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिये गये हैं। परंतु संपूर्ण विश्व के कोरोना मुक्त होने तक यह लडाई अभी लम्बे समय तक चलने की संभावना है क्योंकि अभी तक के अनगिनत सर्वेक्षणों, प्रयोगों, अनुसंधानों के बावजूद भी संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि यह महामारी प्राकृतिक है अथवा मानव निर्मित। हमें मास्क, सेनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, सफाई, सकारात्मकता; सभी मापदण्डों का अनुपालन करना होगा तभी हम इसका सामना कर सकेंगें। लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही हमें प्राकृतिक असंतुलन को भी कम करना होगा तभी मानवजाति का भविष्य सुखमय और सुरक्षित होगा।

आभार

'शोध मंथन' शोध पत्रिका का अप्रैल 2021 विशेषांक 'कोविड 19 महामारी से संघर्षरत विश्व एवं भारत –एक परिदृश्य' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस विशेषांक के लिए शोध पत्रों को आमंत्रित करना, उन्हें एकत्र करना तथा संपादन का कार्य करना संपादक मंडल के लिए एक बहुत ही अच्छा एवं ज्ञान– संवर्धनात्मक अनुभव रहा है। विषय की विस्तृतता, गहनता तथा बहुविषयक प्रकृति को देखते हुए संपादक मंडल ने उक्त शोध पत्रिका में योगदान हेतु विभिन्न उप शीर्षक भी निश्चित किए थे। ये उप शीर्षक हैं– कोरोना काल में व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, कोरोना काल में राहत पैकेज, कोरोना काल में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, कोरोना काल में समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन, कोविड 19–प्रतिरोधात्मक एवं सुधारात्मक नीतियाँ, कोविड–19 काल में भारत की वैश्विक भूमिका एवं प्रभुत्व, कोविड 19 काल में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य–सामाजिक एवं व्यावसायिक, कोविड–19 का वैश्विक एवं भारतीय वित्तीय बाजार पर प्रभाव, कोरोना अवधि में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव, लॉकडाउन–प्राकृतिक पर्यावरण हेतु एक वरदान, कोरोना अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, कोरोना वैक्सीन–निर्माण,उपलब्धता एवं वितरण, कोविड का दूसरा चक्र–चुनौतियाँ एवं तैयारियां, कोविड समय में वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों का योगदान; कोविड समय में साहित्यकारों, कवियों एवं कलाकारों का योगदान, कोविड–19 काल में NGOs की भूमिका, भारत सरकार की कल्याणकारी योजनायें, आत्मनिर्भर भारत एवं कौशल विकास, उद्यमिता विकास योजनायें–विश्व एवं भारत, उदारीकरण, विनिवेश एवं निजीकरण; वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस इत्यादि।

विभिन्न लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडी के माध्यम से एकत्र ज्ञान के इस अथाह सागर को हमने शोध पत्रिका के रूप में संकलित करा है। इस कार्य के लिए हम श्री विशाल मित्थल, अनु बुक्स, मेरठ का हार्दिक आभार करते हैं जिन्होंने हमारे संकलन को अपनी प्रतिष्ठित, अन्तर्राष्ट्रीय एवं सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रिका 'शोध मंथन' के विशेषांक अप्रैल 2021 के रूप में प्रकाशित करने की सहमति प्रदान की। हम श्री विशाल मित्थल एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही मैं अपने अनुभवी विद्वान साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ संपादन के कार्य में जुड़े हुए हैं। मैं डॉ0 संजय कुमार बंसल, एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा तथा डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता, एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद का अपने साथ संपादक के रूप में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता को इस विशेषांक के सम्पूर्ण कार्य के प्रबंधन एवं समन्वय के लिए विशिष्ट धन्यवाद देता हूँ।

साथ ही मैं अपने सहकर्मी समीक्षा मंडल के विभिन्न साथियों का उक्त शोध पत्रिका की विभिन्न सामग्री के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सामयिक सलाह एवं सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं इस शोध पत्रिका के लिए अपने लेखों, शोध पत्रों एवं केस स्टडीज के माध्यम से योगदान करने हेतु सभी विषय विशेषज्ञों, प्रोफेसर्स, शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

यद्यपि इस शोध पत्रिका एवं इसके प्रकाशन को हर संभव प्रकार से त्रुटिरहित बनाने का भरकस प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ अवांछित त्रुटियां संभावित हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

सधन्यवाद!

डॉ० अभय कुमार मीतल

मुख्य संपादक

विषय-सूची

1. कोविड की वापसी : आकलन एवं चुनौतियाँ
डॉ0 अभय कुमार मीतल 1

2. टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन
डॉ0 संजय कुमार बंसल 6

3. भारत में कोविड–19 टीकाकरण प्रबंधन–एक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अध्ययन
डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता 11

4. कोरोना का दूसरा चक्र – चुनौतियाँ व सावधानियाँ
डॉ0 गीतम सिंह 17

5. भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ
डॉ० कमल सिंह 20

6. वोकल फॉर लोकल
डॉ0 मोनिका अग्रवाल 24

7. मेक इन इण्डिया
डॉ0 शैलेष कुमार पाण्डेय 27

8. कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
डॉ0 अंकुर अग्रवाल, डॉ0 शिवाली चौहान 32

9. कोविड–19 और भारतीय अर्थव्यवस्था
डॉ0 अभय कुमार मीतल, डॉ0 अभिजित मिश्रा 37

10. कोरोना काल में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत
डॉ0 पिंकी बिष्ट 41

11. कोविड–19 महामारी के दौर में मेक इन इंडिया के तहत फार्मास्युटिकल सेक्टर का अवलोकन
डॉ0 श्रवण कुमार 45

12. भारत में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व – कोरोना महामारी के विशेष सन्दर्भ में
डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता 49

13. कोरोना संक्रमण और औषधीय पौधे
डॉ0 रेनू शर्मा 55

14. लॉकडाउन – प्राकृतिक पर्यावरण हेतु एक वरदान
डॉ0 अनिता ए. पाण्डेय 59

15. आत्म–निर्भर भारत एवं कौशल विकास
डॉ० कमल सिंह 63

16. कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन
डॉ0 संजय कुमार बंसल 67

17. कोरोना अवधि में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव
डॉ0 भूपेन्द्र सिंह, विकास शर्मा 70

18. उदारीकरण, विनिवेश एवं निजीकरण
डॉ0 कविता भटनागर 73

19. उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण (भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में)
डॉ0 सीमा मलिक 77

20. कोविड–19 बनाम सरकार की राष्ट्रीय योजना एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
डॉ0 नीरज कुमार, डॉ0 अंकुर अग्रवाल 82

21. कोविड–19 महामारी एवं ट्रिप्स समझौता
डॉ0 श्रवण कुमार 87

22. कोरोना काल में समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन
डॉ0 दीप्ति गुप्ता 89

23. कोविड–19 का दूसरा चक्र : चुनौतियाँ एवं तैयारियाँ
नीरज कुमार, डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता 94

24. लॉकडाउन, प्राकृतिक पर्यावरण एवं महामारी– अन्तर्सम्बन्ध
डॉ0 बी. पी. सिंह 97

25. कोविड–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं का महत्वपूर्ण योगदान एवं आम जनता को तनावमुक्त रखने की एक पहल
डॉ0 रत्ना गर्ग, अक्षय कुमार गोयल 100

26. वर्तमान समय में आध्यात्मिकता की महत्ता
डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह 105

27. कोविड–19 : भारतीय संस्कृति की ओर लौटने का संकेत
डॉ0 दीपा, डॉ0 प्रतीक गुप्ता, डॉ0 शैली रस्तौगी 108

28. बदलते परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज
डॉ0 अंजू बंसल 112

29. वाल्मीकिरामायणम् का उद्देश्य
डॉ0 रंजना अग्रवाल 117

30. जनपद प्रतापगढ़ के संयुक्त एवं एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन
डॉ0 योगेश कुमार, डॉ0 शैलेष कुमार पाण्डेय 122

1

कोविड की वापसी: आकलन एवं चुनौतियाँ

डॉ0 अभय कुमार मीतल

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य विभाग)

साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

कोरोना त्रासदी से सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। कोरोना की प्रथम लहर ने विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को ही सर्वाधिक त्रस्त नहीं किया, वरन् जर्मनी, ब्राजील, भारत, इटली, चाइना समेत विश्व के 220 देश इसकी चपेट में आ गए। प्रथम लहर के दुष्परिणामों से जूझता विश्व वैक्सीन के आने से प्रसन्न भी नहीं हो पाया था कि भयानकतम दूसरी लहर ने सम्पूर्ण विश्व में महामारी को चरम पर पहुंचा दिया। सारी सुरक्षा, सावधानियों के बाद भी हर देश में मानव जाति और अर्थव्यवस्थाएं दोनों ही इससे त्रस्त हैं। आंकड़े अत्यन्त भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अभी तक के सर्वेक्षण, प्रयोग, अनुसंधान यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि यह महामारी प्राकृतिक है अथवा मानव निर्मित। हमें मास्क, सेनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, सफाई, सकारात्मकता; सभी मापदण्डों का अनुपालन करना होगा तभी हम इसका सामना कर सकेंगें। साथ ही हमें प्राकृतिक असंतुलन को भी कम करना होगा तभी मानवजाति का भविष्य सुखमय और सुरक्षित होगा।

मुख्य शब्द– महाशक्ति, वैक्सीनेशन, प्राकृतिक असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक विदोहन

विश्व के पटल पर समय के अन्तराल पर कोई न कोई महामारी किसी न किसी रूप में दस्तक देती रहीं हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व चेचक, कॉलरा, स्पेनिश फलू, हैजा, प्लेग और न जाने क्या–क्या उस समय महामारी के रूप में प्रकट हुए जब संसाधन सीमित थे, आधुनिक सुविधाऐं, अनुसंधान की प्रक्रियाएं एवं विज्ञान भी उतना उन्नत नहीं था, चिकित्सकीय सुविधाएं भी अल्प थीं। यही कारण रहा कि ये सब एक भयावह स्वप्न की भांति मानव जाति के समक्ष उपस्थित हुईं और न केवल धन हानि हुई वरन् जनसंख्या के एक बडे भाग को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उस समय एवं काल में मानव–संसाधनों, सुविधाओं एवं वैज्ञानिक दृष्टि सें उतना सशक्त, समृद्ध एवं सम्पन्न भी नहीं था, यही कारण था कि इन महामारियों से निपटने के लिए जो भी प्रयास उस समय किए गए, वह अत्यन्त अल्प थे और वैश्विक स्तर पर अपार जन–धन का नुकसान हुआ और लगभग प्रत्येक देश अपने आप को असहाय सा अनुभव करता रहा ।

यदि पिछले कुछ समय की बात करें तो Swine flu, Bird flu, HIV, हैपेटाइटिस, डेंगू आदि अनेकों बीमारियां ऐसी आयीं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारी तबाही मचायी और मानव जाति को त्रस्त किया। यद्यपि यह लगभग 70 के दशक से बाद की घटनाएं हैं जब विज्ञान एवं चिकित्सा अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था पर थीं, संसाधनों की दृष्टि से भी विश्व सम्पन्न हुआ था। उसके बाद भी इन महामारियों ने वैश्विक स्तर पर अपना विकराल रूप प्रदर्शित किया और पुनः प्रकृति के सामने मानव सम्पन्न होते हुए भी असहाय सा खड़ा रहा। यहां एक विचारणीय एवं गहन शोध का विषय यह भी है कि ये जितनी भी त्रासदियां, महामारियां मानव के समक्ष उपस्थित हुईं हैं, वे वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं हैं अथवा मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक विदोहन एवं अस्वाभाविक एवं अनावश्यक रूप से प्रकृति दत्त संसाधनों से छेडछाड का परिणाम हैं। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका प्रत्युत्तर अति आवश्यक होने के साथ–साथ यह भी अनिवार्य है कि मनुष्य प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड न्यूनतम करे अन्यथा भविष्य में भी परिणाम घातक हो सकते हैं।

कोविड : एक वैश्विक परिदृश्य

सर्वविदित है कि कोविड की प्रथम आधिकारिक पुष्टि वुहान चाइना में हुई और 2019 के अन्त को इसके प्रकोप का प्रारम्भ माना जा सकता है। कोविड–19 या नोवल कोरोना वायरस को जनवरी 2020 में WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में स्वीकार किया गया। एक शोध के अनुसार इस कोरोना की प्रथम लहर में लगभग 70 प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों की उम्र 40 से अधिक थी और मृत्यु दर बहुत न्यून थी। इसके अतिरिक्त इस शोध के निष्कर्षों मे यह भी पाया गया कि कोरोना के कारण मृतक लोग पूर्व में भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। यह कोरोना का प्रकोप चाइना, अफ्रीका के रास्ते होता हुआ दिसम्बर 2020 तक अपने रौद्र रूप में सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हुआ। सम्पूर्ण विश्व और भारत में मास्क,

सैनिटाइजर, लॉकडाउन सब प्रकार के जतन मार्च–अप्रैल 2020 से प्रारम्भ किए गए। विश्व में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक कोरोना महामारी से प्रताड़ित हुआ है। अमेरिका में अब तक लगभग 3.39 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुये हैं तथा 6.05 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अपने सम्पूर्ण संसाधनों एवं शक्ति के बावजूद भी अमेरिका में इस कोरोना महामारी ने विनाश का वह दृश्य प्रस्तुत किया कि आम जन एवं सम्पूर्ण तंत्र त्राहि–त्राहि कर उठा। अन्य सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रूस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन आदि रहे। संपूर्ण विश्व के 222 देशों में कोरोना ने अपना कोहराम मचाया ।

जब सम्पूर्ण विश्व 2021 के प्रारम्भ में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में कुछ सफलता अनुभव कर रहा था, कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता पाकर सभी देश अपने आपको सुरक्षित सा अनुभव कर रहे थे, तभी इस कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी भयानकता के साथ वैश्विक स्तर पर दस्तक दी कि सम्पूर्ण विश्व मे ऐसा कोहराम मचा जो आज तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद इस दूसरी लहर में जहां प्रभावित व्यक्तियों की उम्र की अब कोई सीमा नहीं, 40 वर्ष से अधिक उम्र के साथ प्रभावितों में कम उम्र के भी अनेकों लोग हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में Death Rate में प्रथम लहर की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि हुई। अद्यतन गैर–सरकारी ऑकड़ों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में कुल लगभग 16.88 करोड़ लोग कोरोना प्रभावित हुये हैं जबकि लगभग 15.05 करोड लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की और पुनः स्वस्थ हो गए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर अद्यतन लगभग 35.06 लाख लोग काल के गाल में समा गए हैं व सम्पूर्ण विश्व में सक्रिय कोरोना प्रभावितों की संख्या लगभग 1.48 करोड है।

वैश्विक परिदृश्य में अब तक कोरोना महामारी के परिदृश्य को इस शोध पत्र में प्रस्तुत तालिका 1 से 4 द्वारा सुगमता से आकलित किया जा सकता है।

समाधान, सावधानियाँ व चुनौतियाँ

सम्पूर्ण विश्व पर कोरोना की इस दूसरी लहर ने अत्यन्त घातक प्रहार किया है। कोराना की पहली लहर के प्रभावों से अभी जनमानस उबर भी नहीं पाया था कि इस दूसरी लहर ने अपनी भयानकता से सम्पूर्ण मानव जाति और सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर दिया। यहां अवश्य उल्लेखनीय है कि कोविड–19 की इस दूसरी लहर के इस विनाशकारी रूप के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं भी उत्तरदायी हैं। यद्यपि विभिन्न शोधों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों ने कोरोना की इस दूसरी लहर की भविष्यवाणी पूर्व में ही कर रखी थी, परन्तु वैक्सीन आने की लापरवाही या प्रथम लहर पर नियंत्रण के अति उत्साह ने हम सबको वैश्विक स्तर पर लापरवाह सा कर दिया था। लोगों ने सुरक्षा चक्रों में शिथिलता प्रारम्भ कर दी थी जिसके कारण कोरोना महामारी की यह दूसरी लहर अपनी प्रथम लहर से भी भयावह रूप में प्रस्तुत हुई है। अभी तक कोरोना महामारी वैज्ञानिकों के लिए गंभीर शोध का विषय है। न्यूनतम से न्यूनतम तापमान या अधिकतम से अधिकतम तापमान से भी इस वायरस का अप्रभावित रहना विश्व वैज्ञानिकों के लिए एक विशिष्ट अचरज है। अभी तक यह ज्ञात करने में वैज्ञानिक असफल हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है अथवा किसी राष्ट्र के वैज्ञानिकों की मानवीय भूल अथवा दुराग्रहपूर्ण चेष्टा का परिणाम है। यथार्थ कुछ भी है परन्तु वर्तमान सत्य यही है कि सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या इससे त्रस्त है, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गयी हैं, आर्थिक ढांचा डगमगाने लगा है। सम्पूर्ण वैश्विक शक्तियों के संयुक्त प्रयासों, वैक्सीन की उपलब्धता तथा नित नए रोकथाम के उपायों के बाद भी इस पर नियंत्रण एक चुनौती सिद्ध हो रहा है।

जहां दूसरी कोरोना लहर अपने चरम पर है, वहीं वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी करके जनमानस के मन में भय और चिन्ता उत्पन्न कर दी है। परिस्थितियां निश्चय ही नियंत्रित अवश्य ही होगीं, मानव सदैव प्रयासरत रहने वाला प्राणी है, उसके प्रयास अवश्य फलीभूत होंगें। हमारा विज्ञान, हमारा चिकित्सा विज्ञान, हमारे प्रयास निश्चय ही इस महामारी के समूल नाश में सफल होंगें। परन्तु यह भी निश्चित है कि इतिहास के पन्नों और जनमानस के हृदय पर 2020–21 की यह भयावह महामारी अपने काले निशान अवश्य अंकित कर जाएगी। प्रथम लहर की असावधानियों और लापरवाहियों का ही परिणाम है कि कोरोना की दूसरी लहर इतना भयावह स्वरूप ले पायी। अतः हम सबको दूसरी लहर पर पूर्ण नियंत्रण एवं तीसरी लहर की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए लेशमात्र भी लापरवाह अब नहीं होना है और भविष्य के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन अवश्य करना है। संक्षेप में यह सावधानियां निम्न हो सकती हैं जिनके आधार पर जनमानस का जीवन कोरोना वायरस से अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है :

1. सभी को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करते हुए उपलब्ध वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवानी चाहिए।
2. न केवल स्वयं की वरन् घर–परिवार, मौहल्ले की पूर्ण साफ–सफाई का ध्यान रखें तथा सम्बन्धित अधिकारियों से सामन्जस्य बैठाकर सम्पूर्ण क्षेत्र के नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराएं।
3. सरकार द्वारा सुझायी गयी गाइडलाइन्स का यथावत् अनुपालन करें। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें ।
4. जब तक कोरोना का कहर जारी है सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्थानों पर न जायें। यदि जाना अति आवश्यक हो तो Social Distancing का विशेष ख्याल रखें।

5. घर से निकलते समय Double Mask का प्रयोग करें। मास्क को नियमित रूप से बदलते रहें अथवा उचित प्रकार से धोते और साफ करते रहें।
6. सेनीटाईजर का उपयोग निरन्तर किसी भी व्यक्ति से सम्पर्क के उपरांत करें। अपने कार्यालय अथवा बैठने के स्थान के सैनीटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करें।
7. तबियत खराब होने या कोरोना के लक्षण होने पर स्वयं घरेलू उपचार या Self Medication न करें तत्काल योग्य चिकित्सक से सम्पर्क करें और उसी की राय के अनुसार उपचार करें।
8. किसी भी दशा में नकारात्मकता एवं अवसाद को स्वयं पर अथवा अन्य लोगों पर न हावी होने दें। स्वयं भी सकारात्मक एवं प्रफुल्लित रहे तथा आस–पास के वातावरण को भी सकारात्मक रखें।
9. बुजुर्गों, बच्चों एवं पहले से किसी बीमार व्यक्ति का विशेष ख्याल रखें और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच योग्य चिकित्सक से कराते रहें।
10. शारीरिक व्यायाम, योग, पौष्टिक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और व्यसनों से बचें।

निष्कर्ष

धीरे–धीरे यह महामारी भी समाप्त हो ही जानी है परन्तु मानव जाति को इससे भविष्य के लिए सबक सीखना होगा। हमारे प्रकृति से खिलवाड़, वनों का कटान, नगरीय क्षेंत्रों का बढ़ना, औद्योगिक कबाड़ का उचित निस्तारण न होना, विनाशकारी गैसों का उत्सर्जन, नित नए वैज्ञानिक प्रयोग, प्रदूषण का बढ़ना और न जाने कितनी चुनौतियां हमारे सम्मुख हैं। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि यदि हमने प्रकृति से सामन्जस्य एवं सौहार्द स्थापित नहीं किया तो भविष्य में भी इसके भयावह परिणाम विभिन्न त्रासदियों एवं महामारियों के रूप में मानव जाति के सम्मुख आते ही रहेंगें। हमें स्वयं सजग होना होगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना होगा। हम विकास करें क्योंकि वह भी अवश्यमभावी प्रकिया है परन्तु प्रयास करें कि प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। यदि प्रकृति अनियंत्रित होगी तो निश्चित रूप से उसके दूरगामी भयावह परिणाम होंगें। अतः सम्पूर्ण मानव जाति को अपनी भविष्य की रणनीतियों में परिवर्तन करना होगा और भविष्य के प्रति सजगता बरतनी होगी, तभी मानव जाति के एक कल्याणकारी भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

कोरोना या कोविड–19 ने मानव जाति पर शारिरिक रूप से तो आघात किया ही है परन्तु उससे भी अधिक घातक और विचारणीय तथ्य यह है कि इसकी भयावहता ने मनुष्य–मात्र को मानसिक रूप से भी अशक्त बनाया है। सभी लोगों में एक अजीब और अनजाना सा भय भी व्याप्त हुआ है जिसके कारण मनुष्य की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं, उनका आत्मिक बल भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया है। इसके अतिरिक्त कोविड की सावधानी में सर्वाधिक प्रमुख दो गज की दूरी (Physical Distance) ने वास्तविक रूप से समाज में सामाजिक दूरी (Social Distance) भी उत्पन्न कर दी है। विवाह अथवा अन्य कार्यक्रमों में संख्या की सीमितता के प्रतिबन्धों के कारण व्यक्तियों की परस्पर सामाजिक दूरी बढ़ चुकी है। यही नहीं, कोविड के कारण मृत्यु होने पर अपने स्वजन भी स्पर्श एवं संस्कारों से अपने को अलग करे हुए हैं। यह वास्तविक सामाजिक दूरी का एक ऐसा उदाहरण है जिसने मानव मात्र को कोविड के भय से संवेदनहीन बना दिया है। हम एक दूसरे की मदद करने के स्थान पर दूरियां बनाने लगें हैं। निश्चय ही सामाजिक दृष्टि से यह एक भयावह स्थिति है। लगातार लॉकडाउन और उसके बढ़ते क्रम ने अनेकों व्यक्तियों एवं परिवारों के समक्ष रोजी–रोटी के गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिए हैं। राज्य, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हिल गयी हैं। अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट उत्पन्न हो गया है। शक्तिशाली राष्ट्र अपने को अशक्त और असहाय अनुभव कर रहें हैं। कोविड के कारण अनेकों और भी ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके प्रत्युत्तर शायद भविष्य के गर्भ में हैं। परन्तु हम सभी के लिए भी यह आवश्यक है कि हम इन सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से चिन्तन करें और इन प्रश्नों और समस्याओं से उबरने के लिए सार्थक प्रयास करें।

सन्दर्भ

- http://covid19 who.int
- http://worlddometers.info/coronavirus
- wikipedia.org
- www.ourworldindata.org
- www.ft.com (coronavirus tracker)
- www.wtc.org
- www.covid19india.org

तालिका 1

कुल कोरोना संक्रमितों की अद्यतन संख्या के आधार पर विश्व के 10 शीर्ष देश

देश का नाम	कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या	कुल कोरोना संक्रमितों का प्रतिशत विश्व के आधार पर
अमेरिका	33947189	20.11
भारत	27157795	16.09
ब्राजील	16195981	9.59
फ्रांस	5609050	3.32
तुर्की	5203385	3.08
रूस	5026168	2.98
यूके	4467310	2.65
इटली	4197892	2.49
जर्मनी	3662568	2.17
स्पेन	3652879	2.16
विश्व	**168830983**	

स्रोत– www.worldometers.info

तालिका 2

कोरोना से मृतकों की अद्यतन कुल संख्या के आधार पर विश्व के 10 शीर्ष देश

देश का नाम	कोरोना से मृतकों की कुल संख्या	कोरोना से मृतकों का प्रतिशत विश्व के आधार पर
अमेरिका	605208	17.26
ब्राजील	452224	12.90
भारत	311421	8.88
मेक्सिको	221960	6.33
यूके	127739	3.64
इटली	125501	3.58
रूस	119600	3.41
फ्रांस	108879	3.11
जर्मनी	88161	2.51
कोलंबिया	85666	2.44
विश्व	**3505776**	

स्रोत– www.worldometers.info

तालिका 3
सक्रिय कोरोना संक्रमितों की अद्यतन संख्या के आधार पर विश्व के 10 शीर्ष देश

देश का नाम	सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या	सक्रिय कोरोना संक्रमितों का प्रतिशत विश्व के आधार पर
अमेरिका	5735539	38.80
भारत	2495558	16.88
ब्राजील	1095425	7.41
ईरान	413912	2.80
अर्जेंटीना	354020	2.39
इटली	268145	1.81
रूस	264478	1.79
मेक्सिको	259872	1.76
फ्रांस	253943	1.72
स्पेन	170820	1.16
विश्व	**14782097**	

स्रोत– www.worldometers.info

तालिका 4
कोरोना से ठीक हुये संक्रमितों की अद्यतन संख्या के आधार पर विश्व के 10 शीर्ष देश

देश का नाम	कोरोना से ठीक हुये संक्रमितों की संख्या	कोरोना से ठीक हुये संक्रमितों की संख्या का प्रतिशत विश्व के आधार पर
अमेरिका	27606442	18.34
भारत	24350816	16.18
ब्राजील	14648332	9.73
तुर्की	5045508	3.35
रूस	4642090	3.08
यूके	4305971	2.86
इटली	3804246	2.53
स्पेन	3402258	2.26
अर्जेंटीना	3157660	2.10
पोलैंड	2630581	1.75
विश्व	**150543110**	

स्रोत– www.worldometers.info

2

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन

डॉ0 संजय कुमार बंसल

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा

सारांश

एक म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन के समूह (Pool) से बना है। इस पैसे को प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड निवेश से उत्पन्न रिटर्न को उस योजना के लिए निवेशकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है और इसलिए यूनिट का मूल्य खर्चों की कटौती के बाद तय होता है। इसे नेट एसेट वैल्यू के रूप में जाना जाता है। शोध पत्र का उद्देश्य टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन पिछले पाँच वर्षों के दौरान करना है जिसमें कोरोना अवधि का एक वर्ष शमिल है। शोध पत्र का उद्देश्य पिछले पांच साल के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है–योजनाओं के सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए। केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, जेएम टैक्स गेन फंड, बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड, पीजीआईएम इंडिया लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का प्रयोग शोध पत्र के उद्देश्यों के लिए लिया किया गया है।

परिचय

एक म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन के पूल से बना है। इस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य परिसंपत्तियों जैसे प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। ये म्यूचुअल फंड पेशेवर प्रबंधकों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये प्रबंधक पूंजी बाजार के बारे में विशेषज्ञ और जागरूक होते हैं। वे फंड की संपत्ति को आवंटित करते हैं और पूंजीगत लाभ या आय में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। यह आय फंड के निवेशकों के लिए होती है।

स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों की संयुक्त होल्डिंग को पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उद्देश्य अपने प्रॉस्पेक्टस में बताए गए निवेश उद्देश्यों से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि म्युचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कई लोगों से एक साथ पैसा लेती है और इसे स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करती है। फंड में प्रत्येक निवेशक इकाइयों का मालिक होता है, जो इन होल्डिंग्स के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कई म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं। निवेश का उद्देश्य सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट होता है। म्यूचुअल फंड निवेश से उत्पन्न रिटर्न उस योजना के लिए निवेशकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किए जाते हैं और इसलिए यूनिट का मूल्य खर्चों की कटौती के बाद तय होता है। इसे नेट एसेट वैल्यू के रूप में जाना जाता है। इस शोध पत्र में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों के लिये किया गया है जिसमें कोरोना अवधि का एक वर्ष शमिल है।

म्यूचुअल फंड के प्रकार

भारत में विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं। ये योजनाएँ विभिन्न लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मोटे तौर पर हम उन्हें तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड में विभाजित कर सकते हैं–

- **इक्विटी फंड्स–**

ये म्यूचुअल फंड योजनाएं मुख्य रूप से कई कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। शेयरों में निवेश तुलनात्मक रूप से जोखिम भरा है।

  - इनका उद्देश्य पूंजी बाजार में कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करना है।

- इनका उद्देश्य उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न उत्पन्न करना है।
- इससे धन सृजन होता है और पूंजी की वृद्धि की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

इक्विटी फंड निम्नलिखित हैं–

1. **लार्ज कैप फंड**– म्यूचुअल फंड्स बडी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में अपने कॉरपस का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं जिन्हें लार्ज कैप फंड कहा जाता है। लार्ज कैप फंड्स को निश्चित समय की अवधि में स्थिर और स्थायी रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। 'भरोसेमंद', 'प्रतिष्ठित' और 'मजबूत' तीन विशेषण हैं जो अक्सर एक लार्ज–कैप फंड का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
2. **मिड कैप फंड**– मिड कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। मिड–कैप वे हैं जो कंपनी आकार के संदर्भ में बड़े–कैप और छोटे–कैप के बीच हैं। तेजी के दौरान, मिड–कैप स्टॉक अपने बड़े–कैप समकक्षों को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां उपयुक्त विकास अवसरों की तलाश में विस्तार करना चाहती हैं। निवेशकों को, ध्यान देना चाहिए कि मिड कैप फंड में अंतर्निहित स्टॉक उनके लार्ज–कैप समकक्षों की तुलना में अधिक अस्थिर हैं। मिड कैप फंड में विवेकपूर्ण स्टॉक चयन, क्षेत्रों में विविधीकरण और बाजार समय के माध्यम से, फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न के लिए लक्ष्य रखते हैं।
3. **स्मॉल कैप फंड्स**– स्मॉल कैप शेयरों में आमतौर पर सबसे ज्यादा ग्रोथ क्षमता होती है, क्योंकि अंतर्निहित कंपनियां युवा होती हैं, और आक्रामक तरीके से विस्तार करना चाहती हैं। स्मॉल कैप फंड्स व्यापार या आर्थिक मंदी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे बड़े और मिड–कैप की तुलना में अधिक अस्थिर हो जाते हैं। वे निवेशक जो स्मॉल–कैप स्पेस में निवेश करने के इच्छुक हैं और उनके पास रिसर्च करने का समय नहीं है, लेकिन उच्च जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, वे स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं।
4. **फ्लेक्सी कैप फंड**– फ्लेक्सी–कैप फंड वे फंड होते हैं जो बाजार पूंजीकरण स्पेक्ट्रम, यानी लार्ज–कैप, मिड–कैप और स्मॉल–कैप शेयरों में कंपनियों में मिश्रित निवेश करते हैं। ये फंड सभी लार्ज–कैप, मिड–कैप और स्मॉल–कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं।
5. **सेक्टर फंड**– सेक्टर फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो एक प्रकार के व्यवसाय या क्षेत्र से संबंधित हैं। एक सेक्टेरियल फंड एक इक्विटी फंड है जो एक ही उद्योग या क्षेत्र से संबंधित व्यवसायों में निवेशकों के पैसे का निवेश करता है। उदाहरण– प्रौद्योगिकी फंड जो केवल प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करते हैं।
6. **थीमेटिक फंड**– यह एक सामान्य विषय में निवेश करता है। उदाहरण, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में वृद्धि से लाभान्वित होंगें। म्यूचुअल फंड जो कई क्षेत्रों के शेयरों में निवेश करते हैं, एक निर्धारित विषय के चारों ओर घूमते हैं उन्हें थीमेटिक फंड के रूप में जाना जाता है। सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को देखते हुए, थीमेटिक फंड कई क्षेत्रों में एक निर्धारित विषय के शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत निवेश करने के लिए कड़ाई से बाध्य हैं।
7. **टैक्स सेविंग स्कीम्स**– टैक्स सेविंग स्कीम वे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट के लिए क्वालीफाई करती हैं। निवेशक इन योजनाओं में पैसा लगा सकते हैं और धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की आय में कटौती का दावा कर सकते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड तीन साल की अनिवार्य लॉक–इन अवधि के साथ आते हैं।

- **डैट (Debt) फंड –**

डैट फंड वे म्यूचुअल फंड हैं जो बॉन्ड और ट्रेजरी बिल जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। डैट फंड उन व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं जो अत्यधिक अस्थिर इक्विटी बाजार में निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं। एक डैट फंड इक्विटी के सापेक्ष एक स्थिर लेकिन कम आय प्रदान करता है। डैट इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले को इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाली कंपनी को पैसा उधार देना माना जा सकता है। एक डैट फंड कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कामर्शियल पेपर और अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड–इंटरेस्ट जेनेरेटिंग सिक्योरिटीज में निवेश करता है। डैट फंड में निवेश करने का मूल कारण स्थिर ब्याज आय और पूंजीगत लाभ अर्जित करना है। ऋण अर्थात डैट साधनों के जारीकर्ता परिपक्वता अवधि के साथ–साथ ब्याज दर भी तय कर देते हैं। इसलिए, उन्हें–निश्चित–आय 'प्रतिभूतियों के रूप में भी जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार निम्न हैं–

1. कम अवधि फंड (निधि)
2. लिक्विड फंड
3. अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड
4. ओवरनाइट फंड
5. मनी मार्केट फंड

- **हाइब्रिड फंड्स–**

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स के वे प्रकार हैं जो एक से अधिक एसेट क्लास में निवेश करते हैं। अक्सर, वे इक्विटी और डैट एसेट्स का संयोजन होते हैं, और कभी–कभी उनमें गोल्ड या रियल एस्टेट भी शामिल होते हैं। इसमें कम सह–संबंध रखने वाली संपत्तियों को मिलाकर पोर्टफोलियो जोखिम को कम किया जा सकता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डैट निवेश का एक संयोजन है जो निवेश उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पिछले पांच साल के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
2. योजनाओं के सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाना।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध पत्र में द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है जो विभिन्न म्यूचुअल फंड वेबसाइटों से प्राप्त किये गये हैं। समंकों में NAV आधारित वृद्धिशील अध्ययन शामिल है। निवेशक ने एक विशेष म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, वह सामान्य रिटर्न की उम्मीद कर रहा है। निवेशक लाभ में वृद्धि हेतु चिंतित है। रिटर्न की गणना एनएवी के आधार पर विशेष तिथि के आधार पर की जाती है। हमने टैक्स सेविंग फंड्स (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स) अध्ययन हेतु लिए हैं। इन योजनाओं में तीन साल की लॉक–इन अवधि होती है। विश्लेषण के उद्देश्य से हमने ग्रोथ ऑप्शन के साथ डायरेक्ट प्लान लिया है।

हमने विश्लेषण के लिए निम्नलिखित योजनाएं ली हैं–

1. केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ फंड
2. जेएम टैक्स गेन फंड डायरेक्ट ग्रोथ
3. बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ
4. पीजीआईएम इंडिया लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ

विश्लेषण

Table 1
Lump sum Investment Return in %
(Investment Made 1 year, 2 years, 3 years, 5 years ago from 30.04.2021)

S.No.	Name	1 year ago	RANK	2 years ago	RANK	3 years ago	RANK	5 years ago	RANK
1	Canara Robeco Equity Tax Saver Direct Growth	66.60	4	24.91	2	17.82	1	18.03	2
2	JM Tax Gain Fund Direct Growth	71.18	2	20.3	4	12.51	4	17.31	3
3	BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Growth	70.68	3	31.53	1	13.84	2	19.58	1
4	PGIM India Long Term Equity Fund Direct Growth	71.51	1	20.32	3	13.02	3	16.22	4

Source: www.moneycontrol.com as on 30.04.2021

तालिका 1 में यह दिखाया गया है कि एकमुश्त राशि का निवेश एक साल, दो साल, तीन साल एवं पांच साल पहले किया गया था। हालांकि ऐसा लगता है कि पिछले एक साल में सभी फंडों का प्रदर्शन ऊंचा रहा है लेकिन इसका मुख्य कारण पूंजी बाजार निफ्टी है और सेंसेक्स उच्च स्तर पर है। पिछले एक साल में कंपनियों ने भारत में लॉकडाउन होने पर भी उच्च लाभप्रदता दिखाई क्योंकि उपभोग लगातार और वृद्धिशील था। समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को एक, दो, तीन, पांच वर्ष पहले और नेट एसेट वैल्यू आधार पर किया गया है। उपरोक्त चार के बीच सबसे अच्छा प्रदर्शनकारी कर–बचत म्यूचुअल फंड बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है।

Table 2
Lumpsum Investment Return in Rupees
(Investment Rs.10,000 Made 1 year, 2 years, 3 years, 4 years & 5 years ago from 30.04.2021)

	Date of Investment	30.4.20		30.4.19		30.4.18		30.4.17		30.4.16	
S.No.	Name	Value Rs.	RANK	Value Rs.	RANK	Value Rs.	RANK	Value Rs.	RANK	Value Rs.	RANK
1	Canara Robeco Equity Tax Saver Direct Growth	16659	4	15622	2	16363	1	18452	2	22894	2
2	JM Tax Gain Fund Direct Growth	17117	2	14487	4	14246	4	16128	4	22224	3
3	BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Growth	17067	3	17326	1	14758	2	19139	1	24458	1
4	PGIM India Long Term Equity Fund Direct Growth	17150	1	14492	3	14442	3	16142	3	21214	4

Source: www.moneycontrol.com as on 30.04.2021

तालिका 2 एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल एवं पांच साल पहले एकमुश्त 10000 रुपए के निवेश के 30 अप्रैल, 2021 को मूल्य को प्रदर्शित करती है। यह पाया गया है कि अधिकतम मूल्य बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का है। दूसरी रैंक है केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ की। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राशि लगभग दोगुनी हो गयी है।

Table 3
Systematic Investment Return in Rupees
(Investment Made 1 year, 2 years, 3 years, 5 years ago)

S.No.	Name	1 year	RANK	2 years	RANK	3 years	RANK	5 years	RANK
	Amount Invested @1,000 per month for	12,000		24,000		36,000		60,000	
1	Canara Robeco Equity Tax Saver Direct Growth – Market Value	15,316	3	33,415	2	52,785	2	99,161	2
2	JM Tax Gain Fund Direct Growth – Market Value	15,114	4	31,672	4	49,350	4	90,816	4
3	BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Growth – Market Value	15,727	1	35,075	1	55,167	1	1,07,727	1
4	PGIM India Long Term Equity Fund Direct Growth – Mkt Value	15,668	2	33,000	3	50,764	3	92,050	3

Source: www.moneycontrol.com as on 30.04.2021

तालिका 3 में यह दर्शाया गया है कि यदि इस योजना में निवेशक प्रति माह एक हजार रुपये का निवेश करता है, अगर उसने एक साल, दो साल, तीन साल, एवं पांच साल पहले से निवेश किया है, तो आज 30 अप्रैल, 2021 को उसकी इकाइयों का मूल्य क्या होगा। फिर से यह पाया गया कि बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के मामले में राशि सबसे अधिक है। पांच साल में निवेश की गई राशि सिर्फ 60,000 रुपये है और यह 1,07,727 रुपये हो गई। राशि दोगुनी से भी ज्यादा हो गयी है। अगला निवेश केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ है। पांच साल में निवेश की गई राशि सिर्फ 60,000 रुपये है और यह 99,161 रुपये हो गई। राशि लगभग दोगुनी हो गयी है।

Table 4
Net Asset Value (in Rupees)

S.No.	Name	As on 30.4.16	As on 30.4.17	As on 30.4.18	As on 30.4.19	As on 30.4.20	As on 30.4.21
1	Canara Robeco Equity Tax Saver Direct Growth	44.65	55.29	62.45	65.51	61.43	100.48
2	JM Tax Gain Fund Direct Growth	11.46	15.73	17.82	17.58	14.88	25.25
3	BOI AXA Tax Advantage Fund Direct Growth	37.46	47.46	61.72	52.88	53.68	91.36
4	PGIM India Long Term Equity Fund Direct Growth	09.96	13.00	14.50	14.49	12.27	20.97

Source: www.moneycontrol.com as on 30.04.2021

तालिका 4 में नेट ऐसेट वैल्यू में उतार–चढ़ाव लिया गया है। 30 अप्रैल 2020 तक पाया गया है कि पूंजी बाजार में गिरावट के कारण एनएवी कम था। लेकिन पिछले एक साल में कोविड 19 की अवधि को कवर करते हुए, बाजार वृद्धि की ओर है। सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक मूड में है। यही कारण है कि निधियों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य अधिक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से यह पता चला है कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड योजनाओं में हम टैक्स बचाने में सक्षम तो होते ही हैं और साथ ही कैपिटल वैल्यू भी बढ़ती है। जब कोई निवेशक व्यवस्थित तरीके से निवेश कर रहा है तो हम बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ और केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ फंड में सबसे अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन लेखक किसी फंड का समर्थन नहीं कर रहा है। इस लेख के पाठक निवेश के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। यह मात्र एक शैक्षिक शोध पत्र है।

संदर्भ

1. www.mutualfundindia.com
2. www.moneycontrol.com
3. www.valueresearchonline.com
4. अन्य वित्तीय समाचार पत्रों की वेबसाइट

3

भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन-एक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अध्ययन

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय

साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

भारत में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए इस वैक्सीन का संतुलित एवं नियंत्रित प्रयोग बहुत आवश्यक है ताकि वैक्सीन और दवाइयों की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी ना हो सके और बिना किसी जाति, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक स्तर के भेदभाव के आधार पर; सभी संक्रमितों को टीका उपलब्ध हो। वैक्सीन प्रबंधन हेतु एक सरकार द्वारा एक विस्तृत नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत वैक्सीन नियोजन, निर्माण से लेकर उसके भंडारण, उसके परिवहन एवं उसके समुचित वितरण इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। भारत सरकार टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्थलों एवं निजी स्थलों दोनों के समन्वित प्रयोग के द्वारा, कोविन पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को डिजिटल आकार प्रकार देकर, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित कर, उपलब्ध वैक्सीन का प्राथमिकता आधार पर आयु विशेष एवं क्षेत्र विशेष के आधार पर आबंटन कर, सशुल्क एवं निःशुल्क दोनों ही प्रकार से टीका उपलब्ध कराकर एवं मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित कर एवं अन्य विभिन्न प्रकार से वैक्सीन उत्पादकों को प्रेरित कर वैक्सीन की पूर्ति बढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने इत्यादि विभिन्न प्रकार से टीकाकरण कार्यक्रम का प्रबंधन, क्रियान्वयन, समायोजन एवं नियंत्रण कर रही है और इस महामारी से लड़ने का सराहनीय प्रयास निरंतर कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास और कॉर्पोरेट जगत द्वारा विभिन्न प्रयासों से निश्चय ही भारत एक सशक्त चिकित्सीय ढांचा विकसित करेगा तथा इस कोरोना महामारी से जल्द ही भारतवासियों को निजात दिलाने में सक्षम हो पाएगा।

मुख्य शब्द– टीकाकरण प्रबंधन, कोविन पोर्टल, फ्रंटलाइन कर्मचारी, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत हम भारत में कोविड–19 टीकाकरण प्रबंधन के विभिन्न आयामों की व्याख्या करेंगे। कोविड–19 टीकाकरण प्रबंधन भारत के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कोरोना संक्रमण के संदर्भ में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है और भारत में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए इस वैक्सीन का संतुलित एवं नियंत्रित प्रयोग बहुत आवश्यक है ताकि वैक्सीन और दवाइयों की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी ना हो सके और बिना किसी जाति, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक स्तर के भेदभाव के आधार पर; सभी संक्रमितों को टीका उपलब्ध हो ।

वैक्सीन प्रबंधन हेतु एक सरकार द्वारा एक विस्तृत नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत वैक्सीन नियोजन, निर्माण से लेकर उसके भंडारण, उसके परिवहन एवं उसके समुचित वितरण इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यह टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गहन शोध मंथन के उपरांत तैयार किया गया है। वैक्सीन की आवश्यकता, निर्मित वैक्सीन, उपलब्ध वैक्सीन, प्रयुक्त वैक्सीन, बर्बाद वैक्सीन, टीका लगने वाले लाभान्वितों का पूरा डाटा बेस कोविन पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।

इस शोध पत्र में हम भारत में टीकाकरण प्रबंधन के विभिन्न आयामों के साथ–साथ अब तक भारत में लगाई गई कोरोना वैक्सीन से संबंधित कुछ परिमाणात्मक तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है।

भारत में कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम हेतु दो स्वदेशी दवाइयों को मान्यता दी गई है– 'कोवैक्सीन' तथा 'कोविडशील्ड'। रूस की वैक्सीन 'स्पुतनिक–V' को भी भारत में मंजूरी दे दी गई दी गई है लेकिन 30 अप्रैल तक भारत में केवल 'कोवैक्सीन' तथा 'कोविडशील्ड' का ही प्रयोग होता आ रहा है। रूस की वैक्सीन की पहली खेप भारत को मई 2021 माह में प्राप्त होगी। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी कई चरणों में लागू किया गया है। 1 मई 2021 से भारत में टीकाकरण का चतुर्थ चरण लागू होने वाला है।

भारत में टीकाकरण प्रबंधन के विभिन्न आयाम

- **कोविन पोर्टल एवं कोविन एप**

भारत में कोविड टीकाकरण की संपूर्ण प्रक्रिया कोविन पोर्टल एवं कोविन एप के माध्यम से डिजिटल बनायी गई है। टीकाकरण के प्रत्येक स्तर से संबंधित डाटा बेस यह एप तैयार करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपने पास के सरकारी अथवा निजी स्थल से अपने मनचाहे टीके को लगवाने की अपनी सुविधाजनक तिथि व समय पर अग्रिम बुकिंग/रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एप व्यक्ति को तिथि व समय आवंटित कर देता है जिस पर टीकाकरण स्थल पर जाकर टीका लगवाया जा सकता है। डाटा बेस भी साथ साथ तैयार होता रहता है। टीकाकरण की प्रत्येक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का डाटा कोविन पोर्टल में फीड करा जाता है चाहे वह वैक्सीन उपलब्धता हो, आवंटित किये गए टीकों की संख्या हो, टीका लगे व्यक्तियों का डाटा हो, प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज का डाटा हो, या वैक्सीन की बर्बादी का अथवा फीडबैक का इत्यादि। इस प्रकार कोविन पोर्टल एवं कोविन एप टीकाकरण कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण; सभी स्तरों पर कारगर है।

- **प्रशासनिक व्यवस्था**

भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के निर्माण, संशोधन, उसके क्रियान्वयन व परिपालन, नियमन, नियंत्रण एवं प्रतिपुष्टि हेतु एक बहुत ही सशक्त निम्न प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया है–

- **केंद्र स्तर पर**– केंद्र स्तर पर National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 अर्थात् NEGVAC का गठन किया गया है जिसका लक्ष्य भारत में कोविड–19 वैक्सीन के सभी पहलुओं पर नियोजन, मार्गदर्शन एवं नियमन करना है। वैक्सीन परीक्षण, वैक्सीन चयन, वैक्सीन के समान वितरण, खरीद, वित्तपोषण, वितरण तंत्र, जनसंख्या समूहों का प्राथमिकताकरण, टीका सुरक्षा निगरानी, क्षेत्रीय सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ समन्वय, संचार और मीडिया व्यवस्था आदि नेग्वेक के कार्य क्षेत्र में आते हैं ।
- **राज्य स्तर पर**–– राज्य स्तर पर स्टेट स्टीयरिंग कमिटी, स्टेट टास्क फोर्स तथा स्टेट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
- **जिला स्तर पर**– जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, अर्बन टास्क फोर्स तथा जिला/नगरपालिका कंट्रोल रूम बनाये गए हैं।
- **ब्लाक स्तर पर**–– खंड स्तर पर ब्लाक टास्क फोर्स एवं ब्लॉक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।

- **समन्वय**

टीकाकरण कार्यक्रम में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालय भी कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रहे हैं। हर मंत्रालय को सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए काम बांट रखें हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जॉन स्नो इंटरनेशनल हेल्थ केयर सलाहकार (जेएसआई), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) इत्यादि भी टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। साथ–साथ विभिन्न पेशेवर संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, रेड क्रॉस, सिविल सोसाइटी संस्थाएं (सीएसओएस), रोटरी क्लब, लायंस इंटरनेशनल क्लब इत्यादि टीकाकरण कार्यक्रम में सरकार के साथ परस्पर सहयोग कर रहे हैं।

- **वैक्सीनेशन उपरांत विपरीत प्रभावों का अवलोकन**

टीकाकरण के उपरांत होने वाले विपरीत प्रभावों के अध्ययन हेतु भी टीकाकरण कार्यक्रम में व्यवस्था की गयी है। इन प्रभावों का अध्ययन भावी शोध एवं वैक्सीन की गुणवत्ता वृद्धि में काम आयेगा। टीकाकरण के विपरीत प्रभावों को अध्ययन हेतु निम्न तीन हिस्सों में बांटा गया है–––

- सूक्ष्म प्रभाव– जैसे सूजन, ज्वर, खुजली, असहजता इत्यादि।
- गंभीर प्रभाव– 100 डिग्री से ज्यादा ज्वर, तीव्रग्राहिता (ANAPHYLAXIS) इत्यादि लेकिन जान का खतरा नहीं।
- अति गंभीर प्रभाव– जैसे मृत्यु हो जाना, स्थायी लकवा या विकलांगता होना, अस्पताल में भर्ती की नौबत आ जाना, सामुदायिक दुष्प्रभाव हो जाना, खून के थक्के जमना इत्यादि।

उपरोक्त दुष्प्रभावों को कोविन पोर्टल पर फीड़ करा जाता है तथा इन दुष्प्रभावों के अध्ययन व सुधारात्मक कार्यवाही हेतु एक राष्ट्रीय टीम भी गठित की गयी है। यह अत्यंत संतोषजनक है कि भारत में टीकाकरण के उपरांत होने वाले विपरीत प्रभाव मुख्यतया 'सूक्ष्म प्रकृति' के ही हैं। टीकाकरण के उपरांत होने वाले विपरीत प्रभावों का प्रतिशत भारत में लगभग 0.014 प्रतिशत है।

- **वैक्सीनेशन स्टाफ का प्रशिक्षण**

टीकाकरण कार्यक्रम हेतु सरकार ने संपूर्ण टीकाकरण व्यवस्था में लगे कार्मिकों (तकनीकी, चिकित्सीय एवं प्रशासनिक एवं अन्य) की समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है। यह व्यवस्था तीन प्रकार से करी गई है–

- प्रशिक्षक के माध्यम से ट्रेनिंग देना जिसमें क्लासरूम प्रशिक्षण एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शामिल है।
- सेल्फ लर्निंग प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से तथा
- उपरोक्त दोनों प्रकार के तरीकों के मिश्रण की सहायता से ट्रेनिंग देना।

वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व अभ्यास के रूप में ड्राई रन के आयोजन भी किये गयें हैं।

- **वैक्सीन भण्डारण एवं परिवहन प्रबंधन**

क्योंकि कोविड–19 की वैक्सीन को सही रखने के लिए उसे एक पूर्व निश्चित तापमान पर रखना जरूरी है अतः सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि वैक्सीन को बिल्कुल सही तापमान पर रखा जाए ताकि बर्बादी कम से कम हो। इस हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिकल एवं नॉन इलेक्ट्रिकल दोनों ही प्रकार के माध्यमों का प्रयोग पूर्व निश्चित किया गया है। वैक्सीन को बर्बादी से बचाए रखने हेतु निम्न स्थानों पर शीतन व्यवस्थाओं की जरूरत है–

- वैक्सीन भंडारण स्तर पर कोल्ड चेन बिंदुओं की व्यवस्था
- वैक्सीन का एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरण करते समय
- टीकाकरण स्थल पर

उपरोक्त प्रत्येक स्तर के लिए भंडारण हेतु आवश्यक शीतन व्यवस्था के नियम इस टीकाकरण कार्यक्रम में प्रदान करे गए हैं। वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिकल एवं नॉन इलेक्ट्रिकल शीतन माध्यमों के साथ–साथ उपयुक्त त्वरित परिवहन माध्यम के चयन की भी बात की गयी है ताकि वैक्सीन का पूर्व निश्चित तापमान मानक स्तर के विपरीत ना चला जाए और साथ ही वैक्सीन अपने नियत स्थल पर समय से पहुंच जाये।

- **टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार**

भारत सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यमों से भारत में टीकाकरण कार्यक्रम एवं इसके विभिन्न पहलुओं के आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु व्यवस्था की गई है । प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जन जागरण को कोविड टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

- **वैक्सीनेशन हेतु चरण**

भारत में वैक्सीनेशन हेतु निम्न चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई गयी है–

- **प्रथम चरण**– भारत में कोविड–19 वैक्सीनेशन का प्रथम चरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर कर्मचारियों एवं फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया ।
- **द्वितीय चरण**– कोविड–19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत 60 वर्ष या ज्यादा उम्र के नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गंभीर रोग से पीड़ित 45 से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिये भी इस चरण में टीका लगाने की शुरुआत हुई।
- **तृतीय चरण**– वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ इसके अंतर्गत 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया।
- **चतुर्थ चरण**– चौथे चरण में जो कि 1 मई 2021 से शुरू होगा; 18 साल एवं उससे ज्यादा वाली उम्र के व्यक्तियों को भी टीका लगवाने की अनुमति होगी।

- **वैक्सीन के प्रकार**

- **कोवैक्सीन**– भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन 'कोवैक्सीन' का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च– नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से किया गया है।
- **कोविडशील्ड**–– भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली दूसरी स्वदेशी वैक्सीन 'कोविडशील्ड' सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (साइरस पूनावाला ग्रुप) द्वारा विकसित की गयी है।

उपरोक्त के अलावा रूस की स्पुतनिक–V वैक्सीन को भी भारत में आकस्मिक प्रयोग की अनुमति दे दी गयी है। वैक्सीन के अतिरिक्त मरीजों के इलाज हेतु सरकार आवश्यक दवाइयों जैसे रेमेडीसिवर, फेबीफ्लू इत्यादि की पूर्ति का नियमन भी कर रही है।

टीकाकरण प्रबंधन संबंधित कुछ परिमाणात्मक तथ्य

- सारणी 1 में भारत में 30 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण की स्थिति को दर्शाया गया है । इस तिथि तक भारत में कुल कोरोना संक्रमण (30 जनवरी 2020 को भारत के केरल में कोरोना की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2021तक) लगभग 1.88 करोड लोगों को था। उपरोक्त अवधि में महामारी से ठीक हुए मरीजों की संख्या लगभग 1.54 करोड़ तथा कुल मृत्यु की संख्या 208330 है। ये संख्यायें प्रदर्शित करती हैं कि भारत में कोरोना काल से प्रारंभ से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक की तिथि तक लगभग 81.99 प्रतिशत लोग ठीक हो चुकें हैं। उपरोक्त अवधि में मृत्यु दर 1.11 प्रतिशत है। 30 अप्रैल 2021 को कुल कोरोना संक्रमितों का लगभग 16.90 प्रतिशत लोग अभी भी कोरोना से ग्रसित हैं ।

- सारणी एक में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 30 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण की स्थिति को भी दर्शाया गया है । इस तिथि तक उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमण (30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक) लगभग 12.18 लाख लोगों को था। उपरोक्त अवधि में महामारी से ठीक हुए मरीजों की संख्या लगभग 8.97 लाख़ तथा कुल मृत्यु की संख्या 12238 है। ये संख्याये प्रदर्शित करती हैं कि कोरोना काल से प्रारंभ से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक की तिथि तक लगभग 73.61 प्रतिशत लोग ठीक हो चुकें हैं। उपरोक्त अवधि में मृत्यु दर 1 प्रतिशत है। 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का लगभग 25.39 प्रतिशत लोग अभी भी कोरोना से ग्रसित हैं ।
- सारणी 2 में वैक्सीनेशन हेतु स्थलों की संख्या प्रदर्शित की गई है । 30 अप्रैल 2021 को भारत में कुल 64042 जगहों पर वैक्सीन लगाए जा रही थी जिसमें लगभग 91.90 प्रतिशत सरकारी स्थल थे तथा 8.10 प्रतिशत निजी स्थल थे । उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुल वैक्सीनेशन स्थल 6482 थे जिसमें 92.24 प्रतिशत सरकारी स्थल थे तथा 7.76 प्रतिशत निजी स्थल थे ।
- सारणी 3 प्रदर्शित करती है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक भारत में अब तक लगभग 15.2 करोड टीके लगाए जा चुके हैं जिसमे से लगभग 82.5 प्रतिशत पहली खुराक तथा 17.5 प्रतिशत दूसरी खुराक के रूप में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लगभग 1.26 करोड लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं जिसमे से लगभग 81.75 प्रतिशत पहली खुराक तथा 18.25 प्रतिशत दूसरी खुराक के रूप में दिए गए हैं।
- सारणी 4 प्रदर्शित करती है कि संपूर्ण भारत में अब तक टीकाकरण कार्यक्रम से 12.54 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं जिसमें लगभग 52.23 प्रतिशत पुरुष तथा 47.77 प्रतिशत महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अब तक 1.03 करोड लाभान्वित हो चुके हैं लगभग 56.31 प्रतिशत पुरुष हैं और 43.69 प्रतिशत महिलाएं हैं ।
- सारणी 5 प्रदर्शित करती है कि टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक भारत में अब तक लगभग 15.2 करोड टीके लगाए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 90.66 प्रतिशत कोविडशिल्ड है तथा 9.34 प्रतिशत कोवैक्सीन है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो अब तक लगभग 1.26 करोड टीके लगाए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 89.68 प्रतिशत कोविडशिल्ड है तथा 10.32 प्रतिशत कोवैक्सीन है ।
- सारणी 6 प्रदर्शित करती है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक 12.54 करोड लोगों को टीका लगाया जा चुका है जिनमें से 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु के लोग 0.47 करोड़, 30 से 45 वर्ष तक की आयु के लोग 1.01 करोड़, 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग 5.77 करोड तथा 60 वर्ष या अधिक आयु के लोग 5.29 करोड़ हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक 102.36 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है जिनमें से 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु के लोग 4 लाख़, 30 से 45 वर्ष तक की आयु के लोग 8.22 लाख़, 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग 47.02 लाख तथा 60 वर्ष या अधिक आयु के लोग 43.12 लाख हैं। भारत एवं उत्तर प्रदेश दोनों के ही संदर्भ में टीकाकरण से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले आयु वर्ग 45 से 60 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं।
- भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक भारत में कोविन एप्प/पोर्टल पर 16.39 करोड़ रजिस्ट्रेशन टीकाकरण हेतु हो चुके हैं। इस संख्या में 4.24 करोड़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 9.57 करोड़ स्थल पर रजिस्ट्रेशन तथा 2.58 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैल्थवर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के हैं। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन 58.39 प्रतिशत स्थल पर रजिस्ट्रेशन हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में कोविड–19 से संघर्ष हेतु एक विस्तृत, सशक्त एवं संयमित नीति अपनाई गई है; चरणबद्ध तरीके से विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा साथ ही साथ टीके एवं दवाइयों की उपलब्धता, उनकी किस्म नियंत्रण, न्यूनतम बर्बादी, समुचित डेटाबेस इत्यादि का प्रबंधन लगभग प्रत्येक आयाम को भारतीय टीकाकरण नीति के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम एवं इसके प्रबंधन को उपरोक्त शोध पत्र में वर्णित विभिन्न बिंदुओं एवं विभिन्न सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्थलों एवं निजी स्थलों दोनों के समन्वित प्रयोग के द्वारा, कोविन ऐप के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को डिजिटल आकार प्रकार देकर, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित कर, उपलब्ध वैक्सीन का प्राथमिकता आधार पर आयु विशेष एवं क्षेत्र विशेष के आधार पर आबंटन कर, सशुल्क एवं निःशुल्क दोनों ही प्रकार से टीका उपलब्ध कराकर एवं मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित कर एवं अन्य विभिन्न प्रकार से वैक्सीन उत्पादकों को प्रेरित कर वैक्सीन की पूर्ति बढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने इत्यादि विभिन्न प्रकार से टीकाकरण कार्यक्रम का प्रबंधन, क्रियान्वयन, समायोजन एवं नियंत्रण कर रही है और इस महामारी से लड़ने का सराहनीय प्रयास निरंतर कर रही है। कुछ समस्याएं भी साथ साथ प्रकट हो रही हैं जैसे ऑक्सीजन की कमी एवं इसकी कालाबाजारी, वेन्टीलेटर्स की कमी, दवाइयों की अनुपलब्धता एवं उनकी कालाबाजारी, कोरोना हेतु टीके की अपर्याप्त पूर्ति, अस्पताल में बैड की कमी, एम्बुलेंस की कमी इत्यादि। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार, कॉर्पोरेट जगत तथा समाज एवं देश की नामी–गिरामी हस्तियां, गैर सरकारी संस्थान इत्यादि समन्वित रूप से प्रयासरत हैं। विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने हेतु ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करके तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता बढ़ाकर, कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक छापे मारकर तथा दोषियों

को उचित दंड देकर, आवश्यक अस्पताल तथा संबंधित विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था करके, बड़े शहरों में एम्बुलेंस की दरें नियमित कर इत्यादि विभिन्न प्रकार से जनता को राहत देने का निरंतर प्रयास करा जा रहा है। विदेशी सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम जो कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बहुत ही सशक्त, संतुलित, नियमित एवं लोचशील कार्यक्रम है जिसमें टीकाकरण से संबंधित सभी आयामों का समुचित चिंतन–मनन–अध्ययन के उपरांत नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जा रहा है। यहां पर यह भी कहना आवश्यक है कि भारत में चिकित्सीय उपकरणों, चिकित्सालयों, कोरोना हेतु आवश्यक दवाइयों तथा कोरोना हेतु टीकों का उत्पादन सार्थक रूप से निरंतर बढ़ाया जाने की परम आवश्यकता है ताकि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुष्प्रभावित ना हो तथा भारत कोरोना कि इस महामारी से कम से कम विनाश के साथ अपने आप को बाहर निकाल पाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास और कॉर्पोरेट जगत द्वारा विभिन्न प्रयासों से निश्चय ही भारत एक सशक्त चिकित्सीय ढांचा विकसित करेगा तथा इस कोरोना महामारी से जल्द ही भारतवासियों को निजात दिलाने में सक्षम हो पाएगा।

संदर्भ

- आरोग्य सेतु एप पर उपलब्ध सूचनाएँ
- भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ
- www.mohfw.gov.in
- www.cowin.gov.in
- www.india.gov.in

सारणी 1

कोरोना की वर्तमान स्थिति (30 अप्रैल 2021 को)

विवरण	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सक्रिय मरीज	3170228	16.90	309237	25.39
ठीक हो गए	15384418	81.99	896477	73.61
मृत्यु हो गयी	208330	1.11	12238	1.00
कुल संक्रमित	18762976	100.00	1217952	100.00

स्रोत–––आरोग्य सेतु एप पर उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 2

वैक्सीनेशन हेतु स्थलों की संख्या (30 अप्रैल 2021 को)

स्थल की प्रकृति	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकारी	58852	91.90	5979	92.24
निजी	5190	8.10	503	7.76
योग	64042	100.00	6482	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 3

कुल वैक्सीनेशन खुराक दी गयीं (30 अप्रैल 2021 तक)

विवरण	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या करोड़ में	प्रतिशत	संख्या करोड़ में	प्रतिशत
पहली खुराक	12.54	82.5	1.03	81.75
दूसरी खुराक	2.66	17.5	0.23	18.25
योग	15.2	100	1.26	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 4

वैक्सीनेशन से लाभान्वितों की संख्या (30 अप्रैल 2021 तक)

विवरण	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या करोड़ में	प्रतिशत	संख्या करोड़ में	प्रतिशत
पुरुष	6.55	52.23	0.58	56.31
स्त्री	5.99	47.77	0.45	43.69
योग	12.54	100.00	1.03	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 5

वैक्सीन का प्रकार (30 अप्रैल 2021 तक)

विवरण	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या करोड़ में	प्रतिशत	संख्या करोड़ में	प्रतिशत
कोविडशील्ड	13.78	90.66	1.13	89.68
कोवैक्सीन	1.42	9.34	0.13	10.32
योग	15.20	100.00	1.26	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 6

आयु के आधार पर लाभान्वितों की संख्या (30 अप्रैल 2021 तक)

आयु	संपूर्ण भारत		उत्तर प्रदेश	
	संख्या करोड़ में	प्रतिशत	संख्या लाख में	प्रतिशत
18 से 30 वर्ष	0.47	3.75	4.00	3.91
30 से 45 वर्ष	1.01	8.05	8.22	8.03
45 से 60 वर्ष	5.77	46.01	47.02	45.94
60 वर्ष एवं अधिक	5.29	42.19	43.12	42.13
योग	12.54	100.00	102.36	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

सारणी 7

कोविन एप/पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या (30 अप्रैल 2021 तक)

विवरण	संपूर्ण भारत	
	संख्या करोड़ में	प्रतिशत
ऑनलाइन	4.24	25.87
स्थल पर पंजीकरण	9.57	58.39
फ्रंट लाइन व हेल्थ केयर कर्मचारी	2.58	15.74
योग	16.39	100.00

स्रोत––– भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ

4

कोरोना का दूसरा चक्र - चुनौतियाँ व सावधानियाँ

डॉ0 गीतम सिंह

असिस्टैंट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

सारांश

कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को किंकर्तव्यविमूढ़ कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु कोई भी इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ समय पूर्व जो स्थिति नियंत्रण में थी, वह यकायक अनियंत्रित कैसे हो गई। इसमें संदेह नहीं कि एक वर्ग महामारी की वर्तमान विकरालता का जिम्मेदार सरकारी व्यवस्थाओं को ठहरा रहा है। कोई यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि व्यवस्था की कमियों के अलावा कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जिसे निभाने में हम से भारी चूक हुई है। हमारी विफलता का कारण हमारी घोर लापरवाही है। ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है जो यह मानकर चल रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता इसलिए न तो उन्हें वैक्सीन की जरूरत है, न मास्क की और न ही शारीरिक दूरी की। ऐसे लोगों की तादाद भी खूब है जो वैक्सीन लगवाने के बाद स्वयं को कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित मान बैठें हैं। बिना मास्क के प्रयोग के, साफ सफाई की अवहेलना और शारीरिक दूरी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य संसाधनों पर निर्भर रहा जाए ऐसा विकासशील देशों में तो संभव ही नहीं है। कोरोना की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए देश में सबसे अधिक जरूरत घरेलू स्तर पर संवाद को मजबूत बनाने की है। साथ ही ऐसे बहुआयामी पक्षों के सामने लाने की भी है जिससे इस महामारी का मुकाबला सकारात्मकता को बनाए रखते हुए किया जा सके। लॉकडाउन के बगैर स्वयं को अनुशासित करके महामारी से लड़ने की तैयारी हमें करनी ही होगी, वरना आने वाले समय में लोग दूसरी अघोषित महामारी अवसाद के शिकार हो जाएंगे, जिसका मुकाबला करना किसी भी अर्थव्यवस्था व सरकार के लिए असंभव होगा।

मुख्य शब्द– कोरोना वायरस, दूसरी लहर, टीकाकरण, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, सैनिटाइजेशन

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड–19 (COVID-19) रखा है जहां CO का अर्थ है कोरोना (CORONA), VI का अर्थ है वायरस (VIRUS), D का अर्थ है डिसीज (DISEASE) और 19 का अर्थ है साल 2019 यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। इस वायरस को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया जो धीरे–धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और यह बहुत ही घातक वायरस है।

कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को पहले से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। यह वायरस दिसंबर 2019 में सबसे पहले चीन के वुहान में पकड़ में आया था। कोरोना वायरस बीमारी में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड वॉश का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिशू पेपर से ढ़ककर रखें। अंडे व मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। जिन लोगों को बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी को 1 साल से अधिक समय हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारें मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही हैं। इसके लिए सख्ती भी बढाई गई है। आयोजनों, समारोह, विरोध प्रदर्शन, सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई है।

जनवरी से टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। इन सब के बावजूद भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं– पहला तो यह कि कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां 1 दिन में 97000 मामले होने में सितंबर तक का समय लग गया था वहीं इस साल 1 दिन में लगभग 4 लाख नये संक्रमितों का आंकड़ा फरवरी से 30 अप्रैल तक के कम समय में ही छू गया।

कोरोना फैलने की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह क्या है? सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं, "बाकी देशों से जो अनुभव आए हैं वह बताते हैं कि कोविड–19 अपनी दूसरी लहर में तेजी से फैलता है।'' लगभग सारे देशों में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन जब लोग असावधान हो जाते हैं तो वायरस के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाती हैं। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। बी.एल. कपूर अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट एंड रेस्पिरेट्री डिसीज विभाग के प्रमुख डॉ संदीप नागर इसके पीछे दो कारणों को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताते हुए कहते हैं कि जब से कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं, तब से लोग लापरवाह हो गए हैं। उन्होंने मास्क लगाना, बार–बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कम कर दिया है। साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद ही वह इम्यून हो गए हैं। अब उन्हें कोरोना नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी वजह है वायरस के नए वेरिएंट, वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं, वे ज्यादा संक्रामक हैं। यू.के. के नए स्ट्रेन में यही पाया गया था। ऐसे में वायरस और लोगों के व्यवहार में एक साथ हुए बदलाव ने दूसरी लहर को जन्म दिया है। भारत में पिछले कुछ समय में वायरस के नए वेरिएंट पाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है। मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न पाए गए हैं। इसका मतलब है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग–अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं। यहां ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वेरिएंट भी मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन वेरिएंट को सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है।

आई.सी.एम.आर. द्वारा किए गए एक सीरो सर्वे के फरवरी में आए नतीजों के मुताबिक हर पांच में से एक भारतीय को कोरोना वायरस हो चुका है। यह सर्वे 17 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किया गया था। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी चर्चा हुई थी। कहा गया था कि हर्ड इम्युनिटी आने पर कोविड–19 का खात्मा हो सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि कॉविड–19 के मामले में हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा लागू नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि ''हर्ड इम्यूनिटी का विचार एक छोटे से क्षेत्र के लिए होता है। इसके अलावा नए वेरिएंट के लिए शरीर में बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं होती है। सिर्फ संक्रमण से स्वस्थ होने से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। नई बीमारियों को वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ती है ताकि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन सके। 60 से 70 प्रतिशत आबादी में इम्यूनिटी आने पर ही उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए स्वतः बनी और वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का जीवन भर सुरक्षा देना जरूरी है लेकिन बीमारी के बाद आई इम्यूनिटी जीवन भर के लिए नहीं होती और न ही वैक्सीनेशन 60 से 70 प्रतिशत आबादी तक पहुंच पाया है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी ही या कब तक आ सकती है।" वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा हथियार बताया गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने में अभी काफी समय लगेगा। डॉक्टर संदीप नायक बताते हैं कि वैक्सीन तभी असर करती है जब उसके दोनों डोज लग जाते हैं। पहली डोज के लगभग एक महीने बाद दूसरी डोज लगती है और उसके 14 दिनों बाद इम्यूनिटी बननी शुरु होती है। ऐसे में अभी 1.38 अरब की आबादी में से लगभग 12.5 करोड़ को ही वैक्सीन लगी है। वह लोग और भी कम हैं जिन्हें दूसरी ड़ोज लग चुकी है। इसलिए वैक्सीन का प्रभाव दिखने में अभी वक्त लगेगा। भारत में कोविड–19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से शुरू हुई थी। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों वाले 45 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इसे खोला गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहली की तुलना में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो बिना देर किए अगले ही दिन उनकी जांच कराई जानी चाहिए यह कहना है मुंबई के रिलायंस अस्पताल के कंसल्टेंट बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष राव का। डॉक्टर सुभाष ने कहा कि कोरोना वायरस म्यूटेशन हुआ है और उसका मौजूदा स्ट्रेन बहुत अधिक संक्रामक है खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में विपरीत रुख नजर आ रहा है। इसमें बड़े लोगों की तुलना में बच्चों को जल्दी लक्षण नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और उनसे बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में पहले लक्षणों के साथ ही बुखार आना, ठंड लगना, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त, भूख नहीं लगना जैसे लक्षण भी नजर आते हैं तो दूसरे दिन ही उनका आर.टी.पी.सी.आर. कराना चाहिए। तुरंत जांच से इलाज भी जल्द शुरू हो जायेगा। जांच में हिचक खतरनाक हो सकती है क्योंकि इससे इलाज में देरी तो होगी ही, संक्रमण भी फैलेगा।

कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को किंकर्तव्यविमूढ़ कर दिया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु कोई भी इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ समय पूर्व जो स्थिति नियंत्रण में थी, वह यकायक अनियंत्रित कैसे हो गई। इसमें संदेह नहीं कि एक वर्ग महामारी की वर्तमान विकरालता का जिम्मेदार सरकारी व्यवस्थाओं को ठहरा रहा है और यह कोई नई बात नहीं है कि दुनिया में जब महामारी का कोई भी रूप सामने आता है तो चारों तरफ आरोप–प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। यह प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही

है। सफलता का श्रेय लेने के लिए सभी तत्पर रहते हैं और असफलताओं की जिम्मेदारी लेने का साहस किसी में नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि समाज का एक अभिन्न भाग होने के कारण सफलताओं और विफलताओं में हमारी सामूहिक भूमिका होती है। सरकारें क्या कर सकती हैं और सरकार की क्या खामियां हैं? आज चारों ओर विमर्श का विषय यही है, ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परंतु कहीं कोई यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि व्यवस्था की कमियों के अलावा कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जिसे निभाने में हम से भारी चूक हुई है। दुनिया में जब कोविड–19 की पहली लहर ने दस्तक दी थी तो कोई समझ ही नहीं पाया था कि यह सब क्यों और किन कारणों से हो रहा है। महामारी के अचानक हमले के लिए कोई तैयार नहीं था। फलस्वरुप सरकारों ने कठोर लॉकडाउन सहित कई कठोर कदम उठाए। उससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई परंतु ज्यादा जरूरी था मानवीय जीवन की रक्षा। पिछले साल और वर्तमान में महामारी के स्वरूप में जो अंतर है वह व्यवस्थागत से कहीं अधिक हमारी जागरूकता की विफलताओं का है क्योंकि अभी तक हम सब जान चुके हैं कि कोविड–19 क्या है, उससे लड़ने और बचाव के तरीकों से भी लगभग सभी परिचित हो चुके हैं। हमारी विफलता का कारण हमारी घोर लापरवाही है। ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है जो यह मानकर चल रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता इसलिए न तो उन्हें वैक्सीन की जरूरत है, न मास्क की और न ही शारीरिक दूरी की। ऐसे लोगों की तादाद भी खूब है जो वैक्सीन लगवाने के बाद स्वयं को कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित मान बैठें हैं। बिना मास्क के प्रयोग के, साफ सफाई की अवहेलना और शारीरिक दूरी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य संसाधनों पर निर्भर रहा जाए ऐसा विकासशील देशों में तो संभव ही नहीं है।

'लैजरेटो इन यूरोप ड्यूब्रोन्विक–द बिगिनिंग ऑफ द क्वारंटाइन रेगुलेशन इन यूरोप' नामक एक शोध में वर्तमान परिस्थितियों का हल दिखाई देता है। चौदहवीं शताब्दी में यूरोप में फैले प्लेग को रोकने के लिए तत्कालीन 'रगुजा' महापरिषद ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए 1377 में कानून बनाया। इसके मुताबिक जाने वाले जहाज व्यापारियों के काफिले को 30 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होता था। अमेरिका स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1918–1919 में स्पेनिश फ्लू के अध्ययन में पाया कि उस महामारी से दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई थी। उस दौरान भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, मरीजों को पृथक रखना, साफ–सफाई जैसे उपाय बीमारी की नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी साबित हुए थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, सेंट लुइस, मिलराको और कंसास में उन शहरों के मुकाबले मृत्यु दर में 30 से 50 प्रतिशत की कमी रही, जहां ऐहतियाती कदम बाद में उठाए गए।

निष्कर्ष

आत्म–अनुशासन व स्वच्छता से इतर हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह भीड़ पर सख्ती करने और कोरोना को रोकने के लिए तालाबंदी करे, क्या यह न्यायोचित होगा, क्योंकि बीते साल तालाबंदी ने तमाम लोगों का रोजगार छीन लिया था। लॉकडाउन स्थायी हल नहीं हो सकता। कोरोना खत्म होने में कितना समय लगेगा। वैज्ञानिक इस पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए कोरोना के प्रति सावधानी बरतना और उस मार्ग को अपनाना जरूरी हो जाता है, जहां मानव जीवन की रक्षा के साथ–साथ, जीविकोपार्जन के साधनों पर भी कुठाराघात ना हो। कोरोना की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए देश में सबसे अधिक जरूरत घरेलू स्तर पर संवाद को मजबूत बनाने की है। साथ ही ऐसे बहुआयामी पक्षों के सामने लाने की भी है जिससे इस महामारी का मुकाबला सकारात्मकता को बनाए रखते हुए किया जा सके। लॉकडाउन के बगैर स्वयं को अनुशासित करके महामारी से लड़ने की तैयारी हमें करनी ही होगी, वरना आने वाले समय में लोग दूसरी अघोषित महामारी अवसाद के शिकार हो जाएंगे, जिसका मुकाबला करना किसी भी अर्थव्यवस्था व सरकार के लिए असंभव होगा। अंत में कहा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कर हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ

1. विभिन्न समाचार पत्र एवं विभिन्न समाचार चैनल
2. www.covid19.com

5

भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ

डॉ० कमल सिंह

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय

हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, उ०प्र०

सारांश

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है, यहाँ की अधिकाँश जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकाँश देशों में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, जो अपने–अपने देश के नागरिकों का कल्याण कर रही हैं। वर्तमान भारत सरकार मई 2014 से लगातार कार्य कर रही है, जो अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की अधिकाँश जनता का कल्याण कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने प्रस्तावना, भारत सरकार की मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त परिचय, वर्तमान भारत सरकार की 5 मुख्य योजनाओं का विस्तृत अध्ययन, भारत सरकार की मुख्य योजनाओं का देश के सर्वांगीण विकास में योगदान का अध्ययन किया है तथा साथ ही साथ हमने एन०डी०ए० सरकार एवं यू०पी०ए० सरकार की कुछ मुख्य योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं, कि जो योजनाएँ भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं, वह देश की अधिकाँश जनता की आकाँक्षाओं पर खरी उतर रहीं हैं।

मुख्य शब्द– एन०डी०ए०, यू०पी०ए०, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बुनियादी ढाँचा, कल्याणकारी योजनाएँ

प्रस्तावना

विश्व के अधिकाँश देशों में सरकारों द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं, जो अपने नागरिकों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों में सर्वांगींण विकास कर रही हैं। भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है, यहाँ के अधिकाँश लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। भारत में भी प्राचीनकाल से ही अनेक ऐसे कार्य शासक या सरकारों द्वारा किये जाते रहे हैं, जो देश की जनता के कल्याण के लिए हों। भारत में मई 2014 से लगातार एन०डी०ए० की सरकार कार्यरत है। भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सख्त एवं तुरन्त फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। भारत के प्रधानमन्त्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही उन्होनें देश के विकास एवं कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनायी हैं, जो देश के विकास एवं कल्याण में सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रधानमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन–ज्योति बीमा योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना, उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना एवं आयुष्मान भारत योजना आदि। ये योजनाऐं देश के कल्याण एवं विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहीं हैं।

भारत सरकार की मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा अनेकों योजनाएँ देश के लोगों के कल्याण के लिए चलायी जा रही हैं, जिनमें से कुछ मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न है–

1. **प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना** :– यह योजना भारत में 1 मई, 2016 को प्रारम्भ की गयी थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के बी०पी०एल० परिवारों को मुफ्त एल०पी०जी० कनेक्शन देना है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बी०पी०एल० परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रू० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 8 करोड़ लोगों को एल०पी०जी० सिलेण्डर बाँटे जा चुके हैं।
2. **प्रधानमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना** :– यह योजना 9 मई, 2015 को कोलकता से शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता है। इस स्कीम के तहत सिर्फ 12 रू० का प्रीमियम देकर एक्सीडेन्ट कवर पाया जा सकता है। इसके तहत 12 रू० के वार्षिक प्रीमियम पर एक्सीडेन्ट से मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी व्यक्ति को 2 लाख रू० की राशि मिलती है।

3. **प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना** :– इस योजना के अर्न्तगत 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रू० वार्षिक का प्रीमियम देकर 2 लाख रूपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
4. **मेक इन इण्डिया योजना** :– इस योजना का शुभारंभ 25 सितम्बर, 2014 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कौशल विकास के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
5. **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना** :– यह योजना सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा 22 जनवरी, 2015 को प्रारम्भ की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है।
6. **स्मार्ट सिटी योजना** :– इस योजना का शुभारंभ 25 जून, 2015 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 100 मुख्य शहरों का चयन करके स्थानीय विकास को सक्षम और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाना है।
7. **नमामि गंगे योजना** :– इस योजना का शुभारंभ 10 जुलाई, 2014 को भारतीय जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा किया गया। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी को पुनजीर्वित करना है।
8. **सौभाग्य योजना** :– प्रधानमन्त्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना का शुभारंभ भारत के बिजली मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी घरों का विद्युतीकरण करना है, जहाँ बिजली नहीं है।
9. **प्रधानमन्त्री आवास योजना** :– इस योजना का शुभारंभ 25 जून, 2015 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नये घरों का निर्माण करके गरीब लोगों को गृह प्रवेश कराना है।
10. **सांसद आदर्श ग्राम योजना** :– यह योजना जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर 11 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक तीन गॉवों तथा 2024 तक कुल 8 गॉवों को गोद लेकर विकसित करना है।
11. **प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना– आयुष्मान भारत** :– यह योजना 23 सितम्बर, 2018 को झारखण्ड की राजधानी राँची से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रू० तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
12. **डिजिटल इण्डिया मिशन** :– यह योजना भारत में 1 जुलाई, 2015 को प्रारम्भ की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की सभी सरकारी सेवाओं को इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है।
13. **स्किल इण्डिया मिशन** :– यह योजना भारत में 15 जुलाई, 2015 को प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के अधिक से अधिक युवाओं का कौशल विकास करना है।
14. **प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना** :– भारत में 1 फरवरी, 2019 को श्री पीयूष गोयल द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी पात्र किसानों को 2000 रू० की तीन किस्तें प्रत्येक वर्ष देना है।
15. **प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना** :– इस योजना का शुभारंभ श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 10 सितम्बर, 2020 को किया गया। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक सभी प्रदेशों और संघ शासित राज्यों में लागू करना है।
16. **अन्य मुख्य योजनाएँ** :– उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त मिशन इन्द्रधनुष अभियान, प्रधानमन्त्री 'मुद्रा' योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सेतु भारतम योजना, स्टैडअप इण्डिया, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, फिट इण्डिया मूवमेंट, गरीब कल्याण रोजगार योजना आदि हैं।

वर्तमान भारत सरकार की पाँच मुख्य योजनाओं का विस्तृत अध्ययन

भारत में वर्तमान समय में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, जो देश के नागरिकों का सर्वांगीण विकास कर रही हैं, उनमें से हम पाँच मुख्य योजनाओं का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं–

1. **स्टार्टअप इण्डिया योजना** :– यह योजना भारत में 16 जनवरी, 2016 को प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल मजबूत स्टार्टअप इको–सिस्टम व संस्कृति को बढ़ावा देने, उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ देश में नौकरी की माँग करने वालों के बजाय नौकरी देने वालों को विकसित करना है। इसके अन्तर्गत स्टार्टअप हेतु आसान अनुपालन, स्टार्टअप खोलने/बंद करने व अन्य कानूनी सहायता, अनुदान व प्रोत्साहन शामिल हैं।

2. **स्टैंडअप इण्डिया योजना** :– स्टैंडअप इण्डिया योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कारोबार को बढ़ावा देना है। इस योजना के अर्न्तगत 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक का लोन समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला कारोबारी को मिलता है, क्योंकि यह माना जाता है कि ये लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं, कि वह अपना कारोबार खुद कर सकें। इसलिए केन्द्र सरकार इन्हें कर्ज देती है।
3. **प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना** :– वर्ष 2015 से भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में यह पहला कदम था। इस योजना के अन्तर्गत देश के लगभग 1 करोड़ युवाओं को 2 महीने से 6 महीने तक का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाने का कार्य किया जा रहा है।
4. **प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना** :– भारत सरकार द्वारा यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गयी थी। यह योजना गैर–कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को 'शिशु' (50 हजार रूपये तक का ऋण), 'किशोर' (5 लाख रूपये तक का ऋण) और 'तरूण' (10 लाख रूपये तक का ऋण) का ऋण प्रदान कर नये उद्यम विकसित करने की दिशा में प्रयास है। ये ऋण किसी भी व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक एवं एन०बी०एफ०सी० द्वारा दिये जाते हैं।
5. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना** :– यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का अधिकार देती है। यह ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गयी पहलों में से एक है।

भारत सरकार की मुख्य योजनाओं का देश के सर्वांगीण विकास में योगदान

भारत सरकार द्वारा देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं, वह समस्त योजनाएँ अपने–अपने क्षेत्र में देश का सर्वांगीण विकास कर रही हैं। मोदीकेयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना भारत में 25 सितम्बर, 2019 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना को जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। प्रधानमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मात्र 12 रू० वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रू० का इंश्योरेन्स कवर दुघर्टना से मृत्यु होने पर उसके नामिनी को मिल जाता है। प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 330 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपये का बीमा कवर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उसके नामिनी को मिल जाता है। प्रधानमन्त्री दुर्घटना बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई, 2015 से लगातार चल रही हैं। इन दोनों योजनाओं से जुड़कर देश के करोडों लोग इसका फायदा उठा रहें हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। भारत में कृषि के लिए 12 जुलाई, 2015 को प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गयी। इस योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और उसके लिए सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिड़ी प्रदान करना है। 1 मई, 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को एल०पी०जी० कनेक्शन मुप्त दिये जा रहें हैं, जिसके अन्तर्गत गैस सिलेंडर एवं गैस चूल्हा फ्री में दिया जाता है। 25 जून, 2015 से पूरे देश में प्रधानमन्त्री आवास योजना चल रही है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए मकान बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से एवं अन्य समस्त योजनाओं के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है।

यू०पी०ए० सरकार की पाँच मुख्य योजनाओं का अध्ययन

एन०डी०ए० सरकार से पहले वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक भारत में यू०पी०ए० की सरकार थी। यू०पी०ए० सरकार भी देश के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ चला रही थी, उनमें से पाँच मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है–

1. **मनरेगा** :– इस योजना का पुराना नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) था। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना यू०पी०ए०–1 में 2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा था। यू०पी०ए०–1 की यह बहुत ही महत्वाकाँक्षी योजना थी। 2 अक्टूबर, 2009 को गाँधी जी के जन्म दिवस के मौके पर इस योजना का नाम महात्मा गाँधी नेशनल रोजगार गारन्टी अधिनियम कर दिया गया था। यू०पी०ए० सरकार अपने बजट में इस योजना पर सबसे अधिक धनराशि खर्च करती थी।
2. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०)** :– यू०पी०ए० सरकार की दूसरी सबसे बढ़ी योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) थी। इसका नाम बाद में बदलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया था। सरकार इस योजना पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करती थी। इस योजना में देश में बहुत बडा घोटाला भी हुआ था।
3. **प्रधानमन्त्री आवास योजना** :– इस योजना का पुराना नाम इन्दिरा आवास योजना था, जिसे बाद में बदलकर राजीव गाँधी आवास योजना कर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पात्र गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाते थे। इस योजना पर यू०पी०ए० की सरकार भारी–भरकम धनराशि खर्च करती थी।

4. **प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना** :– यह योजना भी यू०पी०ए० सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना पर सरकार भारी–भरकम धनराशि खर्च करती थी। इस योजना के अन्तर्गत देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया था, ताकि देश का सर्वांगीण विकास किया जा सके।
5. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– यू०पी०ए० सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर अच्छी–खासी धनराशि खर्च करती थी, क्योंकि भारतीय कृषि यहाँ के निवासियों की जीविका का मुख्य साधन है क्योंकि यहाँ की अधिकाँश जनता गाँवों में निवास करती है।

एन०डी०ए० सरकार एवं यू०पी०ए० सरकार की कुछ मुख्य योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

दोनों सरकारों की पाँच मुख्य योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन निम्न प्रकार है–

1. वर्ष 2014 तक देश के मात्र 54 प्रतिशत गाँव ही सड़क से जुड़े हुए थे, जो वर्ष 2014 के बाद एन०डी०ए० सरकार में बढ़कर 82 प्रतिशत तक पहुँच गये। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने प्रधानमन्त्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान एवं प्रधानमन्त्री सड़क योजना पर जमकर खर्च किया है।
2. सड़क यातायात पर राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार (एन०डी०ए०) का विशेष जोर रहा। वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 120543 किमी० का हो गया, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू०पी०ए०) सरकार के समय में वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क मात्र 92851 किमी० था। वर्ष 2013–14 में मात्र 12 किमी० प्रतिदिन की औसत से सड़क बन रही थी तो एन०डी०ए० की सरकार के समय वर्ष 2017–18 में प्रतिदिन का औसत 27 किमी० था।
3. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से बी०पी०एल० परिवारों को आवास बनवाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 45000 रू० एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 48500 रू० की धनराशि दी जाती थी। यह योजना पहली बार वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गयी थी। पी०एम० आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। जनवरी 2021 तक पूरे देश में 41 लाख घर पूरे हो चुके हैं, और लगभग 70 लाख आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। पी०एम० आवास योजना के अन्तर्गत घर खरीदने पर 2.67 लाख रूपये की सब्सिड़ी प्रदान की जाती है।
4. यू०पी०ए० सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना था। एन०डी०ए० सरकार ने वर्ष 2019 में आयुष्मान भारत योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना को मोदीकेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अन्तर्गत देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है।
5. 1 अप्रैल, 2010 को भारत सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। इसे यू०पी०ए० सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। एन०डी०ए० की सरकार ने 1 मई, 2016 को प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना चलायी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त बी०पी०एल० परिवारों को मुफ्त गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर तथा कनेक्शन देना है। इस योजना से अब तक लगभग 8 करोड़ परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। एन०डी०ए० सरकार की यह योजना बहुत बड़ी एवं अच्छी है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधानमन्त्री बने हैं, उन्होनें तब से ही भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए अनेकों योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। चाहे प्रधानमन्त्री आवास योजना हो या आयुष्मान योजना या प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना हो या पी०एम० किसान सम्मान निधि योजना तथा प्रधानमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना हो या प्रधानमन्त्री जीवन–ज्योति बीमा योजना या अन्य कोई भी योजना हो, ये समस्त योजनाएँ वर्तमान समय में बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, और अपने उद्देश्य में सफल हो रही हैं। वर्ष 2014 से पहले भारत में यू०पी०ए० की सरकार थी, उस सरकार की भी कई योजनाएँ जैसे मनरेगा एवं शिक्षा का अधिकार आदि बहुत ही अच्छी योजनाएँ थीं, जो देश का अच्छी तरह से विकास कर रही थीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, वह अच्छी तरह से काम कर रही हैं और देश का चौतरफा विकास कर रही हैं।

सन्दर्भ

1. करेन्ट अफेयर्स वार्षिकांक –2021
2. कुरूक्षेत्र– ग्रामीण विकास को समर्पित–मासिक पत्रिका–फरवरी, 2020
3. भारतीय अर्थव्यवस्था– वी०के० पुरी एवं एस०के० मिश्र
4. https://www. economictimes.com
5. https://www.aajtak.in>story
6. https://www.pmmodiyojana.in>pradhan

6

वोकल फॉर लोकल

डॉ0 मोनिका अग्रवाल
भूतपूर्व शोध छात्र, वाणिज्य विभाग
साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

देश के तीव्र विकास के लिए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल का संदेश सम्पूर्ण भारत को दिया गया। 15 अगस्त 2020 को अपना लगातार सातवां स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए देश के लोगों को श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की सराहना करनी चाहिए। यदि हम स्थानीय उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो यह न केवल स्थानीय पहचान को मजबूत करेगा बल्कि उस क्षेत्र के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। महामारी के दौरान लोकल उत्पादों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमें यह सबक सीखना चाहिए और स्थानीय उत्पादों को बढावा देना चाहिए ।

मुख्य शब्द– अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, आर्थिक पैकेज, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद

लोकल फॉर वोकल का अर्थ

पी0एम0 नरेन्द्र मोदी की ओर से देश में एक नई मुहिम चलाई गई है, जिसे मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल नाम दिया है। लोकल फॉर वोकल शब्द लोगों के लिए नया है और कई सारे लोगों को लोकल फॉर वोकल का अर्थ क्या है, लोकल फॉर वोकल के फायदे और ये नारा क्यों दिया गया है, इसके बारे में पता नहीं है।

देश की अर्थव्यस्था को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। लोकल फॉर वोकल के जरिए मोदी जी ने देश की जनता को देश में बने उत्पादों को खरीदने के लिए और देश में ही उत्पादों का निर्माण करने का संदेश दिया है।

लोकल फॉर वोकल का उद्देश्य

लोकल फॉर वोकल का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है जोकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आत्मनिर्भर बनाना है। नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जनता से अनुरोध किया है कि अब वो आत्मनिर्भर बनें और दूसरे देशों के उत्पादों पर निर्भर होना बंद कर दें। खुद से ही देश मे चीजों का उत्पादन किया जाए और भारत के लोग इन उत्पादों को ही खरीदें।

लोकल फॉर वोकल के फायदे

इसके फायदे निम्नलिखित हैं :–

1. लोकल फॉर वोकल की मदद से देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पहली बार किसी सरकार द्वारा की गई है।
2. लोकल फॉर वोकल की मदद से लोगों को अपना व्यापार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. इस अभियान की वजह से देश के लोगों को देश के उत्पादों को खरीदने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
4. ये कदम देश में नौकरियों की कमी को भी पूरा करेगा।

आखिर क्यों पड़ी लोकल फॉर वोकल की जरूरत

दरअसल भारत देश अन्य देशों पर काफी निर्भर करता है, जिसकी वजह से अन्य देशों की कंपनियां भारत में व्यापार करके खूब धन कमा रही हैं, ऐसा होने से इन देशों की अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत

करने की जगह क्यों न अपने देश में ही उत्पादन किया जाए ताकि हमारे देश की जनता स्वदेशी सामान खरीद सके और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिले।

कोरोना काल ने दी लोकल फॉर वोकल बनाने की सीख

कोरोना काल के दौरान देश को लोकल बनने का सबक मिला है। दरअसल कोरोना के वक्त भारत को पीपीई किट, टेस्टिंग किट व अन्य चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा था। वहीं चीन से जो पीपीई किट और टेस्टिंग किट भारत की ओर से खरीदे गए थे, वो सही नहीं थे। कोरोना के दौरान लोकल उत्पादों की अहमियत समझ आई और सरकार ने देश को लोकल फॉर वोकल बनाने की तरफ एक कदम उठाया।

भारत सरकार का लक्ष्य है कि लोकल प्रोडक्ट और लोकल सप्लाई चैन को देश में मजबूत करें। ऐसा करने से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा और लोकल अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। वहीं लोकल से ग्लोबल बनने का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा।

लोकल फॉर वोकल बनने के लिए भारत सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए और अब भारत में खुद से ही पीपीई किट, टेस्टिंग किट और दवाईयां बनायी जा रही हैं। कोरोना काल के दौरान कई सारी भारतीय कंपनियॉ आगे आयीं और इन उत्पादों को बनाया गया। ऐसा करने से इस बुरे दौर में लोगों को रोजगार मिल सका और साथ में ही देश ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी रखा।

मोदी जी के लोकल फॉर वोकल नारे की वजह से ही देश के लोग चीन के उत्पादों को खरीदने से बच रहे हैं और केवल उन्हीं उत्पादों को खरीद रहे हैं जो कि देश द्वारा बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है।

विदेशी कंपनियों का है कब्जा

भारत के कई सारे ऐसे बाजार हैं, जहां पर केवल विदेशी कंपनियों का ही दबदबा है, इसलिए अब वो समय आ गया है कि देश लोकल फॉर वोकल बनेगा और विदेशी कंपनियों के कब्जे को भारत ही हर मार्केट से हटायेगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बिस्कुट, चॉकलेट, पानी, चिप्स जैसी मार्केट पर केवल विदेशी कंपनियों का कब्जा है।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट में देशवासियों को बड़ा मंत्र दिया है– इकोनॉमी के साथ–साथ देश को कोरोना मुक्त रखने का आत्मनिर्भरता का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कडी के तौर पर काम करेगा, यह आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रूपए का है, ये पैकेज भारत की जी0डी0पी0 का करीब–करीब 10 प्रतिशत है। पी0एम0 मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर ,लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, हमारे MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises) के लिए है जो करोडों लोगों की आजीविका का साधन हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार हैं।

लोकल फॉर वोकल के लिए तैयार रहे हर देशवासी

पीएम मोदी ने माना कि ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने देश के हमारे गरीब भाई–बहनों की संघर्ष–शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्टस खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है, लोकल से ग्लोबल बनने का यह बड़ा अवसर है, इसलिए लोकल के लिए वोकल रहें।

लोकल ने ही हमें बचाया

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, श्रमिक, प्रवासी मजदूर हों, मछुवारे हों, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। कोरोना ने हमें Local manufacturing, Local supply chain और Local Marketing का भी महत्व समझा दिया है। लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना जैसी महामारी ने देश और दुनिया के अधिकतर देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, उसके असर इन सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में भी देखने को मिल रहे हैं। भारत में इसके असर यहां की विविधता और ग्रामीण शहरी व्यवस्था में रहने वाले नागरिकों के संदर्भ में अन्य देशों से काफी अलग हैं। ऐसे मे हमें भारत की विविधता और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड–19 से फैली महामारी से लडना है। इससे लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल होने की बात कही है वो भारत की सामाजिक अवधारणा में वर्षों से रही है। उदारीकरण और बढ़ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव में उस पर ध्यान न कभी सरकारों द्वारा किया गया, न ही कभी नागरिकों ने इसे समझा। अब जब दुनिया के सामने एक संकट खड़ा है तो वह सब अवधारणायें याद आने लगी हैं जिन्हें कभी समझते हुए भी दरकिनार किया गया।

महात्मा गांधी ने गांव में रहकर आत्मनिर्भर रहने का मूल मंत्र अपने सम्पूर्ण जीवन काल में दिया। आज अगर गांधी दर्शन पर गौर किया जाए तो स्वदेशी अपनाओ से लेकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिखेगा, वही आज के समय की जरूरत है। उदाहरण से समझ

पाएंगें कि आज जब पूरे देश में पूर्ण बंदी है तब हमें अपने जरूरत के सामान की चिंता होने लगी है, 24 घंटे में प्रयोग किए जाने वाले हर एक सामान की उपयोगिता महसूस होने लगी है।

वहीं समाज के लिए सकरात्मक सोचने वाले लोगों को सेवा भाव का मौका भी मिला है। हर एक प्रदेश के किसी भी जिले में आप इन समाजसेवियों के निस्वार्थ भाव से किए जा रहे प्रयासों को देख सकते हैं। गरीब मजदूरों को खाना खिलाने से लेकर, उनके ठहरने की भी सामर्थ्यानुसार जिम्मेदारी लेते लोग दिख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर बनो स्कीम की राशि 20 लाख करोड़ रुपये जरूर है लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरह से लोग अपने आस–पास के लोगों की मदद कर रहे हैं, वह वाकई काबिले तारीफ है।

दूसरी तरफ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पूरे संकट काल में जहां हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है, वहीं इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर और गरीब व्यक्तियों पर दिखाई पड़ता है। वो कमाने खाने की जद्दोजहद में एक राज्य से दूसरे राज्य में सालों से टिके हुए थे, लेकिन इस महामारी के काल ने उन्हें फिर उसी गांव में जाने को मजबूर किया, जहां साहूकारी और कर्ज के बोझ में वो हमेशा से डूबे रहते थे। उनको अब इस मौके पर महसूस भी होने लगा है कि मजदूर होने से बेहतर है एक किसान होना, क्योंकि किसान के पास अगर जमीन है तो उसमें कुछ भी उगाकर उसी आत्मनिर्भर सिद्वांत के जरिए जिंदा रह सकते हैं जिसका जिक्र हमेशा से गांधी जी किया करते थे और अब प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। एक किसान अपने खेत में जिस अनाज को उगाता है, वह देखते ही देखते आशीर्वाद, पतंजलि, अमूल जैसे बड़े ब्राण्ड बन जाते हैं और उन पर ऐसा यकीन एक उपभोक्ता का बनता है कि उससे वो निकल नहीं पाते हैं।

आज जब स्थिति सामान्य नहीं है, तब उपभोक्ता कुछ भी किसी भी ब्राण्ड का सामान लेने के लिए तैयार है। हमेशा से यह भेदभाव रहा है कि देश में बनने वाले सामान की स्थिति को थोड़ा नीची दृष्टि से देखा गया। कपड़े से लेकर खाद्य–पदार्थों तक में ग्लोबल होने की हमारी सोच अब क्या बदलेगी? फिल्म स्टार्स से लेकर मंत्री, नेता, खिलाड़ी, बड़े उद्योगकर्मी भी अब इस मूल–मंत्र से जुड़ सकेंगें? खिलाड़ियों का लाखों रूपये की पानी की बोतल से लेकर उनके कुत्ते के बिस्कुट तक में उनकी अन्तर्राष्ट्रीय सोच क्या अब दिखना बंद होगी? ऐसे कई सवाल मन में हैं लेकिन उनके उत्तर क्या इस संकट के बाद बदले हुए मिल पाएंगें, यह देखना होगा।

निष्कर्ष

हम अपने आस–पास में उगाई जा रही सब्जी या किसी लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायता करते हुए इस महामारी के संकट से लड़ें तो निश्चित तौर पर देश आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन बयानबाजी और सिद्वांतों के सिर्फ घोषणा में बदल देने मात्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। देश का मजदूर इस संकट के बाद अपने गांव की तरफ लौट रहा है, कोशिश की जानी चाहिए कि अब वे अपने राज्य में रहकर ही ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनें जिससे दोबारा ऐसे संकट आने पर भारत एक कदम आगे खडा दिखाई दे।

स्वास्थ्य सुविधाओं की मार खा रहे भारत के गांव और कस्बों मे हालत कैसे होंगें, हम सभी यह बेहतर जानते हैं। इसे बोल और लिख कर खुद को निराशा की स्थिति में ले जाने का समय नहीं है, जो है जितना है उसी में ही इस संकट से लड़िये और सरकार द्वारा जारी नियमों के पालन के साथ उनका सम्मान भी एक सच्चे देशभक्त की पहली कोशिश होनी चाहिए क्योंकि हम यदि सुरक्षित हैं तो राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका निभा लेंगें।

फिलहाल वक्त लोकल से वोकल होने का है, तो आसपास के लोगों से समान खरीदिए, उन्हें सहायता दीजिए और जो आत्मनिर्भर हैं वो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें ना कि उनका हिस्सा खाने को लालायित बनें।

संदर्भ

- www.livehindustan.com
- www.outlookhindi.com
- http://hi.m.wikipedia.org

7

मेक इन इण्डिया

डॉ0 शैलेष कुमार पाण्डेय
असिस्टैंट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग
एम.डी.पी.जी. कालेज, प्रतापगढ़

सारांश

'मेक इन इण्डिया' अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को की। 'मेक इन इण्डिया' का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है जिसका निर्माण भारत में किया गया हो। 'मेक इन इण्डिया' पहल 4 स्तम्भों पर आधारित है जिनकी पहचान न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ये स्तम्भ हैं– नई प्रक्रियायें, नई अवसंरचना, नये क्षेत्र, न्यू माइंडसेट। वैश्विक महामारी कोविड–19 के इस दौर में, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम महामारी से निपटने में एक कारगर कदम साबित हो रहा है। कोरोना काल के इस संकट में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम ने स्वदेशी उत्पादों के साथ हैंड सेनिटाइजर, मास्क और अन्य चिकित्सीय सामग्रियों का निर्माण करके देश में उक्त सामग्रियों की मांग को पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का दर्शन है कि देश में सुव्यवस्थित शासन कायम किया जाय तथा नौकरशाही पर अंकुश लगाते हुए लालफीताशाही को खत्म किया जाय तथा डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाय। अगर ऐसा होता है कि भारतीय ग्रामीण अंचल एवं दुर्गम क्षेत्रों में मेक इन इण्डिया की वैचारिकी की सफलता को कोई बाधित नहीं कर सकता।

मुख्य शब्द– मेक इन इण्डिया कार्यक्रम, बुनियादी ढाँचा, एफ.डी.आई., ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विनिर्माण

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार देश की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने पर ही देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अपने दस सूत्रीय एजेण्डे के माध्यम से प्रधानमन्त्री नौकरशाहों के मनोबल में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में सुधार, नये विचारों का स्वागत एवं उनके समीचीन होने पर उन पर अमल, कामकाज में पारदर्शिता, टेंडर और अन्य सरकारी कामों के लिए ऑनलाइन बोली, मंत्रालयों के बीच तालमेल, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रणाली के तहत काम करना, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर काबू, बुनियादी ढाँचें में सुधार, निवेश बढ़ाने पर जोर, नीतियों व योजनाओं के अमल में समय सीमा का ध्यान आदि कार्य करना चाहते हैं।

'मेक इन इण्डिया' इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को की और ठीक उसके 40 दिनों के अन्दर उसे अमलीजामा पहनाने की दिशा में कार्यवाई शुरू की।

'मेक इन इण्डिया' का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है जिसका निर्माण भारत में किया गया हो। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि भारत में बिकने वाली हर वस्तु पर 'मेक इन इण्डिया' लिखा हो परन्तु यह तभी सम्भव है जब सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाये अर्थात् 'मेक इन इण्डिया' की संकल्पना साकार की जाये।

मेक इन इण्डिया अभियान के स्तम्भ

'मेक इन इण्डिया' पहल 4 स्तम्भों पर आधारित है जिनकी पहचान न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ये स्तम्भ हैं–

1. **नई प्रक्रियायें**– 'मेक इन इण्डिया' उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में 'व्यापार करने में आसानी' को मान्यता देती है। कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कई पहल की जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य व्यवसाय के पूरे जीवन चक्र के दौरान उद्योगों को लाइसेन्स प्रणाली से मुक्ति और डी–रेगुलेट करना है।

2. **नई अवसंरचना**– आधुनिक और सुगम अवसंरचना की उपलब्धता हो इसीलिए सरकार आधुनिक उच्च गतिसंचार और एकीकृत लाजिस्टिक व्यवस्था के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों को विकसित करने का कार्य कर रही है।
3. **नये क्षेत्र**– 'मेक इन इण्डिया' ने विनिर्माण, बुनियादी ढाँचें और सेवा गतिविधियों के 25 क्षेत्रों की पहचान की है और विस्तृत जानकारी इंटरैक्टिव वेब–पोर्टल और पेशेवर रूप से विकसित विज्ञापनों के माध्यम से साझा की जा रही है। एफ.डी.आई. को रक्षा उत्पादन, निर्माण और रेलवे के बुनियादी ढाँचें के लिये अनुमन्य किया गया है।
4. **न्यू माइंडसेट**– सरकार को एक नियामक के रूप में देखने के लिए उद्योग आदी है। 'मेक इन इण्डिया' का इरादा सरकार द्वारा उद्योग के साथ बातचीत में प्रतिमान बदलाव लाकर इसे बदलने का है। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योग का भागीदार होगी।

मेक इन इण्डिया अभियान हेतु किये गये कार्य

प्रश्न उठता है कि 'मेक इन इण्डिया' को कार्यरूप में लाने के लिए क्या पहल की गई? पहली बार अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए रेलवे, बीमा, रक्षा और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र खोले गये हैं। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। एफ.डी.आई. में इस वृद्धि की घोषणा वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16 मई 2020 को की थी। निर्माण और निर्दिष्ट रेल अवसंरचना परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत की एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है।

एक निवेशक सुविधा सेल भी है जो निवेशकों को भारत में उनके आगमन के समय से देश से उनके प्रस्थान तक सहायता करता है। यह 2014 में पूर्व–निवेश चरण, निष्पादन और डिलीवरी सेवाओं के बाद भी सभी चरणों में निवेशकों को सेवायें देने के लिए बनाया गया था।

सरकार ने भारत की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंक में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। 2020 में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स' में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत इस सूचकांक में दक्षिण–एशिया में सर्वोच्च स्थान पर रहा।

श्रम सुविधा पोर्टल, eBiz पोर्टल आदि को लान्च किया गया है। eBiz पोर्टल भारत में व्यवसाय शुरू करने से जुड़ी ग्यारह सरकारी सेवाओं के लिए एकल–खिड़की तक पहुँच प्रदान करता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक अन्य परमिट और लाइसेंस में भी छूट दी गई है। सम्पत्ति पंजीकरण, करों का भुगतान, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, अनुबंध लागू करना और विरोध का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हैं।

अन्य सुधारों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया, विदेशी निवेशकों के आवेदन के लिए समयबद्ध मंजूरी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं का स्वचालन, मंजूरी देने में राज्यों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, दस्तावेजों की संख्या घटाना शामिल हैं। सुधारों में निर्यात और सहकर्मी मूल्यांकन, स्व–प्रमाणन आदि के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल हैं। सरकार निवेश के पीपीपी मोड के माध्यम से मुख्य रूप से भौतिक बुनियादी ढाँचें में सुधार की उम्मीद करती है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों ने निवेश में वृद्धि देखी है। समर्थित माल गलियारे भी विकसित किये जा रहे हैं।

सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना शुरू की है, उन पर काम चल रहा है। ये गलियारे भारत की लम्बाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं, जिसमें समावेशी विकास पर रणनीतिक ध्यान केन्द्रित किया गया है जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ायेगा। गलियारे निम्नलिखित हैं–

- दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
- अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
- बेंगलुरू–मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC)
- चेन्नई–बेंगलुरू औद्योगिक गलियारा (CBIC)
- विजाग–चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)

मेक इन इण्डिया अभियान हेतु सरकारी योजनायें

'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनायें शुरू की गई हैं–

- **कौशल भारत**– यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों में भारत में सालाना 10 मिलियन व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य रखता है। 'मेक इन इण्डिया' को वास्तविकता में बदलने के लिए कुशल मानव संसाधन को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में औपचारिक रूप से कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत जनसंख्या का केवल 2 प्रतिशत है।
- **स्टार्टअप इण्डिया**– इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य विचार एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देता है, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करता है।
- **डिजिटल इण्डिया**– उसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित और डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इण्डिया एक ऐसी क्रान्ति है जो बिना किसी सीमा को जाने–पहचाने लोगों को सूचना का अधिकार देती है। मुख्य रूप से गाँवों को

इंटरनेट कुशल बनाने के लिए प्रकल्पित यह परियोजना, एक ऐसे संसाधन के रूप में उभरकर सामने आती है जिसका प्रयोग ग्रामीण, पिछड़े और गुमनाम इलाकों को राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए किया जा सकता है।

- **प्रधानमंत्री जनधन योजना**– यह आम जनता की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन की योजना है अर्थात् बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण क्रेडिट, बीमा, पेंशन–एक किफायती तरीके से।
- **स्मार्ट सिटीज–** इस मिशन का लक्ष्य भारतीय शहरों को बदलना और उनका कायाकल्प करना है। इसका लक्ष्य कई उप–पहलों के माध्यम से भारत में 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है।
- **अमृत**– AMRUT कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। इसका उद्देश्य बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करना और भारत के 500 शहरों को अधिक जीवंत और समावेशी बनाना है।
- **स्वच्छ भारत अभियान**– यह भारत को अधिक स्वच्छ बनाने और बुनियादी स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन है।
- **सागरमाला**– इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों को विकसित करना और देश में बंदरगाह के महत्व एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन** (ISA)– यह 121 देशों का एक गठबंधन है, उनमें से ज्यादातर धूप वाले देश हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित हैं। यह सौर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और उस सम्बन्ध में नीतियाँ तैयार करने के उद्देश्य से भारत की पहल है।
- **ए.जी.एन.आई.आई.** (Accelerating Growth of New India's Innovations)- AGNII लोगों को जोड़ने और नवाचारों के व्यवसायीकरण में सहायता करके देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए नए भारत के नवाचार के लिये ए.जी.एन.आई.आई. या त्वरित विकास को लान्च किया गया था।

मेक इन इण्डिया मिशन के उद्देश्य

'मेक इन इण्डिया' मिशन के प्रमुख रूप से निम्न उद्देश्य हैं–

- विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि प्रति वर्ष 12–14 प्रतिशत करने के लिए 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ बनाना।
- 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी, गरीब और ग्रामीण प्रवासियों के बीच आवश्यक कौशल सेट बनाना।
- घरेलू मूल्य वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी गहराई में वृद्धि करना।
- पर्यावरण–स्थायी विकास का होना।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

मेक इन इण्डिया अभियान के सम्मुख चुनौतियाँ

पुनः प्रश्न उठता है कि 'मेक इन इण्डिया' के सम्मुख क्या चुनौतियाँ हैं। भले ही इस अभियान को कुछ तिमाहियों में सफलता मिली हो, लेकिन आलोचनायें भी हुई हैं। कुछ आलोचनायें निम्न हैं–

- भारत में लगभग 60 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है। विनिर्माण पर जोर कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कहा जाता है। यह कृषि योग्य भूमि के एक स्थायी व्यवधान का कारण बन सकता है।
- यह भी माना जाता है कि तेजी से औद्योगिकीरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है।
- बड़े पैमाने पर एफडीआई आमन्त्रित करने का एक नतीजा यह है कि स्थानीय किसान और छोटे उद्यमी अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- विनिर्माण पर जोर प्रदूषण और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का कारण बन सकता है।
- देश में भौतिक अवसंरचना सुविधाओं में गम्भीर कमी है। अभियान को सफल होने के लिए देश में उपलब्ध बुनियादी ढाँचें का विकास करना और भ्रष्टाचार को कम करना आवश्यक है। यहाँ भारत, चीन से सबक ले सकता है, जिसने 1990 के दशक में वैश्विक विनिर्माण के अपने हिस्से में 2.6 प्रतिशत से 2013 में 24.9 प्रतिशत तक सुधार किया है। चीन ने तेजी से रेलवे, रोडवेज, बिजली, हवाई अड्डों आदि जैसे अपने भौतिक बुनियादी ढाँचे का विकास किया है।

मेक इन इण्डिया मिशन की प्रगति

मेक इन इण्डिया मिशन की प्रगति के कुछ बिन्दु निम्नवत हैं–

1. जी.एस.टी. की शुरूआत ने व्यवसायों के लिए कर प्रक्रिया प्रणाली को आसान बना दिया है। जी.एस.टी. मेक इन इण्डिया अभियान के लिए एक पूरक है।

2. देश में डिजिटलीकरण ने गति पकड़ ली है। कराधान, कम्पनी निगमन और कई अन्य प्रक्रियाओं को आसान बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए आनलाइन किया गया है। इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इण्डेक्स में भारत की रैंक को ऊपर कर दिया है।
3. इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 नाम के नये इनसॉल्वेंसी कोड ने एक ही कानून में इनसॉल्वेंसी से सम्बन्धित सभी कानूनों और नियमों को एकीकृत किया। यह कोड वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
4. प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी वित्तीय समावेशन की योजनाओं के कारण मई 2019 तक 356 मिलियन नये बैंक खाते खोले गये। एफडीआई उदारीकरण ने भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक को अनुकूल बनाने में मदद की है। बड़े एफडीआई प्रवाह से रोजगार, आय और निवेश का सृजन होगा।
5. इन्फ्रॉस्ट्रक्चर और कनेक्टिवीटी को भारतमाला और सागरमाला जैसी योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न रेलवे बुनियादी ढाँचा विकास योजनाओं के माध्यम से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। Bharat Net देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक दूरसंचार बुनियादी ढाँचा प्रदाता है। यह शायद दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना है।
6. सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत को दुनिया में नं0 6 पर स्थान दिया गया है। कुल मिलाकर भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में दुनिया में 5वें स्थान पर है।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का फोकस 25 क्षेत्रों पर है इनमें शामिल है– आटोमोबाइल, आटोमोबाइल घटक, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन निर्माण, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रानिक सिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, IT और BPM, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन; खनन, तेल और गैस; फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाहों और शिपिंग, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष, कपड़ा और वस्त्र, थर्मल पावर, पर्यटन और आतिथ्य और कल्याण।

मेक इन इण्डिया अभियान के लाभ

मेक इन इण्डिया अभियान ने देश के लिए कई सकारात्मक विकास किये हैं जिनसे अनेक लाभ हुए हैं जो निम्नवत हैं–

- रोजगार के अवसर पैदा करना।
- आर्थिक विकास को बढ़ाकर जीडीपी को बढ़ाना। जब एफडीआई प्रवाह बढ़ेगा तो रूपया मजबूत होगा।
- छोटे निर्माताओं को एक जोर मिलेगा, खासकर जब विदेशों के निवेशक उनमें निवेश करते हैं। जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे तो वे विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी को भी अपने साथ लायेंगे।
- मिशन के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक ऊपर उठा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण केन्द्र और कारखाने स्थापित करने से इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत भारत में व्यापार करने में आसानी पर केन्द्रित उपायों की एक श्रेणी भी शुरू की गई है। ब्राण्ड नये, सूचना प्रौद्योगिकी संचालित एप्लीकेशन और ट्रैकिंग प्रक्रियायें फाइलों और लाल फीताशाही की जगह ले रही हैं। राज्य सरकार के स्तर पर लाइसेन्सिग नियमों को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने के लिए उन्हें वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए कई नई पहलें शुरू की गईं।

श्रम कानून में संशोधन से लेकर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने और विनियामक वातावरण के युक्तिकरण से औद्योगिक लाइसेन्स की वैधता बढ़ाने तक 'मेक इन इण्डिया' को साकार करने के लिए बहुत सारे बदलाव किये गये हैं।

आज भारत की साख पहले से ज्यादा मजबूत है। मेक इन इण्डिया निवेश के द्वार खोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के इस दौर में, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम महामारी से निपटने में एक कारगर कदम साबित हो रहा है। कोरोना काल के इस संकट में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम ने स्वदेशी उत्पादों के साथ हैंड सेनिटाइजर, मास्क और अन्य चिकित्सीय सामग्रियों का निर्माण करके देश में उक्त सामग्रियों की मांग को पूरा किया। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि इस संकटकालीन अवस्था में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की पहल व कार्यक्रमों की सहायता से न केवल पर्याप्त हैण्ड सेनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, डिस्पेंसर्स का निर्माण व अन्य आवश्यक सामग्रियों का निर्माण भारतीय माँग को पूरा करने के लिए किया गया बल्कि देश इसका निर्यात भी करने में सक्षम हो गया है।

निष्कर्ष

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की सफलता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हम सभी आम जनमानस को मिलकर इसकी सफलता का प्रयास करना होगा। इस दिशा में सर्वप्रथम हमें अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा। हम बाजार में चीन निर्मित सामानों को बिना सोचे–समझे बिना बिल के क्रय कर लेते हैं। हम सभी को अपने कर्तव्यों का अहसास भी होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी जी का दर्शन 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस' का है अर्थात देश में सुव्यवस्थित शासन कायम किया जाय तथा नौकरशाही पर अंकुश लगाते हुए लालफीताशाही को खत्म किया जाय तथा डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाय। अगर ऐसा होता है कि भारतीय ग्रामीण अंचल एवं दुर्गम क्षेत्रों में मेक इन इण्डिया की वैचारिकी की सफलता को कोई बाधित नहीं कर सकता।

संदर्भ सूची

1. कुरूक्षेत्र, फरवरी, 2016– विभिन्न अंक
2. योजना, जनवरी, 2016– विभिन्न अंक
3. www.makendia.com
4. www.dristhias.com
5. www.byjus.com

8

कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ0 अंकुर अग्रवाल
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद

डॉ0 शिवाली चौहान
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावों का विश्लेषण एवं बेरोजगारी दर का विश्लेषण करना है। बेरोजगारी की दर को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर आम मजदूर, वेतनभोगी कर्मचारी एवं स्वः नियोजित में क्रमशः 66 प्रतिशत, 61 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 82 प्रतिशत, 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत पायी गई है, इससे विकटमय स्थिति का आभास होता है। कोविड–19 का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा। भारत का राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को जीवित करने हेतु असंगठित वर्ग को संगठित करना, लघु उत्पादकों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, एक तरह के व्यापारियों का गुट बनाकर इकट्ठा पूँजी निवेश से बड़े पैमाने का व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करना जिससे पैमाने की बचतें प्राप्त हो सकें एवं भारतीय धरोहरों को व्यावसायिक रूप प्रदान करके प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। उत्पादन के नये स्रोत एवं उत्पादन में वृद्धि से देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है एवं इससे बेरोजगारी दर को भी कम किया जा सकता है। कोविड–19 की वजह से जो जीवन शैली में बदलाव आया है उसको व्यवसाय से जोड़कर बिगड़ती हुई स्थिति को नियन्त्रण में लाया जा सकता है। गाँवों के लोगों को शहरों में पलायन करने से रोकने हेतु गाँवों में ही रोजगार के नये अवसर प्रदान करने चाहियें जिससे भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहाँ आर्थिक परिणाम अधिक बुरे हो सकते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले इस महामारी को और फैलने से रोकना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है। ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर सकते है, वो कच्चा माल नहीं खरीद सकते, बनाया हुआ माल बाज़ार में नहीं बेच सकते तो उनकी आमदनी बंद ही हो जाएगी। कोविड–19 ने विश्व के लिए एक नयी नीति, नयी तकनीक एवं नये व्यवसाय के आयामों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह शोधपत्र इसी बदलाव पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द– कोविड–19, भारतीय अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी दर, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र

प्रस्तावना

विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मानव समाज को कई वरदानों से अभिभूत किया है किन्तु भविष्य के गर्भ में पनप रहे अभिशापों से अनभिज्ञ होकर उसे अपनी सफलता मानकर हम मुस्कुराते रहे। यह धरा जो जन–जीवन से परिपूर्ण है उसे विनाश के पथ पर अग्रसर करने मे कहीं न कहीं हम जिम्मेदार है। वैश्विक महामारी कोई पहली बार नहीं हुई है किन्तु वैश्वीकरण के कारण एवं इस बार इसके फैलने का अनुपात कहीं ज्यादा है। कोरोना वायरस महामारी जिसका पहला मामला 01 दिसम्बर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में आया था किन्तु आज तक यह लहर समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। विश्व का CFR (Case Fatality Rate) 2.1 प्रतिशत है।

शोधपत्र का उद्देश्य

1. कोविड–19 के प्रभावों का भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी दर का विश्लेषण करना।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्रदान करने हेतु सुझाव प्रदान करना।

कोरोना वायरस और भारत

कोरोना वायरस महामारी की पुष्टि भारत में पहली बार 30 जनवरी 2020 को हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल 2021 तक इस वायरस से भारत में 1,87,62,976 मामलों की पुष्टि की गई है जिसमें 2,08,350 लोगों की मृत्यु हुई है। CFR भारत का 1.5 प्रतिशत है।

22 मार्च 2020 को भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। संपूर्ण भारत को बंद करने का निर्णय 24 मार्च 2020 को लिया गया।

लॉकडाउन पहला चरण	–	25 मार्च–14 अप्रैल 2020
लॉकडाउन दूसरा चरण	–	15 अप्रैल–03 मई 2020
लॉकडाउन तीसरा चरण	–	04 मई–17 मई 2020
लॉकडाउन चौथा चरण	–	18 मई–31 मई 2020

कोविड–19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण कई व्यवसाय और उद्योग प्रभावित हुए। घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है, ऐसे में ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे, वो कच्चा माल नहीं खरीद पा रहे और बनाया हुआ माल बाजार में नहीं बेच पा रहे जिससे उनकी आमदनी बंद हो गई। अर्थव्यवस्था में लगभग 10 प्रतिशत का संकुचन देखा जा सकता है।

दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है। वैश्विक जीडीपी में रोज कमी दर्ज़ की जा रही है, लाखों लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि 90 देश उससे मदद मांग रहे हैं। आई.एल.ओ. के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में ढाई करोड़ नौकरियाँ खतरे में हैं। कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुनः शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लोग घूमने नहीं निकल रहे, नया सामान नहीं खरीद रहे लेकिन, कम्पनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चों को भुगतान तो करना ही है। ये नुकसान झेल रही कम्पनियां ज्यादा समय तक भार सहन नहीं कर पांएगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। सम्पूर्ण लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था थम गई। 3 महीने के लिये moratorium घोषणा की गई जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। धीरे–धीरे अनलॉक प्रक्रिया 1 जून 2020 से प्रारम्भ की गई जिससे अर्थव्यवस्था का चक्र धीरे–धीरे चलने लगा। इस दौरान कार्यशैली में कई परिवर्तन हुए जैसे घर से काम (Work from home), कहीं से भी काम (Work from anywhere) और 2 गज की दूरी (Social Distance) आदि कार्य करने के अभिन्न अंग बन गये। ई–शॉपिंग की तरफ लोगों का रूझान बढ़ा और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने अपनी जड़ें मजबूत कीं। जहाँ पर इतने परिवर्तन हो रहे थे, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। भारतीय सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में 87 प्रतिशत छोटे व्यवसायों को बंद करना पड़ा। मार्च 2020 को बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत थी जो अप्रैल 2020 को बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई किन्तु अब उसमें सुधार आया है।

तालिका संख्याः 1

कोविड–19 का रोजगार पर प्रभाव प्रतिशत में

रोजगार पर प्रभाव	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
आम मजदूर	66 प्रतिशत	82 प्रतिशत
वेतनभोगी कर्मचारी	61 प्रतिशत	77 प्रतिशत
स्वः नियोजित	45 प्रतिशत	87 प्रतिशत

Source- Research and Development Statistics by Ministry of Science & Technology, Govt. of India

आरेख संख्याः 1
कोविड–19 का रोजगार पर प्रभाव

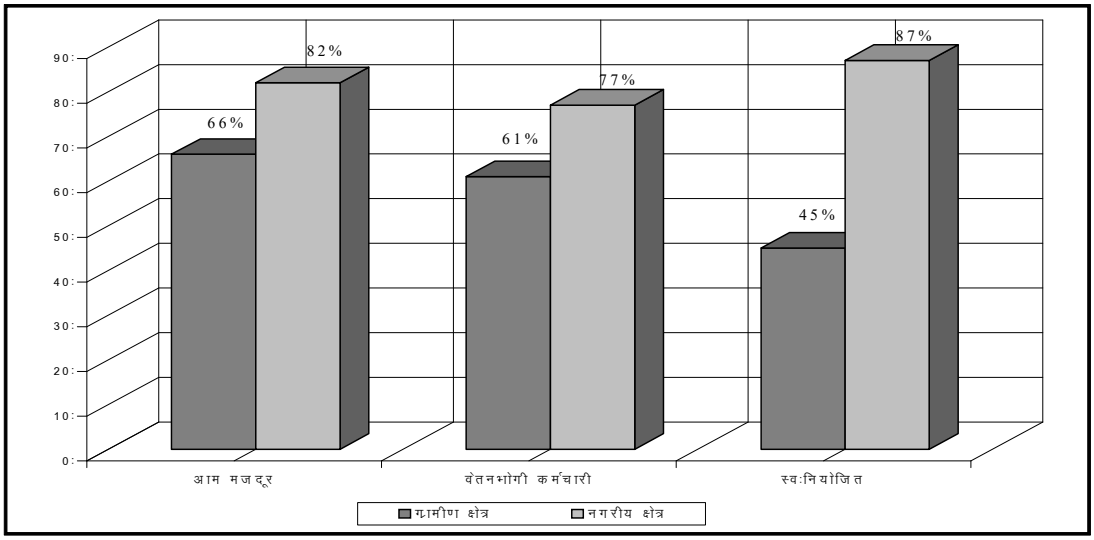

लॉकडाउन की वजह से कई मजदूरों को शहर से पलायन करना पड़ा। प्राइवेट कम्पनियों व छोटे व्यवसायियों ने अपने कर्मियों को निकाल दिया जिससे भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गयी। लॉकडाउन का प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ा जिसका ब्यौरा नीचे दिये गये जीडीपी के आंकड़े बताते हैं–

तालिका संख्याः 2
जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्र.सं.	त्रैमासिक वित्तीय वर्ष	जीडीपी वृद्धि दर
1	अप्रैल–जून वित्तीय वर्ष 2019–2020	+ 5.4
2	जुलाई–सितम्बर वित्तीय वर्ष 2019–2020	+ 4.5
3	अक्टूबर–दिसम्बर वित्तीय वर्ष 2019–2020	+ 3.3
4	जनवरी–मार्च वित्तीय वर्ष 2019–2020	+ 3.1
5	अप्रैल–जून वित्तीय वर्ष 2020–2021	- 24.4
6	जुलाई–सितम्बर वित्तीय वर्ष 2020–2021	- 7.3
7	अक्टूबर–दिसम्बर वित्तीय वर्ष 2020–2021	+ 0.4

Source - Research and Development Statistics by Ministry of Science & Technology, Govt. of India

आरेख संख्या–2

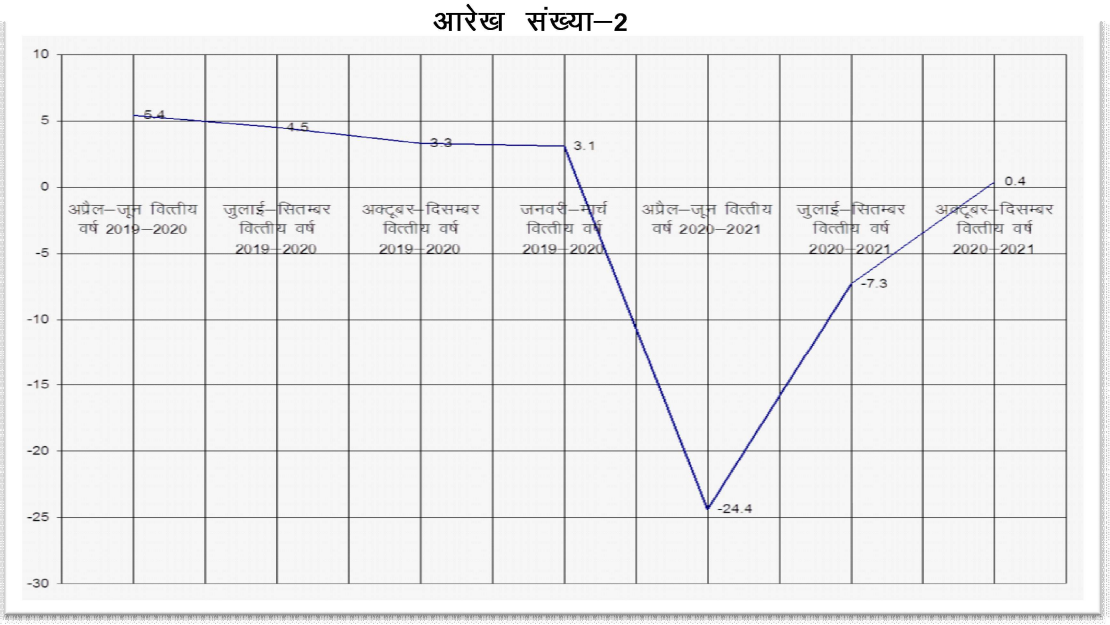

इस वैश्विक महामारी का सीधा असर समस्त देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। जून 2020 तिमाही में जीडीपी 38.08 लाख करोड़ रूपये रही जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 49.18 लाख करोड़ रूपये थी। इस प्रकार 24.4 प्रतिशत गिरावट आई। जीडीपी की वृद्धि ऋणात्मक हुई। आई.एम.एफ. के अनुसार अभी कुछ समय भारत की जीडीपी की वृद्धि दर में गिरावट रहेगी। इस गिरावट को विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अधिक समझा जा सकता है।

तालिका संख्या : 3
प्रथम तिमाही वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	2020-21 प्रथम तिमाही वृद्धि दर
कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ	- 51.4%
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ	- 39.3%
माइनिंग सेक्टर ग्रोथ	- 41.3%
ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रोथ	- 47.3%

Source - Research and Development Statistics by Ministry of Science & Technology, Govt. of India

जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च धीमी गति से हुआ, निजी निवेश एवं निर्यात कम हुआ और गत वर्ष जून तिमाही (2020) की दर 5.2 फीसदी ही रह गई। इस महामारी की वजह से सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। पर्यटन, रिटेल और आतिथ्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 55 प्रतिशत तक का योगदान रहता है किन्तु इसकी वृद्धि की दर 47.3 प्रतिशत ऋणात्मक तक ही रह गई। देशी पर्यटकों में 20 प्रतिशत, विदेशी पर्यटकों में 75 प्रतिशत, होटल बुकिंग में 70 प्रतिशत एवं रेस्तरां के व्यापार में 30–35 प्रतिशत गिरावट देखी गई। इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए भारत सरकार 'आत्म निर्भर भारत' के अंतर्गत राहत पैकेज लेकर आई जिसको पांच अंशों में विभाजित किया गया है।

पहला अंश– लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए
दूसरा अंश– गरीब प्रवासी एवं किसानों के लिए
तीसरा अंश– कृषि सम्बन्धित
चौथा अंश– नये क्षितिज विकास के लिए
पंचम अंश– सरकारी सुधार और प्रवर्तन

तालिका संख्याः 4
सरकार द्वारा राहत पैकेज (रूपये करोड़ में)

पहला अंश–	5,94,550
दूसरा अंश–	3,10,000
तीसरा अंश–	1,50,000
चौथा एवं पंचम अंश–	48,100
योग	11,02,650
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	1,92,800
आरबीआई उपाय	8,01,603
कुल योग	22,97,053

Source – Various Press Releases, Govt. of India

भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्रदान करने हेतु सुझाव

भारत सरकार ने राहत पैकेज के रूप में भारत को एक बार फिर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर दिया किन्तु भारत की सबसे बड़ी समस्या भारत का असंगठित वर्ग है जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान दर सबसे अधिक है। सबसे पहले असंगठित वर्ग को संयोजित करके सभी व्यापारियों को एक श्रेणी में लाकर इन लघु उत्पादकों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिये, एक जैसा व्यापार करने वाले लघु उत्पादकों का गुट बनाना चाहिये जिससे इकट्ठा पूंजी निवेश से व्यापार बड़े पैमाने पर किया जा सके। दूसरा भारतीय संस्कृति एवं

परम्परा से जुड़ी हुई धरोहरों को व्यावसायिक रूप देने से कई बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा जैसे यूपी सरकार द्वारा चलाया गया हुनर हाट या मध्यप्रदेश द्वारा जरी के काम को प्रोत्साहन देने हेतु 'राग भोपाली' प्रदर्शनी का आयोजन करना। इस प्रकार हमारी गुम होती जा रही संस्कृति को भी संजोया जा सकता है एवं इसे आमदनी का स्रोत भी बनाया जा सकता है। कोविड–19 के दौरान सबसे बड़ी समस्या मजदूर पलायन की रही। कई मजदूर कई दिनों तक पैदल ही अपने गाँवों की ओर निकल पड़े। तीसरा सर्वागीण विकास अर्थात् गांवों में भी उद्योगों को स्थापित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना जिससे ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन कम हो। एक क्षेत्र की विशेषता को पहचानकर उसे व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करने से वास्तव में भारत में आत्मनिर्भर अभियान के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

निष्कर्ष–

कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। कोरोना से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आयी है। यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ा है। बैंक एनपीए की समस्या से अब तक निपट रहे हैं। हालांकि, सरकार निवेश के जरिए, नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ़्तार देने की कोशिश कर रही थी पर बहुत अधिक सफलता सरकार को नहीं मिली है। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात ने जैसे अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर दिया है, न तो कहीं उत्पादन है और न मांग, लोग घरों में हैं, कल कारखानों तथा दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। कोरोना से लड़ाई अब दोहरी है,। संसार का प्रत्येक देश 'सेहत' और 'अर्थव्यवस्था', दोनों के विनाश को सीमित करने में जुटे हैं। भारत में संक्रमण रोकने की कवायद जोर पकड़ रही है, लेकिन आर्थिक राहत में भारत पिछड़ गया है।

संदर्भ–

1. "Corona's Impact, 4.5% GDP Estimates in 2020: Government" . Amar Ujala . The original July 9, 2020 Archive . Retrieved 25 July 2020.
2. "the IMF said, Kovid -19 consistently spread the risk for the Indian economy" . Hindustan Live . Retrieved 25 July 2020.
3. "6 Factor" which shows that reforms have started in the country's economy " . Navbharat Times . Retrieved 25 July 2020.
4. ''कोरोना का प्रभाव, 2020 में 4.5 फीसदी जीडीपी का अनुमानः सरकार'' अमर उजाला, मूल से 9 जुलाई 2020 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
5. "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
6. "Coronavirus Update (Live): 25,592,318 Cases and 853,437 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer". www.worldometers.info
7. "At -23.9%, GDP Contracts For First Time In Over Four Decades". NDTV.com.
8. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवाणी, विभिन्न तिथियों से सम्बन्धित
9. https://www.covid19india.org/
10. https://prsindia.org/covid-19/cases
11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_recession_in_India
12. www.publicationsdivision.nic.in

9

कोविड-19 और भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ0 अभय कुमार मीतल
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

डॉ0 अभिजित मिश्रा
असिस्टैंट प्रोफसर, वाणिज्य विभाग
एस0 एस0 (पी0जी0) कालेज, शाहजहांपुर

सारांश

कोरोना महामारी की प्रथम एवं द्वितीय लहर की भयानकता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अशक्त प्रायः कर दिया है। यातायात अवरोध, पर्यटन उद्योग में कमी, उपभोक्ता गतिविधियों का शिथिल होना, आपूर्ति एवं उत्पादन में कमी, शेयर बाजार का प्रभावित होना, व्यवसाय एवं उद्योग–धंधों का चौपट हो जाना, आयात–निर्यात में गिरावट, सरकारी खजाने का खाली होना, बेरोजगारी और कालाबाजारी में वृद्धि और न जाने कितनी ही समस्याएं हैं जिन्होंने कोरोना काल मे अर्थव्यवस्था के सम्मुख कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकारों को इस ओर सार्थक कदम उठाने होंगें, राहत पैकेज एवं रियायतों की घोषणा करनी होगी। आम आदमी से लेकर बड़े उद्योग–धंधों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। सरकार के सम्मुख सबसे बडी चुनौती यह है कि उसको सब नियमित भी करना है, अर्थव्यवस्था को सशक्त भी बनाना है और कोविड पर नियंत्रण भी बनाए रखना है। साथ ही तीसरी लहर की आशंका से सजग रहना है और सभी को जागरूक भी बनाना है।

मुख्य शब्द– राहत पैकेज, बेरोजगारी, कालाबाजारी, कामगारों का पलायन, जोखिम

2019 के अंत में चीन देश के वुहान शहर से उत्पन्न नोवल कोरोना वायरस जो कोविड–19 के नाम से जाना जा रहा है, सारे संसार की मानव जाति के लिए एक खतरा बना हुआ है। इस कोरोना वायरस ने जहां प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सम्पूर्ण मनुष्य जाति के सम्मुख स्वास्थ्य, प्राण और अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है, वहीं परोक्ष रूप से सभी देशों की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक ढांचे को भी झकझोर दिया है। जब सभी देशों को ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस वायरस पर एक हद तक अब नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं तब इसकी भयावह दूसरी लहर ने एक ऐसा तांडव वैश्विक स्तर पर वर्तमान में मचाया है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं पुनः अपने समक्ष राहत के लिए मार्ग खोज रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक पटल पर भी कोविड–19 के स्याह के बादल अत्यन्त घने हो गए हैं। 2020 के प्रारम्भ में कोविड ने भारत में भी अपनी दस्तक दे दी थी। कोविड के प्रसार ने भारत को महीनों के लॉकडाउन का एक ऐसा नवीन अनुभव कराया जिसे शायद आने वाली पीढ़ियॉ एक सबक के रूप में ग्रहण करेंगीं। अनेकों उद्योग बन्दी की कगार पर पहुॅच गए, अनेकों कर्मचारियों की नौकरी चली गयी, कामगार मजदूरों का जीवन–यापन दूभर हो गया, कामगारों का पलायन, चिकित्सा पर व्यय, यातायात के साधनों का अभाव, विभिन्न यातायात साधनों का अब तक नियमित न हो पाना, कोरोना वायरस सम्बन्धी अज्ञानता एवं भ्रान्तियां, अनेकों संस्थानों एवं उद्योगों द्वारा पारिश्रमिक और वेतनों में उल्लेखनीय कटौतियां आदि और न जाने कितनी ही विषमताएं थीं जिन्होंने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया और आम आदमी के समक्ष अपने और परिवार के जीवन यापन का संकट उत्पन्न कर दिया। भारत सरकार ने अपनी इस शिथिल होती अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उददेश्य से मई 2020 में 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में 115 बेसिस पाइंट्स की कमी करने की घोषणा की और 2020 के अंत में जब भारत की अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे पटरी पर लौटनी शुरू हुई, काम–धंधे, उद्योग धंधे कुछ नियमित होने शुरू हुए, नौकरी पेशा लोगों ने अपने ऑफिस नियमित रुप से जाना शुरू किया, सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्कूल–कॉलेज पुनः संचालित होने शुरू हो गए थे; तभी कोविड–19 की दूसरी लहर की भयानकता ने पुनः सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। सर्वाधिक चिन्ताजनक बात यह है कि जहां कोरोना की प्रथम लहर में विश्व के सभी देश प्रभावित थे, वहीं दूसरी लहर की भयावहता का सर्वाधिक तांडव भारत में ही हो रहा है। यद्यपि अन्य देशों में भी इसका प्रकोप दिखायी दे रहा है परन्तु सर्वाधिक विनाश एवं प्रभाव विश्व में मात्र भारत में ही दृष्टिगोचर हो रहा है। वर्तमान स्थिति में अलग–अलग प्रदेशों में लॉकडाउन की क्रमिक रूप से बढ़ती हुई अवधि, कामगारों का पलायन, सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध; काम–धंधों, कार्यालयों, उद्योगों का बन्द होना आदि; भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए पुनः ऐसा संकट उत्पन्न कर चुके हैं कि शायद अब 2021 के अंत तक भी सन्तुलन या राहत की स्थिति उत्पन्न होनी निश्चय ही असंभव न हो परन्तु अत्यन्त कठिन अवश्य है।

कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव

कोरोना वायरस या कोविड–19 की इस विनाशकारी महामारी ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अनेकों अध्ययन एवं विश्लेषण विभिन्न संस्थाओं एवं विद्वानों द्वारा किए गये हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यस्था भी बहुत बुरी तरह इस महामारी से प्रभावित हुई है। यह महामारी ऐसे वक्त में भारत में आयी जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दवाब के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही शिथिलता की मार झेल रही थी। 26 मई 2020 को CRISIL ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में मंदी का सर्वाधिक बुरा दौर है। विश्व बैंक के एक ताजा अनुमान के आधार पर 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट अपेक्षित है और इसके घटकर 2.8 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गयी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लगभग देश भर में लॉकडाउन है जो कि प्रादेशिक स्तरों पर क्रमिक रूप से विभिन्न रूपों में बढ़ाया जा रहा है। सभी फैक्ट्री, कारखाने, कार्यालय, मॉल्स, व्यवसाय, दैनिक व्यापारिक गतिविधियां, सामान्य यातायात, शिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि सब बन्द हैं। घरेलू आपूर्ति एवं मांग के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है और जोखिम की मात्रा में वृद्वि होने के कारण घरेलू निवेश में किसी भी सुधार की संभावना भी विलम्बित होनी अवश्यमभावी है। यह सारी परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर में पहुंच चुकी है और हमें इससे उबरने के लिए अनेकों भागीरथ प्रयासों की आवश्यकता होगी। कोविड की इस महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष निम्न क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं अथवा चुनौतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं :

आम जीवन अस्त व्यस्त :–

बार–बार लॉकडाउन की स्थिति और सार्वजनिक जीवन पर विभिन्न प्रतिबंधों के चलते आम जनमानस का सामान्य जीवन अत्यन्त विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है और जीवन में एक अजीब सी अनिश्चितता और डर का समावेश हो गया है। विशेषकर दूसरी लहर की भयावहता, मृत्यु दर का अधिक होना, तीसरी और चौथी कोरोना लहर की आशंका अनेकों ऐसी बातें हैं जिसने आम जीवन पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव डाला है वरन् सामाजिक जीवन भी विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है।

आर्थिक गतिविधियों का प्रतिबंधित होना :–

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों का घरों को पलायन हो रहा है, निरन्तर लॉकडाउन के कारण सभी कारखाने, उद्योग–धंधे, व्यवसाय, मॉल्स आदि बन्द प्रायः है, बाजार की सामान्य गतिविधियां लगभग नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में सभी आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित हुई हैं। बाजार में रूपये के आदान प्रदान में कमी आयी है। हर क्षेत्र में उत्पादन से लेकर विक्रय तक गिरावट का दौर जारी है जिससे व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां निरन्तर शिथिल होती चली जा रही हैं।

उपभोक्ता गतिविधियों में गिरावट :–

जब आम व्यक्ति की आय में कमी हो रही है, नौकरी पेशा व्यक्ति, उद्योग धंधे, व्यवसाय सभी में मंदी का दौर हो तो ऐसी स्थिति में बाजार में निरन्तर आर्थिक गतिविधियों मे कमी आनी स्वभाविक है। बाजार में जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी, धन का अभाव होगा तो उसकी क्रयशक्ति कम होगी जिसके कारण उपभोक्ता क्रियाओं और गतिविधियों में निरन्तर ह्रास देखने को मिल रहा है। उपभोक्ता अपनी अनिवार्य एवं मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा, ऐसे में अन्य अतिरिक्त वस्तुओं के क्रय का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

आपूर्ति की कमी एवं मंहगाई में वृद्धि :

आर्थिक गतिविधियों पर विभिन्न प्रतिबंधों के कारण, बार–बार लॉकडाउन के कारण उत्पादन संस्थायें, कारखाने और सभी उद्योग उत्पादन करने में असमर्थ हो रहे हैं। उत्पादन की निरन्तरता में कमी आने से बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में स्वभाविक रूप से कमी आ रही है और उधर लॉकडाउन के डर से आम व्यक्ति अधिक क्रय करके संग्रह करने की प्रवृति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में हो रहा है। मंदी के दौर मे आपूर्ति की कमी और मूल्यों में वृद्धि के कारण कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलने के अवसर उत्पन्न हो रहें हैं।

अनियमित यातायात :–

कोरोना की प्रथम लहर के चलते सन् 2020 में सभी प्रकार का यातायात पहले पूर्ण रूप से बन्द किया गया और अभी ट्रेन तो पूर्ण रूप से नियमित भी नहीं हो पायी थी कि कोराना की दूसरी लहर ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। सरकारी बस सेवाओं और ट्रेन सेवाओं की बात यदि छोड़ भी दे तो भी अनेकों एयरलाइंस कंपनियॉ दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गयीं हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें बन्द होने, राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित होने और कोरोना महामारी के भय ने यातायात पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने कोरोना टेस्टिंग आदि के जो प्रतिबंध लागू किए हैं, उनसे भी आम आदमी अभी किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बच रहा है और अत्यन्त आवश्यक होने पर ही यात्रा कर रहा है।

पर्यटन उद्योग का पतन :–

कोरोना काल में यदि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक विपरीत रूप से किसी उद्योग पर अधिक प्रभाव पड़ा है तो वह पर्यटन उद्योग ही है। अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन एवं उड़ानें बन्द होने के कारण विदेशी पर्यटकों का भारत आना पूर्ण रूप से बन्द है। यही नहीं, कोरोना के भय की लहर

के कारण व्यक्ति जब घर से बाजार तक भी मात्र अति आवश्यक होने पर ही जा रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी का भी किसी पर्यटन के लिए जाना मात्र अब एक कल्पना सी हो गयी है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहां आवाजाही न होने के कारण होटल, रेस्टोरेंट, गाइड़ आदि सभी के काम–धंधे चौपट होने की कगार पर हैं। पर्यटनों के अभाव में सभी की आय या तो बन्द है या उसमें उल्लेखनीय कमी आयी है।

शेयर बाजार में गिरावट :–

पिछला कुछ समय ऐसा आ गया था जब भारत आर्थिक रूप से अत्यन्त सशक्त होता जा रहा था, उसकी आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय छवि में बहुत सुधार हुआ था। इस सबका मिला–जुला परिणाम यह हुआ कि भारत में शेयर बाजार भी चमकने लगा। परन्तु कोरोना महामारी की इस विभीषका ने शेयर बाजार की इस चमक को फीका कर दिया और विनियोगकर्ताओं की आशाओं पर तुषारापात हो गया। उद्योग–धंधों के चौपट होने, व्यावसायिक गतिविधियों के शिथिल होने आदि का सीधा प्रभाव शेयर बाजार पर हुआ और विनियोगकर्ताओं की सक्रियता में कमी आने के कारण सम्पूर्ण शेयर बाजार की गतिविधियां भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं।

आयात–निर्यात में कमी :–

उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही कम नहीं हुई है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव हुआ है। पहले, कोरोना की पहली लहर ने विश्व के 220 देशों को प्रभावित किया और उसके बाद आई दूसरी लहर ने तो लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। भारत में तो दूसरी लहर का प्रकोप सर्वाधिक देखने को मिला है। भारत के न केवल आयात में कमी हुई है वरन् निर्यात में भी उल्लेखनीय कमी आयी है। सामान्य व्यक्ति की आवर्ती आय में कमी होने के कारण व्यक्ति संकटकाल के लिए संजोकर रखी धनराशि का उपयोग करने के लिये ही विवश हो गया है। सम्पूर्ण विश्व में हर देश की अर्थव्यवस्था के संकट में आ जाने के कारण वैश्विक स्तर पर आयातों में कमी हुई जिसके फलस्वरुप भारत के निर्यातों में स्वतः कमी स्वभाविक है जिसका अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

बेरोजगारी में वृद्धि :–

कोरोना महामारी की प्रथम लहर ने सारे काम–धंधों और उद्योग–धंधों को मृतप्रायः स्थिति में पहुंचा दिया जिसके कारण लाखों लोगों के रोजगार एवं नौकरी उनसे छिन गए। अनेकों कंपनियों, फैक्ट्रियों और संस्थानों ने अपने कार्मिकों के वेतन और पारिश्रमिक में उल्लेखनीय कटौतियां कर दीं जिससे प्रत्यक्ष–परोक्ष एवं दृश्य–अदृश्य बेरोजगारी में वृद्वि हुई है। 2020 के अंत में जब यह लगने लगा कि अब परिस्थितियां सुधार की ओर हैं, कोरोना नियंत्रित स्थिति में है, रोजगार की स्थितियां पुनः नियमित होने लगी हैं; तभी भारत में महाविनाशकारी कोरोना की दूसरी लहर ने पहली लहर से भी अधिक कोहराम मचाना प्रारम्भ कर दिया। उद्योग धंधे, कल–कारखाने, व्यवसाय, रोजगार सब पुनः लॉकडाउन में बन्द हो गए और बेरोजगारी की स्थिति पुनः कार्मिकों के समक्ष उपस्थित हो गयी। कोरोना पूर्व की स्थिति में भी भारत में बेरोजगारी की समस्या प्रमुख समस्याओं में थी, अब कोरोना काल में यह स्थिति और भी भयावह हो गयी है।

संघीय अथवा सरकारी आय में कमी :–

कोरोना महामारी की प्रथम एवं दूसरी लहर से त्रस्त तथा तीसरी लहर की आशंका ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जीर्ण किया है। उत्पादन उद्योग, अन्य उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियां, उपभोक्ता गतिविधियां शून्य प्रायः हो गयी हैं जिसका सीधा प्रभाव राजकीय आय और राजकोष पर पड़ा है। प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली कर राशि में राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कमी हुई है। मई 2020 में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज सरकार द्वारा घोषित किया गया, उसके कारण भी राजकीय खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। वैक्सीन की निःशुल्क उपलब्धता, कोविड रोकथाम के उपाय, चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण आदि का भार भी सरकारी खजाने को वहन करना पड़ रहा है। कोरोना की इस महामारी की विभीषिका के मध्य अम्फान जैसे तूफानों का सामना भी भारत के विभिन्न प्रान्तों ने किया जिससे राज्य और केन्द्र को राहत कार्यों में सहायता के लिए विशाल धनराशि व्यय करनी पड़ी। मई 2021 में ताउते, यास तूफान की भविष्यवाणी भी मौसम विभाग कर चुका है।

निष्कर्ष, सुधार के उपाय एवं आवश्यक कदम :–

कोरोना महामारी की प्रथम लहर ने जहां भारत की अर्थव्यवस्था एवं संघीय ढांचे को कमजोर किया, वहीं बची खुची कसर कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता ने पूरी कर दी। उद्योग–धंधे, व्यवसाय सभी एक कठिन स्थिति में दिखायी दे रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, दैनिक कामगारों के समक्ष रोजी–रोटी का संकट है। इन परिस्थितियों में राज्य एवं केन्द्र सरकारों को अपने राहत के द्वार पुनः खोलने होंगें। पुनः एक वृहद् राहत पैकेज घोषित करना होगा। विभिन्न प्रकार की आवश्यक रियायतें प्रदान करनी होंगीं। अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग राहतें घोषित करनी होंगीं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए निश्चित अवधि तक मुफ्त राशन और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्माणी संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, अन्य सभी व्यवसाय एवं उद्योग–धंधों को भी उचित आकलन के आधार पर राहत पैकेज, आर्थिक सहायता, रियायतें और आवश्यक होने पर कर ढांचे में भी छूट प्रदान की जानी अति आवश्यक है। सरकार को कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही पर भी कठोर कदम उठाकर नियंत्रण करना होगा जिससे बढ़ती मंहगाई पर अंकुश लग सके तथा राहत राशि सुपात्रों एवं उचित हाथों में बिना किसी कठिनाई के पहुंचना सुंनिश्चित हो सके। बाजार की गतिविधियों के पुनः सुचारू संचालन के लिए बाजारों को कोविड की सावधानियों को दृष्टिगत रखते हुए समयबद्ध एवं नियोजित तरीके से खोलना होगा और क्रमिक एवं योजनाबद्ध विधि से नियंत्रणों और प्रतिबन्धों को समाप्त करना होगा। उपभोक्ता की क्रय शक्ति को पुनः सशक्त

करने हेतु उदार एवं सरल ऋण नीति एक कारगर हथियार सिद्ध हो सकती है। सरकारी स्तर पर रोजगार को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ किया जा सकता है। यहां यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है कि हमें व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को खोलना और नियमित करना है जिससे अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो, वहीं दूसरी ओर हमें कोरोना महामारी को नियंत्रित भी रखना है और तीसरी लहर के प्रति सजगता में कमी भी नहीं आने देनी है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योजनाओं का सरलीकरण एवं उदारवादी नीति सहायक सिद्ध हो सकती है। सभी राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा उद्योगों, कारोबारों, व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं पर कोरोना के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान करने के लिए गहन अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत राहत के लिए समस्त आवश्यक कदम, रियायतें एवं योजनाएं तत्काल लागू करनी होंगीं तभी हम आने वाले भारत के एक सशक्त और सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

संदर्भ :–

1. जनसत्ता – विभिन्न अंक
2. द हिन्दू – विभिन्न अंक
3. www.worldometer.info
4. www.ndtv.co
5. www.bbc.com
6. www.drishtiias.com

10

कोरोना काल में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत

डॉ0 पिंकी बिष्ट

अर्थशास्त्र प्रवक्ता

रा0 इ0 का0 हिनौला, सल्ट (अल्मोड़ा)

सारांश

कोरोना काल के दौर में जब सम्पूर्ण विश्व में निराशा का माहौल था और विकसित देशों की सरकारें भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गई थी तो ऐसे समय में भारत की सरकार ने कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि इससे उत्पन्न परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा और इसे अपने आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के एक अवसर के रूप में देखा। यद्यपि कोरोनाकाल में जिस तरह विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है और न ही भारत को अभी सही मायनों में एक आत्मनिर्भर देश कहा जा सकता है किन्तु जिस मजबूती के साथ हम अपने दम पर कोरोना से लड़ने के लिए हर आवश्यक वस्तु का निर्माण न केवल अपने लिए कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों को भी उनकी आपूर्ति कर रहे हैं, उससे आत्मनिर्भर बनने की हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति तथा क्षमता दोनों परिलक्षित हो रहे हैं। कोरोना महामारी की इस परीक्षा में हमारे प्रदर्शन ने न केवल भारतीयों को अपितु सम्पूर्ण विश्व को यह विश्वास दिला दिया है कि भारत बहुत जल्द ही न केवल आत्मनिर्भर देश बनेगा बल्कि वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता देश भी बनेगा।

मुख्य शब्द– आत्मनिर्भर, क्षमता, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना का यह काल भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं और भारतीय जनमानस के लिए सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है और किसी आपातकाल से कम नहीं है। हाल के वर्षों में शायद ही कोई ऐसी आपदा आई हो जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग काल–कवलित हुए हों। कोरोना से बचाव हेतु जिस व्यापक स्तर पर देशव्यापी लॉकडाउन लगाए गए वे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वर्षों पीछे धकलने के लिए काफी थे परिणामस्वरूप भारत की जीडीपी ऋणात्मक हो गई थी। किन्तु इन सब के बावजूद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यापक विनाश की भूमि में ही नये विकास के पुष्प पल्लवित होते हैं, आवश्यकता होती है तो सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छाशक्ति की। यद्यपि सतही तौर से देखने पर वर्तमान परिदृश्य में नकारात्मक बातें ही ज्यादा दिख रही हैं किन्तु आपदा के इस समय में भारतीय चिकित्सा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में कई ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो भविष्य में आमूलचूल परिवर्तनों को जन्म देंगे। आपदा का यह समय ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उस नींव को तैयार कर रहा है जहाँ हम आत्मनिर्भर भारत के वर्षों पुराने स्वप्न को पूर्ण करेंगें। वर्तमान समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाये रखने के लिए ऐसे सकारात्मक परिवर्तनों पर नज़र बनाये रखना आवश्यक है जो बिना किसी शोर–शराबे के भारतीय चिकित्सा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में इस कोरोना काल में हो रहे हैं।

जहाँ 20वीं शताब्दी तक विश्व में उन देशों को शक्तिशाली तथा सामर्थ्यवान माना जाता था जिनके पास विशाल और आधुनिक हथियारों वाली सैन्य शक्ति होती थी, वहीं 21वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में ही यह बात प्रमाणित होने लगी कि अब विश्व का नेतृत्त्व उन देशों के हाथों में जाने वाला है जिनके पास सक्षम और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगी तथा जिनमें न केवल अपनी आवश्यकताओं अपितु विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होगी। इस नवीन परिस्थिति का आकलन करने वाले देशों में सर्वप्रथम देश हमारा पड़ोसी चीन था जिसने अपने तकनीकी कौशल और सस्ते श्रम के आधार पर न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपितु सम्पूर्ण वैश्विक बाजार को चीनी उत्पादों से भर दिया और अत्यधिक अल्पकाल में विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा। पड़ोसी देश चीन के साथ निरन्तर खराब रिश्तों और उसके उत्पादों पर बढ़ती हमारी निर्भरता ने भारतीय राष्ट्रवादी विद्वानों तथा भारत की सरकार को इस बात पर विचार करने को मजबूर कर दिया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे थे कि चीन पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। भारत के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों से आयात में वृद्धि करने का विकल्प था, जिससे हमारी चीन पर निर्भरता कम हो सकती थी किन्तु भारत का विश्व शक्ति बनने का सपना तभी साकार हो सकता था जब किसी भी अन्य देश पर निर्भर होने की अपेक्षा भारत आत्मनिर्भर बनता।

यद्यपि स्वतंत्रता की प्राप्ति से ही भारतीय आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखने लगे थे तथा समय–समय पर इसके प्रयास भी किए गये किन्तु अपेक्षित गति प्राप्त नहीं की जा सकी। भारत के आत्मनिर्भर बनने में एक बड़ी बाधा पूँजी तथा कौशल का अभाव भी था जिसके बिना आत्मनिर्भर होना सम्भव ही नहीं था। आत्मनिर्भरता की अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए नियोजित रूप से एक अभियान के रूप में कदम बढ़ाने की शुरूआत भारत सरकार ने तब की, जब 25 सितम्बर, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ''मेक इन इंडिया'' अभियान की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है जिससे भारत में न केवल रोजगार और पूँजी का निर्माण होगा अपितु भारतीय श्रमिकों को नवीन तकनीकी और मशीनों से काम करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा तथा भारत में पूँजी और कौशल की कमी को दूर किया जा सकेगा।

यद्यपि ''मेक इन इंडिया'' अभियान के परिणामस्वरूप भारत में विदेशी निवेश काफी बढ़ा तथा छः औद्योगिक गलियारों का विकास हुआ किन्तु फिर भी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग की पूर्ति और भारतीय उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लक्ष्य से हम अभी भी दूर थे। भारत सरकार ने ऐसे उद्यमियों जिनके अन्दर सामान्य से कुछ अलग हटकर काम करने की क्षमता तथा विज़न है, जो कुछ नये उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं तथा तेजी से बदलते विश्व को कुछ नया दे सकते हैं, के लिए ''स्टार्टअप इंडिया'' तथा ''स्टैंडअप इंडिया'' जैसे अभियानों की शुरूआत की तथा 23 दिसम्बर 2020 तक 41061 स्टार्टअप्स की पहचान की गई। आरम्भ में ऐसे कई देश थे जो उपभोक्ता वस्तुओं के वैश्विक बाजार में पहले से ही एकाधिकार बनाए हुए थे और बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करते थे जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती थी और उनके उत्पाद सस्ते हो जाते थे जिनका मुकाबला करना भारत के स्टार्टअप उद्योगों के लिए कठिन हो रहा था।

वर्ष 2019 के अन्त से ही विश्व कोविड–19 (कोरोना) महामारी की जद में आने लगा था जो 2020 के शुरूआत से अनियन्त्रित हो गया था। इस महामारी ने वैश्विक माँग में व्यापक परिवर्तन कर दिया। वैश्विक बाजार को अब विलासिता की वस्तुओं या सुविधाजनक वस्तुओं के स्थान पर जीवन रक्षक वस्तुओं की आवश्यकता थी। इस नई आवश्यकता की जितनी तीव्र माँग थी उतनी ही धीमी इसकी पूर्ति थी। यद्यपि चीन द्वारा इस महामारी को कुछ समय तक विश्व के अन्य देशों से छुपाया गया और इस बीमारी के विरूद्ध जीवन रक्षक उत्पादों के उत्पादन में कुछ बढ़त भी बनाई गई किन्तु उसके उत्पादों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी। कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यस्था को अत्यधिक नुकसान पहुँचाया, लम्बे लॉकडाउन ने विश्व के अनेक देशों के आर्थिक विकास को लगभग रोक ही दिया था। कोविड–19 से जीवन की रक्षा हेतु आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के सन्दर्भ में लगभग सभी देश एक जैसी स्थिति में थे और एक ही पंक्ति में खड़े थे।

कोरोना महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया था। कोरोना से बचाव के लिए जब सरकार ने विदेशी आयात पर रोक लगाई तो यह भी स्पष्ट हो गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति के लिए यदि हमें तैयार रहना है तो अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु का निर्माण हमें भारत में ही करना होगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के समय जिस तरह औद्योगिक मजदूरों का पलायन हुआ उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय मजदूर आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि उसके पास कुछ दिन के भरण–पोषण हेतु भी बचत नहीं है तथा कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे किसानों की भी थी और भारत की यह बहुसंख्यक आबादी जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाती है तब तक आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना भी सम्भव नहीं है। कोरोना काल ने भारत को वास्तविक अर्थ में आत्मनिर्भरता के महत्त्व को समझा दिया है। 12 मई, 2020 को जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी तो उसी समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने विज़न को भी सार्वजनिक रूप से देशवासियों के सम्मुख रखा और इस आपदा के समय को अवसर के रूप में बदलने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में जहाँ गरीबों, श्रमिकों तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास करने सम्बन्धी घोषणाऐं की गईं ताकि भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति में वे पुनः असहाय न हो जाऐं, वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु घोषणाऐं भी शामिल थीं। भारत में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गरीब व छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा जिन्हें पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की गई जिसमें रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों को ऋण मुहैया कराने की भी व्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ''लोकल फॉर वोकल'' होने का नारा भी दिया ताकि हमारे स्थानीय उत्पादों की न केवल माँग बढ़े अपितु उनको वैश्विक पहचान भी मिले।

कोरोना काल के दौर में जब सम्पूर्ण विश्व में निराशा का माहौल था और विकसित देशों की सरकारें भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गई थी तो ऐसे समय में भारत की सरकार ने कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि इससे उत्पन्न परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा और इसे अपने आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के एक अवसर के रूप में देखा। कोरोना प्रसार के शुरूआती समय में जब इसके इलाज के तरीकों पर शोध होने आरम्भ ही हुए थे तब हाइड्रोऑक्सीक्लोरोक्विन को इसके इलाज में कारगर माना जा रहा था जिसके उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी था किन्तु इसके उत्पादन में एक समस्या थी कि इसके कच्चे माल सक्रीय दवा घटकों (A.P.I.) का आयात चीन से होता था और जब कोरोना के कारण चीन से आयात बन्द हुआ और चीन में भी उत्पादन बन्द हुआ तो हमारे लिए इस दवा का निर्माण करना

कठिन हो गया जिससे हमें यह सीखने को मिला कि यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में हमें कच्चे माल से लेकर अन्तिम उत्पाद के उत्पादन तक सभी चरणों में आत्मनिर्भर होना होगा, परिणामस्वरूप भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री–मंडल ने निर्णय लिया कि अगले पाँच वर्षों के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से बल्क ड्रग्स पार्क्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को दवा निर्माण का मुख्य केन्द्र बनाने के उद्देश्य से महंगी दवाइयों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और वैश्विक फार्मा कम्पनियों को भारत में आकर्षित करने हेतु फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए 15 हजार करोड़ रूपये की पीएलआई योजना भी बनाई जिसके परिणाम भी जल्द ही दिखने लगेंगें। पीएलआई योजना के तहत सरकार द्वारा दवा बनाने की प्रक्रिया में उपयोगी मध्यवर्ती घटकों तथा कच्चे माल सक्रीय दवा घटकों (A.P.I.) के निर्माण हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए 6940 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

कोरोनाकाल ने हमारे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में न केवल सहायता की बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए विवश भी किया। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) हो या एन–95 मास्क, सर्जिकल मास्क, मेडिकल गॉगल्स या वेंटिलेटर, कोरोना के विरुद्ध जीतने के लिए ये सभी मूलभूत आवश्यक सामग्री में आते हैं जिनका आयात भारत विदेशों से करता था। कोरोना ने जहाँ अचानक इन सभी की माँग बहुत अधिक बढ़ा दी थी, वहीं वैश्विक व्यापार बन्द होने से आयातों से होने वाली पूर्ति भी लगभग बन्द हो गयी थी। अब भारत के पास केवल दो ही विकल्प थे या तो हाथ पर हाथ रखकर विदेशों से आयात करने तक इन्तजार करना या इस चुनौती को स्वीकार करते हुए स्वयं उत्पादन करना। भारत ने दूसरा विकल्प चुना और दो माह में ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। अमूमन यही स्थिति एन–95 मास्क, सर्जिकल मास्क, मेडिकल गॉगल्स, वेंटिलेटर तथा सैनिटाइजर के उत्पादन में भी हुई जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन अब भारत में ही होने लगा है। कोरोना काल में जब विश्व के अधिकांश देश कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया के विकसित देशों की ओर देख रहे थे, भारत ने फिर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करते हुए न केवल स्वदेश में ही विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड जैसे मेक इन इंडिया टीके बनाए बल्कि विश्व के अन्य देशों को उपलब्ध भी कराए। इस समय तक भारत विश्व के लगभग 80 देशों को 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक निर्यात कर चुका है और इस प्रकार चेचक जैसे रोगों के टीकों को आयात करने वाला देश, कोरोना के टीकों का निर्यातक देश बन गया। अभी भारत की कम्पनियाँ अपने विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर भारत में ही नये टीकों के निर्माण में लगी हैं। हैदराबाद की डॉ. रेड्डी लैब कोविड–19 के लिए रूस में निर्मित टीके स्पुतनिक वी, जिसका 60 से 70 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन भारत में होना है, के लिए भारतीय साझेदार है। इतना ही नहीं क्वाड के चार देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक भारत में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज़ तैयार करने का लक्ष्य रखा है जिससे कोरोना टीकों के क्षेत्र में भारत का गढ़ बनना निश्चित है।

निष्कर्ष

यद्यपि कोरोनाकाल में जिस तरह विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है और न ही भारत को अभी सही मायनों में एक आत्मनिर्भर देश कहा जा सकता है किन्तु जिस मजबूती के साथ हम अपने दम पर कोरोना से लड़ने के लिए हर आवश्यक वस्तु का निर्माण न केवल अपने लिए कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों को भी उनकी आपूर्ति कर रहे हैं, उससे आत्मनिर्भर बनने की हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति तथा क्षमता दोनों परिलक्षित हो रहे हैं। यद्यपि भारतीय स्वास्थ्य सेवाऐं सम्भवतः इस शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं किन्तु जिस तरह भारत ने अल्पकाल में ही दवाइयों के उत्पादन और निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि की है वह भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है और इससे भी सकारात्मक बात यह है कि यहाँ दवा उत्पादन की लागत अमेरिका तथा पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। कोविड–19 जहाँ भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के सामने नई–नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है, वहीं यह भारत में नए चिकित्सकीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर भी बन गया है। अमेरिका द्वारा वैक्सीन निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल पर रोक लगाना, जो बड़े संघर्ष के बाद ही हटाई गई, से यह भी स्पष्ट हो गया कि कच्चे माल के निर्माण में आत्मनिर्भर होना भी बहुत आवश्यक है। चालू वित्त वर्ष के बजट में शोध एवं नवाचार के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की घोषणा करना बताता है कि भारत चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु सही दिशा में गतिमान है। कोरोना काल में भारत द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का परिणाम ही है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत 48वें स्थान पर पहुँच गया है जो पहले से चार पायदान ऊपर है। यदि भारत कोरोना काल के अपने अनुभवों का सही दिशा में इसी प्रकार प्रयोग करते हुए सही प्रयास करता रहा तो सम्भवतः वर्ष 2030 तक भारत का फार्मा सैक्टर मौजूदा 40 अरब डॉलर से तीन गुना बढ़कर 120 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। कोरोना महामारी की इस परीक्षा में हमारे प्रदर्शन ने न केवल भारतीयों को अपितु सम्पूर्ण विश्व को यह विश्वास दिला दिया है कि भारत बहुत जल्द ही न केवल आत्मनिर्भर देश बनेगा बल्कि वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता देश भी बनेगा।

सन्दर्भ

1. zeenews.india.com
2. www.punjabkesari.in
3. www.patrika.com
4. www.bbc.com
5. www.drishtiias.com
6. ddnews.gov.in

11

कोविड-19 महामारी के दौर में मेक इन इंडिया के तहत फार्मास्युटिकल सेक्टर का अवलोकन

डॉ0 श्रवण कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

मुल्तानीमल मोदी कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद

सारांश

कोरोना वायरस से जन्मी महामारी कोविड–19 से विश्वभर में आक्रांत फैला हुआ है जिससे समूची मानवजाति एक असाधारण स्वास्थ्य संबंधी त्रासदी से त्रस्त है। महामारी ने ना केवल स्वास्थ्य संबंधी चुनौती उत्पन्न की है बल्कि देश में आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित किया है। वर्तमान में भारत ही नहीं विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थायें भी अनिश्चितता के उच्च–स्तर का सामना कर रहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट ही नहीं है कि किस देश के द्वारा क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं। अधिकांशतः महामारी को फैलने से रोकने के लिये किये गये उपायों को दैनिक आधार पर अपनाया जा रहा है। इस आपातकालीन स्थिति ने सभी देशों को अपनी नीतियों पर विचार–विमर्श करने को मजबूर कर दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में कोविड–19 महामारी के प्रकोप में मेक इन इंडिया के तहत फार्मास्युटिकल सेक्टर का अवलोकन किया गया है। जहाँ भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, तो वहीं इस बढ़ते क्षेत्र में कई बड़ी चुनौतियाँ भी हैं।

मुख्य शब्द– मेक इन इंडिया, कोविड–19 महामारी, फार्मास्युटिकल सेक्टर

कोरोना वायरस से जन्मी महामारी कोविड–19 से दुनियाभर में आक्रांत है। वर्ष भर से भी अधिक का समय हो चला है और महामारी के विरूद्ध समूची मानवजाति की लड़ाई अभी भी जारी है। वर्तमान में स्थिति पहले से भी अधिक भयावह है। देश में पर्याप्त चिकित्सा संबंधी आवश्यक संसाधनों की कमी से वैश्विक महामारी की वजह से देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुये आवश्यक चिकित्सा संबंधी संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया गया। परन्तु इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण रोजगार का संकट खड़ा हो गया। देश में पहले से ही बेरोजगारी की दर 7.8 प्रतिशत थी। ऐसे में लॉकडाउन से उपजी नई परिस्थितियों ने नौकरियों पर संकट खड़ा कर दिया है।

लॉकडाउन से न केवल लोगों के रोजगार संकट में आये बल्कि इसने अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाया है। आर्थिक गतिविधियाँ सुस्त हो गयी हैं जिससे वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति व माँग दोनों प्रभावित हैं। अर्थशास्त्र की शब्दावली में कहें तो इससे आय का चक्रवात प्रवाह भंग होता है। आय के चक्रवात प्रवाह में अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन के साधनों का परिवारों से उत्पादक फर्मों की ओर प्रवाह होता है जिसके बदले में उत्पादक फर्मों से परिवारों की ओर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। उत्पादक फर्में अपने उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती हैं और आगे वही प्राप्त भुगतान परिवारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय कर दिया जाता है। इस प्रकार से आय का चक्रवात प्रवाह पूरा होता है।

महामारी के कारण लगाये गये लॉकडाउन ने अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार को भी पूरी तरह से ठप कर दिया है, इसके कारण निर्यात महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुये। इसका सबसे अधिक असर टेक्सटाइल, चमड़ा–उद्योग, दवा उद्योग आदि अधिक रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक देखा गया। परन्तु इन सभी क्षेत्रों में से दवा उद्योग (फार्मास्युटिकल सेक्टर) सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ भी अधिक खड़ी हैं। कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये किये गये उपायों ने राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्पादन क्रियाओं व आपूति श्रृंखला को बाधित किया है।

कोविड–19 महामारी ने 124 से भी अधिक देशों को अपनी चपेट में लिया है। मौजूदा स्थिति में चिकित्सा उपकरणों और दवा उत्पादों की माँग उत्पादन क्षमता से अधिक हो गई है। परिणामस्वरूप कई देशों के नीति–निर्माताओं व विश्लेषकों ने देश में ही आवश्यक माँग को पूरा करने के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित किया। भारत के विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने निजी सुरक्षा उपकरणों

जैसे विभिन्न मैडिकल सामानों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है जिसमें सभी प्रकार के मास्क, काले चश्मे, दस्ताने, सभी प्रकार के वेंटिलेटर और 14 दवायें शामिल हैं। इनके विनिर्माण के लिये आवश्यक डायग्नोस्टिक किट, प्रयोगशाला अभिकर्मकों, सैनिटाइजर आदि वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये अधिकांश को प्रतिबंधित कर दिया गया।

दुनिया जहाँ कोरोना महामारी से अस्त–व्यस्त है वहीं चीन की जी.डी.पी. में 2021 की पहली तिमाही में 18.3 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हासिल हुई है। इसके विपरीत 2020 में लॉकडाउन की वजह से प्रथम तिमाही में जीडीपी में 6.8 प्रतिशत की भारी गिरावट आयी थी। चीन ने बहुत ही व्यवस्थित उपायों को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है, वहीं विश्व के अन्य देश आज भी महामारी से संघर्षरत हैं।

कोविड–19 महामारी पर चीन के साथ तनावपूर्ण राजनयिक व व्यवसायिक संबंधों के साथ अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक निवेशकों को अपनी विनिर्माण गतिविधियों को भारत, बांग्लादेश, थाइलैंड और वियतनाम जैसे अन्य देशों की ओर हस्तान्तरित किया है। इस सन्दर्भ में महामारी ने भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनने और अपने निर्यात आधार को विस्तृत करने का अवसर प्रदान किया है जिसमें भारत में मेक इन इंडिया पहल के अन्तर्गत इसको गति प्रदान की जा सकती है।

मेक इन इंडिया पहल

25 सितम्बर, 2014 को केन्द्र सरकार ने देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की थी। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को शामिल कर उनमें रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरुप उत्पादन करना और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को कम करना है। भारत में इस कार्यक्रम के तहत पूँजी व तकनीकी निवेश में प्रगति होने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी घरेलू कंपनियों का पता लगाने का भी प्रयास किया गया है जो नई तकनीक व प्रौद्योगिकी को विकसित करने की क्षमता रखती हैं ताकि वे विश्व–स्तर पर अपनी पहचान बना सके।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम चार स्तम्भों पर आधारित है। ये चार स्तम्भ हैः– नई प्रक्रिया, नई आधारभूत संरचना, नए क्षेत्र, नई विचारधारा।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

- विनिर्माण क्षेत्र में 12–14 प्रतिशत प्रति वर्ष विकास दर को बढ़ाना।
- अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन नौकरियों का निर्माण करना।
- 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में जी.डी.पी. में योगदान 25 प्रतिशत तक बढ़ाना (बाद में 2025 तक संशोधित)।

कोरोना महामारी ने यूँ तो देश के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। जब से नोवल कोरोना वायरस 2019 को, 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक महामारी कोविड–19 के रूप में घोषित किया, तब से मेक इन इंडिया के तहत दवा उद्योग (फार्मास्युटिकल सेक्टर) ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके सामने सबसे अधिक चुनौतियाँ खड़ी हैं। महामारी के कारण फार्मास्युटिकल सेक्टर पर तत्काल प्रभावों में मुख्यतः आवश्यक वस्तुओं की माँग में परिवर्तन, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में कमी, संचार, तकनीकी विज्ञान, तथा अनुसंधान व विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन शामिल हैं।

फार्मास्युटिकल सेक्टर

भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर दवा की अद्यतन मात्रा में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य में दसवाँ सबसे बड़ा उद्योग है। फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उद्योग का कुल आकार (दवाओं और चिकित्सा उपकरणों) में लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार दवा उद्योग की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 15–16 प्रतिशत दर्ज की गई है। भारत विश्व स्तर पर जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वह दुनिया में विभिन्न टीकों की माँग का करीब 50 फीसदी, अमेरिका में जेनरिक दवाओं की माँग का 40 फीसदी और ब्रिटेन में सभी दवाइयों का 25 फीसदी मुहैया कराता है। देश के दवा (फार्मास्युटिकल) उद्योग की विश्व में कुल दवाइयों के निर्यात में भागीदारी 3.5 फीसदी है। भारत में इस उद्योग में 3,000 पंजीकृत दवा कंपनियाँ और 10,500 से भी अधिक उत्पादन इकाइयाँ हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2022 तक 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। परन्तु इस बढ़ते क्षेत्र में कई बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। भारत में सर्जिकल, कॉर्डिएक स्टंट और इलेक्ट्रॉनिक जैसे चिकित्सा उपकरणों की कुल आवश्यकता का 86 फीसदी आयात किया जाता है। वहीं दवा के प्रमुख अवयवों के उत्पादन में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2023 तक कंपनियों को उत्पादन में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 1 लाख करोड़ (1.3 अरब डॉलर) के एक कोष की स्थापना की है ताकि चीन से आयात घटाया जा सके। दवा उद्योग में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है। इसी के साथ देश का बायोटेक्नोलॉजी उद्योग भी बढ़ रहा है। इस तरह दवा उद्योग सालाना 30 फीसदी वृद्धि के साथ वर्ष 2025 तक 100 अरब डॉलर का कारोबारी लक्ष्य हासिल करना चाहता है।

महामारी के दौर में भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर में व्यापार

भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया सहित 200 से भी अधिक देशों को किया जाता है। भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका, यू.के., साउथ अफ्रीका और रूस को निर्यात करता है। भारत आयातों

में सबसे अधिक आयात चीन, अमेरिका, इटली और जापान से करता है। भारत के फार्मास्युटिकल व्यापार को निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका – 1

फार्मास्युटिकल सेक्टर में भारत के निर्यात और आयात (वर्ष 2020–21)

(मिलियन डालर)

महीनें	ड्रग्स और फार्मास्युटिकल निर्यात	फार्मास्युटिकल उत्पाद का आयात
जनवरी, 2020	1782.96	549.12
फरवरी, 2020	1745.47	474.99
मार्च, 2020	1545.58	412.48
अप्रैल, 2020	1531.06	434.10
मई, 2020	1977.18	590.66
जून, 2020	2018.21	536.29
जुलाई, 2020	2057.75	738.62
अगस्त, 2020	1976.21	592.76
सितम्बर, 2020	2241.15	630.73
अक्टूबर, 2020	2077.29	600.35
नवम्बर, 2020	1989.15	534.91
दिसम्बर, 2020	2204.11	623.54
जनवरी, 2021	2074.60	549.80

स्रोत– विदेश व्यापार महानिदेशालय संगठन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका में साल 2020 के सितम्बर माह में निर्यातों का मूल्य (2241.15 अमेरिकी मिलियन डॉलर) सबसे अधिक रहा। आयातों का मूल्य साल 2020 के जुलाई माह में सबसे अधिक (738.62 अमेरिकी मिलियन डॉलर) था।

महामारी के समय में भारत से दवाओं के निर्यातों में प्रमुख निर्यात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का देखा गया है, जब से भारत ने इस पर से प्रतिबंध हटाया है तब से यह दवा न केवल अमेरिका अपितु भारत ने अपने पड़ोसी देशों सहित 55 देशों को इस दवा का निर्यात किया है। भारत से दवाओं के ऐसे सहयोग को देखते हुए ही इस उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के कई प्रमुख कारण हैं। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कई ऐसी स्वास्थ्य योजनायें शुरू की हैं जिससे गरीब व कमजोर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुँच सकें। जैसे– आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, Promotion of Bulk Drug Scheme आदि। भारत में विदेशी निवेश के लिये फार्मास्युटिकल सेक्टर शीर्ष आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपकरण में स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गयी है। ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में भी स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में 74 फीसदी से अधिक और 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के लिये सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

निष्कर्ष

वर्तमान में कोरोना एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसने न केवल स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ खड़ी हैं अपितु देश के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना असर छोड़ा है। इस बढ़ते क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ अधिक हैं तो वहीं दीर्घकाल में इसमें रोजगार सृजन व विकास की गति के अवसर भी विद्यमान हैं। इसलिये सरकार को मानवजाति के समक्ष स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा में खर्च को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर महामारी के प्रकोप में भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है और मजबूती से विकास की राह पर अग्रसर है। हमारे देश में संक्रामक बीमारियों की जाँच के लिये एक ठोस तन्त्र की आवश्यकता हैं। कोरोना जैसी महामारी के लिए बेहतर प्रबंधन भी एक उपचार ही है जिसका बड़ी कुशलता से पालन किया जाये। हालांकि देश में हाल के वर्षो में वित्त मंत्री द्वारा बजट 2021–2022 में स्वास्थ्य योजनाओं पर व्यय की मात्रा में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। लेकिन अभी भी यह व्यय कम है। विशेषज्ञों की राय में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के चार फीसदी तक लाने की आवश्यकता है तभी हम भविष्य में संक्रामक बीमारियों से आसानी से मुकाबला कर सकेंगें।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्र, एस0के0 और पुरी, वी0के0 (2020), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिकेशन्स हाऊस, 32 वाँ संस्करण, पृ0 314–315.
2. आहुजा, एच0एल0 (2012), उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, एस–चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृ0 23–24.
3. पांडेय, किसलय (2020), कोरोना एक चुनौतीं, इंडिया टुडे पत्रिका, 26 अगस्त 2020, पृ0 57.
4. फोकस, हर मर्ज का इलाज, इंडिया टुडे पत्रिका, 26 अगस्त, 2020, पृ0 52–53.
5. जैड़ा, मदन (2021), भारी पड़ गई कुछ कमियाँ, हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 28 अप्रैल 2021, पृ0 11,
6. न्यूज मेकर, 55 देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दे रहा भारत, गंभीर समाचार पत्रिका, 1–15 मई, 2020, पृ0 10–16.
7. Annual Report. (2019-20). Government of India, Department of Pharmaceuticals, pp. 2-3.
8. India Pharma. (2020). Propelling access and acceptance, realising true potential, Mckiney & Company, pp. 37-38.
9. Aneja, Puneet. (2016). Make in India: New Paradigm for Social Economic Growth in Inda, Indian Jaurnal of Research, Paripex, pp. 1-2.
10. Annual Report. (2020-21). Department of Commrce, Goverment of India Ministry of Commerce & Industry, pp 41-42.
11. Year and Review. (2020): Ministry of Chemicals & Fertilizers, 1 Jan, 2021, PIB Delhi.
12. Trade in Medical Goods in the contex of Tackling covid-19: Developments in the first Half of 2020. (22 Dec 2020) World Trade organization, Document Repart, p.1
13. Directorate General of foreign Trade Statishics Division, Monthly Bullation on foreign Trade Statistics. (2020). pp. 51-54.
14. https://www.pib.gov.in
15. https://www.pharmaceuticals.gov.in
16. https://www.makeinindia.com

12

भारत में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व - कोरोना महामारी के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय

साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

कोविड–19 महामारी के वर्तमान समय में निगमीय अर्थात् कॉर्पोरेट जगत विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। प्रभावी मांग में कमी आई है, फलस्वरूप उत्पादन का स्तर नीचे गिर गया है, श्रम तथा अन्य उत्पादन साधनों का अभाव है। लाभों की मात्रा कम हो रही है। कॉर्पोरेट जगत के लिए इस परिस्थिति में सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु धन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत का कॉर्पोरेट जगत ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सी.एस.आर. गतिविधियों में सक्रिय रुप से संलग्न है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में पिछले 3 वर्षों में कॉर्पोरेट जगत द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के दूसरे हिस्से में क्योंकि सरकार द्वारा 'पीएम केयर्स फंड' में अंशदान को एक अनुमन्य सी.एस.आर. गतिविधि मान लिया गया है, को केंद्र बिंदु बनाकर कॉर्पोरेट जगत का इस फंड में योगदान का संक्षिप्त वर्णन करा गया है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर सक्रिय रुप से सी.एस.आर. गतिविधियों में संलग्न है तथा साथ ही कोविड–19 की विषम परिस्थितियों में भी पीएम केयर्स फंड में अंशदान के माध्यम से तथा अन्य विभिन्न प्रकार से कोविड के साथ लड़ाई में तथा कोविड–19 पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास पहुंचाने में अनेकानेक प्रकार से संलग्न है।

मुख्य शब्द– सी.एस.आर., कॉर्पोरेट सेक्टर, कोविड–19, राहत एवं पुनर्वास

आधुनिक व्यवसाय का उद्देश्य मात्र केवल लाभ उपार्जन नहीं है अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी वर्तमान में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य बन गया है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व फर्म स्तर पर श्रमिकों, स्थानीय पर्यावरण के प्रति, समाज स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों, ग्राहकों, परंपरा, संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति तथा वैश्विक स्तर पर संपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन तथा आम आदमी के जीवन यापन के स्तर के प्रति हो सकता है। भारत में निगमीय अर्थात् कॉर्पोरेट जगत विभिन्न माध्यमों से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन सतत रूप से करता आ रहा है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility i.e. C.S.R.) को संक्षिप्त रूप में सी.एस. आर. भी कहा जाता है।

वर्ष 2013 से पहले तक कंपनियों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन एक स्वैच्छिक क्रिया थी, लेकिन कंपनी अधिनियम में 2013 में किये गए संशोधन के द्वारा धारा 135 के अंतर्गत इन दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य कर दिया गया है। ये अनिवार्यताएं 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गईं हैं। फलस्वरूप प्रत्येक कंपनी को अपने लाभों का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित विभिन्न कार्यों में, जिनको सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, पर खर्च करना पड़ता है अन्यथा की दशा में जुर्माने एवं सजा का भी प्रावधान इन कानूनों में करा गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में पिछले 3 वर्षों में कॉर्पोरेट जगत द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के खर्च का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के दूसरे हिस्से में क्योंकि सरकार द्वारा 'पीएम केयर्स फंड' में अंशदान को एक अनुमन्य सी.एस.आर. गतिविधि मान लिया गया है, को केंद्र बिंदु बनाकर कॉर्पोरेट जगत का इस फंड में योगदान का संक्षिप्त वर्णन करा गया है।

यह शोध पत्र मुख्यता द्वितीयक समंकों पर आधारित है। ये समंक सी.एस.आर. गतिविधियों के सरकारी पोर्टल, कंपनी मामलों के मंत्रालय, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख एवं शोध पत्र, समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाएं एवं इंटरनेट इत्यादि पर उपलब्ध सामग्री से प्राप्त करे गयें हैं। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय रीतियाँ जैसे वर्गीकरण एवं सारणीयन तथा अंकगणितीय रीतियाँ जैसे प्रतिशत इत्यादि का प्रयोग करा गया है। समंक समयावधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 अर्थात् तीन वर्ष रखी गई है।

सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु वैधानिक बाध्यता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रभावानुसार––

- प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्तियां 500 करोड रूपये या अधिक हैं या जिसकी वार्षिक बिक्री 1000 करोड़ रुपये या अधिक है या जिसका वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ पांच करोड रूपये या अधिक है, वह अपने तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों पर खर्च करेगी।
- 2019 में किये गए संशोधन के तहत सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन ना करने की दशा में दोषी कंपनी पर 50000 रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी अधिकारी को तीन वर्ष तक की जेल या 50000 रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा जेल एवं जुर्माना दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।

सी.एस.आर. गतिविधियों के तहत अनुमन्य क्षेत्र

सी.एस.आर. गतिविधियों के तहत अनुमन्य क्षेत्र की सूची भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दी गयी है जिनको निम्न प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है–

- भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने हेतु उपाय, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपाय, सफाई संबंधी उपाय और पीने के पानी की उपलब्धता हेतु उपाय,
- बच्चों, स्त्रियों, बुजुर्गों एवं विकलांग लोगों के लिये शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा हेतु उपाय एवं जीवनयापन साधनों को बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम,
- लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण हेतु उपाय, महिलाओं और अनाथों के लिए घर एवं छात्रावास निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम एवं अन्य सुविधायें, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों में असमानता को दूर करने हेतु विभिन्न उपाय,
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन व संरक्षण हेतु उपाय, पशु कल्याण, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय,
- राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें पुराने भवनों, ऐतिहासिक भवनों का पुनर्निर्माण एवं कलाकृतियों का पुनर्निर्माण भी सम्मलित है, परंपरागत कला एवं हस्तकला का संवर्धन एवं विकास, सार्वजानिक पुस्तकालयों का निर्माण,
- सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त लोगों, युद्ध की विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए किए गए कार्य,
- ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर के खेल, विकलांगों हेतु ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहन,
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोष जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास, सहायता एवं कल्याण है,
- तकनीकी इनक्यूबेटर्स के लिए योगदान जो अनुमन्य शिक्षण संस्थाओं में लगाए गए हैं,
- ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र का विकास,
- आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण भी शामिल है।

समंक विश्लेषण

- सारणी 1 सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या, सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु कार्यक्रमों की संख्या एवं सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय की राशि को प्रदर्शित कर रही है। वर्ष 2017–18 से 2018–19, उपरोक्त तीनों समंकों में वृद्धि दिखा रहा है परन्तु 2019–20 में इन समंकों में कमी आयी है। 2019–20 में कोरोना का प्रकोप शुरू हो जाने के कारण कंपनियों के लाभ कम हुए थे, फलस्वरूप इन समंकों में कमी परिलक्षित हो रही है।
- सारणी 2 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के संदर्भ में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या, सी.एस.आर. गतिविधियों में समाहित किये गये जिलों की संख्या एवं सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय की राशि को प्रदर्शित कर रही है। वर्ष 2017–18 से 2018–19, उपरोक्त तीनों समंकों में वृद्धि दिखा रहा है परन्तु 2019–20 में इन समंकों में कमी आयी है। 2019–20 में कोरोना का प्रकोप शुरू हो जाने के कारण कंपनियों के लाभ कम हुए थे, फलस्वरूप इन समंकों में कमी परिलक्षित हो रही है।
- सारणी 3 में भारत की शीर्षस्थ 5 कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) द्वारा सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय को वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 हेतु दर्शाया गया है। पॉचों ही कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर इन तीन वर्षों में वृद्धिशील रूप में व्यय किया गया है। 2019–20 कोरोना काल में भी तीनों ही कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक व्यय किया गया है अर्थात ये कंपनियां कोरोना काल में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का समुचित रूप से निर्वहन कर रहीं हैं।

- सारणी 4 में सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय को व्ययों की मद के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। सी.एस. आर. गतिविधियों पर व्यय का मुख्य भाग बच्चों, स्त्रियों, बुजुर्गों एवं विकलांग लोगों के लिये शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा हेतु उपाय एवं जीवनयापन साधनों को बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर; भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने हेतु उपाय, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपाय, सफाई और पीने के पानी की उपलब्धता हेतु उपाय पर; ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन संरक्षण हेतु उपाय, पशु कल्याण, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों पर खर्च हुआ है।

कोविड महामारी के समय निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व

कोविड–19 महामारी के वर्तमान समय में कॉर्पोरेट जगत विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। प्रभावी मांग में कमी आई है, फलस्वरूप उत्पादन का स्तर नीचे गिर गया है, श्रम तथा अन्य उत्पादन साधनों का अभाव है। लाभों की मात्रा कम हो रही है। कॉर्पोरेट जगत के लिए इन परिस्थितियों में सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु धन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है।

वास्तव में कोविड महामारी का यह समय भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए दुविधा भरी स्थिति लेकर आया है। क्योंकि लाभ अपर्याप्त हैं लेकिन साथ ही कोविड महामारी से लड़ने की देश–समाज हित की भावना भी प्रबल है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यही उठता है कि वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करें।

लेकिन भारत के संदर्भ में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत का कॉर्पोरेट जगत ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सी.एस.आर. गतिविधियों में सक्रिय रुप से संलग्न है। भारत का निगमीय जगत इस मुश्किल भरी स्थिति में भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से पीछे नहीं भागा है। वह हर कदम पर सरकार के साथ खड़ा है चाहे वह पीएम केयर्स फंड में अंशदान हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महामारी से बचने के तरीकों में सहयोग एवं महामारी पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास में सहायता।

23 मार्च 2020 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड–19 हेतु खर्च को भी अनुमन्य सी.एस.आर. गतिविधियों में शामिल किया जायेगा तथा इसको कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7 में वर्णित निम्न मदों में शामिल किया जा सकता है – भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने हेतु उपाय, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपाय, सफाई(स्वच्छ भारत कोष में अंशदान भी शामिल है) तथा आपदा प्रबंधन।

कॉर्पोरेट जगत द्वारा कोरोना महामारी में मुख्य रुप से सहयोग पीएम केयर्स फंड के माध्यम से किया गया है। इसलिए पीएम केयर्स फंड को केंद्र बनाकर भारतीय कॉर्पोरेट जगत का सी.एस.आर. गतिविधियों का अध्ययन करने का प्रयास शोध पत्र के इस प्रखंड में किया गया है।

आकस्मिक परिस्थितियों हेतु प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय नागरिक सहायता एवं राहत कोष अर्थात् पीएम केयर्स फंड

(Prime Minister's Citizen Assistance & Relief in Emergency Situations Fund)

कोविड तथा कोविड जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से निबटने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को की, जिसमें भारत एवं विदेशों से भी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट जगत एवं व्यक्ति दान दे सकते हैं।

कोविड परिस्थितियों एवं इसके जैसी आकस्मिक एवं असहज परिस्थितियों से लड़ने हेतु भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की है जो प्रभावित लोगों को सहायता एवं राहत प्रदान करने के काम आयेगी। महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना इस कोष का उद्देश्य है। इसका निर्माण गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए तथा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है।

इस कोष के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं तथा भारत के शिक्षा मंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री इस कोष के ट्रस्टी होंगे। इसके अतिरिक्त इस कोष का अध्यक्ष; शोध, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, प्रशासन तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से अतिरिक्त ट्रस्टी भी चुनने का अधिकारी है।

प्रधानमंत्री के इस कोष में अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत भी सौ प्रतिशत छूट में आता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सी.एस.आर. गतिविधियों में भी इस कोष में अंशदान शामिल होता है। पीएम केयर्स फंड में विदेशी अंशदान भी आ सकता है, इस हेतु विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 में आवश्यक व्यवस्था की जा चुकी है।

31 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड के अंकेक्षित प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अनुसार पीएम केयर्स फंड में कुल स्वैच्छिक अंशदान 3075.86 करोड रुपये प्राप्त हुआ है तथा विदेशी अंशदान 39.67 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। साथ ही उपरोक्त तिथि पर 35.33 लाख रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड में अंशदान देने वालों की सूची जारी नहीं की गई है तथा इसमें से किए गए व्ययों का भी विस्तृत एवं स्पष्ट वर्णन सरकार द्वारा अभी नहीं करा गया है। फलस्वरूप गैर सरकारी तथा अपुष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ मुख्य अंशदाताओं की सूचना एकत्र करी गयी है। गैर सरकारी तथा अपुष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचना कहती है कि 20 मई 2020 तक इस कोष में 9677.9 करोड़ रूपये अंशदान प्राप्त हो चुका है तथा 2098.2 करोड़ रूपये अंशदान प्राप्य है।

सरकार द्वारा 13 मई 2020 को दी गई सूचना के अनुसार अब तक लगभग 3100 करोड रुपये पीएम केयर्स फंड में से खर्च हेतु अनुमन्य किए जा चुके हैं। इनमें से 2000 करोड रुपये 50000 भारत निर्मित वेंटीलेटर्स के लिए है जो सरकारी अस्पतालों को प्रदान करें जाएंगे, 1000 करोड़ रूपये प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदान किए गए हैं तथा 100 करोड़ रुपये कोविड वैक्सीन के विकास हेतु प्रदान किए गए हैं।

सरकार के अनुसार भारत की जनता को निशुल्क कोविड वैक्सीन हेतु भी इस कोष का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार ने इस कोष से भारत के सरकारी चिकित्सालयों में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन निर्माण संयन्त्र लगाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही इस कोष से 1 लाख मिनी ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स क्रय करने का निर्णय भी सरकार ने किया है।

भारत की शीर्षस्थ कंपनियों द्वारा कोविड महामारी के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड –पीएम केयर्स फंड में अंशदान 500 करोड़ रूपये, महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकार प्रत्येक को 5 करोड़ रूपये, मुंबई में 100 बिस्तरों वाला कोविड चिकित्सालय, प्रतिदिन 1 लाख फेस मास्क का निर्माण, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 50 लाख जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन, कोविड कार्य में लगे वाहनों को निशुल्क ईंधन इत्यादि।
- टाटा ग्रुप – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 500 करोड़ रूपये, 1000 करोड़ रूपये कोविड महामारी से लड़ने हेतु विभिन्न प्रकार से।
- आदित्य बिरला ग्रुप – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 400 करोड़ रूपये।
- इनफोसिस लिमिटेड – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 50 करोड़ रूपये, 50 करोड़ रूपये कोविड महामारी से लड़ने हेतु विभिन्न प्रकार से।
- एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 150 करोड़ रूपये।
- वेदांता, बजाज समूह, अडानी समूह, JSW समूह – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 100 करोड़ रूपये प्रत्येक के द्वारा।
- हीरो साइकल्स एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड – 100 करोड़ रूपये प्रत्येक के द्वारा कोविड महामारी से लड़ने हेतु विभिन्न प्रकार से।
- लारसन एंड टुब्रो – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 150 करोड़ रूपये।
- Paytm – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 150 करोड़ रूपये।
- कोटक महेन्द्रा बैंक – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 25 करोड़ रूपये, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष 10 करोड़ रूपये।
- अजीज प्रेमजी समूह – कोविड महामारी से लड़ने हेतु विभिन्न प्रकार से 1125 करोड़ रूपये।
- अडाणी समूह – पीएम केयर्स फंड में अंशदान 100 करोड़ रूपये।

पीएम केयर्स फंड में अंशदान के अलावा भी भारतीय कॉर्पोरेट जगत कोरोना महामारी से लड़ाई में विभिन्न आकार प्रकार से सतत रूप से संलग्न है चाहे वह पीपीपी किट, फेस मास्क, सैनिटाइजर टेस्टिंग किट्स, वेंटीलेटर्स प्रदान करने की बात हो, ऑक्सीजन सिलिंडर व ऑक्सीजन कनसेनट्रेटर्स प्रदान करने की बात हो या कोविड अस्पताल या कोविड मरीजों हेतु बेड प्रदान करने की बात हो। कॉर्पोरेट जगत हर प्रकार से कोरोना के साथ लड़ाई में साथ है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में 875 कोविड बेड्स के संचालन की स्वयं जिम्मेदारी ली है।

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली 'कोविडशील्ड' के दाम देशहित में 400 से घटाकर 300 रूपये कर दियें हैं। इसी प्रकार भारत बायोटेक ने भी राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली 'कोवैक्सीन' के दाम देशहित में 600 से घटाकर 400 रूपये कर दियें हैं। उद्योग जगत ने उत्पादन क्रियाओं में प्रयोग की जाने वाली ऑक्सीजन को भी कोविड–19 पीड़ितों की मदद के लिए चिकित्सालयों को उपलब्ध कराने के लिए हामी भर दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए भारत की शीर्ष कंपनियां कल्याण कोष के माध्यम से जीवनयापन हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान कर रही हैं। कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को यथासंभव वर्क फ्रॉम होम इत्यादि की व्यवस्था भी प्रदान की हुई है। हर प्रकार से औद्योगिक जगत सरकार एवं समूचे स्वास्थ्य ढांचे के साथ स्वार्थ रहित तरीके से कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध पत्र में किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत का निगमीय अर्थात् कॉर्पोरेट जगत सी.एस.आर. गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है चाहे वह पीएम केयर्स फंड में अंशदान की बात हो या किसी अन्य प्रकार से कोविड मरीजों की मदद करने में सरकार, चिकित्सालयों एवं पूरी व्यवस्था के साथ सहयोग। पिछले 3 वर्षों के सी.एस.आर. समंकों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2019–20 में सी.एस.आर. गतिविधियों पर पिछले 2 वर्षों के मुकाबले कम धनराशि व्यय हुई है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि वर्ष 2019–20 में कंपनियों के लाभ कोविड कारणों से कम रहे, फलस्वरूप सी.एस.आर. गतिविधियों पर भी कम राशि खर्च हुई है। सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय का मुख्य भाग बच्चों, स्त्रियों, बुजुर्गों एवं विकलांग लोगों के लिये शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा हेतु उपाय एवं जीवनयापन साधनों को बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर, भूख,गरीबी और कुपोषण को मिटाने हेतु उपाय, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपाय, सफाई और पीने के पानी की उपलब्धता हेतु उपाय पर, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन संरक्षण हेतु उपाय, पशु कल्याण, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों पर खर्च हुआ है। वैसे तो कोविड–19 के साथ युद्ध में भारतीय कॉर्पोरेट जगत का योगदान बहुत ही सराहनीय है लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो कि सी.एस.आर. गतिविधियों को पूरा करते समय ध्यान रखने

योग्य हैं। कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी करके, अपने कर्मचारियों की मजदूरी–वेतन में कटौती करके तथा खराब आर्थिक स्थिति होते हुए भी पीएम केयर्स फंड में अंशदान दिया है। साथ ही कुछ कंपनियों ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी सार्थक उपाय नहीं करें हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि आप अपने कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती करके परोपकार हेतु पीएम केयर्स फंड में योगदान कर रहे हैं। इस दशा में पीएम केयर्स फंड में अंशदान देना इन कंपनियों के लिए उचित प्रतीत नहीं होता। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि कुछ अच्छी कंपनियों ने सी.एस.आर. गतिविधियों पर परोपकार की भावना से नहीं केवल कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु ही न्यूनतम व्यय करा है। यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि सी.एस.आर. गतिविधियों का आशय केवल कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति ही नहीं है, इसके पीछे देश हित, समाज हित एवं वैश्विक हित की भावना भी है।

सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करते समय कंपनी को यह ध्यान रखना होगा कि उसकी श्रम शक्ति जिससे उसे भविष्य में उत्पादन कार्यों में काम लेना है, उन पर व उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। साथ ही कंपनी की ख्याति, कंपनी का बजट, कंपनी की भावी योजनायें, वैधानिक औपचारिकताओं को भी सी.एस.आर. पर खर्च करते समय ध्यान रखना होगा। उपरोक्त सीमाओं के साथ यह कह सकते हैं कि भारत का कॉर्पोरेट जगत कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में सरकार, अस्पतालों एवं संपूर्ण व्यवस्था के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है एवं मौद्रिक–अमौद्रिक दोनों ही रूपों में सहयोग कर रहा है। अंत में हम यह भी कहना चाहेंगें कि सरकार ने वैधानिक रूप से 2 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा जो सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अनुमन्य करी है, इस सीमा को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दें तो सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए ज्यादा राशि उपलब्ध हो पाएगी।

सन्दर्भ

- www.csr.gov.in–– राष्ट्रीय सी.एस.आर. डाटा पोर्टल की अधिकृत वेबसाइट
- www.mca.gov.in –––कंपनी मामलों का विभाग, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट
- द टाइम्स ऑफ इंडिया –––विभिन्न अंक
- द हिन्दू ––– विभिन्न अंक
- कंपनी अधिनियम 2013 नवीनतम संशोधनों सहित
- 'PM CARES Received At Least $1.27 Bn In Donations-Enough To Fund Over 21.5 Mn COVID-19 Tests' by Anoo Bhuyan & Prachi Salve 20 May 2020&&&www.indiaspend.com

सारणी 1

भारत में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या, सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु कार्यक्रमों की संख्या एवं सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय

वर्ष	सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या	सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु कार्यक्रमों की संख्या	सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय (करोड़ रूपये)
2017-18	21450	23882	13890
2018-19	24932	30620	18655
2019-20	5223	18765	17885

स्रोत — www.csr.gov.in एवं www.mca.gov.in पर उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन –विभिन्न अंक

सारणी 2

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या, सी.एस.आर. गतिविधियों में समाहित किये गये जिलों की संख्या एवं सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय

वर्ष	सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय हेतु अर्ह कंपनियों की संख्या		सी.एस.आर. गतिविधियों में समाहित किये गये जिलों की संख्या		सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय (करोड़ रूपये)	
	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड
2017-18	720	178	42	8	303	87
2018-19	847	207	56	10	477	173
2019-20	347	102	47	11	362	84

स्रोत — www.csr.gov.in एवं www.mca.gov.in पर उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन –विभिन्न अंक

सारणी 3

सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में भारत की शीर्षस्थ 5 कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय

(करोड़ रूपये)

कंपनी का नाम	2017–18	2018–19	2019–20
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	745	849	909
टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड	400	434	602
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड	375	444	535
इनफोसिस लिमिटेड	313	342	360
हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड	116	126	144

स्रोत — www.csr.gov.in एवं www.mca.gov.in पर उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन –विभिन्न अंक

सारणी 4

सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में मदवार सी.एस.आर. गतिविधियों पर व्यय (करोड़ रूपये)

व्यय की मद	2017–18		2018–19		2019–20	
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
शिक्षा, दिव्यांग एवं जीवनयापन	5960	42.91	7500	40.20	7222	40.38
खेलों को प्रोत्साहित करना	228	1.64	295	1.58	237	1.33
पर्यावरण, पशु कल्याण, संसाधनों का संरक्षण	1369	9.86	1517	8.13	1336	7.47
लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था गृह, असमानता को कम करना	501	3.61	518	2.78	459	2.57
स्वास्थ्य भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता	3339	24.04	4959	26.58	4865	27.20
विरासत, कला और संस्कृति	284	2.04	190	1.02	492	2.75
अन्य क्षेत्र (प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और सशस्त्र बलों के लिए लाभ और प्रशासनिक उपरिव्यय)	43	0.31	120	0.64	73	0.41
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	176	1.27	300	1.61	537	3.00
ग्रामीण विकास	1480	10.65	2309	12.38	1885	10.54
झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र का विकास	35	0.25	50	0.27	11	0.06
स्वच्छ भारत कोष	214	1.54	94	0.50	39	0.22
स्वच्छ गंगा कोष	5	0.04	5	0.03	1	0.01
अन्य कोष	256	1.84	711	3.81	702	3.93
विविध	1	0.01	88	0.47	25	0.14
योग	13891	100.00	18656	100.00	17884	100.00

स्रोत — www.csr.gov.in एवं www.mca.gov.in पर उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन –विभिन्न अंक

13

कोरोना संक्रमण और औषधीय पौधे

डॉ0 रेनू शर्मा

असिस्टैंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग

गोकुल दास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

सूक्ष्म जीव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और इनके कारण हमें विभिन्न बीमारियां भी हो जाती हैं। एक सूक्ष्मजीव कोरोना वायरस ने दिसम्बर 2019 से एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर दिया है। कोरोना वायरस एक रेशीय राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। वैज्ञानिक दिन–रात कड़ी मेहनत करके वैक्सीन बनाने में भी सफल रहे हैं, वैक्सीन के द्वारा वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज द्वारा वायरस के संक्रमण को रोका जाता है। लेकिन हमें केवल वर्तमान में उपलब्ध वैक्सीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह इसका सटीक इलाज नहीं है। इसलिए कुछ वैकल्पिक तरीकों का भी अन्वेषण करना चाहिए, जिसमें औषधीय पौधे भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। विश्व में औषधीय पौधों का प्रयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा किया जाता रहा है। इस शोध पत्र के माध्यम से हम, कोविड–19 से लड़ने के लिए कुछ औषधीय पौधों की भूमिका पर विचार करेंगें। हर्बल दवाओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दवाएं सुरक्षित हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है।

मुख्य शब्द– कोरोना वायरस, प्रतिरक्षा, औषधीय पौधे

परिचय

2019 के अंत में, डब्ल्यू.एच.ओ. चाइना कंट्री ऑफिस को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया होने की जानकारी मिली। 13 जनवरी 2020 को, अधिकारियों ने थाईलैंड में नॉवल कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि की। 30 जनवरी 2020 को, डब्ल्यू.एच.ओ. के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेबियस ने प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। 11 फरवरी 2020 को इस नॉवल कोरोनवायरस को कोविड–19 नाम दिया गया और 11 मार्च 2020 को डब्ल्यू.एच.ओ. ने कोविड–19 को महामारी के रूप में वर्गीकृत किया।

कोरोना वायरस प्रकृति में पाये जाने वाले वायरस का एक बड़ा समूह है। यह कोरोनाविरिडी कुल, ऑर्थोकोरोनाविरिडी उपकुल और नीडोव्हाईरेल्स आर्डर में आते हैं। उपकुल ऑर्थोकोरोनाविरिडी को चार वंश में वर्गीकृत किया गया है अल्फाकोरोनावायरस, बीटाकोरोनावायरस, गामाकरोनावायरस और डेल्टाकरोनावायरस। बीटाकोरोनावायरस को पांच उपवंश सरबेकोवायरस, एम्बेकोवायरस, हिबेकोवायरस, मेरबेकोवायरस और नोबेकोवायरस में विभाजित किया गया जिसमें SARS & CoV और 2019-nCoV सबजेनस सरबेकोवायरस से संबंधित है। SARS & CoV2 एक रेशीय राइबो न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें 28,882 बेस पेयर्स जीनोम होता है (Malik et al. 2020) जो संरचनात्मक प्रोटीन जैसे स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड और गैर–संरचनात्मक प्रोटीन जैसे आरएनए–डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेस, कोरोनावायरस मुख्य प्रोटीज और पैपैन जैसे प्रोटीज को एनकोड करती है (Chen et al. 2020)। कोरोना वायरस की कोरोना जैसी उपस्थिति तथाकथित स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, या पेप्लोमर्स के कारण होती है, जो वायरस के लिए मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। स्पाइक में दो कार्यात्मक सबयूनिट S1 और S2 हैं, एक सबयूनिट S1, होस्ट सेल की सतह पर एक रिसेप्टर को बांधता है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम (ACE2) कहा जाता है जो होस्ट सेल की सतह झिल्ली में पाया जाता है और सबयूनिट S2, वायरस के कोशिका झिल्ली के संलयन में योगदान देता है (Walls et al. 2020)। विभिन्न देशों ने कोविड–19 से लड़ने के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया है। कुछ दवाएं हैं जो आरएनए–डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेस, स्पाइक प्रोटीन और एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम द्वितीय (ACE2) पर प्रतिक्रिया करती हैं लेकिन कोविड–19 का कोई पूर्ण उपचार नहीं है ।

प्राचीन समय से ही औषधीय गुणों के कारण पौधों का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता रहा है। दुनिया के लगभग सभी धर्मों ने विभिन्न पौधों में औषधीय गुणों के समाहित होने के कारण, पौधों से उपचार की ओर इशारा किया है और उनका दृढ़ विश्वास है कि अगर प्रकृति ने किसी बीमारी को उत्पन्न किया है, तो उसका समाधान भी प्रकृति में ही होगा। हम कोरोनावायरस के संदर्भ में औषधीय पौधों का प्रयोग; शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या आरएनए–डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेस, स्पाइक प्रोटीन और एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम द्वितीय के साथ औषधीय पौधों की प्रतिक्रिया द्वारा किया जा सकता हैं। भारत में, आयुष मंत्रालय ने एक काढ़े की सिफारिश की जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ औषधीय पौधों से तैयार किया जाता है। हर्बल पारंपरिक दवाओं का उपयोग चीन में भी किया गया है और सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुये हैं।

विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक तरीकों का संक्षिप्त अवलोकन

प्राचीन काल से ही लोग प्रकृति के माध्यम से अपनी बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। वेदों में भी पौधों के औषधीय गुणों का उल्लेख किया गया है चाहे वह यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद। सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित चिकित्सा पर आधारित एक महत्वपूर्ण साहित्य हैं। उन्होंने संस्कृत में 700 औषधीय पौधों का वर्णन किया हैं (Sharma P.V. 2007)। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस (371–287 ईसा पूर्व) ने 500 से अधिक औषधीय पौधों का वर्गीकरण किया। समय–समय पर, पौधों के औषधीय गुणों की पहचान की गई और आने वाली पीढ़ियों द्वारा उन औषधीय पौधों का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया गया है। च्यवनप्राश का प्रयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, इसमें बारह महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो आंवला (Phyllanthus emblica), नीम (Azadiracta indica), पिप्पली (Pipal longum), अश्वगंधा (Withania somnifera), सफेद चंदन (Santalum album), तुलसी (Ocimum sanctum), इलायची (Elettaria cardamomum), अर्जुन (Terminalia arjuna), ब्रह्मी (Bacopa monnieri), केसर (Crocus sativus), घृत और शहद हैं। त्रिफला भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है, जिसमें पाउडर के रूप में आंवला (Phyllanthus emblica L.), बहेड़ा (Terminalia bellerica) व हरीतकी (Terminalia chebula) के फल शामिल हैं। त्रिफला का उपयोग इसकी एंटीऑक्सिडेंट, एंटीइन्फ्लेमेटरी, रोगाणुरोधी और एंटीडायबिटिक प्रक्रिया के लिए किया जाता है (Peterson et al. 2017)।

कई दवाओं के स्रोत पौधे हैं जैसे कि मॉर्फिन को पोस्ता (Papaver somniferum) के पौधे से, सर्पगंधा (Rauwolfia serpentine) से रिसरपिन (reserpine), वीपिंगविलो से एस्पिरिन (Salix alba, Salix nigra आदि), फॉक्सग्लोव फूल (Digitalis lanata) से डाइक्सिन, कुनैन को सिनकोना ऑफिसिनैलिस (Cinchona officinalis) से प्राप्त किया गया हैं।

कोविड–19 की रोकथाम में कुछ प्राकृतिक उपचार

भारत में, आयुष मंत्रालय ने तुलसी (Ocimum sanctum), दालचीनी (Cinumomum verum), कालीमिर्च (Piper nigrum), सूंठी (Zingiber officinale) और मुन्नक्का (Vitis vinifera) से बने काढ़े का प्रयोग करने की सलाह दी। इस काढ़े में स्वाद के अनुसार गुड़ और/या नींबू का प्रयोग किया जाता है। दिन में एक या दो बार प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में यह कोविड–19 संकट के दौरान वायरस की प्रभावशीलता को कम करता है। इससे पहले सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आयुष–64 को मलेरिया के लिए विकसित किया था, जो चार आयुर्वेदिक उत्पादों का एक संयोजन है। ये चार उत्पाद जलीय छाल का अर्क (Alstonia scholaris), जलीय प्रकंद निकालने (Picrorhiza kurroas), पूरे पौधे का जलीय अर्क (Swertia chirata) और महीन चूर्ण बीज का गूदा (Caesalpinia crista) हैं।

चीन ने भी हर्बल दवाओं के माध्यम से कोरोनावायरस से ग्रसित 214 रोगियों में से 90 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्त किया (Hong & Zhi et al. 2020)। वुहान विश्वविद्यालय के झोंगनन अस्पताल (Zhongnan Hospital) के विशेषज्ञों ने विभिन्न हर्बल दवाओं की कोविड–19 की तीव्रता के अनुसार संस्तुति की है (Jin et al. 2020)। चीन ने 2003 में SARS & CoV के दौरान भी हर्बल उपचार का इस्तेमाल किया था। लियानहुआकिंग्वेन (Lianhuaqingwen), एक चीनी हर्बल दवा, जो ग्यारह पौधों की प्रजातियों का मिश्रण है, कोविड–19 के उपचार में उपयोग किया जाता है। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा कोविड–19 के उपचार के लिए इस चीनी हर्बल मिश्रण की अनुशंसा की गई है (Yang Y- et al. 2020)। इसमें Forsythia suspensa, Lonicera japonica, Ephedra sinica, Prunus armeniaca, Isatis tinctoria, Dryopteris crassirhizoma, Houttuynia cordata, Pogostemon cablin, Rheum palmatum, Rhodiola rosea vkSj Glycyrrhizza uralensis शामिल हैं। ये हर्बल दवाएं बीमारी की तीव्रता को कम करती हैं। (Li et al. 2020)।

कोविड–19 के उपचार के लिए कुछ औषधीय पौधे

करक्यूमिन एक प्राकृतिक पॉलीफिनॉलिक यौगिक है, जो कि Curcuma longa के प्रकंद में और Curcuma की अन्य प्रजातियों में पाया जाता है जो Zingiberaceae कुल से सम्बन्धित है और कोविड–19 के रोगियों के इलाज के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हमारे देश में करक्यूमा प्रजाति का उपयोग इसके एंटीऑक्सिडेंट, एंटी–इंफ्लेमेटरी, एंटीमुटाजेनिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीकैंसर गुणों के कारण एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में किया गया है। Curcuma longa में 96.4 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 6.3 प्रतिशत प्रोटीन, 5.1 प्रतिशत वसा, 3.5 प्रतिशत खनिज और 13.1 प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। इसके अर्क में करक्यूमिनोइड्स होता है जिसमें 77 प्रतिशत करक्यूमिन, 17 प्रतिशत डिमेथॉक्सीकरक्यूमिन और 3 प्रतिशत बिसडिमेथॉक्सीकरक्यूमिन होता है। इन करक्यूमिनोइड्स विशेष रूप से करक्यूमिन में औषधीय गुण होते हैं (B.Kocaadam and S.Anlier 2017)। करक्यूमिन में रिसेप्टर प्रोटीन ACE 2 के साथ अच्छी बाध्यकारी क्षमता होती है जो कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकता है।

क्योंकि यह वायरस स्पाइक को ACE 2 रिसेप्टर प्रोटीन से बांधता है और एंडोसाइटोसिस के माध्यम से संक्रमण करता है। Zingiberaceae कुल का एक ओर पौधा गलंगल (Alpinia galangal) औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इस पौधें को नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण और फेफड़ों की टॉनिक गतिविधि के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। इस पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग इसके एंटी–फंगल, एंटी–ट्यूमर, रोगाणुरोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी–डायबिटिक, एंटीऑक्सिडेंट, एंटीअल्सर आदि गुणों के लिए कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है। एक आणविक डॉकिंग विश्लेषण ने SARS & CoV-2 से लड़ने में गलंगल यौगिकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है (Utomo et al. 2020)।

लहसुन (Allium sativum) का प्रयोग औषधीय पौधे के रूप में प्राचीन समय से होता रहा है। यह Amaryllidaceae कुल से सम्बन्धित है। इसका प्रयोग संक्रामक रोगों के उपचार हेतु किया जाता है, यह ब्लड थिनर तथा हृदय संबंधी बीमारियों के लिए लाभदायक है। एक आणविक डॉकिंग विश्लेषण के अनुसार SARS & CoV-2 के संक्रमण पर लहसुन के वाष्पशील ऑर्गोसल्फर यौगिकों के उच्च निरोधात्मक प्रभावों का प्रदर्शन किया गया। यह प्रभाव SARS & CoV2 संक्रमण का कारण ACE2 की बाइंडिंग के कारण होता हैं। लहसुन के एसेंशियल ऑयल के प्रमुख घटक एलिल डाइसल्फाइड और एलिल ट्रिसल्फाइड एंटीवायरल गतिविधि प्रदर्शित करते हैं (Thuy et al. 2020)।

क्विनिन एक अल्कलॉइड रसायन है जो सिनकोना छाल का मुख्य घटक है। इसका लाभकारी प्रभाव सबसे पहले जेसुइट मिशनरियों द्वारा खोजा गया था। 1820 में कुनैन को पियरे जोसेफ पेलेटियर और जोसेफ कैवेंटो द्वारा पृथक और नामांकित किया गया था। क्विनिन और अन्य एल्कलॉइड्स जैसे क्विनिडीन, सिनकोनीन और सिनकोनिडीन मलेरिया के उपचार हेतु सभी प्रभावी हैं और बहुत से देशों में कोविड –19 के इलाज में इसका प्रयोग हो रहा है (Devaux et al. 2020)। कुनैन का प्रभाव एक सिंथेटिक एंटीमैलेरियल क्लोरोक्वीन दवा के समान है। आजकल, क्विनिन सल्फेट कोविड–19 उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक बन गया हैं । क्योंकि क्विनिन सल्फेट RIG & I और IFN-a संश्लेषण को बढ़ाकर एक एंटीवायरल एजेंट के रूप में कार्य करता है। फिर दोनों PKR (IFN stimulating gene) की सक्रियता के माध्यम से वायरल m-RNA के अनुवाद को रोककर किसी भी वायरल प्रोटीन का संश्लेषण रोक देता है।

अश्वगंधा (Withania somnifera) एक लोकप्रिय भारतीय औषधीय पौधा है। अश्वगंधा में फाइटोकेमिकल्स के मुख्य रासायनिक घटक विथनॉलाइड हैं, जिसमें ट्राइटरपेनैक्टोन्स–विथमोलॉइड्स, विथफेरिन शामिल हैं जो प्रमुख रूप से एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण प्रदर्शित करते हैं। होस्ट एंजाइम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीज सेरीन 2 (TMPRSS 2) होस्ट कोशिकाओं में वायरस को संक्रमण करने देता है। यदि यह एंजाइम ब्लॉक हो जाये तो यह ACE2 के साथ वायरस संलयन को रोकता है, जिससे यह वायरस के संक्रमण को रोकने में सहायक होता हैं। अश्वगंधा के पत्तों से निकला विथोनेन TMPRSS2 के उत्प्रेरक साइट (His296, Asp345 and Ser 441) को बाइंड करके उसकी सक्रियता को कम कर सकता है; Kumar et al. 2020)।

निष्कर्ष

कोविड –19 से पूरा विश्व ग्रस्त है। आजकल भारत में इसका विकराल रूप दिख रहा है, जिससे हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अत्यधिक दबाव आ गया है। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर विकल्प है इसलिए यदि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लें तो हम विभिन्न रोगों से बच सकते हैं। आयुष मंत्रालय का काढ़ा, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश आदि सभी इम्युनिटी बूस्टर की भूमिका निभाते हैं। कोविड –19 संक्रमण को रोकने के लिए वायरस की होस्ट सेल की बाइंडिग साइट को बाइंड करने वाले और रिप्लिकेशन चक्र को प्रभावित करने वाले फाइटोकेमिकल का उपयोग करके वायरस संक्रमण को रोक सकते हैं। करक्यूमिन, एलिल डाइसल्फाइड, एलिल ट्रिसल्फाइड, क्विनिन और विथोनेन आदि फाइटोकेमिकल्स के प्रयोग द्वारा हम बाइंडिग साइट को बाइंड कर रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं।

संदर्भ सूची

- Chen Y., Guo Y., Pan Y., Zhao Z.J. (2020). Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV. Biochem. Biophys. Res. Commun. 525(1), 135-140. 10.1016/j.bbrc.2020.02.071
- Devaux, C. A., Rolain, J. M., Colson, P., and Raoult, D. (2020). New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? Int. J. Antimicrob. Agents 55 (5), 105938. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105938
- Hong-Zhi D. U., Hou X. Y., Miao Y. H., Huang B. S., Liu D. H. (2020) Traditional Chinese Medicine:an effective treatment for 2019 novel coronavirus pneumonia (NCP). Chin. J. Not.Med. 18(3), 226-230. 10.1016/51875-5364(20)30022-4.
- Hui, D. S., Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., Petersen, E. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health. The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases, 91, 264-266.
- Jin Y. H.,Cai L., Cheng H., Deng T., Fan Y. P., et al. (2020). A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (COVID-19) infected pneumonia (standard version). Mil. Med. Res. 7 (1), 4. 10.1186/s40779-020-0233-6.
- Kocaadam,B. and N.S.anlier, (2017).”Curcumin,an active component of turmeric (curcuma longa) and its effects on health,” Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol.57, no.13,pp.2889-2895.
- Kumar, V., Dhanjal, J. K., Bhargava, P., Kaul, A., Wang, J., Zhang, H., et al. (2020). Withanone and Withaferin-A are predicted to interact with transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2) and block entry of SARS-CoV-2 into cells. J. Biomol. Struct. Dyn. 1–13. doi: 10.1080/07391102.2020.1775704

- Li H., Wang Y. M., Xu J. Y., Cao B. (2020). Potential Antiviral Therapeutics for 2019 Novel Coronavirus. Chin. J. Tuberc. Respir. Dis. 43 (3), 170–172. 0.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.004.
- Malik, Y. S., Sircar, S., Bhat, S., Sharun, K., Dhama, K., Dadar, M., … Chaicumpa, W. (2020). Emerging novel coronavirus (2019-nCoV)—Current scenario, evolutionary perspective based on genome analysis and recent developments. Veterinary Quarterly, 40(1), 68– 76.
- Peterson, C.T., Denniston, K., And Chopra, D. (2017). Therapeutic uses of triphala in ayurvedic medicine.J.Altern.Complementary Med. 23(8),607-614. doi:10.1089/acm.2017.0083.
- Sharma, P. V. Susruta-Samhita. Ninth Edition. Varanasi (India): Chaukhambha Orientalia, 2007.
- Thuy B. T. P., My T. T. A., Hai N. T. T., Hieu L. T., Hoa T. T., Thi Phuong Loan H., et al. (2020). Investigation into SARS-CoV-2 resistance of compounds in garlic essential oil. ACS Omega 5 (14), 8312–8320. 10.1021/acsomega.0c00772
- Utomo, R. Y., Ikawati, M., and Meiyanto, E. (2020). Revealing the potency of citrus and galangal constituents to halt SARS-CoV-2 infection. https://doi.org/10.20944/preprints202003.0214.v1
- Walls, A. C., Park, Y. J., Tortorici, M. A., Wall, A., McGuire, A. T., Veesler, D. (2020). Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell 181, 281–292.e6. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.058
- WHO. WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
- Yang Y., Islam M. S., Wang J., Li Y., Chen X. (2020). Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New coronavirus (SARS-CoV-2CoV-2): A Review and Perspective. Int. J. Biol. Sci. 16(10), 1708. 10.7150/ijbs.45538.

14

लॉकडाउन - प्राकृतिक पर्यावरण हेतु एक वरदान

डॉ0 अनिता ए. पाण्डेय

एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग

धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ

सारांश

बढ़ती जनसंख्या और विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के लिए बाध्य कर दिया, फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता चला गया। विश्व के देशों द्वारा पर्यावरण के असंतुलन और उससे होने वाले दुष्प्रभावों को समझा गया है तथा उसके निराकरण हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास भी किये जा रहे हैं परन्तु संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पता चला जिसने शीघ्र ही पूरे विश्व को एक घातक महामारी के रूप में अपनी चपेट में ले लिया। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न देशों द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया। भारत में भी 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था व मनुष्य के जीवन पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु इससे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में चौकाने वाले सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिन्हें दशकों के प्रयास के बाद भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में आशातीत सफलता प्राप्त हुई और जल प्रदूषण नियंत्रण में भी सुधार दिखाई दिया। लॉकडाउन पर्यावरण के लिए संजीवनी की तरह काम करते हुए वरदान साबित हुआ।

मुख्य शब्द–कोविड–19 वायरस, लॉकडाउन, पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण नियंत्रण।

वैश्विक स्तर पर मानवीय गतिविधियों का आकलन करें तो हमें मानव के विकास के साथ साथ प्रकृति के विनाश के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या और विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन हेतु बाध्य कर दिया, फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला गया। अत्यधिक औद्योगीकरण और वैश्वीकरण ने खाद्य, हवा एवं जल तक को अशुद्ध कर दिया है। इन अशुद्धियों के कारण हम तरह–तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पूरे विश्व के देशों द्वारा पर्यावरण के असंतुलन और उससे होने वाले दुष्प्रभावों को समझा गया है तथा उसके निराकरण हेतु वैश्विक स्तर पर एवं घरेलू स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु विश्व के देशों में सहमति भी बनी है। ओजोन की लेयर में कमी भी चिन्ता का विषय रही है। विश्व के देश ओजोन लेयर को कम करने वाले रसायनों का उत्सर्जन कम करने पर सहमति जताते हुए इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन को दूर करने की गति इतनी धीमी है कि हम प्रदूषित एवं जहरीली हो गयी हवा में सांस लेने को बाध्य हो गये हैं। हमारे प्राकृतिक जल स्रोत भी इतने प्रदूषित हो गये हैं कि मनुष्य ही नहीं बल्कि जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक हो गयें हैं।

माह दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोविड–19 वायरस का पता चला जिसका संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि इसने शीघ्र ही पूरे विश्व को एक घातक महामारी के रूप में अपनी चपेट में ले लिया। यह वायरस मनुष्य के फेफड़े को संक्रमित कर श्वसनतंत्र की क्रियाशीलता कम कर देता है और गंभीर संक्रमण की स्थिति में व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाती है। कोविड –19 का प्रसार संक्रमित मनुष्य से तथा संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आयी वस्तुओं से अन्य स्वस्थ मनुष्यों व जीवों में होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रसार रोकने के लिए विभिन्न देशों द्वारा दूसरे देशों से आने जाने वाले लोगों व वस्तुओं पर पाबन्दी लगा दी गयी।

देश के अन्दर भी मानव गतिविधि को रोकने के लिए 22 मार्च 2020 को सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन के कारण सड़कों, ट्रेनों और वायुयान के माध्यम से होने वाला यातायात रूक गया। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त गतिविधियां रूक गयीं। धुंआ उगलती फैक्ट्रियां व धूल बिखेरते निर्माण सब रूक गये। फैक्ट्रियां बंद होने से उनसे निकलने वाला कचरा भी नदियों में जाना कुछ हद तक बन्द हो गया। एक तरफ लॉकडाउन से मानव के जनजीवन एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु दूसरी तरफ इस लॉकडाउन के कारण

वायरस के प्रसार को रोकने के साथ–साथ प्रदूषण के विभिन्न मोर्चों पर सफलता भी मिलती दिखायी दे रही है। विश्वभर के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों द्वारा लॉकडाउन के कारण पर्यावरण (वायु, जल, ध्वनि आदि) पर हुए प्रभाव का अध्ययन किया गया।

लॉकडाउन का वायु प्रदूषण पर प्रभाव–

वायु प्रदूषण की परिभाषा के अनुसार वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक उपक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक सम्पत्ति को हानि पहुंचे या हमारी प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हो या उसे हानि पहुंचे; वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु सभी मनुष्यों, जीवों व वनस्पतियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य बिना भोजन पानी के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है परन्तु हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना मुश्किल है। वायु में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत आक्सीजन, 0.03 प्रतिशत कार्बनडाईआक्साइड एवं शेष निष्क्रिय गैसें और जलवाष्प होती है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायुमण्डल में उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य अस्वास्थ्यकर गैसों एवं कणों की उपस्थिति बढ़ गयी है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि वनस्पतियों, जीव–जन्तुओं, जलवायु, मौसम, ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ता है। वायु प्रदूषण पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्यों को दमा, गले का दर्द, निमोनिया, ब्रांकाइटिस, सिरदर्द, उल्टी, फेफड़े का कैंसर, हदय रोग, जुकाम, खांसी व आखों में जलन जैसी समस्यायें हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में भी कमी आ जाती है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीव जन्तुओं का श्वसन तंत्र और केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का भी कारण बन जाता है। विश्व के देशों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए अपने–अपने स्तर से एवं मिलकर समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में भी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 लागू किया गया है।

हवा में पीएम$_{2.5}$ की मात्रा 60 और पीएम$_{10}$ की मात्रा 100 तक होने पर ही हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है। वहीं इसकी मात्रा बढ़ने पर इसे खतरनाक माना जाता है। आई0आई0टी0 रूड़की से प्रकाशित एक शोध में दिल्ली और मुम्बई में लॉकडाउन से पूर्व एवं लॉकडाउन के बाद वायु में प्रदूषण के घटक पीएम$_{10}$, पीएम$_{2.5}$, NO_2 और SO_2 के स्तर में आयी कमी और O_3 के स्तर में आयी वृद्वि का अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि दिल्ली और मुम्बई में पीएम$_{10}$, पीएम$_{2.5}$, NO_2 और SO_2 में क्रमशः 55 प्रतिशत, 49 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 19 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 78 प्रतिशत, 39 प्रतिशत, की कमी पायी गयी। दोनो शहरों में ओजोन (O_3) के स्तर में वृद्धि पायी गयी। ओजोन के स्तर में वृद्धि का कारण छव् के उत्सर्जन में कमी को बताया गया।

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

NO के लेवल में कमी ने ओजोन के विघटन को कम किया जिससे ओजोन के स्तर में वृद्धि पायी गयी। विश्व के देशों जैसे अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन आदि में भी लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी दिखायी दी। अमेरिका के न्यूयार्क शहर में लॉकडाउन की अवधि में वायु प्रदूषण 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो गया। चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25 प्रतिशत तक की कमी आयी। उक्त से स्पष्ट है कि लॉकडाउन की अवधि में वायु प्रदूषण में व्यापक कमी आयी। पर्यावरणीय तौर पर हवा इतनी शुद्ध हो गयी है कि मैदानी शहरों से नजदीकी पहाड़ों की चोटियां साफ दिखायी पड़ रही थीं। उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर के निदेशक के अनुसार हिमालय की धवल चोटियां साफ दिखने लगी हैं। वायु प्रदूषण के कम हो जाने से रात को आसमान में तारे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे जो लॉकडाउन से पूर्व नहीं दिखते थे।

अमेरिकी अंतरिक्ष ऐजेंसी नासा के सैटेलाइट टेरा द्वारा लिए गये चित्रों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भारत की ऐयरोसोल आप्टिकल डेप्थ कम हुई है, जिसके कारण आकाश स्वच्छ हुआ है तथा वायु में घुलित अशुद्धियां जैसे –पीएम$_{2.5}$ और पीएम$_{10}$ अपने 20 वर्षों के निम्नतम स्तर पर हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष ऐजेंसी के कापरनिकस सैटेलाइट के अनुसार भारत में नाइट्रस आक्साइड के स्तर में उल्लेखनीय कमी मार्च 2020 के अन्तिम सप्ताह में देखी गयी। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार, लॉकडाउन के कारण दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ में 30 फीसदी की गिरावट आई। अहमदाबाद और पुणे में इसमें 15 प्रतिशत की कमी आई है। नाइट्रोजन आक्साइड प्रदूषण (एनओएक्स) का स्तर भी कम हो गया है। एनओएक्स प्रदूषण मुख्य रूप से ज्यादा वाहनों के चलने से होता है। एनओएक्स प्रदूषण में पुणे में 43, मुंबई में 38, और अहमदाबाद में 50 प्रतिशत की कमी आई है।

लॉकडाउन का नदियों के जल की गुणवत्ता पर प्रभाव–

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड–19 के कारण लॉकडाउन से नदियों के प्रदूषण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। अध्ययन में देश की 19 मुख्य नदियों को शामिल किया गया। प्रदूषण के विभिन्न मानकों यथा– pH, बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (BOD), पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा (DO) Faecal Coliform (FC) का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन की अवधि में नदियों में कुछ स्तर तक प्रदूषण में सुधार हुआ है। आर्गेनिक प्रदूषण तथा बैक्टिरियल लोड में कमी पायी गयी परन्तु शहरों के किनारे नदियों में बैक्टिरियल लोड में सुधार कम दिखा। कारण यह बताया गया कि शहरों के सीवर लाइन का नदियों में गिरना बन्द नहीं किया गया।

वैतरणी, महानदी, नर्मदा, और पेन्नार नदियों का पानी लॉकडाउन से पूर्व तथा लॉकडाउन के बाद दोनों स्थितियों में प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों पर सही पाया गया।

घग्गर नदी को पूर्व लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद दोनों स्थितियों में प्राथमिक जल गुणवत्ता के मानकों पर खराब पाया गया।

साबरमती और माही दो नदियां ऐसी थीं जिनमें लॉकडाउन का कोई असर नहीं पाया गया। दोनों नदियां प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों पर क्रमशः 55.6 और 92 प्रतिशत पायी गयीं।

07 नदियों के जल के प्राथमिक जल गुणवत्ता के मानक में सुधार पाया गया– ब्राहमणी (85 से 100 प्रतिशत), ब्रह्मपुत्र (87.5 से 100 प्रतिशत), कावेरी (90.5 से 96.97 प्रतिशत), गोदावरी (65.8 से 78.4 प्रतिशत), कृष्णा (84.6 से 94.4 प्रतिशत), तापी (77.8 से 87.5 प्रतिशत), यमुना (42.8 से 66.67 प्रतिशत)।

लॉकडाउन की अवधि में 05 नदियों के जल में कोई सुधार नहीं पाया गया बल्कि गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गयी। व्यास (100 से 95.45 प्रतिशत), चम्बल (75 से 46.15 प्रतिशत), गंगा (64.6 से 46.2 प्रतिशत), सतलज (87.1 से 78.3 प्रतिशत), स्वर्णरेखा (80 से 53.3 प्रतिशत)। इन नदियों में जल की गुणवत्ता खराब होने का कारण बिना शोधन किये अथवा आंशिक शोधन किये गये सीवेज का नदियों मे छोड़ना, सूखा मौसम होने के कारण प्रदूषणों का उच्च स्तर पर रहना और अन्य नदियों से स्वच्छ जल की कोई धारा न मिलना; बताया गया।

लॉकडाउन का ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव–

लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधियां सीमित हो गयीं। सड़कों पर वाहनों का शोर शराबा बन्द हो गया। औद्यौगिक इकाइयों में उत्पादन ठप्प हो जाने के कारण इकाइयों के भारी मशीनरी/कलपुर्जों का शोर समाप्त हो गया। ट्रेनों और समय–समय पर उड़ने वाले वायुयानों के शोर लगभग बन्द हो गये। जो ध्वनि प्रदूषण प्रायः मानक से उपर रहता था, लॉकडाउन में मानक से नीचे पहुंच गया।

औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 तथा रात में 70 डेसीबल का शोर मानक के अनुरूप है। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 तथा रात में 45 डेसीबल की ध्वनि मानक के अनुरूप है। ज्यादा समय तक ध्वनि प्रदूषण में रहने वाले व्यक्ति में ऊंची आवाज में सुनने, चिड़चिड़ापन, नींद न आने जैसी समस्यायें हो जाती हैं। गम्भीर स्थितियों में तनाव, उच्च रक्तचाप, स्मृति खोने और अवसाद की स्थिति भी पायी जाती है।

दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भूकम्प विज्ञानियों द्वारा कोविड–19 के कारण किये गये लॉकडाउन से ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया । अध्ययन में 117 देशों के 268 स्थानों पर लगाये गये सेंसर्स के डाटा को शामिल किया गया। डाटा के विश्लेषण से यह तथ्य संज्ञान में आया कि उच्च फ्रीक्वेन्सी वाली ध्वनि जो मनुष्यों की गतिविधियों से पैदा होती है, में मार्च से मई 2020 के बीच 50 प्रतिशत तक कमी आयी है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण होने वाली यह शांति अब तक की विश्व की सबसे लम्बी शान्ति है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण में कमी उच्च जनसंख्या घनत्व वाले विश्व के शहरों जैसे– सिंगापुर और न्यूयार्क में पायी गयी। दुनिया के टूरिस्ट केन्द्रों पर भी ध्वनि प्रदूषण में कमी देखी गयी। भूकम्प विज्ञानी जो अध्ययन में शामिल थे, द्वारा बताया गया कि आप इसको शान्ति की एक तरंग के रूप में देख सकते हैं, जो जनवरी 2020 में चीन से प्रारम्भ होकर इटली और उसके आगे मार्च–अप्रैल 2020 तक फैलती जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि विभिन्न देशों द्वारा लॉकडाउन लगाने के कारण ध्वनि प्रदूषण में आयी कमी अवकाश के दिनों जैसे क्रिसमस और नये वर्ष पर होने वाली बन्दी के कारण ध्वनि प्रदूषण में आयी कमी से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण में कमी का स्तर विश्व के भिन्न–भिन्न देशों मे भिन्न–भिन्न कारणों से भिन्न–भिन्न पाया गया।

लॉकडाउन के कारण ध्वनि प्रदूषण में आयी गिरावट का अध्ययन अलीगढ़ में भी किया गया। लॉकडाउन में लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत का अनुभव हुआ। तालानगरी औद्यौगिक क्षेत्र, सेन्टर प्वाइंट, दीनदयाल अस्पताल व ज्ञान सरोवर कालोनी में ध्वनि प्रदूषण मानक से कम पाया गया। दिन में तालानगरी में ध्वनि प्रदूषण सामान्यतः 77 से 80 डेसीबल के बीच रहता था, लेकिन 07 अप्रैल को 40.6 डेसीबल रिकार्ड किया गया। सेंटर प्वाइंट पर दिन में 80 डेसीबल ध्वनि प्रदूषण लॉकडाउन से पहले रिकार्ड किया गया था जो अब 48.6 डेसीबल रिकार्ड किया गया। इसी तरह से आवासीय कालोनियों व दीनदयाल अस्पताल के परिसर में भी ध्वनि प्रदूषण में कमी दर्ज की गयी। ध्वनि प्रदूषण के कारण चिड़ियों के चहचहाने की आवाज घरों में अन्दर तक सुनाई नहीं पड़ पा रही थी, अब प्रदूषण कम हो जाने पर स्पष्ट सुनाई पड़ रही है।

लॉकडाउन का सिस्मिक नोयज पर प्रभाव–

सिस्मिक नोयज वह शोर है, जो धरती की बाहरी सतह यानि क्रस्ट पर होने वाले कम्पन के कारण धरती के भीतर एक शोर के रूप में सुनायी देता है। इस शोर को सटीक तौर पर मापने के लिए शोधकर्ता और भू–विज्ञानी एक डिटेक्टर की रीडिंग का सहारा लेते हैं। लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधियां, सड़क पर मोटरगाड़ी, वायुयान व रेलगाड़ियां बन्द हो गयीं। समस्त निर्माण कार्य तथा कलकारखाने भी बन्द हो गये। सिस्मोमीटर्स से जुटाये गये आंकड़ों से पता चलता है कि लॉकडाउन की अवधि में धरती पर शोर के स्तर में कमी आयी है और सिस्मिक नोयज भी घटा है। लॉकडाउन में सतह पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर इतना कम हो गया कि पृथ्वी के अन्दर होने वाली छोटी–छोटी हलचलों को भी मापने में कामयाबी मिली है, जो अन्य स्थिति में सतह पर शोर के कारण सम्भव नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार के एक अध्ययन में यह बात सामने आयी कि मेक्सिको में धरती के 15 कि0मी0 नीचे एक कम फ्रीक्वेन्सी का भूकम्प आया था, जिसे मापा जा सका।

निष्कर्ष–

कोरोना महामारी से भयाक्रांत समूचे विश्व में लॉकडाउन ने कोराना संक्रमण को कम करने के साथ ही पर्यावरण को स्वस्थ होने का अवसर दे दिया है। लॉकडाउन पर्यावरण के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। वायु व ध्वनि प्रदूषण में भारी गिरावट दर्ज की गयी है। जल प्रदूषण में

भी कमी आयी है। प्रदूषण में दर्ज की गयी अप्रत्याशित गिरावट स्पष्ट संदेश दे रही है कि प्रदूषण कम करने के परम्परागत तरीकों से हम प्रदूषण कम नहीं कर पाएंगें। हमें पूरे विश्व में साप्ताहिक लॉकडाउन जैसे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ेगा। विकास की अन्धी दौड़ के स्थान पर संसाधनों के विवेकशील उपयोग पर बल देना पड़ेगा।

संदर्भः–

1. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख।
2. प्रतिमा कुमारी और दुर्गा टोशनीवाल, आई.आई.टी. रूड़की का शोधपत्र।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की प्रकाशित रिपोर्ट दिनांक 18.09.2020
4. विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री।

15

आत्म-निर्भर भारत एवं कौशल विकास

डॉ० कमल सिंह

एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय

हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, उ०प्र०

सारांश

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है, ताकि भारत को किसी भी क्षेत्र में दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही भारत में वर्ष 2015 से कौशल विकास योजना के माध्यम से देश के ऐसे लोगों को जो कम पढ़े–लिखे हैं या जिनकी पढ़ाई छूट गयी है, को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराके रोजगार के लिए तैयार कराना है। प्रस्तुत शोधपत्र में हमने प्रस्तावना, आत्मनिर्भर भारत के मुख्य स्तम्भ, भारत में कौशल विकास तथा भविष्य की रूपरेखा एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने भारत के भविष्य के निर्माण में आत्म–निर्भर भारत अभियान एवं कौशल विकास योजना की महत्वपूर्ण भूमिका, भारत के भविष्य के निर्माण में आत्म–निर्भर भारत एवं कौशल विकास के लिए चुनौतियों एवं सम्भावनाओं का अध्ययन किया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि आत्म–निर्भर भारत अभियान को उसके पाँच स्तम्भों के माध्यम से काफी हद तक सफल बनाया जा सकता है, साथ ही साथ कौशल विकास योजना के माध्यम से भारत में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य शब्द– आत्मनिर्भर, डेमोग्राफी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बुनियादी ढाँचा

प्रस्तावना

आत्म–निर्भर भारत एवं कौशल विकास योजना का विचार सर्वप्रथम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का है, क्योंकि वह भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनाना चाहते हैं ताकि भारत को किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। इसलिए उन्होनें 12 मई, 2020 को सार्वजनिक रूप से पहली बार इसका उल्लेख किया था। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आत्म–निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पाँच स्तम्भ बताये हैं, जो क्रमशः अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, सिस्टम (व्यवस्था), डेमोग्राफी एवं माँग हैं। कौशल विकास योजना भारत में वर्ष 2015 से चल रही है। इस योजना का शुभारम्भ भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जुलाई 2015 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को बाजार की दृष्टि से उपयुक्त कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें विश्व बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त बनाना है। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न कौशल विकास योजनायें जैसे स्टार्टअप इण्डिया, स्टैंडअप इण्डिया, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना आदि बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिनके माध्यम से देश के लाखों युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वह खुद का रोजगार कर सकें।

आत्म–निर्भर भारत के मुख्य स्तम्भ

आत्म–निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमन्त्री जी ने पाँच स्तम्भ बताये हैं, जो निम्न हैं–

1. **अर्थव्यवस्था** :– यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो भारत के विकास में न केवल इंक्रिमेन्टल चेंज लाये बल्कि कवाँटम जम्प भी लाये।
2. **बुनियादी ढाँचा** :– आत्म–निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एक ऐसा बुनियादी ढाँचा होना चाहिए जो न केवल आधुनिक भारत की पहचान बने, बल्कि विदेशी कम्पनियों को भारत में व्यवसाय करने के लिए आकर्षित करे।
3. **सिस्टम (व्यवस्था)** :– आत्म–निर्भर भारत अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए भारत में एक ऐसी व्यवस्था हो, जो आधुनिक तकनीक को अपनाये एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाये।
4. **डेमोग्राफी** :– आत्म–निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में डेमोग्राफी भारत की ताकत है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्त्रोत है, क्योंकि यह जनसंख्या भारत में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का अच्छी तरह से दोहन करके, देश के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

5. **माँग** :– आत्म–निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा घरेलू बाजार है, क्योंकि विश्व में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है, वहाँ पर बाजार भी ज्यादा होता है, इसलिए घरेलू बाजार को पूरी क्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरूरत है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग में वृद्धि हो सके।

वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण देश को हुए आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए 27 लाख करोड़ रूपये के तीन आर्थिक पैकेजों की घोषणा की थी, जो भारत की जी०डी०पी० का लगभग 13 प्रतिशत था। इस आर्थिक पैकेज से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक सफल बनाने का मौका मिला।

भारत में कौशल विकास तथा भविष्य की रूपरेखा

देश में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए वर्तमान समय में न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को कौशल सम्पन्न बनाना, उनके कौशल में सुधार करना और फिर से कौशलों का प्रशिक्षण देना आज समय की माँग है, और विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए इसका बड़ा महत्व है। इसलिए लोगों को कौशल सम्पन्न बनाने का चिरस्थायी माहौल बनाने के लिए कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण को व्यावसायिक शिक्षा का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में कौशल विकास के ऑनलाइन तरीकों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। कौशल–सम्पन्न बनाने की प्रणाली को मजबूत करने में निजी क्षेत्र और उद्योगों की भागीदारी का फायदा उठाया जाना चाहिए। इससे रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। कौशल सम्पन्न नौजवानों में नियोजनीयता, रोजगार उद्यमिता और स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल पाठयक्रमों में अपना उद्यम शुरू करने हेतु उद्यमिता एवं तकनीकी जानकारी के बारे में भी बताया जाना चाहिए। टैक्नोलॉजी के युग में देश की श्रमशक्ति को भावी नौकरियों के लिए तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए श्रमिकों के कौशल के स्तर में लगातार सुधार करने के साथ ही नये कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारत को वैश्विक बाजार के लिए श्रमिक तैयार करते समय अपनी विशाल जनसंख्या का फायदा भी उठाना चाहिए। इससे भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की परिकल्पना को बल मिलेगा। वैश्विक बाजारों के लिए कौशल प्रशिक्षण को विशेषज्ञतापूर्ण बाजार अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करके आसान बनाया जा सकता है जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों में माँग और आपूर्ति में अन्तर का विश्लेषण करेंगें और इस तरह भारतीय श्रमशक्ति के लिए अवसरों की पहचान करेंगें। भारत ने लोगों को कौशल–संपन्न बनाने में अब तक सराहनीय प्रगति की है, लेकिन इसकी व्यापक क्षमता और इस कार्यक्रम के जरिए कौशल–संपन्न बनाये जाने वाले लोगों की बढ़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सभी प्रतिभागियों को शामिल करके ईमानदारी से लगातार और अभिनव प्रयास करने की जरूरत है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास

वर्ष 2014 में एन०डी०ए० की सरकार आने के बाद से भारत में युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2014 में ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में स्टार्टअप इण्डिया, स्टैंडअप इण्डिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना आदि शामिल हैं। महिलाओं के लिए भी कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण अनिवार्य है। भविष्य की पीढ़ियों को समृद्ध करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही, कौशल विकास में नये नवाचारों और प्रौद्योगिकी को भी समाहित करने की जरूरत है। रोजगार के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास की स्थिति को तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका–1

श्रमबल भागीदारी दर (एल०एफ०पी०आर०), कामगारों की संख्या का अनुपात (डब्ल्यू०पी०आर०) और युवाओं में बेरोजगारी दर (आयु वर्ग– 15–29 वर्ष)

श्रमिक संकेतक अखिल भारतीय	प्रतिशत
श्रमबल भागीदारी दर (15–29 वर्ष)–कुल	38.20
श्रमबल भागीदारी दर (15–29 वर्ष) –पुरूष	58.80
श्रमबल भागीदारी दर (15–29 वर्ष) –महिला	16.40
श्रमबल भागीदारी दर (15–29 वर्ष) –ग्रामीण	38.10
श्रमबल भागीदारी दर (15–29 वर्ष) –शहरी	38.50
कामगारों की संख्या का अनुपात (15–29 वर्ष) –कुल	31.40
कामगारों की संख्या का अनुपात (15–29 वर्ष) –पुरूष	48.30
कामगारों की संख्या का अनुपात (15–29 वर्ष) –महिला	13.50
कामगारों की संख्या का अनुपात (15–29 वर्ष) – ग्रामीण	31.80
कामगारों की संख्या का अनुपात (15–29 वर्ष) – शहरी	31.40
बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) –कुल	17.80
बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) –पुरूष	17.80
बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) –महिला	17.90
बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) –ग्रामीण	16.60
बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) –शहरी	20.60

स्रोत :– एन०एस०एस०ओ० वार्षिक रिपोर्ट, पी०एल०एफ०एस०, 2019

तालिका–1 में 15–29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में एल०एफ०पी०आर० और डब्ल्यू०पी०आर० का उल्लेख किया गया है। इस आयु वर्ग के लोग भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों के सबसे सम्भावित लक्षित समूह हैं।

भारत ने विश्व में अपने आप को कृषि उत्पादन में साबित किया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। परन्तु वर्तमान समय में अधिकतर किसान कृषि त्यागना चाहते हैं और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बढ़ती आबादी, घटती उपजाऊ कृषि भूमि, कम होते रोजगार तथा निवेश एवं बाजार के जोखिमों ने बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दीं हैं। कृषि में कौशल विकास इन चुनौतियों का उचित समाधान बन सकता है, किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में युवाओं का कौशल विकास अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। निम्नलिखित तालिका के माध्यम से भारतीय कृषि में कुल कार्यबल में कौशलपूर्ण शिक्षा का स्तर दिखाया गया है–

तालिका–2

भारत में कुल कार्यबल में कौशलपूर्ण शिक्षा का स्तर (हजार में)

कौशलपूर्ण शिक्षा का स्तर	कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	गैर विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
औपचारिक डिग्री / उपाधि	40	323	133	1542
औपचारिक डिप्लोमा / सर्टिफिकेट (स्नातक से निम्न स्तर)	427	1273	471	3491
औपचारिक डिप्लोमा / सर्टिफिकेट (स्नातक से उच्च स्तर)	287	341	265	1918
कुल प्रशिक्षित	754	1937	869	6951
कुल कार्यबल का प्रतिशत	0.3	4	2	6.3

स्रोत :– राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान नीति आयोग, भारत सरकार (2013)

भारत के सभी स्कूलों में वर्ष 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करना एवं कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में उद्यमिता व कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2017 के शुरू में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत देश के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाने की पहल की है।

भारत के भविष्य के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं कौशल विकास योजना की महत्वपूर्ण भूमिका

आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमन्त्री श्री नरेद्र मोदी जी पहले से ही जाने जाते हैं, क्योंकि जब वह गुजरात के मुख्यमन्त्री थे, तब गुजरात में भयंकर भूकम्प आया था। उसमें बहुत कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन मोदी जी ने गुजरात को पहले से भी अधिक अच्छी तरह से विकसित कर दिया। कोरोना वायरस महामारी जैसी वैश्विक आपदा के बीच भारत ने जो सबसे ज्यादा कमी महसूस की, वह लोकल प्रोडक्टस की थी। मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं तीव्र निर्णय लेने की क्षमता के कारण भारत लोकल, वोकल एवं ग्लोबल की थ्योरी पर कदमताल करने लगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए ही भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ने 27 लाख करोड़ रूपये के तीन आर्थिक राहत पैकेजों की घोषणा की थी, जो जी०डी०पी० का लगभग 13 प्रतिशत था। इस राहत पैकेज से एम०एस०एम०ई० के कल्याण के लिए 16 घोषणाएं की गयीं, तो गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई मुख्य घोषणाएँ की गयीं, जिसमें किसनों की आय दोगुनी करने के लिए की गयी घोषणाएँ भी शामिल हैं। इस राहत पैकेज के अतिरिक्त भी भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अनेक ठोस कदम उठा रही है। कौशल विकास हमारे जीवन में हमारी प्रतिभा को आगे जाकर विकसित करना एवं उसे नया रास्ता एवं तरक्की का मोड़ देना है। कौशल का विकास युवा लोगों में उनकी पढ़ाई के समय उचित रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि देश के सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास हो, और देश के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हों। भारत में लोगों को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए चिरस्थायी माहौल बनाने की आवश्यकता है। कौशल विकास के ऑनलाइन तरीकों को बढ़ावा देकर न केवल मौजुदा प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि यह व्यावहारिक और किफायती समाधान है। कौशल सम्पन्न बनाने की प्रणाली को मजबूत करने में निजी क्षेत्र और उद्योगों की भागीदारी का फायदा उठाया जाना चाहिए। कौशल के प्रशिक्षण से न केवल रोजगार खोजने वाले तैयार होने चाहिएं, बल्कि रोजगार देने वाले नियोक्ता भी पैदा होने चाहिएं। भारत में प्रशिक्षुता को लोकप्रिय बनाने और सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही काम करते हुए सीखने का वह बेहतरीन तरीका है, जिससे किसी व्यक्ति की नियोजनीयता कई गुना बढ़ जाती है। रोजगार खोजने वालों और रोजगार प्रदाताओं का साझा पोर्टल होना चाहिए। वर्तमान तकनीक के इस युग में देश की श्रमशक्ति को भावी नौकरियों के लिए तैयार करना जरूरी है।

भारत के भविष्य के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत एवं कौशल विकास के लिए चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

कोरोना वैश्विक महामारी के बाद अस्त–व्यस्त और पस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था में जान फूँकने की जरूरत है, यद्यपि भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ने 27 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। निःसंदेह मोदी जी का लोकल के लिए वोकल बनकर उसे ग्लोबल बनाने

का सपना चुनौतियों को अवसर में बदलने का मूलमन्त्र हो सकता है। किन्तु जितना यह आसान लग रहा है, उतना ही जटिल है। इसलिए भारत के आत्मनिर्भर भारत बननें में अनेक काँटे और चुनौतियाँ हैं। हमारे देश में आज भी अनेक उपकरण, मशीनें और कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है, इसलिए अनेक वस्तुओं को बनाने की लागत बहुत अधिक आती है। भारत में कौशल विकास योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे–

1. भारत में अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता है।
2. भारत में आज भी अधिकाँश लोगों में उद्यमिता कौशल की कमी है।
3. अधिकाँश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार एवं वेतन का स्तर निम्न है।
4. कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का आकर्षण कम है।
5. भारत में नियोक्ता का रवैया भी ठीक नहीं है।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है।
7. भारत में कृषि क्षेत्र में कार्यरत किसानों तथा युवाओं में कौशलता का अभाव है।

भारत में कौशल विकास की कुछ प्रमुख सम्भावनाएँ निम्न हैं–

1. कृषि में आय वृद्धि हेतु नये उद्यमों में कौशल विकास जरूरी है।
2. कौशल विकास के लिए कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा पहल करना अनिवार्य है।
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कौशल विकास हेतु पहल की जानी चाहिये।
4. प्रशिक्षण या प्रशिक्षण बाजार तैयार करने के लिए नये दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है।
5. बेमेल कौशल प्रशिक्षण एवं उद्योग की जरूरतों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट एवं अस्त–व्यस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ही भारत सरकार एवं रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने पिछले वर्ष देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन राहत पैकेज जो दिये थे, वह जी०डी०पी० के लगभग 13 प्रतिशत थे, तथा 27 लाख करोड़ रूपये के थे। इतने भारी भरकम राहत पैकेज के उपरान्त भी वर्ष 2020 में भारत की विकास दर नकारात्मक रही थी। पिछले वर्ष वैश्विक विकास दर 3.3 प्रतिशत नकारात्मक रही, और राहत पैकेज एवं अन्य सरकारी प्रयासों द्वारा वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 12.5 प्रतिशत रहने का अनुमान आई०एम०एफ० ने व्यक्त किया है। इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान अपने लक्ष्य में सफल हो सकता है। वर्ष 2015 से कौशल विकास अभियान पूरे देश में चल रहा है, किन्तु भारत में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसका यह मतलब है कि कौशल विकास अभियान अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है, किन्तु इसका यह मतलब भी कतई नहीं है कि यह योजना अपने लक्ष्य से भटक गयी है। इस योजना के अंतर्गत भारत ने लोगों को कौशल–सम्पन्न बनाने में जबरदस्त प्रगति की है। अंत में हम यह कहना चाहेंगें कि भारत की भविष्य की पीढ़ियों को समृद्ध करने के लिए महिलाओं को भी सशक्त एवं कौशल–सम्पन्न बनाना बेहद जरूरी है, तथा साथ ही कौशल विकास में नये नवाचारों और प्रौद्योगिकी को भी समाहित करने की जरूरत है।

सन्दर्भ

1. https://www.drishtiias.com › hindi
2. https://www.hindikiduniya.com
3. https://www.pmmodiyojna.in>aatm-nirb...
4. दैनिक जागरण, 7 अप्रैल 2021, पेज–2
5. कुरूक्षेत्र– ग्रामीण विकास को समर्पित– मासिक पत्रिका– फरवरी, 2020
6. भारतीय अर्थव्यवस्था– वी० के० पुरी एवं एस० के० मिश्र

16

कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन

डॉ0 संजय कुमार बंसल

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

एन.आर.ई.सी. कॉलेज, खुर्जा

सारांश

कोरोना वायरस एक नए प्रकार का वायरस है, जो अभी तक मानव में नहीं पाया जाता था। इस कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार सप्लाई चैन में बाधाएं आदि आईं हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु हमें देश के लिए, देश के हित में काम करना होगा। हमें व्यापक अवधारणा अपनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए न केवल सरकार बल्कि नागरिकों को भी काम करना चाहिए। अगर व्यवस्था में सरकार और नागरिक सब मिलकर काम करें तो अल्प समय में हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

मुख्य शब्द– आर्थिक मंदी, व्यापार सप्लाई चैन, रोजगार सृजन कार्यक्रम, मिडिल क्लास

परिचय

कोरोना वायरस का सर्वप्रथम प्रकोप दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में हुआ। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे आम सर्दी से लेकर श्वसन तंत्र के रोग हो सकते हैं। नोबेल करोना वायरस एक नए प्रकार का वायरस है, जो अभी तक मानव में नहीं पाया जाता था। इस कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार सप्लाई चैन में बाधाएं आदि आईं हैं। कोरोना वायरस से न केवल विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी सबसे बुरी तरह प्रभावित है। कोरोना वायरस के कारण गत 1 वर्ष में पूरे विश्व में लॉकडाउन से सभी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। भारत भी अनेक क्षेत्रों में इससे अछूता नहीं था। कोरोना वायरस के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट भी आई है। भविष्य में भी इसकी संभावना रहेगी क्योंकि भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र पर दबाव और कोरोना वायरस प्रसार ने दबाव इस हद तक बढ़ा दिया है कि आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित होने लगी है। आर्थिक दर को प्रभावित करने के मुख्य कारक लॉकडाउन, घरेलू आपूर्ति तथा मांग में परिवर्तन हैं।

उद्देश्य

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का अध्ययन करना है तथा साथ ही कोरोना काल में सरकार के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए गए, यह देखना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव एवं सरकार द्वारा लिए गए कदम

कोरोना की लहर से बचाने के साथ–साथ सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं को दूर करना लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ साथ सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात करने को प्राथमिकता दी है जिससे प्रकोप को कम करके लोगों में विश्वास कायम किया जा सके और अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाया जा सके। सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कार्यक्रम परियोजनाएं बनाई गयीं हैं। यह वायरस स्वास्थ्य के साथ–साथ श्रमिक संकट और आर्थिक संकट पैदा कर रहा है। श्रमिक संकट में मजदूरों के पलायन से औद्योगिक इकाइयों को पूरी क्षमता पर चलाना असंभव हो गया है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की चैन प्रभावित है, इसलिये आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

एनएसडीएल के अनुसार साल 2020–21 में घरेलू इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 37 अरब डॉलर का निवेश किया। यह गत दो दशकों में सबसे अधिक निवेश था। घरेलू इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के शेयरों का मूल्य 2020–21 में रिकॉर्ड 555 अरब डालर तक पहुंच गया। सितंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच इसमें 105 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इसके मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशकों का निवेश 203 अरब डॉलर था, जो एफपीआई के मुकाबले आधे से भी कम है। भारत में वित्त वर्ष में निकासी से अधिक निवेश देखा गया है, परंतु मार्च 2021 में निकासी अधिक हुई और गिरावट का दौर दिखाई दिया। 25 अप्रैल, 2021 तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 7,622 करोड़ रुपये निकाले हैं। राज्य सरकारों की लॉकडाउन और टीकाकरण कार्यक्रम से निवेशकों में बिकवाली दिखाई दी।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार, इस महामारी से वित्त वर्ष 2020–21 में लगभग एक करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी गई। इसमें एमएसएमई तथा अन्य औद्योगिक इकाईयां लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुईं। सरकार के द्वारा लोगों की आजीविका बचाने हेतु विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 की संक्रमण दर बढ़ने से 19 अप्रैल 2021 को सेंसेक्स में 883 अंकों की गिरावट हुई जिसका मुख्य कारण देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा तथा अन्य राज्यों में संभावनाओं के कारण हुआ। रुपये की गिरावट के कारण सेंसेक्स तथा निफ्टी में उतार–चढ़ाव हुआ। सेंसेक्स 19 अप्रैल 2021 को 1.81 प्रतिशत गिरकर 47,942.42 पर बंद हुआ। निफ्टी 14,359.45 पर बंद हुआ। इस सप्ताह अर्थात अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में पूंजी बाजार पर कोविड–19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि, कंपनियों के तिमाही नतीजों के आने, वैश्विक संकेतकों के परिवर्तन के कारण निफ्टी 50 में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिला। 20 अप्रैल 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी में उतार–चढ़ाव देखने को मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों तथा स्थानीय स्तर पर सख्त पाबंदी से निवेशक भयभीत रहे और बिकवाली पर रहे। अगले दिन पूंजी बाजार में टीकाकरण अभियान में तेजी के कारण बढ़त भी दिखाई दी।

भारत सरकार के द्वारा बाजार में निवेश को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय के नियमों में छूट दी गई। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मंत्रालय तथा विभाग; उपकरण, संपत्तियां, उन्नत तकनीक आदि खरीदते हैं। सरकार के द्वारा कैश मैनेजमेंट से जुड़ी बाधाएं भी अगले आदेश तक लागू न करने के निर्देश दिए गए जिससे कि अर्थव्यवस्था को गतिमान किया जा सके।

S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वर्ष 2021–22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है। महामारी पर रोकथाम कर इसे बढ़ाया जा सकता है।

म्यूचुअल फंड उद्योग में वर्ष 2020–21 में 81 लाख नए खाते जोड़े गए। अप्रैल 2021 तक म्यूचुअल फंड के फोलियो का कुल आंकड़ा 9.78 करोड़ तक पहुंच गया। बाजार में पूंजी बाजार में अप्रैल में निफ्टी 50 में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स कम और ज्यादा होने के कारण व्यक्तियों ने म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया। साथ ही उन्होंने सेंसेक्स में गिरावट की उम्मीद में म्यूचुअल फंड बेचे भी।

भारत में बैंकों में भी लगातार आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला। भारत में बैंकों में एनपीए एक समस्या है। वैसे सरकार निवेश के माध्यम से उनकी आर्थिक मदद कर रही है और नियमों में राहत देकर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद दे रही है परंतु कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को जाम कर दिया और बैंकों को भी प्रभावित कर दिया है।

भारत में भविष्य निधि का संग्रह करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है। इससे एडवांस लेने की छूट और छोटी कंपनियों में नियोक्ताओं के अंशदान को 3 माह टालने का प्रस्ताव किया गया है।

कोरोना की लहर के कारण भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्यटन उद्योग, शेयर बाजार, दवा कंपनियों सहित सभी सेक्टर प्रभावित हैं। चीन में भी उत्पादन में कमी का असर भारत पर दिख रहा है। पर्यटन क्षेत्र में भारत प्रभावित इसलिए भी हुआ क्योंकि अन्य देशों ने हवाई यात्राएं प्रतिबंधित की हैं। वाहन उद्योग इससे प्रभावित हुआ क्योंकि भारतीय वाहन निर्माता कंपनियां उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत कच्चा माल चीन से आयात करती हैं और वर्तमान में आपूर्ति बंद है।

21 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने फिक्की तथा सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में व्यापार की लॉकडाउन की स्थिति की चुनौतियों को सुना जिसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि जरूरी सेवाओं की सूची केंद्र जारी करे तथा सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो। इसके अतिरिक्त बीमा तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालयों को लॉकडाउन में खोलने की अनुमति की मांग भी शामिल थी।

इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा कि महामारी ने डिजिटल विभाजन को बढ़ा दिया है। प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह दिखाना चाहिए कि डिजिटल होने के लाभ उन लोगों को भी प्राप्त हों जो स्मार्टफोन के मालिक नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कौशल तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की है, जिनमें से करीब 3 मिलियन भारत में हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रतिबंधों के कारण, निर्माण और सेवा क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रेस्तरां, पर्यटन से श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है। इससे नियोक्ताओं के लिए चुनौतियां खड़ी हो गईं हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि इन छोटे नियोक्ताओं के पास श्रमिकों को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता नहीं है। कुछ उद्योगों को उत्पादन से नहीं रोका जाना चाहिए जैसे कपड़ा और कांच। लॉकडाउन के कारण कई कंपनियों के लिए स्टॉक बेकार पड़ा हुआ है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बाजारों में कंपनियां श्रम–शक्ति को कम करने के लिए छंटनी कर रही हैं। कुछ वित्तीय दबाव विशेष रूप से छोटे व्यवसायों की समाप्ति का कारण बन रहे हैं। एक और अन्य समस्या है कि राज्यों में अलग–अलग कर्फ्यू समय होते हैं और अक्सर लॉकडाउन प्रोटोकॉल अलग होता है, जिससे माल की आवाजाही में कठिनाई होती है।

सुझाव

भारत में आर्थिक गतिविधियों को सही करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए जिसमें प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को लिया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों के माध्यम से एक रूपरेखा तैयार की जाए ताकि उचित योजना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ भारतीय प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक समाधान योजना बनानी चाहिए।

सरकार को प्रत्येक सेक्टर को ऋण देना होगा। सरकार को उनकी सहायता के लिए हर क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना होगा। यह व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार को विदेशी वित्तीय निवेशकों को अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए रियायतें देनीं चाहिएं। ये रियायतें कम कागजी कार्रवाई के रूप में हो सकतीं हैं। भारत में महामारी का प्रकोप और लॉकडाउन से उनके मन का आत्मविश्वास डगमगा है। साथ ही घरेलू उद्योगपति को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। योजनायें नागरिकों के समर्थन से ईमानदार तरीके से क्रियान्वित होनीं चाहिएं क्योंकि विदेशी निवेशक भी पैसा तभी लगाएंगें। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बुनियाद भारतीय विदेशी जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके द्वारा भारत में पैसा भेजा जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य मुख्य बुनियाद मिडिल क्लास है। यही वह क्लास है जो अर्थव्यवस्था के लिए स्तंभ की तरह कार्य करती है। अतः सरकार को इसके लिए एक विशेष कर राहत पैकेज देना चाहिए जिससे ना केवल निवेश को बढ़ावा मिले, अपितु उनके पास खर्च करने के लिए भी धन उपलब्ध हो और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके। अर्थव्यवस्था में संकट के समय मिडिल क्लास सबसे अधिक कमजोर कड़ी मानी जाती है क्योंकि सरकार के द्वारा कभी भी उसे राहत पैकेज नहीं दिया जाता और वह उस से वंचित रह जाती है। अतः उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब आबादी वाली साइड में शिफ्ट हो जाता है जो अर्थव्यवस्था की विकास की गति में बाधा पहुंचाता है। आईएमएफ के अनुसार यह जरूरी है कि भारत को अपने इस मिडिल क्लास को सुरक्षित करना होगा और इसको विशिष्ट पैकेज देना होगा। चूंकि बड़ी संख्या में करदाता इस वर्ग से हैं, इसलिए हम उन्हें निवेश करने या कर का भुगतान करने का विकल्प दे सकते हैं। यदि वे निवेश का विकल्प चुन रहे हैं तो सरकार को बुनियादी ढांचे और अन्य औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश बांड पेश करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कमजोर आबादी वाले लोग, जैसे किसान, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले दैनिक मजदूरों को भी रोजगार के अवसर सर्जन कर स्थानीय स्तर पर लोकल फॉर वोकल की सरकार की घोषणा से अधिकतम राहत मिलनी चाहिये। सरकार को उत्पादन सेक्टर में भी कई और राहत पैकेज देने चाहियें जिससे कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की जा सके।

सरकार को रिवर्स माइग्रेशन समस्या को भी ध्यान में रखकर गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित होने की संभावना है। भारत में यह रिवर्स माइग्रेशन समस्या सकारात्मक तरीके से हल हो सकती है। गाँव की ओर पलायन करने वाली जनसंख्या गाँवों में बसायी जा सकती है। इस कार्यबल का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है और साथ ही सरकारी कार्यक्रमों की सहायता से लघु इकाइयों को विकसित किया जा सकता है।

वैक्सीन के स्तर पर विश्व की सभी कंपनियों को भारत में वैक्सीन संयंत्र लगाने की अनुमति देकर तथा कीमत नियंत्रित कर टीकाकरण अभियान में तेजी लाकर इस महामारी को रोका जा सकता है। सरकार भारत में विभिन्न फार्मा कंपनियों को कोवैक्सीन और कोविडशील्ड बनाने का लाइसेंस भी प्रदान कर सकती है ताकि वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। यह नागरिकों को टीकाकरण में मदद करेगा।

भारत को विकास की गति का अवलोकन करना होगा और अपनी चीन पर निर्भरता को खत्म करना होगा। भारतीय उद्योग जो चीन पर निर्भर हैं, उनको सहायता प्रदान कर उनको जीवन दान देना होगा। इसके अतिरिक्त देश को आर्थिक संकट से दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा अधिक गतिमान करना होगा। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कम या ज्यादा होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम महामारी पर किस प्रकार काबू कर पाते हैं।

निष्कर्ष

ऊपर दिए गए विभिन्न सुझावों की मदद से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम करने से निश्चित रूप से देश को मदद मिलेगी। हमें देश के लिए, देश के हित में काम करना होगा। हमें व्यापक अवधारणा अपनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए न केवल सरकार बल्कि नागरिकों को भी काम करना चाहिए। अगर व्यवस्था में सरकार और नागरिक सब मिलकर काम करें तो अल्प समय में हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

सन्दर्भ

1. www.moneyconrol.com
2. www.rbi.org.in
3. www.sebi.gov.in
4. www.nseindia.com
5. इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स– विभिन्न अंक।

17

कोरोना अवधि में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव

डॉ0 भूपेन्द्र सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
बरेली कालेज, बरेली

विकास शर्मा
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
बरेली कालेज, बरेली

सारांश

वर्तमान समय में कोविड–19 महामारी के द्रुत तथा व्यापक प्रसार ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बौना सिद्ध कर दिया है। संक्रमण के वैश्विक मामले 16 करोड़ को पार कर गए हैं और 34 लाख लोग कालकलवित हो चुके हैं। यह महामारी अपनी संक्रामकता तथा वैश्विक प्रसार के कारण व्यापक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक बदलावों का कारण बन रही है। समाज में गुंथे–बुने सभी सामाजिक संबंध अपने जीवन को बचाने और इस संक्रमण से बचने के प्रयास में बेमानी सिद्ध हो रहे हैं। लोग अपने घनिष्ठों की शवयात्रा में तक जाने से बच रहे हैं। अर्थजगत में विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाऍं लॉकडाउन के दुष्परिणामों के चलते ध्वस्त हो गई हैं। राजनीतिक दृष्टि से संसार बहुध्रुवी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। चीन की बादशाहत स्थापित हो रही है। चीन के संबंध अन्य देशों के साथ बिगड़े हैं जबकि भारत के संबंध मधुर हुए हैं। कोरोना अवधि में कोरोना कुप्रबंधन के कारण राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता गिरी है तथा नागरिक अपने राष्ट्र की सरकारें बदलने को उद्धत हुए हैं।

मुख्य शब्द– कोरोना, संक्रमण, प्रसार, लॉकडाउन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बदलाव

परिचय

वर्तमान समय एक ऐसा समय है जब मानव महामारियों के मामले में इतिहास को स्वयं को दोहराते हुए देख रहा है। निकट अतीत में अनेकों महामारियों यथा जीका, इबोला, स्वाइन फ्लू, मर्स, सार्स आदि से संबंधित समाचार हमने समाचार पत्रों में पढ़े तथा दूरदर्शन पर देखे भी हैं। किंतु इन महामारियों का प्रसार वैश्विक नहीं था। अतीत में वैश्विक प्रसार वाली भी अनेकों महामारियों ने इस धरा को डोलने पर विवश कर दिया था यथा एड्स, एनफ्लूएंजा महामारी, स्पेनिश फ्लू इत्यादि। इन वैश्विक महामारियों ने सैकड़ों लोगों को कालकलवित कर दिया था, साथ ही ये महामारियॉ विश्व के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिदृश्य में विकराल परिवर्तनों का कारण बनीं थीं। ऐसी ही एक वैश्विक महामारी कोविड–19 से आज सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। ये महामारी नवम्बर 2019 में चीन के वुहान शहर से निकल कर अत्यंत अल्प समय में ही सम्पूर्ण विश्व में फैल गई। भारत में भी अप्रैल माह 2020 तक इस महामारी के मामले बड़ी संख्या में दृश्यमान हो चुके थे। इस महामारी के केन्द्र मुख्य रूप से सबल तथा विकसित देश ही बने हैं तथा अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस महामारी से सर्वाधिक त्रस्त हुआ है जहॉ अप्रैल 2021 तक कोरोना के लगभग 3.23 करोड़ मामले आये हैं और लगभग 5.75 लाख लोग काल के गाल में समा गये हैं। अप्रैल 2021 तक सम्पूर्ण विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 15.1 करोड़ तथा मृत्यु का ऑकड़ा लगभग 31.7 लाख तक पहुॅच चुका है। भारत की स्थिति भी भयावह है जहॉ अप्रैल 2021 तक लगभग 1.88 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा लगभग 2.08 लाख लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सम्पूर्ण धरा को भयावह रूप से प्रभावित करने वाली कोविड–19 महामारी के कारण समाज, अर्थतंत्र तथा राजनीति में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिनका वर्णन अग्रलिखित शीर्षकों में है:–

कोरोना अवधि में सामाजिक बदलाव

मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में सामाजिक नियमों तथा विधायी कानूनों के अनुसार ही रहना है। इसी समाज में कोरोना के द्रुत गति से प्रसार के कारण व्यापक सामाजिक बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कोरोना एक अति संक्रामक महामारी है अतः इससे बचने का सबसे कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन करना है जबकि समाज के लोगों में अपनत्व का भाव जागृत करते के लिए सामाजिक निकटता परमावश्यक है। अब जब सामाजिक दूरी जो कि सामाजिक अलगाव का कारण बनती है, वह ही संक्रमण और मृत्यु से बचने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय बन जाए तो इंसान बेचारा क्या करे? और ऐसे में तो सामाजिक अलगाव अवश्यंभावी ही है। भारत में इस महामारी की दूसरी लहर की काली छाया में जिस प्रकार के हृदय विदारक समाचार आ रहे हैं वे कोरोना अवधि में हुए विकराल सामाजिक बदलावों की ओर स्पष्टतः इंगित

कर रहे हैं। कोरोना काल की इस निष्ठुर अवधि में निकट संबंधी भी अपने कोरोना संक्रमित संबंधीजनों के लिए किसी भी प्रकार से मददगार सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अनेकों संक्रमित ऐसे हैं जिनको अपने सगे संबंधियों के मुंह फेर लेने के कारण कोई अस्पताल ले जाने वाला तक नहीं है। सर्वाधिक हृदयाघातिनी बात यह है कि मृत्यु हो जाने पर संक्रमितों की अर्थी को चार कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। दूर का या पास का कोई भी संबंधी या मित्र संकट की इस घड़ी में अपनों का साथ देने को तैयार नहीं है। मित्रों और सगे संबंधियों का एक दूसरे के घर आवागमन अवरुद्ध है। विवाह हो रहे हैं मगर पण्डाल सूने पड़े हैं। अन्य घरेलू सामाजिक कार्य हो रहे हैं मगर अपनों का टोटा है। ये सभी बातें कोरोना काल में घट रहे विकट सामाजिक बदलाव की द्योतक हैं। दूसरी ओर कोरोना काल में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन के कारण महीनों तक सड़कें, बाजार तथा अन्य सार्वजनिक स्थान लोगों से पूर्णतः या आंशिक रूप से खाली रहे हैं। लोग घरों में कैद रहे हैं जिसके कारण आम परिवारों के सदस्यों के बीच पारस्परिक संवाद में वृद्धि हो रही है जो उनके बीच पारस्परिक प्रेम, सहयोग, संवेदनशीलता तथा भाईचारे में वृद्धि कर रही है। हॉ, कई परिवारों में यह पारिवारिक कलह का कारण भी बन रहा है, यह भी सत्य है।

कोरोना काल में समाज में जो अलगाव दृष्टिगोचर हो रहा है वह मात्र भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में परिलक्षित हो रहा है और इस अलगाव के मूल में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान के जोखिम की ही चिंता है। यह कटु सत्य है कि इस महामारी के दौर में लोग अपना जीवन जोखिम में डालकर अपनों की कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं किंतु यह मृदु सत्य है कि लोगों ने अपनी संवेदनशीलता को तिलांजलि नहीं दे दी है और वे स्वमन से अपनों की सहायता करना चाहते हैं किंतु जीवन के जोखिम का प्रश्न उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस कोरोना काल में लोग तन से अपनों से दूर भले ही हों लेकिन मन से वे और निकट आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के अवसान के पश्चात लोगों के आपसी संबंध पहले से और अधिक सुदृढ़ होकर उभर कर आयेंगें क्योंकि तब न जीवन का कोई जोखिम होगा और न सरकारी नियमों के तहत सामाजिक दूरी के पालन की कोई मजबूरी।

कोरोना अवधि में आर्थिक बदलाव

अर्थतंत्र संसार के सबसे नाजुक तंत्रों में से एक है। यह तंत्र तनिक सी चोट लगने पर भी बिखर जाता है और फिर इसे समेटना एक बहुत दुरूह कार्य हो जाता है। इस नाजुक तंत्र के लिए कोरोना काल प्रलयंकारी सि़द्ध हो रहा है। इस क्रूर महामारी के काल के चलते सम्पूर्ण विश्व में व्यापक आर्थिक बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। संचार तथा आवागमन एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीकी के द्रुत और अत्याधुनिक साधनों के कारण आज विश्व एक 'वैश्विक ग्राम' की अवधारणा पर चल रहा है और संसार सिमट कर बहुत छोटा सा प्रतीत होने लगा है। लेकिन कोरोना काल इस अवधारणा के कारण और इस अवधारणा के लिए कुठाराघाती सिद्ध हो रहा है। 'वैश्विक ग्राम' की अवधारणा के कारण ही यह महामारी कुछ ही महीनों के अंतराल पर संपूर्ण धरा पर प्रसार पा सकी और इस प्रकार की महामारियॉ यदि भविष्य में भी बार बार वैश्विक प्रसार पाती हैं तो हो सकता है कि संसार के राष्ट्र 'वैश्विक ग्राम' की अवधारणा को तिलांजलि देने के बारे में सोचें क्योंकि वैश्विकरण के लाभों से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों का जीवन है। 'वैश्विक ग्राम' की इस अवधारणा के बीच ही कोरोना महामारी की अति संक्रामकता के कारण विभिन्न देशों ने संक्रमण रोकने तथा अपने नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए कई महीनों तक संपूर्ण लॉकडाउन का सहारा लिया। भारत में भी 6–8 महीनों तक भिन्न भिन्न दिशानिर्देशों के साथ लॉकडाउन लगा रहा। संसार के लगभग सभी देशों ने विदेशी उड़ानों पर महीनों पूर्ण प्रतिबंध लगाकर रखे। भारत में ऐतिहासिक रूप से रेलों के पहिये पहली बार महीनों रुके रहे। इन सब कदमों का परिणाम यह हुआ कि पर्यटन तथा हॉस्पिटैलिटी उद्योग की कमर पूरी तरह टूट गई और होटल और रेस्टोरेंट बंदी की स्थिति में पहुॅच गए। वैश्विक तौर पर सभी प्रकार की औद्योगिक, निर्माणी और वाणिज्यिक गतिविधियॉ ठप्प पड़ गईं। इस आर्थिक जड़ता और निष्क्रियता का प्रभाव यह पड़ा कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाऍं ध्वस्त हो गईं। अर्थव्यवस्था के लगभग सारे क्षेत्र लंबी निष्क्रियता के कारण डॉवाडोल हो गए। भारत में कृषि तथा फार्मा को छोड़कर लगभग सभी आर्थिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के रोजगार वृहद मात्रा में छिन गए और आर्थिक चक्र रुक सा गया। अप्रैल–जून 2020 की तिमाही में लगभग सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर रसातल में चली गई। इस अवधि में भारत ने 23.9, स्पेन ने 22.1 और ब्रिटेन ने 21.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर अर्जित की। 23.9 प्रतिशत की भीषण गिरावट ने भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल सा ला दिया। परंतु यह गिरावट सामान्य या नैसर्गिक नहीं थी वरन इस गिरावट का मूल कारण आर्थिक गतिविधियों में महीनों का ठहराव था। लॉकडाउन में ढील मिलते ही आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि अक्टूबर–दिसंबर 2020 की तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। लोगों को रोजगार मिलने लगे और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र बेहतर ऑकड़ों के साथ सामने आये। उपरोक्त ऑकड़े बताते हैं कि कोरोना काल ने भारतीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर अति प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

वर्ष 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते भारत तथा अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं को जो आघात लगा है उससे उबरने में उन्हें काफी समय लग जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोरोना का प्रकोप जारी है और इसकी आगे आने वाली लहरों के अधिक खतरनाक होने की संभावना है, भारत समेत अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन भविष्य में कैसा रहेगा इस पर अभी स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

कोरोना काल में राजनीतिक बदलाव

राजनीतिक तंत्र यद्यपि अर्थतंत्र की भॉति अत्यधिक नाजुक तो नहीं किंतु फिर भी पर्याप्त नाजुक है जो बड़े धक्कों का आघात सरलतापूर्वक सह नहीं पाता और अतिशीघ्र चरमरा जाता है। कोरोना जैसी घातक संक्रामक महामारी के कारण जो सामाजिक बदलाव आये और आर्थिक आभाऍं

महामारी के अंध तिमिर में खो सी गईं, उन सबके परिणामस्वरूप विश्व पटल पर राजनीतिक उठापटक वृहद स्तर पर देखी गई। विश्व राजनीति के बदले स्वरूप में चीन पर कोरोना महामारी का जानबूझ कर प्रसार करने और महामारी की अतिसंक्रामकता के बारे में जानते हुए भी समय पर अन्य देशों को इसकी जानकारी न देने के व्यापक आरोप लगे जिसके कारण चीन के साथ अधिकतम देशों के संबंध खराब हुए। भारत की सदाशयता तथा विकट कोरोना संक्रमण काल में अन्य देशों की यथासंभव सहायता करने के कारण विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध और अधिक मजबूत हुए। कोरोना काल में दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। अमेरिका महामारी के संक्रमण को रोकने में व्यस्त है और चीन इस महामारी पर बहुत पहले ही काबू पाकर आर्थिक, सैन्य, अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीकी समेत सभी क्षेत्रों में अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व का अगुआ बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। कोरोना महामारी की सूचना और प्रबंधन इत्यादि को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जैसी आलोचना हुई वह भी स्वयं में ऐतिहासिक है।

कोरोना की भयावहता का समय पर अंदाजा न लगा सकने के कारण विभिन्न देशों में अतिशीघ्रता से कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुँच गया। विभिन्न देशों की सरकारें इस महामारी का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाईं जिसके कारण करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हुए और लाखों की संख्या में कालकलवित हो गए। विश्व की श्रेष्ठतम स्वास्थ्य व्यवस्था वाले देश अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन इत्यादि भी इस महामारी के सम्मुख नतमस्तक हो गए। विश्व के लगभग सभी देशों का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह विफल हो गया। लाचारी का आलम यह था कि अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इत्यादि कम पड़ गये; शवगृहों में शव रखने को स्थान कम पड़ गया; कब्रिस्तानों में शव दफनाने को जमीन कम पड़ गई। इन सब अव्यवस्थाओं के चलते विभिन्न राष्ट्रों की जनता अपने राजनीतिक नेतृत्व से रुष्ट हो गई और विभिन्न देशों विशेषकर अमेरिका, यूरोप के देशों और ब्राजील आदि में विरोध प्रदर्शन होने लगे और जनता अपनी सरकारों से इस्तीफे की मांग करने लगी। अमेरिका, इटली, मलेशिया आदि देशों में कोरोना महामारी नेतृत्व परिवर्तन का विशेष कारण बनी और दर्जनों राष्ट्रनेताओं की लोकप्रियता रसातल में चली गई।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कोरोना अवधि में चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा राजनीतिक; सभी क्षेत्रों में विकट व्यापक बदलाव दृष्टिगोचर हुए हैं तथा हो रहे हैं। सामाजिक संबंधों में हुए विराट परिवर्तनों से संक्रमण काल में लोगों की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा दृश्यमान है। आर्थिक जगत तो लगता है कि 360 डिग्री उल्टा घूम गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और अर्थजगत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो कोरोना महामारी के प्रकोप से लहूलुहान न हुआ हो। विश्व राजनीति में भी विशाल राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। विश्व एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता प्रतीत हो रहा है। कोरोना संक्रमण विश्व के अनेक देशों में नेतृत्व परिवर्तन का कारण बना है और इसने अनेक वैश्विक नेताओं के कद को घटा कर बहुत छोटा कर दिया है। कुल मिलाकर संसार में जिस भी प्रकार के और जिस स्तर के बदलाव कोरोना महामारी की अवधि में हुए हैं, सामान्य दिनों में उस प्रकार के परिवर्तनों की उम्मीद भी कदाचित नहीं की जा सकती थी।

सन्दर्भ सूची

- https://www.worldometers.info/coronavirus/
- https://voxeu.org/article/political-consequences-covid-pandemic
- https://www.mygov.in/covid-19
- https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/#dossierSummary
- https://ssir.org/rethinking_social_change_in_the_face_of_coronavirus

18

उदारीकरण, विनिवेश एवं निजीकरण

डॉ0 कविता भटनागर
विभागाध्यक्षा एवं एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
जी. डी. एच. जी. कालेज, मुरादाबाद

सारांश

आजादी के उपरांत हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उस काल के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली थी क्योंकि यह आवश्यक था कि सरकार उद्योगों के विकास में सक्रिय भागीदारी करे। 1980 के दशक से ही विश्व समुदाय वैश्वीकरण की ओर चल पड़ा था लेकिन भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक उद्योगों की आरक्षित नीति पर ही केन्द्रित थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि सन 1991 तक भारतीय उद्योग पूंजी और विदेशी निवेश की कमी और असामान्य रूप से बढ़ी कर की दरों से पीड़ित हो गये। सन 1991 के बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जो वैश्वीकरण पर आधारित थी। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योगों का व्यापक उदारीकरण, लाइसेंसी राज से मुक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विदेशी पूंजी प्रवाह सुगम बनाना, आयकर तथा निगम कर की दरों में कमी आदि अनेक उपाय अपनाए गए। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस दौरान निजीकरण और विनिवेश की प्रणाली को विकसित किया गया। निजीकरण से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री से सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण करना होता है। मोदी सरकार ने तो निजीकरण और विनिवेश के अपने इरादे 2014 में ही जाहिर कर दिए थे। सरकार की मंशा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की है। निजीकरण और विनिवेश दोनों ही सरकारी उद्यमों और सरकार के लिए फायदे का सौदा है। सरकार को इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से जो धनराशि प्राप्त होती है, वह सरकार जनसामान्य के लाभ के लिए उपयोग कर सकती है और इन उपक्रमों पर सरकार के आवर्ती खर्चों में भी कमी आती है।

मुख्य शब्द– वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश, आर्थिक सुधार

आजादी के उपरांत हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उस काल के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली थी क्योंकि यह आवश्यक था कि सरकार उद्योगों के विकास में सक्रिय भागीदारी करे। दो सौ साल के विदेशी उपनिवेश ने हमारे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था और ऐसे में उद्योगों विशेषकर मूलभूत उद्योगों को राज्य की सहायता और सुविधाओं की आवश्यकता थी। उस समय बड़े उद्योगों के लिए न तो निजी पूंजी बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी और न ही विकसित प्रौद्योगिकी तक निजी उद्यमियों की पहुँच थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इस काल में विश्व अर्थव्यवस्था पूँजीवाद और साम्यवाद दो धाराओं में बँटी हुई थी जिसमें से पूँजीवाद का नेतृत्व अमेरिका और साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 1980 के दशक में पूँजीवाद की एक नई लहर चल पड़ी थी जो वैश्वीकरण पर आधारित थी। सोवियत संघ भी इससे अछूता नहीं रहा था और 1991 तक आते–आते सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक छवि विखंडित हो गयी। सोवियत संघ अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त हो गया जिनमें से अनेक राष्ट्रों ने पूँजीवाद को अपनाया।

1980 के दशक से ही विश्व समुदाय वैश्वीकरण की ओर चल पड़ा था लेकिन भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक उद्योगों की आरक्षित नीति पर ही केन्द्रित थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि सन 1991 तक भारतीय उद्योग पूंजी और विदेशी निवेश की कमी और असामान्य रूप से बढ़ी कर की दरों से पीड़ित हो गया। आरक्षित उद्योगों के कारण लाइसेंस राज स्थापित हो गया था और परिणाम स्वरूप सरकारी और सार्वजनिक उद्योगों की गुणवत्ता और लाभ में कमी आने लगी थी। संवैधानिक नियम और कानूनों ने आर्थिक वृद्धि और विकास की समस्त प्रक्रिया को स्थिर कर दिया। सन 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ने देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। उस समय देश स्वतंत्रता के पश्चात के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां मात्र एक सप्ताह के आयात का

खर्च चुकाने योग्य रह गई थीं, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जा रही थी और हमारी मुद्रा कमजोर हो रही थी। सन 1991 के बजट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जो वैश्वीकरण पर आधारित थी। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योगों का व्यापक उदारीकरण, लाइसेंसी राज से मुक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी, निजी क्षेत्र के लिए अधिक उद्योगों को खोलना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विदेशी पूंजी प्रवाह सुगम बनाना, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और आयकर तथा निगम कर की दरों में कमी आदि अनेक उपाय अपनाए गए।

वैश्वीकरण की अवधारणा में विश्व को एक भूमंडलीय गांव के रूप में देखा जा रहा था। इस नई अवधारणा में विश्व के सभी देशों के मध्य बिना किसी अवरोध के आयात और निर्यात की कल्पना की गई थी। ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा था जिसमें पूंजी और वस्तुओं के प्रवाह में एक देश से दूसरे देश के मध्य कोई संवैधानिक रुकावट न हो, जिससे संपूर्ण विश्व एक भूमंडलीय गांव के समान व्यापार कर सके। किसी एक देश के विकास और प्रौद्योगिकी का लाभ सभी देश समान रूप से उठा सकें। ऐसा तभी संभव है जब सभी देश अपने व्यापारिक नियमों और प्रतिबंधों में ढील प्रदान करें और अपनी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण लाएं। उदारीकरण की इस प्रक्रिया में सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति औचित्यहीन है। अनेक पूंजीवादी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली जैसे देशों ने कमोबेश इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, वहीं तत्कालीन सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने उदारीकरण की इस नीति को अपनाने में रुचि नहीं दिखलाई। सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात अनेक साम्यवादी देशों को भी इस उदारीकरण की प्रक्रिया में भागीदारी करनी पड़ी। चीन जैसा साम्यवादी देश भी आज वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया का सक्रिय और प्रमुख भागीदार है।

वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी पूंजी के प्रवाह से भारतीय उद्योगों की पूंजी और लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंचे, विदेशी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार और भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाजार की उपलब्धता संभव हुई। प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार बढ़ने से उत्पादों की गुणवत्ता में भारी सुधार देखा गया। सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भी निजी और विदेशी पूंजी का आवागमन सुगम हो गया। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ।

नरसिम्हाराव सरकार के समय आरंभ की गई उदारीकरण की इस व्यवस्था को अग्रवती सरकारों– वाजपेयी सरकार, मनमोहन सरकार और मौजूदा मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। वाजपेयी सरकार के काल में ऐसे निर्णय लिए गए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक बाधाओं को दूर किया गया। इस दौरान विदेशी पूंजी का भारत में बहुत ज्यादा निवेश हुआ। निजीकरण और विनिवेश की प्रणाली को विकसित किया गया।

वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की गई जिसके पहले मंत्री अरुण शौरी बने। इस दौरान पहली बार स्ट्रेटजिक सेल के माध्यम से 12 सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया। इन महत्वपूर्ण कंपनियों में मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, भारत एलमुनियम, विदेश संचार निगम शामिल हैं। इनमें से हिंदुस्तान जिंक और भारत एलमुनियम को अनिल अग्रवाल ग्रुप, मारुति उद्योग जापान के सुजुकी और विदेश संचार निगम टाटा ग्रुप को हस्तगत किए गये।

मनमोहन सरकार के समय अनेक सार्वजनिक उपक्रमों जैसे एनएचपीसी, एनटीपीसी, आरईसी, एनएमडीसी आदि का पूंजी बाजार के माध्यम से विनिवेश किया गया था। इस दौरान लगभग 33 कंपनियों में विनिवेश करके 92724 करोड़ रुपऐ जुटाए गए थे।

निजीकरण से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण करना होता है। निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार अपनी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी व्यवसायियों को बेच सकती है या सेवा प्रदान करने वाले ऐसे क्षेत्रों को जिस पर सरकार का आधिपत्य था, निजी क्षेत्रों के लिए आवंटित कर सकती है। निजीकरण की एक पद्धति विनिवेश की भी है जिसमें सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के पूर्ण या आंशिक शेयर किसी निजी व्यवसायी या आम जनता को बेच सकती है। इस विनिवेश में विनिवेश के नियमों के अंतर्गत विदेशी निवेशक भी भागीदारी कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं को निजी ठेके या पट्टे पर देना भी निजीकरण की एक पद्धति है। निजीकरण में उदारीकरण और विनियमन की प्रक्रिया शामिल होती है। सरकार अपने एकाधिकार वाले उद्योगों में एकाधिकार के नियमों में ढील देकर उद्योग में प्रतिस्पर्धा आमंत्रित करती है और अवरोधों का उन्मूलन करती है। निजीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इससे उद्योगों में दक्षता बढ़ती है, जिससे लाभप्रदता में बढ़ोतरी होती है। लाभप्रदता निवेश योग्य पूंजी को आकर्षित करता है।

1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 1992–93 मे 31 सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बिक्री के लिए निकाले गए। इन शेयरों को खुली नीलामी के द्वारा एक आरक्षित मूल्य के आधार पर बेचने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस प्रक्रिया में सिर्फ बैंक, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड को ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति थी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों, देशीय और विदेशी मुद्रा बाजार में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। विदेशी निवेश संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों, म्यूचअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई। बैंकों में 49 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी का निवेश संभव किया गया। सार्वजनिक और निजी बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर निश्चित किए गए, बैंक ब्याज दरों को आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया, गैर निष्पादित आस्तियों के लिए नियम बनाए गए। 1991–92 में सरकार ने 2500 करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा और लगभग 3058 करोड़ों रुपए विनिवेश से जुटाने में सफल रही।

वैश्वीकरण के फलस्वरूप ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी लगा रही हैं। भारतीय कंपनियों ने भी विदेशों में अपने संस्थान और अधिग्रहण करने आरंभ कर दिए थे। ओएनजीसी विदेश, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वेदांता, डॉक्टर रेड्डीज, इंफोसिस, एचसीएल टेक जैसी अनेक कंपनियां या तो अपने कार्यालय अनेक देशों में खोल चुकी हैं या विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करके विकसित हो रही हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है।

मोदी सरकार ने तो निजीकरण और विनिवेश के अपने इरादे 2014 में ही जाहिर कर दिए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा था कि व्यापार चलाना सरकार का काम नहीं है। वित्त वर्ष 2021–22 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार भारतीय पूंजी बाजार का सबसे बड़ा शेयर निर्गम एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त सरकार इस वर्ष भारत पैट्रोलियम, एयर इंडिया, शिपिंग कारपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत अर्थ मूवर्स जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को स्ट्रैटेजिक डिस–इनवेस्टमेंट के आधार पर विनिवेश करना चाहती है। इसके अतिरिक्त सरकार की योजना कुछ सार्वजनिक बैंकों में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की है।

देश में लगभग 300 सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। सरकार की मंशा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की है। परमाणु ऊर्जा, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और चुनिंदा वित्तीय सेवाओं को रणनीति क्षेत्र माना जाता है। इनमें से भी अनेक क्षेत्रों में सरकार अपनी हिस्सेदारी आंशिक रूप से कम करने के समर्थन में है। सरकार का तर्क है कि असक्षम और सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बने सरकारी उपक्रमों से पीछा छुड़ाना चाहिये। कोरोना के उपरांत राजकोषीय घाटे को भी इस विनिवेश के जरिए कम किया जा सकेगा।

मौजूदा सरकार की विनिवेश नीति चार सूत्रों पर आधारित है–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इकाइयों को निजी सैक्टर को बेचना

(2) गैर लाभप्रद केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का एकीकरण करना

(3) केंद्रीय उपक्रमों में प्रतिभूतियों का विक्रय करना और

(4) ऐसे उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी और कम करना जहां सरकार की अंशधारिता 51 प्रतिशत से नीचे आ गई है। अब सरकार उद्यमों में अपनी अंशधारिता स्ट्रैटेजिक सेल के माध्यम से 51 प्रतिशत से कम कर देना चाहती है जिससे उद्यम का संचालन निजी हाथों में चला जाए।

सारणी 1

विभिन्न सरकारों के द्वारा विनिवेश लक्ष्य और प्राप्तियां

सरकार	विनिवेश लक्ष्य करोड़ रूपये	प्राप्तियाँ करोड़ रूपये	प्रतिशत
वाजपेयी सरकार (एनडीए)	63500	29900	47
मनमोहन सरकार (यूपीए–1, यूपीए–2)	133000	92724	70
मोदी सरकार (एनडीए)	309237	280490	91

स्रोत– मुम्बई स्टाक मार्केट विनिवेश डाटा

सारणी 2

गत कुछ वर्षों के विनिवेश लक्ष्य और प्राप्तियां

वर्ष	लक्ष्य (रू.करोड)	प्राप्ति (रू. करोड)	उपलब्धि प्रतिशत
2012–13	30000	23957	79.86
2013–14	40000	15819	39.55
2014–15	43425	24349	56.07
2015–16	41000	23997	58.53
2016–17	56500	46247	81.85
2017–18	100000	100057	100.06
2018–19	80000	84972	106.22
2019–20	105000	50299	47.90

स्रोत – निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

निष्कर्ष

निजीकरण की यह आलोचना की जाती है कि निजीकरण के फलस्वरूप निजीकरण की कीमत उसके कर्मचारियों को चुकानी पड़ती है। यह आलोचना ठीक नहीं है। कुशल प्रबंधन के फलस्वरुप निजी क्षेत्र में जाने से सार्वजनिक उपक्रमों के आकार और व्यापार में हुई वृद्धि से अनेक बेरोजगारों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण का लाभ आपूर्तिकर्ताओं समेत जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को पहुंचता है। निजी क्षेत्र में गए सार्वजनिक उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने पर कर्मचारियों की छटनी अपरिहार्य हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि सरकार निजी क्षेत्र के स्वामी से इस शर्त पर सार्वजनिक उपक्रम का सौदा करती है कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छँटनी नहीं की जाएगी और इसी कारण उपक्रम कम कीमत पर बेच देती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बेचने का विरोध करने वाले अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि भारत जैसे गरीब देश में ये सरकारी कंपनियां सामान्य लोगों की मदद करने के लिए बेहद जरूरी संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर विनिवेश के समर्थक अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार का काम देश के प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने का है न कि कारोबार चलाने का। अंतः सरकार को इन कम्पनियों के व्यापार से बाहर आ जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से कम्पनियों के प्रबंधन से बाहर न आकर अपनी अंशधारिता धीरे–धीरे कम करती जाए तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

निजीकरण और विनिवेश दोनों ही सरकारी उद्यमों और सरकार के लिए फायदे का सौदा है। निजीकरण के द्वारा विनिवेश कर देने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार को दो–तरफा फायदा होता है। एक तो सरकार को उन सार्वजनिक उपक्रमों से मुक्ति मिल जाती है जो या तो घाटे में चल रहे हैं या नाममात्र का मुनाफा दर्ज कर रहे हैं। ऐसे सार्वजनिक उपक्रम नौकरशाही और राजनीतिक नियंत्रण के मध्य फँसे होते हैं और इसी कारण संतोषजनक परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे उपक्रम यद्यपि रोजगार में सहायक होते हैं लेकिन पर्याप्त पूँजी की कमी, सब्सिडी पर निर्भरता और सरकारी संरक्षण जैसे अनेक मूलभूत दोषों से ग्रस्त रहते हैं। यह देखा गया है कि जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया गया था वे उद्यमियों के लिए फायदे का सौदा बने और अपनी मूल कीमत से कई गुना वर्तमान कीमत पर कार्य कर रहे हैं। उनकी लाभप्रदता में भी असामान्य वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ सरकार को इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से जो धनराशि प्राप्त होती है वह सरकार जनसामान्य के लाभ के लिए उपयोग कर सकती है और इन उपक्रमों पर सरकार के आवर्ती खर्चों में भी कमी आती है। विनिवेश और निजीकरण का फैसला, इस प्रकार सरकार के लिए दो–तरफा फायदे का फैसला होता है।

संदर्भ–

1. 'ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ एंड पावर्टी इन इंडिन्यन कान्टेक्स्ट' आर्टीकल डाक्टर कविता भटनागर, एडिटेड पुस्तक श्री वी बी जुगाले 'ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ एंड पावर्टी '(2004) पेज नम्बर 182–188
2. आर्थिक सर्वे 2019–20
3. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मार्च 2021– स्टेट ऑफ़ इकोनोमी– श्री शक्ति कांता दास
4. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2019–20 प्रकाशित– भारतीय रिजर्व बैंक
5. विकास की नयी उम्मीदें – आर्टिकल श्री शक्ति कांता दास

19

उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण
(भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में)

डॉ0 सीमा मलिक

असिस्टैंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद

सारांश

किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्राकृतिक साधनों की सामूहिक शक्ति ही देश के आर्थिक विकास की सीमा एवं प्रकृति निर्धारित करती है। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, भारत को प्रकृति ने प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से मालामाल कर रखा है, इसीलिए भारत को प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक धनी देश कहा जाता है। यहां विशाल भूमि, जल, वन एवं खनिज संसाधन हैं। इसके वैभव से प्रभावित होकर ही विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर बार–बार हमला कर अपना कब्जा जमाया एवं इसकी संपत्ति को लूट कर ले जाते रहे। सहस्त्रों वर्षों की परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी प्राप्त हुई, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी, असंतुलित और अविकसित स्थिति में थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर देश में चहुमुखी आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। विकास की रफ्तार की धार और तेज करने के लिए तथा खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 1991 को अपनाया गया जिसके बाद से अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की प्रवृतियां तेजी से विकसित हुई हैं।

मुख्य शब्द– प्राकृतिक संसाधन, पंचवर्षीय योजनायें, औद्योगिक नीति, लाइसेंस व्यवस्था

प्राचीन समय से ही भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से एक अत्यंत मजबूत अर्थव्यवस्था रही है, जिसके विश्व के अन्य भागों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपने शासन के दौरान कच्चा माल भारत से सस्ती दरों पर खरीदा जाता था और फिर तैयार माल भारत के बाजारों में सामान्य से कहीं अधिक उच्च कीमत पर बेचा जाता था, जिसके कारण भारत को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस उद्देश्य से विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाई गईं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की गईं। 1950 में जब भारत ने 3.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसे ब्रिटिश राज के अंतिम 50 सालों की विकास दर से तिगुना हो जाने का जश्न मनाया था। समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया था। सन 1950 और 1960 के दशक में अधिकांश विकासशील राष्ट्रों ने प्रगति और समृद्धि के लिए जो रणनीति अपनाई उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक नए विकासशील देशों ने उत्साह पूर्वक विकास के इसी रूप को अपनाया परंतु कुछ वर्षों के भीतर ही वे इसके परिणामों को देखकर निराश हो गए। 70 और 80 के दशक में विश्वव्यापी मंदी के चलते अधिकांश विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। इसका प्रमुख कारण इन राष्ट्रों द्वारा लिया गया भारी ऋण था जो 70 के दशक के अंतिम वर्षों में धीरे–धीरे एकत्रित होने लगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो निवेश किया गया था उसका कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं आया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोई अवशेष पैदा नहीं कर पाए, जिसके कारण विकास में कोई सहायता नहीं मिली। परिणामस्वरूप विश्वव्यापी धरातल पर परिवर्तन की मांग होने लगी। विकासशील समाज में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया और बाजार अर्थव्यवस्था की सहकारी शक्तियों ने शासन की समस्याओं को जन्म दिया है। भूमंडलीकरण ने औद्योगीकरण को भी प्रभावित किया है। भारत में वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति और बाद में किए गए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरुप औद्योगीकरण का काफी विकास हुआ।

नए आर्थिक सुधारों में मुख्यतः तीन को शामिल किया गया–

1– उदारीकरण

2– भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण)

3– निजीकरण

उदारीकरण

उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार आर्थिक क्रियाओं पर लगे हुए अनेक प्रतिबंधों को या तो पूर्ण रूप से हटा लेती है या फिर कुछ सीमा तक मुक्त कर देती है जिसके पीछे उसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है।

भारत में नवीन औद्योगिक नीति 1991 के बाद से आर्थिक अंकुशों और औद्योगिक नियंत्रणों व बहुत से आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ को सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत में उदारीकरण के प्रथम उद्घोषक थे। उनके बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा बाद वाली केंद्र में सत्तारूढ़ हुई सभी सरकारों ने इसी उदारीकरण विचारधारा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में भारत आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। 1991 से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र में नियमन प्रणालियों को विभिन्न प्रकार से लागू किया गया था। देश में औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को किसी फर्म को स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी ना किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। बहुत से उद्योगों में तो निजी उद्यमियों को प्रवेश करना ही मना था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। नई औद्योगिक नीति के आरंभ होने के बाद से इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि जैसे उत्पादों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं।

वित्तीय क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वित्तीय क्षेत्र को संभालता है। आर.बी.आई. के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। कोई बैंक कितनी मुद्रा जमा रखेगा, ब्याज दर क्या रखेगा, विभिन्न क्षेत्रों को कब व कितना उधार देगा यह सब आर.बी.आई. ही तय करता है। रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। बैंकों की पूंजी में विदेशी हिस्से की सीमा 50 प्रतिशत कर दी गई है। विदेशी निवेश संस्थाओं (एफ.आई.आई.) तथा व्यापारिक बैंक, म्यूच्यूअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है।

सरकार की राजकोषीय नीतियों में भी बदलाव आया है। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। कर की दर अधिक न होने से बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से आय का विवरण दे देते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का एक और तत्व सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

विदेशी विनिमय के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया, जिसके कारण देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। वर्तमान में तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहे हैं।

स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारने और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश व तकनीक की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश नीति में भी बदलाव किया गया। नए सुधारों के तहत अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए हैं। भारतीय वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तस्करी को रोकने के लिए सोने–चांदी के आयात को सस्ता कर दिया गया है। इस प्रकार उदारीकरण का देश की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भूमंडलीकरण

भारत की नवीन आर्थिक नीतियों में एक अन्य नीति अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) की है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव करना है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित लेनदेन ही भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) कहलाता है। भूमंडलीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान–प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो। जब सभी देश समान नियम के अनुशासन में व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो वास्तव में वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही वास्तव में भूमंडलीकरण होता है। भूमंडलीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगें। यह समस्त विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। भारत में नवीन आर्थिक नीतियों के तहत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है। इन उपायों को विभिन्न

चरणों में लागू किया जाना है। भूमंडलीकरण का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी पूंजी निवेश कर रही हैं। परिणामस्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं को चीजों की अलग–अलग किस्में न्यून दरों पर प्राप्त हो रही हैं। आधारभूत ढांचों की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। संचार क्षेत्र में भी तेजी के साथ प्रगति हुई है। अब निजी क्षेत्र अन्य देशों से कच्चे माल तथा तकनीक के आयात के लिए स्वतंत्र हैं। आयात तथा निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कई भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं जैसे– टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबेक्सी, एशियन पेंट आदि। वैश्वीकरण के कारण ही अब भारत माल का निर्यात और आयात भी बड़े पैमाने पर करने लगा है। हमारे व्यवसाय सभी प्रकार के विदेशी बाजारों में प्रवेश कर चुके हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न उद्योगों के बीच होड़ पैदा की है। यह होड़ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि कर रही है। भारत में विकास की रफ्तार काफी तीव्र हो गई है। भारत तेजी से विश्व बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी नीति से संबंधित एक अमेरिकी पत्रिका के अनुसार वैश्वीकरण के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बहुत आवश्यकता है। वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश कुछ बाजारोन्मुखी आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम क्रियान्वित करें। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ सिद्धांत एवं कार्यक्रम बनाए गए हैं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करना, बाजार की शक्तियों द्वारा ब्याज की दरों का निर्धारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दरवाजों को खुला रखना आदि। राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश और नए निवेश में निजी क्षेत्र की प्रमुखता द्वारा निजीकरण को प्रोत्साहन, संपत्ति के अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, संस्थागत एवं रचनात्मक सुधार करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा आर्थिक क्रियाओं में पारदर्शिता आदि कार्यक्रमों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों की उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और कृषि की विकास दरों में गतिरोध उत्पन्न हो गया और विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ने लगा परंतु अब स्थिति पहले से बेहतर हो गई है।

निजीकरण

उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ ही साथ भारत में निजीकरण के क्षेत्र में आर्थिक सुधार तेजी से लागू किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी आजादी के बाद 1991 में लागू हुई नई औद्योगिक नीति ने विकास की एक नई रफ्तार पैदा कर दी है। अब तो सरकार का रुख निजी उपक्रमों के प्रति काफी उदार बना हुआ है। सरकार की नई सोच ने निजी क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है और इस क्षेत्र में जान सी फूंक दी है।

निजीकरण के तहत सरकार अपने स्वामित्व वाले अधिकांश क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंप देती है। इस प्रकार निजीकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकारी नियंत्रण को घटाकर देश में आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित किया जाता है। निजीकरण के लिए सामान्य तथा विराष्ट्रीयकरण, विनियंत्रण, विनियमन, आर्थिक उदारीकरण, वित्तीय स्वतंत्रता, विनिवेश, प्रबंध व्यवस्था का हस्तांतरण आदि विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार की इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना होता है। निजीकरण के तहत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग न केवल सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावकारी होगा बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ाएगा।

इस प्रकार निजीकरण से सामाजिक स्वामित्व को निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे सरकारी क्षेत्र के स्थान पर जनता का क्षेत्र विकसित होने लगता है और आर्थिक क्षेत्र में सरकारी प्रभुत्व कम होने लगता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में निजीकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं– औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक शांति स्थापित करना, उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार करना, उपक्रमों के बीच प्रतियोगी माहौल तैयार करना, सरकारी उपक्रमों को घाटे से उबारना, देश में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, देश के उपक्रमों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना अर्थात उनका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना तथा देश में तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का वातावरण तैयार करना, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक कम ओहदे को बड़ा ओहदा देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के नए सैट तैयार करना।

सरकार द्वारा निजीकरण को अपनाने की अनेक वजह थीं, जिसने सरकार को निजीकरण की प्रक्रिया अपनाने को प्रेरित किया जैसे– सार्वजनिक उपक्रमों में अविवेकपूर्ण मूल्य नीति का होना, उद्देश्यों व लक्ष्यों का अभाव पाया जाना, नियमों और नीतियों का अत्यधिक होना, उनमें नवप्रवर्तनों का अभाव पाया जाना, सृजन क्षमता का अभाव, उपक्रमों की रुग्णता तथा घाटे का लगातार बढ़ता जाना, हड़ताल व तालाबंदी का होना, कर्मचारियों में कर्मठता की कमी एवं उत्पाद की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता को दर्शाते हैं एवं निजीकरण को और ज्यादा बढ़ावा देने की ओर प्रेरित करते हैं।

नवीन औद्योगिक नीति के बाद से आर्थिक अंकुशों, औद्योगिक नियंत्रणों व बहुत से आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ को सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में भारत आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज कोई

क्षेत्र नहीं है जिसे निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के आर्थिक दबाव के फलस्वरुप भी भारत में निजीकरण को प्रोत्साहन मिला है।

नवीन औद्योगिक नीति में उदारीकरण व निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई जिसे 1993 में पुनः घटाकर 6 कर दिया गया वर्तमान में तो यह संख्या घटाकर 4 ही कर दी गई है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्यता को धीरे–धीरे कम किया जा रहा है। सरकार भविष्य में लाइसेंस अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने निजी क्षेत्र के साहसियों को बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में लगभग 17 से अधिक निजी एयरलाइंस कार्य कर रही हैं। सरकार ने जनोपयोगी सेवा जैसे टेलीफोन संचार को संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र को भी अनुमति प्रदान की है। परिणामस्वरूप टेलीफोन सेवाओं पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो रहा है। बीमा व्यवसाय में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने के साथ ही सरकार सार्वजनिक सेवाओं जैसे पानी व विद्युत की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, सड़क व पुलों का निर्माण व रखरखाव, रेलवे प्लेटफार्म व अस्पतालों आदि का रखरखाव, बैंकिंग सेवा आदि क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र को छूट प्रदान कर रही है। भारत के जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता ही जा रहा है जहां वर्ष 1950–51 में इस क्षेत्र का योगदान 29.55 प्रतिशत था वहीं अब यह कई गुना बढ़ गया है। इसी तरह रोजगार में भी इसकी हिस्सेदारी 39.1 प्रतिशत से बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले कर की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है।

उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण के दुष्प्रभाव

इस प्रकार आर्थिक सुधारों के तहत भूमंडलीकरण, निजीकरण व उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार काफी तेज हो गई है और लगभग हर क्षेत्र में आधुनिकता को तेजी से अपनाया जा रहा है। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मजबूती से खड़ी होने में सक्षम हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। भूमंडलीकरण से लघु उद्योगों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। रोजगार में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। विकसित देशों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं निजीकरण से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं रह पाने का खतरा मंडराने लगा है। निजी क्षेत्र मनमाने तरीके से व्यवहार करता है। निजी संस्थानों की पहली प्राथमिकता संस्थान का लाभ बढ़ाना होता है न की जनता का हित सोचना। क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं के बढ़ने का खतरा पैदा होने का डर रहता है। कर्मचारियों का मनोबल कम होने लगता है जब बाहरी कंपनी आकर भारतीय कंपनियों में प्रवेश करके अपनी शेयर पूंजी बढ़ाते जाते हैं और अंत में भारतीय कंपनियों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से दुष्प्रभाव हैं जो आने वाले समय में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इसी तरह उदारीकरण से भी अनेकों नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत धरती के गर्भ से भारी मात्रा में अवैध खुदाई कर खनिज–अयस्क निकाले गए हैं। देशी–विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट की है। विदेशी पूंजी निवेश भी हुआ है लेकिन उद्योग अर्थात विनिर्माण एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तो न के बराबर हुआ है। कोका–कोला एवं पेप्सी जैसी कंपनियों के पूंजी निवेश और लाभ कमाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लगातार गरीबी, बेरोजगारी और मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। आज खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। रसायनिक उर्वरकों की कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया गया है। इससे किसानों के आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता प्रतीत हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया के देशों में भारत का स्थान लगातार बहुत नीचे 133 के आसपास बना हुआ है। ऊंची वृद्धि दर के बावजूद भारत दुनिया के धनी देशों के इर्द–गिर्द भी नहीं है। अमीर और उच्च मध्यम वर्ग के लोग अमीर बनते जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती खाई के कारण समाज में असंतोष, तनाव, झगड़ों एवं अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार अनेकों तरह के सामाजिक, आर्थिक नुकसान आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद बढ़ें हैं।

निष्कर्ष

वास्तव में जब भी कोई देश नई आर्थिक नीति बनाता है तो निजी क्षेत्र के व्यापक विकास व विस्तार तथा विदेशी कंपनियों को प्रवेश के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि नीति के तहत देश के कुछ विशेष उत्पादों को अनावश्यक रूप से लाभ तथा बहुसंख्यक जनसंख्या के हितों की उपेक्षा होती हुई पाई जाए। यह भी संभव है कि भुगतान संतुलन को ठीक करने व अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मृगमरीचिका में भारतीय अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जकड़ में आ जाए। भारत में घरेलू उदारीकरण व बाहरी उदारीकरण और वैश्वीकरण की क्रियाएं साथ–साथ चलने से कुछ कठिनाइयां आने लगी हैं लेकिन यदि प्रयास किया जाए तो हम आधुनिकीकरण, मानवीय व सामाजिक न्याय में सामंजस्य बिठाते हुए अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक व कुशल बना सकते हैं। भारत 1 अरब 38 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाला देश है। अपने मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से प्रयोग करके व नई आर्थिक नीतियों का इससे तालमेल बिठाते हुए यदि ईमानदारी व कर्मठता के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ा जाएगा तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि आने वाला कल भारत का ही होगा और आर्थिक सुधार देश की विकास गति को अपने चरम पर ले जाएंगें।

संदर्भ सूची–

- Kindleberger C.P. - Economic Development
- Rostow W.W. - Theories of Economic Growth
- Sen R.K. & B. Chatterjee (2001) - Indian Economy
- Sandesara J.C. - Industrial Policy and Planning
- Ahluwalia I.J. & I.M.D. Little (EDS)(1999) - India's Economic Reforms and Development

20

कोविड-19 बनाम सरकार की राष्ट्रीय योजना एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 नीरज कुमार
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

डॉ0 अंकुर अग्रवाल
असिस्टैंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

जिस तरह से कोविड–19 एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में पैर पसार रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को एक साथ आकर एक विश्वव्यापी नीति बनानी होगी ताकि इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में जब कोरोना जनवरी 2020 से प्रथम बार धीरे–धीरे पैर पसार रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में हम सभी भारतीयों ने इस महामारी का डटकर सामना किया। लेकिन पुनः कोविड–19 अप्रैल 2021 से इतना अधिक प्रभावी व गतिशील हो रहा है कि इससे पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए इस शोधपत्र के माध्यम से कोविड–19 को लेकर सरकार को एक राष्ट्रीय योजना बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं। इस बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए सरकार को आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर कोविड–19 की जांच करने के लिए जो भी उपयुक्त टेस्ट हैं इनकी किटों का, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवनदायिनी दवाइयों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिये ताकि इस प्रकार की आपदा से बचने के लिए उठाये गये कदम ज्यादा से ज्यादा कारगर सिद्ध हों।

मुख्य शब्द– कोविड–19, आरटीपीसीआर, राष्ट्रीय योजना, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर

प्रस्तावना

कोविड–19 की भारत में जो वर्तमान स्थिति है वह इतनी भयावह है कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि विश्व के किसी भी देश ने ऐसा भयानक मंजर न कभी देखा है न सुना होगा। अब भारत सरकार इसे आपातकाल की दशा में देख रही है और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। 28 अप्रैल 2021 तक भारत में कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 18368096 हैं जो कि हमारे देश की कुल 135 करोड़ जनसंख्या का 1.36 प्रतिशत है। जबकि 28 अप्रैल 2021 तक कोरोना से संक्रमित होकर 15078276 व्यक्ति ठीक हुए जोकि कुल संक्रमितों का 82.09 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि हमारे देश में चिकित्सा सुविधा अन्य विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम होने के बावजूद भी उपचार के बाद ठीक होने की दर ज्यादा है। अगर मृत्यु दर की बात कही जाए तो कोरोना संक्रमण के दौरान मृतक व्यक्तियों की संख्या 204812 है जोकि कोरोना संक्रमित कुल व्यक्तियों का 1.11 प्रतिशत है। अगर विकसित देशों (अमेरिका, ब्राजील, इटली, स्पेन व अन्य देश) के साथ तुलना की जाये तो यह प्रतिशत काफी कम है। कोरोना के कारण हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से चरमरा गई है। जब कोरोना तीव्र गति से भारत में पैर पसार रहा था तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और पहले 60 से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन और बाद में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन का कार्य बहुत अधिक गति से प्रारम्भ किया और अब 1 मई 2021 से 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों को भी पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेण्डर एवं वैंटीलेटर को लेकर आज पूरे देश में हाहाकर मचा हुआ है। इससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से पूरे देश में 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट जुलाई 2021 तक लगवाना सुनिश्चित किये गयें हैं और इसमें एमएसएमई सेक्टर व बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ जनसहभागिता को भी आधार बनाया गया है ताकि संकट की घड़ी में किसी भी तरीके से इस देश में उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से समय रहकर निपटा जा सके। ऐसा नहीं कि इसमें केवल केन्द्र सरकार ही पूर्ण सहयोग दे रही है बल्कि इसमें राज्य सरकारों का भी उतना ही योगदान है। कोविड के समय में सरकारें केन्द्रित होकर एक राष्ट्रीय योजना अग्रसारित कर रही हैं। आज की विषम परिस्थितियों में पूरा विश्व भारत जैसे विकासशील देश के साथ खड़ा है, इन्हीं परिस्थितियों से यह पता चलता है कि कौन–कौन से देश एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और इसमें यू.एन.ओ. की भी अहम भूमिका है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस कोरोना काल में सही दिशा निर्देशित कर समय–समय पर पूर्ण सहयोग दिया है।

साहित्य–समीक्षा

कोरोना वायरस महामारी की शुरूआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसम्बर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों मे से अधिकतर लोग बुहान सी–फूड मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019–nCoV प्रारंभिक नाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70 प्रतिशत वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स–कोरोना वायरस में पाए जाते हैं।

20 मार्च 2020 तक थाईलैण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, यूएसए, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इटली, कतर, दुबई, कुवैत और अन्य 160 देशों में कोरोना के मामले सामने आये हैं।

23 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का फैसला किया।

अनुसंधान क्रियाविधि

शोधकर्ता ने केवल एक सप्ताह के समंकों के आधार पर कुछ परिणाम जानने की कोशिश की है। शोधकर्ता ने द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया है और समंकों का टी–परीक्षण (t-test) के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया है। उपचार से सही हुए व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों और इसके साथ कोरोना टेस्टिंग व वैक्सीन के बीच सह–सम्बन्ध ज्ञात किया गया है। भारत में 22 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक कोविड–19 समंकों के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. कोरोना के बाद उपचार से हुए सही व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का अध्ययन करना।
2. कोरोना के दौरान उसमें हुई टेस्टिंग और लगायी गयी वैक्सीन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
3. कोविड–19 में सरकार की राष्ट्रीय योजना का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

H_0: कोरोना के बाद उपचार से सही हुए व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कोई अंतर नहीं है।

H_0: कोरोना के दौरान टेस्टिंग कराने वाले व्यक्तियों की संख्या और वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई अंतर नहीं है।

अध्ययन का विश्लेषण

Table No. 1 Weekly Distribution of Corona

Days	New cases	Growth in %	Recovered cases	Growth in %	Deceased	Growth in %
22-04-2021	332518	----	192311	----	2257	----
23-04-2021	346786	4.29	220541	14.68	2620	16.08
24-04-2021	348979	0.63	215803	-2.15	2761	5.38
25-04-2021	354533	1.59	218561	1.28	2806	1.63
26-04-2021	319315	-9.93	248639	13.76	2762	-1.57
27-04-2021	362757	13.60	262039	5.39	3285	18.94
28-04-2021	379164	4.52	270202	3.12	3646	10.99

Source: https://www.covid19india.org

तालिका संख्या 1 के अनुसार कोरोना का साप्ताहिक विश्लेषण दिनांक 22 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक समंकों के आधार पर किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि नए संक्रमित व्यक्तियों में सबसे अधिक वृद्धि (13.60 प्रतिशत) दिनांक 27.04.2021 को हुई तथा सबसे कम नए संक्रमित व्यक्तियों की कमी (–9.93 प्रतिशत) दिनांक 26.04.2021 को रही। संक्रमित व्यक्तियों में से उपचार द्वारा सही हुए व्यक्तियों की सबसे अधिक वृद्धि (14.68 एवं 13.76 प्रतिशत) क्रमशः दिनांक 23.04.2021 एवं 26.04.2021 को हुई तथा सबसे कम संक्रमित व्यक्तियों में से उपचार द्वारा सही व्यक्तियों की कमी (–2.15 प्रतिशत) दिनांक 24.04.2021 को रही। अगर मृत्यु दर का साप्ताहिक आकंलन किया जाये तो सबसे कम मृत्यु दर की कमी (–1.57 प्रतिशत) दिनांक 26.04.2021 को रही। जबकि सबसे अधिक मृत्यु दर में वृद्धि (18.94 प्रतिशत) दिनांक 27.04.2021 को गर्णित की गयी। उपरोक्त तालिका का आकलन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना अपनी चरम सीमा पर पैर पसारे हुए है। जल्द से जल्द भारत सरकार को कोरोना से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना को बनाना होगा ताकि कोरोना को रोकने में हम सार्थक हो सकें।

Table No. 2 Weekly Distribution of Corona's Testing and Vaccination

Days	Testing	Growth in %	Vaccinations	Growth in %
22-04-2021	1651711	----	2211334	----
23-04-2021	1740550	5.38	3147776	42.35
24-04-2021	1753569	0.75	2901412	-7.83
25-04-2021	1719588	-1.94	2536585	-12.57
26-04-2021	1402367	-18.45	994806	-60.78
27-04-2021	1658700	18.28	3359963	237.75
28-04-2021	1723912	3.93	2556181	-23.92

Source: https://www.covid19india.org

तालिका संख्या 2 के अनुसार कोरोना की टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन का साप्ताहिक विश्लेषण दिनांक 22 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक समंकों के आधार पर किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि कोरोना टेस्टिंग की सबसे अधिक वृद्धि (18.28 प्रतिशत) दिनांक 27.04.2021 को हुई तथा सबसे कम कोरोना टेस्टिंग की कमी (–18.45 प्रतिशत) दिनांक 26.04.2021 को रही। वैक्सीनेशन के कार्य में सबसे अधिक वृद्धि (237.75 प्रतिशत) दिनांक 27.04.2021 को हुई तथा सबसे कम वैक्सीनेशन के कार्य में कमी (–60.78 प्रतिशत) दिनांक 26.04.2021 को रही। उपरोक्त तालिका का आकलन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग पर बल देना चाहिए क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा होने से हम संक्रमित व्यक्ति को चिन्हित कर उसको उपचार के लिए अस्पताल भेज सकते हैं जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है।

Table 3
Paired Samples Statistics

Particulars		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
r 1	New cases	349150.2857	7	19524.92304	7379.72725
	Recovered Cases	232585.1429	7	28242.01608	10674.47872
r 2	Testing	1664342.4286	7	121923.53967	46082.76642
	Vaccination	2529722.4286	7	781827.93782	295503.18450

Table 4
Paired Samples Correlations

Particulars		N	Correlation	Sig.
ir 1	New cases & Recovered Cases	7	0.507	0.246
ir 2	Testing & Vaccination	7	0.846	0.017

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात किया गया है कि कोरोना के बाद उपचार से सही हुए व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में मध्यम कोटि का सकारात्मक सहसम्बन्ध (0.507) है तथा कोरोना के दौरान उसमें हुई टेस्टिंग और लगायी गयी वैक्सीन में उच्च कोटि का सकारात्मक सहसम्बन्ध (0.846) है जो दर्शाता है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन भारत में काफी हद तक सार्थक रहे हैं।

Table 5
Paired Samples Test

Particulars		Paired Differences					t	d.f.	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	New cases - RecoveredCases	116565.14	24899.58	9411.1596	93536.86	139593.42	12.386	6	0.000
Pair 2	Testing - Vaccination	-865380.00	681834.07	257709.05	-1495971.3	-234788.65	-3.358	6	0.015

उपरोक्त टी–परीक्षण से यह ज्ञात किया गया है कि Pair-1 में कोरोना के बाद उपचार से सही हुए व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की t-value 12.386 है और इसकी p value 0.000 है जोकि 0.05 से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है अर्थात् कोरोना के बाद उपचार से सही हुए व्यक्तियों और नये कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में सार्थक अंतर है।

Pair-2 में कोरोना के दौरान उसमें हुई टेस्टिंग और लगायी गयी वैक्सीन के टी–परीक्षण में t-value -3.358 है और इसकी p-value 0.015 है जोकि 0.05 से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है अर्थात् कोरोना के दौरान टेस्टिंग कराने वाले व्यक्तियों की संख्या और वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों की संख्या में सार्थक अंतर है।

कोविड–19 से संघर्ष हेतु सरकार की राष्ट्रीय योजना के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव

1. RTPCR टेस्ट या कोरोना को चैक करने में जो भी सम्बन्धित टेस्ट है उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि संक्रमित व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान करके उनको आइसोलेट या अस्पताल में भर्ती किया जा सके और संक्रमण के फैलने से बचा जा सके।
2. सरकार को सप्ताहांत लॉकडाउन के साथ–साथ बाकी दिनों में भी बाजार के खुलने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन करके सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर देना चाहिए। जिस तीव्र गति से यह संक्रमण फैल रहा है ऐसे में यह फॉर्मूला काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है।
3. कोविड–19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जब सप्ताहांत लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारे यातायात से जो वायु प्रदूषण होता है उस पर रोक लगेगी और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी।
4. रेलवे विभाग इस महामारी के चलते सरकार को बहुत सहयोग दे रहा है। रेलवे कोचों का प्रयोग अस्पताल के रूप में आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है और साथ–साथ रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलायी जा रही है जो संकट के समय में बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध हो रही है।
5. कोविड–19 की वर्तमान स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि मेरा सरकार से आग्रह है कि इसमें निजी वाहनों का भी प्रयोग ऐम्बुलेंस के रूप में किया जा सकता है और इन निजी वाहनों में ही ऑक्सीजन व पूरी मेडिकल किट होने से हमारे देश में जो अस्पताल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कुछ हद तक कम हो सकता है। हम निजी वाहनों का प्रयोग माइक्रो कोविड व्यक्ति के लिए माइक्रो–बैड के रूप में कर सकते हैं।
6. मेरा इस देश की वर्तमान सरकार से विनम्र आग्रह है कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको भी कोविड से संक्रमित व्यक्तियों के लिए माइक्रो अस्पताल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
7. इस बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए भारत सरकार को प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड या अन्य वित्तीय संसधानों का प्रयोग नये ऑक्सीजन प्लाण्ट खोलने और वेन्टीलेटर बनाने में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि इन विषम परिस्थितियों का सामना बहुत सहजता से किया जा सके और इसमें समाज व बड़े–बड़े उद्योगपतियों की वित्तीय सहभागिता भी बहुत सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकती है।
8. कोविड–19 के विकराल रूप को देखते हुए जो नये चिकित्सक, एएनएम, जेएनएम, बी.एससी. नर्सिंग किये हुए हैं और वे सभी अभी ऑफ रोल में हैं; उन सभी को सरकार द्वारा जल्द से जल्द भर्ती कर उनकी सहभागिता कोरोना वारियर्स के रूप में सुनिश्चित करनी चाहिए।
9. उत्पादन की इकाइयों व एमएसएमई सेक्टर्स को कम से कम 30 प्रतिशत क्षमता (शिफ्ट के साथ) कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति भारत सरकार को देनी चाहिए जिससे कि कर्मचारियों व मजदूर वर्ग को वित्तीय जोखिम का सामना न करना पड़े। इससे हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद व आर्थिक दशा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पडेगा और इसमें सरकार को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
10. कोविड–19 को देखते हुए पूरे भारत में ऑनलाइन एजूकेशन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प होना चाहिए ताकि शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो और उसमें पूरी पारदर्शिता का परिचय देते हुए सरकार द्वारा यह कदम समाज, शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी सभी के लिए उपयोगी साबित हो।
11. कोरोना काल में पिछले वर्ष 2020 के भांति वर्तमान वर्ष 2021 में भी भारत सरकार को मुफ्त राशन केवल बीपीएल राशनकार्ड धारकों को मई, जून, जुलाई 2021 तक देना चाहिए ताकि वो अपना जीवनयापन आसानी से कर सकें।
12. इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए अगर हो सके तो भारत सरकार को 15 दिनों के लिए मई माह में ''ब्रेक दा चेन'' नाम से एक सफल व अनुशासनात्मक लॉकडाउन लगाना चाहिए। तभी हम पिछले वर्ष की भांति कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक रोक पाने में सफल सिद्ध होंगें।
13. सप्ताह में कम से कम एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक अभिप्रेरणात्मक व्याख्यान समाज व कोरोना काल में लगे हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया जाना चाहिए ताकि हम इस विश्वव्यापी महामारी का सामना दृढ़ निश्चय के साथ कर सकें। इस जागरूकता अभियान से समाज को मानसिक बल के साथ–साथ अभिप्रेरणा भी मिलेगी।

14. अभी तो वैक्सीनेशन व टेस्टिंग का कार्य केवल सरकारी व निजी अस्पतालों में ही हो रहा है, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन व टेस्टिंग किट होगी तो इसे घर–घर अभियान के तहत जल्द से जल्द लागू किया जा सकता है ताकि इस महामारी से जल्द से जल्द निजात पाने में हम सफल हो सकें क्योंकि सरकार ने पहले भी घर–घर जाकर टीकाकरण के काफी अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज के इस कोरोना काल में अगर इस विश्वव्यापी महामारी से निपटना है तो हमें अनुशासन, सरकारी आदेश, मास्क, दो गज की दूरी, समय–समय पर साबुन से हाथ धोने के साथ–साथ शिक्षित व्यक्तियों द्वारा समाज को कोरोना काल में जागरूक करने जैसे अभियान को निरन्तर जारी रखना होगा। इस कोविड–19 में एक राष्ट्रीय योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से केन्द्र–राज्य सरकार को आपसी सहयोग करके भविष्य में सुखद योजनायें बनानी होंगीं, चाहे यें योजनायें मेडिकल, टेस्टिंग, यातायात, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्लाण्ट, ऑनलाइन एजुकेशन व एग्जाम, उत्पादन, मुफ्त राशन वितरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से सम्बन्धित ही क्यों न हो। हम समाज को अधिक से अधिक जागरूक कर इस महामारी से जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। कोरोना से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भारत कम संसाधनों के बावजूद भी कोरोना से लड़ रहा है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा। एक राष्ट्रीय योजना का होना आज बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि सही योजना के माध्यम से ही किसी भी कार्य को बहुत कुशलता से सम्पन्न किया जा सकता है।

संदर्भ

1. "Undiagnosed pneumonia - China (HU) (01): wildlife sales, market closed, RFI Archive Number: 20200102.6866757". Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. (Accessed on 13 January 2021)
2. Cohen, Jon; Normile, Dennis, "New SARS-like virus in China triggers alarm". Science 367 (6475):234–235. PMID 31949058. ISSN 0036- 8075. (Accessed on 17 January 2021)
3. Parry, Jane., "China coronavirus: cases surge as official admits human to human transmission". British Medical Journal. 368. ISSN 1756-1833. (Accessed on 24 January 2021)
4. Schnirring, Lisa; 2020 "WHO holds off on nCoV emergency declaration as cases soar". CIDRAP (Accessed on 24 January 2021)
5. "Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23 January 2020". www.who.int (Accessed on 23 January 2021)
6. Newey, Sarah. "WHO refuses to rule out human-to-human spread in China's mystery virus outbreak". The Telegraph (Accessed on 13 January 2021)
7. Shen, Darley. "New coronavirus can spread between humans—but it started in a wildlife market". Science (Accessed on 24 January 2021)
8. Edwards, Erika. "1st case of coronavirus from China confirmed in U.S." NBC News (Accessed on 20 January 2021)
9. Nectar Gan; Yong Xiong; Eliza Mackintosh. "China confirms new coronavirus can spread between humans". CNN. (Accessed on 20 January 2021)
10. Tan, Weizhen. "China says coronavirus that killed 6 can spread between people. Here's what we know". CNBC ((Accessed on 24 January 2021)
11. https://www.covid19india.org/

21

कोविड-19 महामारी एवं ट्रिप्स समझौता

डॉ0 श्रवण कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
मुल्तानीमल मोदी कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद

सारांश

कोविड–19 महामारी ने एक असाधारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को पैदा किया है जिससे विश्व व्यापार में पेटेंट संरक्षण अधिकार, चिकित्सा उपचार के विकास और उपयोग को लेकर हितधारकों के बीच में बहस का मुद्दा बन गये हैं। इस शोध पत्र में महामारी से संबंधित दवाओं और तकनीकी के पेटेंट अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। महामारी के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिये भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यू.टी.ओ. के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया है कि ट्रिप्स समझौते के तहत व्यापार–संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाये ताकि विनिर्माण क्षमता में कमी वाले देशों में उत्पादन करना संभव हो सके। महामारी की वर्तमान स्थिति एक पारदर्शी और विश्वसनीय कानूनी ढाँचे के महत्व को उजागर करती है जो हितधारकों को एक दूसरे के साथ उत्पादन और आगामी चिकित्सा उपचार और प्रौद्योगिकियों के वितरण पर सहयोग करने का आधार प्रदान करती है।

मुख्य शब्दः ट्रिप्स समझौता, पेटेंट अधिकार, डब्ल्यू.टी.ओ.

भारत वैश्विक महामारी कोविड–19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना विषाणु संक्रमित मरीज ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। महामारी की शुरूआत से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, व्यापार नीति, नवाचार के प्रबंधन और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) से संबंधित मुद्दों पर बहस शुरु हो गयी है। अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार में, बौद्धिक सम्पदा से युक्त वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। यदि देशों द्वारा प्रदान किये जाने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण अपर्याप्त या अनुचित हैं, तो इससे अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विकृत होने का खतरा है। कोविड–19 महामारी के प्रकोप का सामना कर रहे देशों में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2 अक्टूबर, 2020 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की थी। संयुक्त याचिका के माध्यम से दोनों देशों ने 1995 के ट्रिप्स समझौते के तहत व्यापार–संबंधित पहलुओं पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में अस्थायी रूप से छूट देने का अनुरोध किया था ताकि विनिर्माण क्षमता में असक्षम देश भी कोरोना टीके और संबंधित दवाओं का उत्पादन कर सकें। इससे यह होगा कि कोरोना महामारी से संबंधित उपचार कुछ ही बड़े देशों तक सीमित न होकर दुनिया के हर जरूरतमन्द देशों तक पहुँच सकेगा। यदि विश्व व्यापार संगठन से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है, तो भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए दो व्यावहारिक लाभ उत्पन्न होंगें। एक तो भारत में बन रहे टीकों के लिए लाइसेंस का विस्तार करना आसान होगा, जो पहले ही भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को उनका उपयोग करने में अधिक सक्षम कंपनियों को दिए जा चुकें हैं। दूसरा अन्य स्वदेशी टीके भी पेटेंट उल्लंघन की चुनौतियों से मुक्त हो सकेंगें।

ट्रिप्स (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) विश्व व्यापार संगठन के तहत एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता है। ट्रिप्स समझौते पर पहली बार 1986–94 के उरूग्वे दौर के दौरान बातचीत हुई थी जिसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पेश किया गया था। इस समझौते पर डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों द्वारा 1 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर व्यापार विवादों को हल करने और सभी सदस्य देशों को अपने घरेलू उद्देश्यों को प्राप्त करने का आश्वासन देता है तथा ज्ञान और रचनात्मकता में व्यापार को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; जैसे कलात्मक अभिव्यक्ति, संकेत, प्रतीक और वाणिज्यिक डिजाइन तथा आविष्कार आदि। बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सरकारों को अपने आविष्कार, डिजाइन और अन्य कृतियों का उपयोग करने से दूसरों को रोकने का अधिकार प्रदान करते हैं। बौद्धिक सम्पदा में किताबें, पेंटिग और फिल्में कॉपीराइट के तहत आती हैं, आविष्कार पेटेंट के तहत और ब्रांड नाम तथा उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत कराया जा सकता है। प्रत्येक देश इन अधिकारों के माध्यम से ही रचनाकारों और आविष्कारकों को संरक्षण प्रदान करते हैं जिससे वे अपने इन आविष्कारों से समाज को लाभान्वित कर सकें।

इन अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की सीमा दुनिया भर में व्यापक रूप से भिन्न है और ये भिन्नतायें ही अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तनाव का कारण बन गयी हैं। ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि नई प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट संरक्षण उपलब्ध होना चाहिए। आविष्कारों में उत्पादों और प्रक्रियाओं दोंनो को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत यदि सरकार चाहें तो वह आविष्कार के लिये पेटेंट जारी कर सकती है, जब सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के कारणों से इसकी बिक्री को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। सरकार पेटेंट संरक्षण से नैदानिक,

चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा पद्धतियों, पौधों और उनके उत्पादन के लिये जैविक प्रक्रियाओं को भी बाहर रख सकती है। ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद IX.3 और IX.4 के अर्न्तगत असाधारण दशाओं में पेटेंट को माफ किया जा सकता है परन्तु ऐसी परिस्थितियों को चित्रित नहीं किया गया है जब दुनिया एक सदी में स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही हो। ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद–31 पेटेंट धारकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ शर्तों के तहत अपने मालिकों के प्राधिकरण के बिना अनिवार्य लाइसेंस और पेटेंट के सरकारी उपयोग की अनुमति देता है। सभी सदस्य देश स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के लिए ऐसे लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं; जैसे कि दवाएँ, टीके और निदान, उत्पाद या तकनीक जो कोविड–19 महामारी को नियन्त्रित करने में आवश्यक हैं। अनिवार्य लाइसेंस इस महामारी के अंतिम उपचार या टीकों तक पहुँच बढ़ाने के लिए एक नीति उपकरण के रूप में काम कर सकता है। कुछ सदस्य देशों ने तो अनिवार्य लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान भी किया है जिनमें कनाडा, जर्मनी, इस्राइल आदि प्रमुख हैं।

हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव का कई देशों ने विरोध भी किया जिनमें यूरोपीय यूनियन, यू.के., कनाडा और बड़ी दवा कंपनियाँ शामिल हैं। विरोधियों का मानना है कि यदि विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देती है तो इससे दवा और टीके के अनुसंधान पर असर पड़ेगा। नकली दवा या टीके के उत्पन्न होने की आंशका भी जताई जा रही हैं। बड़ी दवा कंपनियाँ इस प्रस्ताव के विरोध में इसलिये भी हैं कि यदि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में छूट मिल जाती है तो दवा कंपनियों को अपने लाभ भी साझा करने पड़ेंगें। इन विरोधों को दृष्टिगत न रखते हुए यदि उस दौर की समीक्षा की जाये जब 1990 के दशक में अफ्रीका में एच.आई.वी./एड्स का प्रसार एक विकराल रूप में सामने आया था। तब उस समय विकसित देशों द्वारा एड्स की 'ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी' दस हजार डॉलर सालाना प्रति मरीज की दर से उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु जब डब्ल्यू.टी.ओ. ने 2003 में बौद्धिक संपदा अधिकारों में कुछ छूट प्रदान की तब इससे अन्य देशों में भी विनिर्माण क्षमता का विकास संभंव हुआ तथा भारत की एक जेनेरिक दवा कंपनी ने इस दवा को महज दो सौ डॉलर में उपलब्ध कराया। नतीजतन, व्यापक पैमाने पर एड्स की दवा का उत्पादन शुरू हुआ और इस महामारी पर नियन्त्रण पा लिया गया। जहाँ आई. पी.आर. नियमों में ढील देने से विनिर्माण क्षमतायें विकसित होंगीं और विकासशील देशों में कंपनियां मुकदमों के डर के बिना टीकों का निर्माण कर सकती हैं। वहीं कुछ चुनौतियाँ भी सामने आयेंगीं क्योंकि इस प्रकार से दी गयी छूट प्रौद्योगिकी को स्थानान्तरित करने के लिये दवा कंपनियों पर बाध्यता नहीं डाल सकती।

वहीं दूसरी ओर भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव का सौ से भी अधिक देशों ने समर्थन किया। परन्तु इसमें अमेरिका का समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दवा निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियाँ अधिकतम अमेरिका में मौजूद हैं जो कच्चा–माल, तकनीक आदि अन्य देशों को स्थानान्तरित करती हैं। अमेरिकी सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन तो किया परन्तु उसने केवल कोविड–19 महामारी के टीकों तक ही बौद्धिक सम्पदा में छूट को सीमित रखा जबकि इन दोनों देशों ने कोविड–19 महामारी के उपचार से संबंधित दवाओं एंव अन्य चिकित्सीय तकनीकों पर छूट का भी प्रस्ताव रखा था।

निष्कर्ष

महामारी की वर्तमान स्थिति में अपर्याप्त विनिर्माण क्षमताओं के कारण तथा पेटेंट धारकों और आर एण्ड डी के उपयोग करने व लाइसेंस प्रणाली के सक्रिय प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान में दवाओं और टीके की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है। यह स्थिति एक पारदर्शी और विश्वसनीय कानूनी ढाँचे के महत्व को प्रकाशित करती है जो हितधारकों के लिये एक दूसरे के साथ विकास, उत्पादन एवं आगामी प्रभावी चिकित्सा उपचार तथा प्रौद्योगिकी के वितरण पर सहयोग करने के लिए एक आधार प्रदान कर सकती है। कोविड–19 महामारी ने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य प्रणालियों और व्यापार प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डाला है। महामारी को नियंत्रित करने में मदद करने वाली प्रौद्योगिकियों की तत्काल खोज ने अभूतपूर्व अनुसंधान प्रयासों और निवेशों को जुटाया है। कुशल नवाचार की पहले से अधिक आवश्यकता है, और नई प्रौद्योगिकियों के लिए समान पहुँच सर्वोपरि है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए आई.पी.आर. का कुशलता से प्रबंधन आवश्यक है। महामारी के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं, स्वास्थ्य, व्यापार और आई.पी.आर. तत्वों पर समग्र रूप से विचार करने तथा वैश्विक सहयोगात्मक प्रयासों की अब पहले से अधिक आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

- गुप्ता, अरविन्द; 2021, 7 मई, ताकि दुनिया में सबको मिले टीका– लाईव हिन्दुस्तान।
- Ranjan, Prabhash. (2021, 10 May). A TRIPS waiver is useful but not a magic pill. The Hindu. p.6.
- Goenka, Ramnath. (2021, 8 May). Potently Fair: Biden's Proposal for liberal IPR regime on Covid Vaccine is welcome. EU must shed its intransigence. The Indian Express. p.8.
- South Centre. (2020, 6 October). Proposal by India and South Africa to waive certain provision of the WTO TRIPS agreement to support the global Covid-19 pandemic response. pp.1-2.
- WTO, WIPO, WHO. (2020). Promoting access to Medical Technologies and Innovation. Second edition. pp.2-7.
- World Trade Organization. (2020, 15 October). The TRIPS Agreement and Covid-19. pp.1-2
- https://www.wto.org

22

कोरोना काल में समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन

डॉ0 दीप्ति गुप्ता
प्राचार्या व विभागाध्यक्षा (मनोविज्ञान विभाग)
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

वर्तमान में कोविड–19 महामारी के दौरान हमारी दिनचर्या में आए परिवर्तन और भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण हम तनाव से जूझ रहे हैं। कोरोना के भयावह होते हालात के बीच महामारी से उपजा तनाव हर किसी के लिए अलग तरह का अनुभव ला रहा है। उम्र, लिंग और यहां तक की जिम्मेदारियों के मुताबिक यह अवसाद लोगों पर भिन्न–भिन्न प्रभाव डाल रहा है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और निराशाजनक सोच आम परेशानियां हैं। अपने दोस्तों, सहपाठियों और हमउम्र साथियों से दूर होकर युवा और बच्चे अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं तो वरिष्ठ जन सामाजिक जुड़ाव की कमी और मेल मिलाप की दूरी से अवसाद और व्यग्रता के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों और बड़ों, दोनों में अवसाद उत्पन्न हो रहा है। साथ ही इस तकलीफदेह दौर में आर्थिक मोर्चे पर कामकाजी लोग स्वयं की नौकरी में अनिश्चितता और फिक्र से तनाव में रह रहे हैं। ग्रहणियों मे बढ़ी व्यस्तता उनके मन को थका रही है जिस कारण उनमें तनाव व्याप्त हो रहा है। कोविड–19 से जूझते हुए सोशल आइसोलेशन के चलते सभी ने कुछ हद तक भटकाव, अलगाव और अनिश्चितता का अनुभव किया है।

इस वैश्विक महामारी में तनाव में नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने देना है। यही अवसर है सामाजिक सरोकार एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए विभिन्न माध्यमों से स्वयं को बेहतर बनाने का। इस विपत्ति काल में एक अच्छी सोच व समझ भरा, सकारात्मक और उम्मीद भरा रास्ता ही जीवन को सहेजने और स्वस्थ रहने का सार्थक मार्ग बन सकता है।

मुख्य शब्द– कोविड–19, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, मानसिक तनाव, व्यायाम व मेडिटेशन, अकेलापन, अवसाद, सकारात्मकता एवं कृतज्ञता।

कोरोना वायरस महामारी ने विश्व भर के करोड़ों लोगों की पूरी दिनचर्या को बिगाड़ कर रख दिया है। महीनों से जारी कोविड–19 के चलते लोगों को अपने घरों में ही कैद होकर रहना पड़ रहा है। उनका समय "इस महामारी से कैसे बचाव किया जा सकता है?" यही सोच कर गुजर रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक (लॉकडाउन) और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस बीच चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बन गया है और मानव दिन–रात इससे जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना आपदा के चलते व्यक्ति "फीयर आफ मिसिंग आउट" के भाव से भी जूझ रहे हैं जिस कारण इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। हाल के सर्वे के अनुसार भारत में 89 प्रतिशत लोग तनाव का शिकार हैं जबकि वैश्विक औसतन 86 प्रतिशत है। यदि समय पर तनाव का प्रबंधन नहीं किया गया तो हृदयाघात एवं लकवा जैसे घातक रोगों से जूझना पड़ सकता है।

लोगों के लिए पूरा माहौल बदल गया है। अचानक से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस बंद हो गए हैं। बाहर नहीं जाना है और दिन भर कोरोना वायरस की ही खबरें देखनी सुननी हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। इसकी वजह से तनाव, चिंता व घबराहट की परेशानी से सभी को गुजरना पड़ रहा है जो कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही इस महामारी के प्रभाव के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों लोगों के ऊपर रोजगार छिनने का संकट पैदा हो गया है। इसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है जो पारिवारिक तनाव, चिन्ता, घबराहट और मानसिक परेशानियों के तौर पर सामने आ रहा है।

संक्रामक रोगों का सभी पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उन पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं हैं। इस बीमारी को लेकर हमारी प्रतिक्रिया मेडिकल ज्ञान पर आधारित ना होकर हमारी सामाजिक समझ से भी संचालित होती है। किसी वैश्विक महामारी का मनोवैज्ञानिक परिणाम सामाजिक ताने–बाने पर भी असर डालता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक ब्राक चिशहोम जो कि एक मनोरोग चिकित्सक भी थे उनकी प्रसिद्ध उक्ति है "बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता"। उनके यह शब्द इस बात का समर्थन करते हैं कि सालों की रिसर्च के बाद इस बात को लेकर कोई भी संशय नहीं रह गया है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर और अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।

ऐतिहासिक रूप से संक्रमणकारी महामारियां आम लोगों में चिंता और घबराहट को बड़े पैमाने पर बढ़ाती हैं। 2003 में सार्स के प्रकोप के दौरान शोधकर्ताओं ने बीमारी के साथ–साथ आने वाली कई मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को भी रेखांकित किया जिनमें अवसाद, तनाव, मनोविकृति और पैनिक अटैक शामिल हैं। वर्तमान में कोविड–19 से प्रभावित लोगों के अनुभव को समझने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति को बनाने के लिए इन कारकों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा करके ही उनके मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। संक्रामक रोग सभी लोगों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, उन लोगों पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं हैं।

इंटरनेट के युग में हम ज्यादातर सूचनाएं ऑनलाइन हासिल करते हैं। यह एक व्यावहारिक परिवर्तन है जिसने स्वास्थ्य विषय पर लोगों के आपसी संवाद को क्रांतिकारी तरीके से बदल कर रख दिया है। मिसाल के तौर पर ट्विटर पर स्वाइन फ्लू के प्रकोप का विश्लेषण करने के लिए किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि ट्विटर यूजर्स ने इन दोनों बीमारियों को लेकर गहरे डर का इजहार किया।

किसी आघात के बाद के तनाव से जूझ रहे लोग या खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने वाले और किसी बीमारी से ग्रसित हो जाने को लेकर आशंकित रहने वाले लोगों को पैनिक अटैक आ सकता है और वह ज्यादा तनावजन्य प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण

दुनियाभर में फैली कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर के लोगों में बीमारी और सामाजिक दूरियां बढ़ने के कारण आज लोगों में डर, तनाव और चिंता पैदा कर दी है। मनोवैज्ञानिकों ने इस महामारी जैसी बीमारी में तनाव को मुख्य कारण बताया है क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस महामारी के बारे में सुनकर तनाव में आ सकता है।

कोविड–19 जैसी महामारी के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों में इस बीमारी के फैलने, स्वास्थ्य की देखभाल करने और मरने के कारण लोगों के काम और अपनों से सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं जिससे व्यक्ति में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसलिए लोग परिवार में किसी व्यक्ति के संक्रमित होने पर उनकी रक्षा एवं देखभाल करने से डरे हुए हैं, जिस कारण संक्रमित व्यक्ति अकेलापन तथा अवसाद के शिकार हो रहे हैं।

इन समस्याओं के अलावा मनोवैज्ञानिकों ने कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस बीमारी के कारण आज लोगों में अन्य बीमारियों के बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिनका लोगों को एहसास भी नहीं हो पा रहा है, जैसे कि घर में माता पिता के काम बंद होने के कारण और बच्चों के स्कूल बंद होने की वजह से उनके बारे में चिंता करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

व्यक्तियों के परेशान होने की तीन वजह है––

1– कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर

2– नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और

3– लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन।

मानव शरीर पर तनाव का प्रभाव

इन महामारी स्थितियों का असर यह होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है। सामान्य स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है तब यह होता है कि हमें कोई आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता, तब घबराहट होती है। ऊर्जाहीन महसूस होता है। फिलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता और उलझन है कि कब तक सब ठीक होगा, पता नहीं। ऐसे में सभी के तनाव में आने का खतरा बना हुआ है।

इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। हर व्यक्ति पर इसका अलग–अलग प्रभाव दिखाई देता है जैसे–

- **शारीरिक प्रभाव–**

  इसके अंतर्गत व्यक्ति को बार बार सिर दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, थकान और ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना आदि लक्षण महसूस होते हैं।

- **भावात्मक प्रभाव–**

  इसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, चिंता, डर, गुस्सा, उदासी और उलझन पैदा हो सकती है।

- **मस्तिष्क पर प्रभाव–**

  ऐसे में व्यक्ति क्या सही है क्या गलत नहीं समझ पाता। बार–बार बुरे स्वप्न मन में आते हैं जैसे मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परिवार का निर्वहन कैसे होगा आदि।

- **मानव व्यवहार पर प्रभाव–**

  ऐसे समय में व्यक्ति नशीले पदार्थों का ज्यादा सेवन करने लगता है जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटका आदि। कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है व चुप रहने लगता है और कोई चीखने चिल्लाने लगता है और कोई ज्यादा टीवी देखने लगता है।

तनाव प्रबंधन

तनाव प्रबंधन से आशय है मानसिक तनाव में कमी लाना। वाटर कैनन और हैंस सेल्ये ने तनाव के अध्ययन पर आरंभिक वैज्ञानिक आधार स्थापित करने के लिए जानवरों पर प्रयोग किया। उन्होंने बाहरी दबाव में पशुओं की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जैसे गर्मी और सर्दी में लंबे समय तक संयम में और शल्य चिकित्सा की प्रतिक्रियाओं में और इन अध्ययनों से मानव प्रणाली को विकसित किया।

संगठित व्यवहारिक मॉडल–

1984 में रिचर्ड लैजारस और सूजैन फोकमैन ने सुझाव दिया कि तनाव मांग और संसाधनों के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप भी होता है अथवा किसी के सहने की क्षमता से अधिक दबाव में भी हो सकता है।

तनाव प्रबंधन और विकास के विचार पर आधारित है कि तनाव एक तनावग्रस्त के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक संसाधन है, जिसमें तनाव की प्रतिक्रिया में सहने की क्षमता, पक्ष को बदलने की क्षमता और मध्यस्थता की अनुमति से तनाव पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

नियमानुसार एक प्रभावी तनाव प्रबंधन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर केंद्रित कारकों की पहचान, जो तनाव पर प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं। लैजरस और फोक मैन की व्याख्या के अनुसार "तनाव व्यक्तियों और उनके बाहरी वातावरण के बीच संगठित व्यवहार पर केंद्रित है"। तनाव प्रबंधन में व्यक्ति के तनाव का विश्लेषण किया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने तनाव की वजह का मूल्यांकन करता है और अपने संसाधनों के द्वारा तनाव पर काबू पाता है।

स्वभाविक स्वास्थ्य मॉडल–

स्वभाविक स्वास्थ्य मॉडल सोच की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहता है कि अंततः यह एक व्यक्ति की सोच की प्रक्रिया है कि वह संभावित तनावपूर्ण बाह्य परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस मॉडल में तनाव का कारण है कि ऐसे समय में अपने आप का मूल्यांकन करना जब असुरक्षा और नकारात्मकता की भावना की परिस्थिति हो। ऐसी अवस्था में शांत दिमाग, आंतरिक ज्ञान और सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर अच्छा महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल शांत दिमाग, आंतरिक ज्ञान और सामान्य बुद्धि को कायम रखते हुए इस मॉडल का प्रस्ताव है कि तनाव ग्रस्त व्यक्तियों की मदद उनकी सोच की प्रकृति को समझ कर करनी चाहिए। विशेष रूप से उन्हें पहचानने के लिए व क्षमता प्रदान करने के लिए, जब वे असुरक्षित सोच की चपेट में हो, उन्हें इससे छुड़ाना है और उन्हें बल देना है कि वे अपनी प्राकृतिक सकारात्मक भावनाओं का उपयोग करें जिससे उनका तनाव कम हो जाएगा।

तनाव प्रबंधन की तकनीक–

समय प्रबंधन की कुछ तकनीकें किसी व्यक्ति के तनाव को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आकृति में जब मांग उच्च हो तो प्रभावी तनाव प्रबंधन सीखने की सीमा तय करने के लिए दूसरों की कुछ मांगों को ना कह देना चाहिए। निम्नलिखित तकनीक को हाल ही में डीस्टैसेलाइजर कनाडा के मेडिकल एसोसिएशन के जनरल द्वारा बताया गया है।

डीस्टैसेलाइजर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के तनाव को दूर किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन की तकनीक सैद्धांतिक प्रतिमान के अनुसरण के अनुसार भिन्न हो जाएगी लेकिन उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं जिनको चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है वरना तनाव अंतहीन हो सकता है। कुछ तरीकों के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें। सकारात्मक विचारों से ओजपूर्ण कैसे रहें और तनाव को कैसे कम करें ? तनाव को निम्नांकित उपायों के माध्यम से दूर करें–

1. खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा और पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी है। बस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें।
2. अपने रिश्ते को मजबूत करें, छोटी बातों का बुरा ना माने। एक दूसरे का ध्यान रखें। नकारात्मक विषयों पर परिचर्चा ना करें।
3. लॉकडाउन के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते परंतु हम घर की छत, खिड़की, बालकनी या घर के बगीचे में आकर खड़े हो सकते हैं। सूरज की रोशनी से भी हम अच्छा महसूस करते हैं।
4. अपनी दैनिक दिनचर्या को बनाए रखें। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना, पीना और व्यायाम करें।
5. इस समय का सदुपयोग आप अपनी हॉबी पूरा करने में करें। वह मनपसंद काम करें जो समय ना मिलने के कारण आप नहीं कर पाए। इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी।
6. अपने मन के डर, उदासी को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को अपने परिजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें।
7. सबसे जरूरी बात है कि हम इस बुरे वक्त में भी अच्छे पक्षों पर गौर करें। जैसे अभी महामारी है लॉकडाउन है, इस बीच आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है इस अवसर पर भी ध्यान दें।
8. मेडीटेशन करें।

कोरोना काल में समय प्रबंधन–

इस महामारी के संकट के समय हम स्वयं को अवसाद से कैसे दूर रखें? इस हेतु समय प्रबंधन अत्यंत जरुरी है। अगर कुशल समय प्रबंधन होगा तो तनाव स्वतः ही कम हो जायेगा। समय प्रबंधन एवं साथ ही तनाव प्रबंधन निम्नांकित उपायों के माध्यम से करें–

- **स्वयं के पास बैठें–** कोविड–19 ने सबको अपने पास बैठा दिया है। जब व्यक्ति स्वयं के पास बैठता है तो ताकतवर बनता है। अभी यह समय परिजनों के पास बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से रूबरू होने का है।
- **सकारात्मक रहें–** हमारा देश, समाज, परिवार एवं परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस समय सकारात्मक विचारों को बनाए रखने के लिए बहुत सा साहित्य उपलब्ध है। मुख्य रूप से गीता और रामायण को पढ़ें। इन्हें आत्मसात करें। इससे मन शांत रहेगा, जीवन को ताकत मिल सकती है। साथ ही अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच सकते हैं। सकारात्मकता आपके पास ही है। खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमारे पास ही हैं।
- **प्रकृति के नजदीक रहें–** सबसे पहली जरूरत तो यह है कि इस समय व्यक्ति प्रकृति की सेवा कर सकता है। जो भी व्यक्ति जैसी भी स्थिति में है, जहां पर भी है प्रकृति की सेवा कर सकता है। जैसे पौधे लगाना, बागवानी करना व गमलों में पानी देना आदि। प्रकृति के करीब आने से समय का ज्यादा उपयोग हो सकता है।
- **बुजुर्गों के अनुभव से सीखें**– हम हमारे बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। उनके पास तजुर्बा है। युवाओं एवं घर के अन्य सदस्यों को उनके पास बैठना चाहिए। बुजुर्गों को बच्चों और युवाओं को अपने पास बैठा कर अपने अनुभवों के साथ कहानियां सुनानी चाहिएं। हर बुजुर्ग को अपने बच्चों को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुषों एवं पंचतंत्र की कहानियां सुनानी चाहिएं। इससे बच्चों में संस्कार पल्लवित होंगें। वर्तमान समय में हम बच्चों को संस्कार तो दे ही सकते हैं, यह उनके जीवन भर काम आएंगें। बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं।
- **तन–मन दोनों को स्वस्थ रखें–** पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं को सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए अपने अंदर गुणात्मक सुधार करना चाहिए। ई लर्निंग का सहारा ले ऑनलाइन कोर्स व व्यवसाय करें। बुजुर्ग महिलाओं से पुराने खानपान के बारे में सीखें। पौष्टिक आहार बनाएं। दादी–नानी की रसोई का खाना इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ही एवं सुरक्षित भी रखेगा।
- **व्यायाम करना–** शरीर को स्वस्थ रखने का आसान तरीका है श्रम करना। अपना काम स्वयं का स्वयं करें। प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें एवं ध्यान करें। पारंपरिक तरीकों को अपनाएं। घर के नौकरों पर निर्भर ना रहें। इन छोटी–छोटी बातों से ना सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है बल्कि तनाव भी दूर होगा।
- **कृतज्ञता का भाव रखें–** जब तक इंसान कृतज्ञ नहीं होगा, वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। हमारी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। परिजनों, बड़े बुजुर्गों, पंचतत्व के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। स्वच्छता की कृतज्ञता को अपनाते हुए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। पुराने समय में कृतज्ञता बहुत होती थी। उस समय हर कृतज्ञता के आगे नमः शब्द जुड़ा होता था। यह नमः शब्द अब संस्कारों में गायब हो गया है। हर व्यक्ति को इस शब्द को आत्मसात करना चाहिए। किसी ना किसी काम में इसे

तलाश लेना चाहिए। इससे अंदर का माहौल बदल जाएगा। हर कारण के लिए हम तीन बार धन्यवाद देने की आदत डालें। इसमें मां को धन्यवाद दें, पानी भी पिएं तो प्रकृति को धन्यवाद दें। यह कृतज्ञता किसी भी कार्य के लिए हो सकती है।

- **खबरों की ओवरडोज ना लें**– आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर चारों तरफ कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आ रही हैं। छोटी, बड़ी, सही, गलत खबर लोगों तक पहुंच रही है। डॉक्टर्स के अनुसार इससे भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि उसे एक ही तरह की बातें सुननी–देखनी पड़ रही हैं और फिर वही सोच रहे हैं। इसलिए सीमित खबरों को ही सुने और अपने विचारों में सकारात्मकता का दृष्टिकोण विकसित करें।

निष्कर्ष

इस प्रकार धैर्य, संयम, आत्मविश्वास व तनाव रहित जीवन से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानीपूर्वक लड़ने की आवश्यकता है। तनाव व अवसाद को निष्क्रिय करने के लिए योग व व्यायाम के नियमित अभ्यास पर जोर दिया जाए। चिंता व तनाव को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। हर व्यक्ति में असीम क्षमता होती है, जब आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा तो तनाव का स्तर घटेगा। एन०एस०एस० और यूनिसेफ की ओर से चलाए जा रहे अभियान "ना डरना है, ना घबराना है, मिलकर कोरोना को हराना है", के माध्यम से युवाओं को इस कठिन अवधि से संघर्ष करने में मदद मिलेगी।

संदर्भ सूची–

1. कैनन डब्ल्यू० (1939) – द विजडम ऑफ द बॉडी, दूसरा संस्करण नॉर्टन पब्स
2. लैजरस, आर० एस० एंड फोक मैन, एस० (1985) तनाव, मूल्यांकन और मुकाबला, न्यूयॉर्क, स्प्रिंगर,
3. मिल्स आर० सी० (1995) रियलाइजिंग मेंटल हेल्थ टुवार्ड ए न्यू साइकोलॉजी ऑफ रेसिलियंसी सल्बर्गर एंड ग्राहम पब्लिशिंग लिमिटेड।
4. सेजमैन जे० ए० (2005)
5. Lehrer. Paul. M: David H. (FRW) Barlow. Robert L. Woolfolk. Wesley E. Sime (2007), Principles and Practice of Stress Management, Third Edition
6. Bower J.E. & Segerstrem, S.C. (2004), "Stress Management, finding benefit and immune function: Positive mechanisms for intervention effects on physiology", Journal of Psychosomatic research
7. Selye. H. (1950), "Stress and the General adaptation syndrome" Br. Med. J. 4667:1383&92PMID15426759

23

कोविड-19 का दूसरा चक्र : चुनौतियाँ एवं तैयारियाँ

नीरज कुमार
शोध छात्र–वाणिज्य
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उ0प्र0

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता
एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय
साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद

सारांश

कोविड–19 महामारी का प्रकोप भारतीय अर्थव्यस्था के लिए भयावह और अभूतपूर्व झटका है। कोरोना वायरस अब तक पूरी दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अगर इतिहास में देंखें तो कोविड–19 जैसी महामारी अब तक नहीं देखी गयी है। इसकी लहर का बार–बार आना किसी भी महामारी का सहज बर्ताव ही है। भारत इस समय हम कोविड–19 की दूसरी लहर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में भी महामारी के शिकार लोगो की संख्या तेजी से बढती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड–19 भी पहले की महामारियों की तरह ही मौसमी बीमारी में तब्दील हो जायेगी। सरकारें इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कार्य कर रही हैं।

मुख्य शब्द–भारतीय अर्थव्यवस्था, महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, टीकाकरण

इस समय पूरा देश महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है। अभी भी पूरे देश में महामारी कानून के प्रावधान लागू हैं और ज्यादातर राज्यों में बहुत अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। परन्तु इन प्रतिबंधों को बार–बार पूरी हठधर्मिता के साथ सार्वजनिक रूप से तोडा जा रहा है। सभी राज्यों में मौजूदा कोविड के दूसरे चक्र का प्रमुख कारण महामारी को लेकर भय न होने के कारण लोगों का नियमों को तोड़ने वाला बर्ताव, महामारी के उपरांत लगी पाबंदियों से परेशानी, संक्रमित लोग जिनका सही रूप से पता नहीं लग पाया है और सुपर स्प्रेडर, और हाल ही में हुए ग्राम पंचायत एवं विधानसभा के चुनाव, शादी का सीजन और स्कूल खोलने व सार्वजनिक परिवहन में भारी भीड़ है। यदि संक्षेप में कहा जाये तो महामारी की रोकथाम के सभी नियमों का ताक पर रख दिया गया है।

राजनीतिक दल इस बात के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं कि उन्होंने महामारी के प्रकोप के दौरान बड़ी–बड़ी राजनीतिक सभाएं करनीं जारी रखीं। भारत के विभिन्न राज्यों में हुए पंचायत चुनाव एवं विधानसभा के चुनाव के लिये स्थानीय स्तर पर हुए सघन प्रचार अभियान के फौरन बाद कोविड की लहर फैलनी शुरु हो गयी थी। पश्चिम बंगाल में भी विधान सभा के चुनावों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विशाल सभाएं करने के बाद नए मामले तेजी से दिखने लगें हैं। यह स्वाभाविक है कि रैलियों में लाखों लोगों का जुटना कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान इतिहास से भी कोई सबक नहीं लेता है। ऐसी ही महामारी सन 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम से फैली थी।

पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में 'शादी के सीजन' के चलते बड़े पैमाने पर संक्रमण की बहुत सी घटनायें देखने को मिली हैं। आज भी शादी ब्याह में सैकड़ों लोग एक बड़े हॉल में एकत्र होते हैं और दो गज़ की दूरी के बगैर शादी का जश्न मना रहे हैं। ये भी महामारी फैलने का एक बड़ा कारण है।

सरकार का जनता से सही तरीके से संवाद और जानकारी का प्रसार, इस महामारी के शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रहा था। लेकिन, बाद में इसमें भी सरकार के द्वारा लापरवाही बरती गयी। बहुत से लेखकों द्वारा ये दावा किया गया कि भारत में कोविड–19 महामारी की दूसरी बड़ी लहर आने की आशंका न के बराबर है क्योंकि उनको लगा कि भारत ने हर्ड इम्युनिटी विकसित करली है। केंद्र सरकार की ओर से भी जो संकेत मिले उनसे सबको ऐसा ही लगा कि भारत ने कोविड–19 महामारी को हराने में सफलता पा ली है। इसी कारण से महामारी के खिलाफ इस जंग में ढिलाई बरती गयी, और तो और सरकार ने संक्रमण को रोकने के उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में जब मरीजों के लिये बैड पाने का हाहाकार मचने लगा, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार इस हालत की गंभीरता के बारे में लोगों को समझा पाने में नाकाम रही।

इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा से संख्या में लोगों का टीकाकरण करना। इसी उपाय से इस महामारी की रोकथाम की जा सकती है। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस को भी स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर टीका लगाकर ही रोका जा सका

है। अब चूँकि भारत में ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो गया है तो ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि अब युद्ध स्तर पर लोगों का टीकाकरण किया जाये, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि ज्यादा जोखिम वाली आबादी का प्राथमिकता पर टीकाकरण किया जाये।

अब यह भी पाया गया है कि कोविड–19 टीके का प्रभाव 80 प्रतिशत के आसपास ही है, तो स्वाभाविक है कि टीके के बाद भी इसके लक्षण दोबारा दिखाए दें परन्तु इससे मृत्यु दर में गिरावट अवश्य आयेगी। इजरायल जैसे देश में कुल आबादी के 60 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण हो चुका है और वहां पर जिंदगी पहले की तरह लगभग सामान्य हो चुकी है। इस देश से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोविड–19 के चलते मृत्यु दर में गिरावट लाने का फायदा यह होगा कि फिर कोरोना एक मौसमी सर्दी खांसी वाला विषाणु बनकर रह जायेगा, सरकार को इसी लक्ष्य को पाना बहुत हद तक अच्छा होगा। पीछे मुड़कर देंखें तो पता चलता है कि बीमारियों की वैक्सीन के परिणाम अलग–अलग देखने को मिलते हैं–

- चेचक की वैक्सीन बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध ही थी, जिसके कारण यह बीमारी जड़ से खत्म हो पाई।
- इसी प्रकार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी कारगर साबित हुई थी।
- दूसरी और खसरा, रोटा वायरस, काली खांसी जैसी बीमारियों की वैक्सीन वायरस के खतरे को कम कर सकती है, परन्तु पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाती है।

कोविड वैक्सीन के तीनो चरणों के लैब परीक्षण में इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि यह लक्षणों की तीव्रता को निश्चित रूप से कम करने में सक्षम है। इस प्रकार यह वैक्सीन जीवन रक्षक तो है ही, इसमें रोग की गंभीरता के कम होने से स्वास्थ्य सेवा पर पड़ने वाले भार को भी कम किया जा सकेगा। यह एक सामान्य तथ्य है कि लक्षणों की तीव्रता को कम करने वाली औषधि रोग के संक्रमण को भी कम करती है। दूसरे, वैक्सीन से हर्ड इम्युनिटी को जोड़कर देखा जा रहा है जो बहत हद तक सही भी है। हर्ड इम्युनिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैक्सीन की क्षमता और टीका लेने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को मिलाकर चलती है। परन्तु इसके लिए देश की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या में कोरोना प्रतिरोधक क्षमता का होना आवश्यक प्रतिशत है, और यदि वैक्सीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता 60 प्रतिशत ही है तो हमें 100 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण करना होगा। निवारण करने के बजाय उपलब्ध आवरण का प्रयोग ही उचित है। वैक्सीन से मिलने वाले सुरक्षा कवच को नकारा नहीं जा सकता है। हमें इसका लाभ लेते हुए सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा।

कोविड–19 पर तथ्यों को जांचे–परखें और अफवाहों से बचें

कोविड–19 महामारी अभूतपूर्व है और दुनिया भर में अपने पैर पसार चुकी है। इस समय भारत में यह बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है, बैड, ऑक्सीजन, के लिये हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में घबराहट है, काफी लोग तो अफवाहों से घिरे हुए हैं।

कोविड–19 आपदा से लड़ने के लिए हजारों स्वास्थ्यकर्मी और पत्रकार दिन–रात काम कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है जो सोशल मीडिया पर कोविड–19 संबंधित अफवाहें और गैर प्रामाणिक जानकारी फैला रहे हैं, हमारे चारों ओर कोविड–19 वायरस पर समाचारों का विस्फोट हो रहा है, ऐसे में हम नागरिकों के लिए फर्जी खबर और वैज्ञानिक तथ्यों में अंतर करना अति आवश्यक हो जाता है। कोविड–19 की खबरों में गलत सूचना और नकली खबर हमें अकल्पनीय स्तरों पर ले जाती है।

हाल ही में ईरान में 40 से अधिक लोगों ने जहरीले एल्कोहल का सेवन किया और इस गलत धारणा पर विश्वास किया कि एल्कोहल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। आज भारत सहित पूरा विश्व कोविड–19 महामारी के साथ–साथ भ्रामक खबरों से भी जूझ रहा है। अज्ञात स्रोतों से एक खबर सामने आई कि गरम पानी से स्नान करने पर कोविड–19 के संक्रमण को कम किया जा सकता है, डब्लू.एच.ओ. ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि गरम पानी से स्नान करने से आप कोविड–19 के संक्रमण से अपने आपको नहीं बचा सकते हैं। यह भी दावा किया गया कि अत्यधिक गरम तापमान या ठन्डे तापमान पर कोरोना वायरस समाप्त हो सकता है। डब्लू. एच.ओ. की वेबसाईट ने इस दावे को भी खारिज किया है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया है कि 10 सेकेंड तक सांस रोककर रखना कोविड–19 के लिए एक प्रभावी परीक्षा है और नियमित रूप से पानी पीने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। यें तथ्य भी असत्य हैं, नियमित पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर है परन्तु कोविड–19 से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। चाइना के एक शोध पत्र ने यह अफवाह फैलाई कि धुम्रपान, एल्कोहल से इस वायरस को कम किया जा सकता है, तत्पश्चात चीन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने शोध पत्र के निष्कर्षों का खंडन किया है। दुनिया में कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है कि निकोटिन का कोई एंटी वायरल प्रभाव है, बल्कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर ही करता है।

कोविड–19 पर विश्वसनीय स्रोतों पर प्रकाशित वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करें

कोविड–19 से बचाव के लिए दिशा निर्देश आज लगभग सभी माध्यमों में दिखाई पड रहे हैं। चिकित्सकों और डब्लू.एच.ओ. के मुताबिक अन्य व्यक्तियों से, कम से कम 2 मीटर की दूरी बनायें रखें, विशेष रूप से उन लोगों से दूरी अवश्य बनायें जो सांस लेने में तकलीफ में हैं, या जो छींकते नजर आते हैं।

आवश्यक है कि अपने आपको, समाज को कोविड–19 पर गलत सूचनाओं और नकली समाचारों के गर्त से बाहर निकालें। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य निभाएं। निम्नांकित संस्थाओं, वेबसाइट और उनमें मौजूदा आंकड़ों का सन्दर्भ लें–

विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् भारत सरकार, विज्ञान समाचार, प्रेस सूचना ब्यूरो आदि।

निष्कर्ष

कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। टीकाकरण कोविड–19 के गंभीर और घटक रूपों के विकास के खिलाफ बढ़ी हुई सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसी समय देश में कोविड–19 के लिए कथित जोखिम को घटाने के लिए स्वास्थ्य संवर्द्धन सामग्री को डिजाईन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा अन्य उपाय जैसे कि एस.एम.एस. उपाय (सैनिटाईजर, मास्क, डिसटेन्सिंग) का पालन कराना भी आवश्यक है। टीकाकरण, संक्रमितों को मानसिक सहायता, सामाजिक समर्थन, संतुलित आहार, सार्वजनिक विश्वास की स्थापना और कोविड–19 की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने सहित विभिन्न उपचारों का संयोजन वैश्विक महामारी से संघर्ष में अवश्य ही मदद करेगा।

संदर्भ

- डब्लू.एच.ओ. कोविड–19 वैक्सीन (इन्टरनेट), विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
- कोविड–19 विनियामक पैकेज (संशोधित), आर.बी.आई. मार्च 2021
- द हिन्दू–विभिन्न अंक
- दैनिक भास्कर– विभिन्न अंक
- www.india.gov.in

24

लॉकडाउन, प्राकृतिक पर्यावरण एवं महामारी- अन्तर्सम्बन्ध

डॉ0 बी. पी. सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग
एस0 वी0 पी0 जी0 कालेज, अलीगढ़

सारांश

पेड़–पौधे हमारे जीवन के रक्षक हैं। वे हमें प्राण–वायु प्रदान करते हैं तथा प्राणियों द्वारा निष्कासित कार्बनडाइआक्साइड का अवषोषण करते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन चक्र सहज रूप से निरंतर चलता रहता है। लेकिन दुःख की बात है कि कुछ स्वार्थी तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन पेड़–पौधों की बेरहमी से कटाई में जुटे हैं, जो हमारे पोषक हैं। इसके फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, और मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन प्राकृतिक पर्यावरण के लिए वरदान है। वर्तमान में लॉकडाउन से प्राकृतिक पर्यावरण में काफी सुधार हुआ है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि में उल्लेखनीय कमी आयी है। सरकार को लॉकडाउन के दौरान एवं लॉकडाउन के बाद भी देश के नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूक करते रहना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण स्वस्थ होगा तो महामारियों का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम होगा।

प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जीवन का आदिकाल से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। प्रकृति की साझेदारी में वायुमण्डल, जलमण्डल, और जैवमण्डल का एक निश्चित अनुपात रहा है। प्रकृति और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। मानव तथा अन्य प्राणियों की आवश्यकतायें प्रकृति से ही पूरी होती हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के महत्व को समझते थे, इसलिए हमारी प्राचीन शिक्षा–पद्धति प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित थी।

जिन पंच तत्वों से मानव को जीवन मिलता है वे हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। वे पंचतत्व हैं– पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और पवन। जीवन समाप्त होते ही ये पॉचों तत्व प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन को चलाने में प्रकृति के महत्व को ध्यान में रखकर मनुष्य को प्रकृति संरक्षण में अपना दायित्वपूर्ण कर्तव्य निभाना चाहिए।

मनुष्य प्रकृति की एक अनमोल एवं विलक्षण रचना है। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ और अधिक समझदार है क्योंकि वह अपने और परहित के बारे में सोच सकता है। परन्तु बिडम्बना यह है कि स्वार्थी मनुष्य अपनी खुशहाली और अधिकाधिक सुख–सुविधाऐं पाने के लालच में प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने के उद्देश्य से नई–नई तरकीबें खोजने में लगा है। स्वार्थ में लिप्त मानव को यह नहीं मालूम कि उसके द्वारा प्रकृति के अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन जिस तेजी से बिगड़ता जा रहा है उसका खामियाजा अन्ततः मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है। प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ कर वह अपने की पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए प्रकृति के साथ सतत एवं उचित सामंजस्य बनाए रखने में ही मनुष्य की समझदारी की परीक्षा है।

भारत में जनसंख्या जैसे–जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही मनुष्य की आवश्यकताऐं भी अधिक बढ़ती जा रही हैं। खाद्यान की पूर्ति के लिए अधिक अन्न उत्पादन की जरूरत हो रही है। फलतः वन–भूमि को कृषि–भूमि में बदलने का सिलसिला जारी है और वन–क्षेत्र घटता जा रहा है। आबादी के बढ़ने से मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काट कर कल–कारखाने लगाए जा रहे हैं। इससे भी वन–क्षेत्र घटने लगा है। वन–क्षेत्र की कमी होने से वन्य पशु–पक्षी और वनस्पतियॉ प्रभावित हो रहीं हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मनुष्य को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदायें झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना–19 महामारी, भूकम्प, अनावृष्टि एवं अन्य आपदाओं के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है।

प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़–पौधे, पशु–मानव सब मिलाकर पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में इन सबकी मात्रा और रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहे। विगत करोड़ों वर्षों से जब से पृथ्वी पर मनुष्य, पशु–पक्षी और अन्य जीव और जीवाणु उपभोक्ता बनकर आये, तब से प्रकृति का यह चक्र निरन्तर चल रहा है।

सन् 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 54 करोड़ 50 लाख थी, जो अब सन् 1994 के प्रारम्भ में 5 अरब 86 करोड़ के आस–पास हो गई, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 79 अरब है। जिन देशों ने इस चेतावनी को समझा और उसके लिए कार्य योजनायें बनायीं, वे

आज भी पर्यावरण के कई संकटों से प्रभावित नहीं हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन आदि।

प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चिन्तन बहुत पुरानी बात नहीं है। केवल पिछले 50 वर्षों में कुछ ऐसी घटनाऐं घटित हुई हैं जिसमें अप्रत्याशित रूप से मानव और पशुओं की जानें गईं हैं। फलस्वरुप प्राकृतिक पर्यावरण की दिशा में अनेक चर्चाऐं, विचार–विमर्श और सेमीनार हुईं हैं।

भारत में पिछले वर्षों में अनेक योजनाऐं बनायीं गयीं और कई प्रकार के प्रयास किये गये परंतु परिवार नियोजन, वृक्षारोपण आदि योजनाओं के पूर्व निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सके। ऑकड़ों के अनुसार पिछले 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.8 प्रतिशत हो गई है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन ने राष्ट्रीय लक्ष्य रखे और उन्होंनें सख्ती से ठोस योजना के क्रियान्वयन से उन्हें प्राप्त किया।

भारत एक विशाल देश है जोकि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है, किन्तु जनसंख्या 17.8 प्रतिशत है। यहॉ की विभिन्न ऋतुऐं मनुष्य के स्वास्थ्य और सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक है। यहॉ के विस्तृत भू–खण्ड में पहाड़, झीलें, नदियों, झरने, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियॉ, औषधीय जड़ी–बूटियॉ और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खनिज पदार्थ हैं। यद्यपि यहॉ का पर्यावरण सभी प्राणियों को स्वस्थ्य और सुखी जीवन की सुविधाऐं प्रदान करने में सक्षम है, फिर भी उसका आवश्यकता से अधिक दोहन करना प्राकृतिक–आपदाओं को आमंत्रित करना होगा।

लॉकडाउनः– प्राकृतिक पर्यावरण हेतु वरदान

सरकार का; मानव को ऐसे पर्यावरण में, जिसमें वह सुखी और मर्यादा पूर्ण जीवन जी सके, तथा जहॉ स्वतन्त्रता, समानता और रहन–सहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, जीने का मूलभूत अधिकार हो और साथ ही उसके वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित और सुधरे हुए पर्यावरण को उपलब्ध कराने का; महत्वपूर्ण दायित्व है।

उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा कोरोना–19 महामारी से मनुष्यों के जीवन को बचाने हेतु वर्तमान परिवेश में लॉकडाउन समय की जीवनदायनी मॉग है। लॉकडाउन का भी संयमित एवं संतुलित प्रयोग सरकार समय–समय पर महामारी के प्रसार एवं दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सफलतापूर्वक कर रही है। भारत के प्रमुख राज्यों उ0प्र0, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडू, केरल, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में लॉकडाउन का महामारी रोकथाम पर तथा प्राकृतिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव आया है।

लॉकडाउन लगाकर सरकार विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगा रही है ताकि देश में मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण संतुलित, स्वच्छ एवं महामारी को रोकने में असरदार बन सके। समय–समय पर लगाए गए लॉकडाउन के द्वारा सरकार ने देश में औद्योगिक क्रियाओं पर तथा मानव की अन्य आर्थिक एवं आर्थिक क्रियाओं पर, अनावश्यक आवागमन पर आदि पर अंकुश लगाने की कोशिश करी है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार लॉकडाउन अवधि में पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय कमी आई है तथा प्राकृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

किंतु अत्यधिक लंबा लॉकडाउन किसी भी समाज एवं देश के हित में नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे मानव के जीवन यापन, देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन से प्राकृतिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव तो पडता ही है। आवश्यकता है कि लॉकडाउन हटने के बाद भी मानव को स्वयं न कि सरकार के दबाव में, ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में संतुलन, समन्वय बना रहे, उसे वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, उसे जहरीली एवं अस्वास्थ्यप्रद गैसों के बीच में न रहना पड़े।

प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण द्वारा कोविड–19 जैसी महामारी से बचाव किया जा सकता है। जो सुधार पर्यावरण में लॉकडाउन की विभिन्न बाध्यताओं के अंतर्गत हुआ था, वह सुधार मानव को स्वयं ही अपनी गतिविधियों के माध्यम से करने चाहिएं, उसे अपनी दिनचर्या, रहन–सहन के तौर–तरीके को बदलना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जरूरी जागरूकता, सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों के प्रति सक्रिय सहयोग और सबसे बड़ी चीज सकारात्मकता, ये सब निश्चय ही मानव जाति को इस महामारी से लड़ने तथा प्राकृतिक पर्यावरण को भावी मानव जाति के लिए सुरक्षित एवं श्रेष्ठ बनाने की राह में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा।

सरकार को लॉकडाउन के दौरान एवं लॉकडाउन के बाद भी देश के नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूक करते रहना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण स्वस्थ होगा तो महामारियों का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम होगा।

आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण द्वारा कोविड–19 जैसी महामारी से बचाव किया जा सकता है। मनुष्य के अच्छे जीवन स्तर और कार्य करने के पर्यावरण की आवश्यकता हेतु तथा पृथ्वी पर ऐसी स्थिति बनाने के लिए जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति आवश्यक है। कम विकास तथा प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को दूर करने के लिए विकासशील देशों को, उनके अपने प्रयासों के अतिरिक्त समुचित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता यथासम्भव तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध होनी चाहिए।

मनुष्य अपने पर्यावरण का रचयिता तथा उसे ढालने वाला दोनों ही है जिससे उसे भौतिक स्थिरता तथा बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आत्मिक बुद्धि के अवसर मिलते हैं। मानव जाति की लम्बी और टेढ़ी–मेढ़ी विकास यात्रा में अब इस ग्रह (पृथ्वी) पर ऐसी स्थिति आ गई है, जब

मनुष्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तेज गति के साथ अपने पर्यावरण को अनेक प्रकार से और अपूर्व ढंग से बदलने की शक्ति अर्जित कर ली है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार ऐसे प्रमुख विषय हैं, जिनसे पूरे विश्व के लोगों के हित तथा उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यही पूरे विश्व के लोगों की आवश्यक आकांक्षा और सभी सरकारों का कर्तव्य भी है। जलप्रदूषण को रोकना और जल संग्रहण करना आज की ज्वलत समस्याऐं हैं। मानसून कमजोर होने पर मनुष्यों और जीव–जंतुओ की हालत दयनीय हो जाती है तथा वनस्पतियॉ सूखने लगती हैं। अतः गिरते हुए भू–जल स्तर को ऊॅचा उठाने के नये–नये तरीके अपनाने की जरूरत है।

जैसे–जैसे औद्योगिक विकास हो रहा है, वैसे ही वायुप्रदूषण और जलप्रदूषण के साथ ध्वनिप्रदूषण भी विकराल रूप धारण कर रहा है। चारों ओर शोरगुल से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। स्वस्थ मनोरंजन के साधन और प्राकृतिक पर्यावरण ही मानसिक प्रदूषण से मुक्ति दिला सकता है।

सरकार एवं मानव दोनों का ही; मानव व उसकी भावी पीढ़ी को ऐसे पर्यावरण में, जिसमें वह सुखी, सुरक्षित, सुधरा हुआ और मर्यादापूर्ण जीवन जी सके, तथा जहॉ स्वतंत्रता, समानता और रहन–सहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, जीने का मूलभूत अधिकार हो; ऐसे पर्यावरण को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण दायित्व भी है। मनुष्य पर वन्य प्राणियों एवं उनके आश्रय–स्थलों की सुरक्षा और विवेकपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी है, जिन्हें अनेक कारणों से भारी खतरा हो गया है। मनुष्य की लालची प्रवृत्ति और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण घटते वन–क्षेत्र से वन्य जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जहॉ पशु–पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है, वही जनोपयोगी औषधीय जड़ी–बूटियों की कई प्रजातियॉ लुप्त होती जा रही हैं।

अतः सरकार को आर्थिक विकास की योजना बनाते समय प्राकृतिक संरक्षण (वन्य–जीव सहित) को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। वृक्षारोपण कर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमण्डल में बढ़ाई जा सकती है। वन–सम्पदा जीवन के लिए संजीवनी है। प्रकृति ने समस्त प्राणियों के लिए जो सुविधाऐं सहज रूप से सुलभ कराई हैं, उनसे पूरा–पूरा संतुलित लाभ न उठाना मनुष्य की नासमझी है। प्रसन्नता की बात है कि हमारा शासन पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए करिबद्ध है। आज आवश्यकता है, शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जन–रूचि जाग्रत कर पर्यावरण के महत्व से जन–सामान्य को अवगत कराने और प्रचुर–प्रचार–प्रसार की। तभी जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में सहायता मिल सकेगी।

अब नगरीय जीवन की सुख–सुविधाओं, विकास के साधनों की उपलब्धता और चमक–दमक ने अभावग्रस्त ग्रामवासियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इसके कारण वे नगरों की ओर भाग रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो नगरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगेगी और गॉव वीरान हो जायेंगें। गॉवों में भी नगरों जैसी सुख–सुविधाऐं और तरक्की के अवसर प्रदान कर ग्रामीणों की इस पलायन प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड–19 महामारी की भयावह स्थिति से गुजर रहा है। प्रतिदिन लगभग लाखों संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। भारत देश में तो इस महामारी की पराकाष्ठा है। भारत सरकार इसे रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके लिए कोविड टीके की डोज 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग तथा अब 18 से 44 वर्ष के लिए भी टीके की डोज लगना प्रारम्भ हो गया है ताकि मनुष्यों में इम्यूनिटी को बढ़ाकर बचाव किया जा सके। लॉकडाउन का भी संयमित एवं संतुलित प्रयोग सरकार समय–समय पर महामारी के प्रसार एवं दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सफलतापूर्वक कर रही है। भारत के प्रमुख राज्यों उ0प्र0, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडू, केरल, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में लॉकडाउन का महामारी रोकथाम पर तथा प्राकृतिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव आया है। वर्तमान में लॉकडाउन से प्राकृतिक पर्यावरण में काफी सुधार हुआ है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि में उल्लेखनीय कमी आयी है। सरकार को लॉकडाउन के दौरान एवं लॉकडाउन के बाद भी देश के नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूक करते रहना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण स्वस्थ होगा तो महामारियों का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम होगा। स्वास्थ्य के प्रति जरूरी जागरूकता, सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों के प्रति सक्रिय सहयोग और सबसे बड़ी चीज सकारात्मकता, ये सब निश्चय ही मानव जाति को इस महामारी से लड़ने की राह में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एम0के0 गोयल, ''अपना पर्यावरण 1995''
2. एम0ए0 हक, ''पर्यावरण पत्रिका 2003''
3. सविन्द्र सिंह, ''पर्यावरण भूगोल 2018''

25

कोविड-19 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं का महत्वपूर्ण योगदान एवं आम जनता को तनावमुक्त रखने की एक पहल

डॉ0 रत्ना गर्ग
असिस्टैंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद (बिजनौर)

अक्षय कुमार गोयल
शोध छात्र व राष्ट्रीय स्वयं सेवक
गाजियाबाद

सारांश

वर्तमान कोविड–19 वायरस से संपूर्ण विश्व ग्रसित है। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का सर्वप्रथम केस दक्षिण भारत के केरल में सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन द्वारा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए प्रयास किये। इसी लॉकडाउन की अवधि में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने घर पर रहकर ही मास्क तैयार किये, अपने निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों को जागरूक किया तथा साथ ही पोस्टर, गीत, कविताओं के माध्यम से कोविड–19 से बचाव हेतु सार्थक संदेश दिये। साथ ही जो युवा लॉकडाउन में अवसाद से ग्रस्त हुए, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेविकाओं ने अपने अपने अनुभव साझा किये तथा अवसाद ग्रसित व्यक्तियों को तनावमुक्त रखने में अहम भूमिका निभाई।

मुख्य शब्द– कोविड–19, राष्ट्रीय सेवा योजना, लॉकडाउन, तनावमुक्त

वर्तमान कोविड–19 वायरस से संपूर्ण विश्व ग्रसित है। नवंबर 2019 में चीन की लैब से निकलकर धीरे–धीरे यह वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिये। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का सर्वप्रथम केस दक्षिण भारत के केरल में सामने आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को जनता से अपील की कि 21 मार्च को जनता कर्फ्यू में अपना पूर्ण सहयोग दें। 21 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा जिसमें भारत की जनता ने अपना संपूर्ण योगदान दिया, फिर प्रधानमंत्री मोदीजी ने 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। 15 अप्रैल सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया। 4 मई 2020 से 17 मई तक तृतीय लॉकडाउन लगा, फिर चतुर्थ लॉकडाउन 10 मई से 31 मई तक रहा। इसी तरह लॉकडाउन का पाँचवा चरण 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक रहा। इसी लॉकडाउन की अवधि में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने घर पर रहकर ही मास्क तैयार किये, अपने निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों को जागरूक किया तथा साथ ही पोस्टर, गीत, कविताओं के माध्यम से कोविड–19 से बचाव हेतु सार्थक संदेश दिये। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने जनता को कोविड–19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करते हुए दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, हाथ की सफाई की महत्ता इत्यादि को बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं का मूल उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने हेतु लोगों को जागरूक करना था। धीरे–धीरे स्वयं सेविकाओं ने मास्क बनाकर प्रवासी मजूदरों को दिये, साथ ही प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करायी तथा निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की तथा उनकी सहायता की। साथ ही जो युवा लॉकडाउन में अवसाद ग्रस्त हुए, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेविकाओं ने अपने अपने अनुभव साझा किये तथा अवसाद ग्रसित व्यक्तियों को तनावमुक्त रखने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना काल में राष्ट्रीय सेवा योजना में 1.50 लाख युवाओं ने जन जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना काल में मास्क बैंक की भी स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश के महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली के जनपद बिजनौर में सर्वप्रथम मास्क बैंक का शुभारम्भ किया गया, तत्पश्चात कई जिलों में मास्क बैंक की स्थापना की गयी। साथ ही बाल पेटिंग के माध्यम से भी राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने जनजागरूकता

अभियान चलाया। स्वयं सेविकाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के साथ–साथ योग करके भी लोगों को स्वस्थ रहने के उपाय बताये। गर्भवती महिलाओं को भी स्वस्थ रहने एवं मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए जागरूक किया। स्वयं सेवक और सेविकाओं ने प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री के साथ–साथ ही मास्क एवं सेनिटाइजर भी वितरित किये। भारत सरकार और उ0प्र0 सरकार की जूम ऐप के माध्यम से कई महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय निदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेस में कार्यक्रम अधिकारियों से उनकी इकाई के स्वयं सेवक व सेविकाओं की सूची मांगी गई, जिससे ये कोरोना वायरस के विरूद्ध जारी जंग में राहत कार्यों में भी अपनी सक्रिय सहभागिता करे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक/सेविकाओं ने ग्रामीणों को कोरोना के खिलाफ जंग से जीतना है, इस हेतु उन्हें बताया कि–

- **कोविड–19 क्या है?**

  कोविड–19 'नोवल कोरोना वायरस' के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। इसके सामान्य लक्षण हैं– बुखार, सूखी खाँसी, सांस लेने में कठिनाई, कुछ रोगियों में मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, नाक बंद, नाक बहना, गले में खराश या दस्त जैसे सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं।

- **कोविड–19 कैसे फैलता है?**

  जब कोविड–19 से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह या नाक से निकली बूंदों द्वारा यह रोग फैलता है। ऐसा मुख्यतः दो तरह से हो सकता हैः

  - प्रत्यक्ष निकट संपर्क– कोविड–19 ग्रस्त रोगी या संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है।
  - अप्रत्यक्ष संपर्क– थूक की बूंदें सतहों और कपड़ों पर कई दिनों तक जीवित रहती हैं। इसलिए ऐसी किसी भी संक्रमित सतह या कपड़े को छूने और उसके बाद मुंह, नाक या आँखों को छूने से यह बीमारी फैल सकती है। कोविड–19 के पनपने की अवधि 1 से 14 दिन है। यह बीमारी उन संक्रमित व्यक्तियों से भी फैल सकती है जिनमें कोई गम्भीर लक्षण नहीं है।

- **कोविड–19 के संक्रमण से कैसे बचे या इसे दूसरों में फैलने से कैसे रोकें?**

  इस हेतु निम्न प्रयास करें–

  - **सामाजिक दूरी बनाने का प्रयास करें–**
    - भीड़ जैसे कि मेला, हाट, धार्मिक स्थानों में एकत्रीकरण, सामाजिक महोत्सव आदि से बचें।
    - सार्वजनिक स्थानों पर आपके और अन्य लोगों के बीच कम से कम 2 गज के फासले की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेषकर यदि उन्हें खांसी, बुखार आदि जैसे लक्षण हों तो उनकी छींक और थूक की बूंदों के सीधे संपर्क से बचें।
    - जितना हो सके घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
    - आपसी संपर्क से बचें– जैसे हाथ मिलाना, हाथ पकड़ना या गले लगना।
    - मेज, कुर्सी, दरवाजे की हैंडल आदि जैसे सतहों को छूने से बचें।
  - **साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें व अपने हाथों को साबुन और पानी से बार–बार धोएं–**
    - बाहर से घर आने पर या अन्य लोगों से मिलकर आने पर विशेषकर तब जब वे बीमार हों।
    - खांसते या छींकते समय अपने चेहरे को हाथों से छूने के बाद।
    - खाना बनाने, खाने या बच्चों को खिलाने से पहले।
    - शौचालय का उपयोग करने और सफाई करने या कचरे के निपटान के बाद।
    - खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या तौलिये से ढक लें। अपने रूमाल को कम से कम दिन में एक बार अवश्य धोएं।
    - अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी से खांसे या छींकें, अपने हाथों से नहीं।

* थूक की बूंदों को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं या जोर से या चिल्लाकर न बोलें।
* अपनी आँखों, नाक और मुँह को गंदे हाथों से न छुए।
* सुनिश्चित करें कि घर की सतहों और अन्य वस्तुओं को नियमित रूप से साफ किया गया हो।

- **संक्रमण का पता लगने पर–**
  - एक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में आपको उन सभी लोगों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा जा सकता है जिन्होंने पिछले 14 दिनों में किसी अन्य देश या भारत के अंदर अन्य राज्य की यात्रा की हो।
  - उनके नाम पीएचसी में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साझा करें लेकिन किन्हीं अन्य के साथ साझा न करें।
  - उन्हें अगले 14 दिनों के लिए घर में ही एकांत में रहने की सलाह दें।
  - उन्हें बताए कि कोविड–19 के लक्षणों के लिए वे स्वयं की निगरानी करें।
  - उन्हें बताएं कि यदि कोविड–19 के लक्षण विकसित होते हैं तो वो आपको सूचित करें और कोविड–19 हेल्पलाइन नंबर पर बात करें।
- **घर पर क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति के लिए निर्देश–**
  - घर में एक अलग कमरे मे रहें, कोशिश करें कि अलग शौचालय वाला कमरा हो तो बेहतर होगा। अन्य व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने का प्रयास करें।
  - हर समय मास्क पहनें यदि मास्क उपलब्ध नहीं है तो एक साफ सूती कपड़ा लें और इसको एक डबल परत में मोडकर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए अपने चेहरे पर बाँध लें।
  - अपने अलग बर्तन, तौलिया, बिस्तर आदि का उपयोग करें जो नियमित रूप से अलग से साफ किए जाने चाहिएं।
  - फर्श, मेज, कुर्सी और दरवाजे की हैंडल आदि जैसी सतहों को कम से कम दिन में एक बार अवश्य साफ करना चाहिए।
  - सुनिश्चित करें कि परिवार का केवल एक तय सदस्य ही ऐसे व्यक्ति की देखभाल करे।
- **घर पर क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति की देखभाल करने वाले के लिए निर्देश–**
  - कमरे में प्रवेश करते समय एक मीटर की दूरी बनाये रखें।
  - अपने मुँह को मास्क या दो परत के सूती कपड़े से ढक कर रखें।
  - कमरे से बाहर आने के बाद अपने हाथ अवश्य धोएं।
- **मास्क का उपयोग कैसे करें–**
  - मुँह पर मास्क लगाने से पहले अपने हाथ अवश्य धो लें।
  - सुनिश्चित करें कि यह ढीला ना हो और मुँह और नाक दोनो ढके हों।
  - मास्क को सामने से न छुएं, केवल बगल से स्पर्श करें।
  - मास्क बदलने के बाद अपने हाथों को धोना सुनिश्चित करें।
  - हर 6–8 घंटे में मास्क बदलें या इसके नम/गीला हो जाने पर बदलें।
  - यदि डिस्पोजेबल मास्क का उपयोग किया जाता है तो मास्क को केवल ढक्कन लगे हुए डस्टबिन में ही फेंकें और डस्टबिन में एक प्लास्टिक बैग भी लगा होना चाहिए।
  - यदि कपड़े के मास्क का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम दिन में एक बार अवश्य धोएं।

कोविड–19 से जुड़ी भ्रांतियाँ बनाम उनकी वास्तविकता–

- **कोविड–19 से जुड़ी भ्रांतियाँ–** कोरोना वायरस मच्छरों के माध्यम से फैल सकता है। कोविड–19 के लक्षणों से ग्रसित व्यक्ति ही बीमारी फैला सकता है। लहसुन एवं शराब के सेवन से कोविड–19 से बचाव हो सकता है।
- **कोविड–19 से जुड़ी वास्तविकता**– कोरोना वायरस मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। लोगों को बार–बार हाथ धोना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कोविड–19 बीमारी उन संक्रमित व्यक्तियों से भी फैल सकती है, जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। लहसुन एवं शराब के सेवन से कोविड–19 से बचाव नहीं हो सकता है।

भारत में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में महामारी से सम्बन्धित आंकड़ें (अप्रैल 24, 2021 के अनुसार)

क्र0 सं0	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	मामले	सक्रिय	ठीक होने वालों की संख्या	मृत्यु
	भारत	16610481	2552940	13867997	189544
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	5569	146	5358	65
2	आंध्र प्रदेश	1009228	74231	927418	7579
3	अरूणाचल प्रदेश	17430	453	16921	56
4	असम	233453	13942	218339	1172
5	बिहार	378442	76420	300012	2010
6	चंडीगढ़	37232	4622	32180	430
7	छत्तीसगढ़	622965	123479	492593	6893
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6142	1785	4353	4
9	दिल्ली	980679	92029	875109	13541
10	गोवा	73644	11040	61628	976
11	गुजरात	467640	100128	361493	6019
12	हरियाणा	402843	64057	335143	3643
13	हिमाचल प्रदेश	84065	12246	70539	1280
14	जम्मू कश्मीर	156344	16993	137240	2111
15	झारखंड	190692	43415	145499	1778
16	कर्नाटक	1274959	214330	1046554	14075
17	केरल	1350501	179311	1166135	5055
18	लद्दाख	13089	2034	10920	135
19	लक्ष्यद्वीप	1805	920	884	1
20	मध्यप्रदेश	472785	87640	380208	4937
21	महाराष्ट्र	4161676	693632	3404792	63252
22	मणिपुर	30151	590	29180	381
23	मेद्यालय	15631	1238	14236	157
24	मिजोरम	5283	644	4627	12
25	नागालैंड	12889	457	12338	94
26	ओडिशा	394694	36718	356003	1973
27	पुडुचेरी	51372	6330	44314	728
28	पंजाब	326447	43943	274240	8264
29	राजस्थान	483273	117294	362526	3453
30	सिक्किम	7037	693	6207	137
31	तमिलनाडू	1051487	95048	943044	13395
32	तेलंगाना	387106	58148	326997	1961
33	त्रिपुरा	34429	645	33390	394
34	उत्तराखंड	1013370	273653	728980	10737
35	उत्तर प्रदेश	142349	29949	110379	2021
36	पंश्चिम बंगाल	713780	74737	628218	10825

Source - https://prsindia.org/covid-19/cases

मुस्कुराएगा इंडिया

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ इंडिया ने 'मुस्कुराएगा इंडिया' काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरूआत की। 'मुस्कुराएगा इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के काउंसलर्स द्वारा, कोरोना के कारण संक्रमित, आइसोलेटेड या फिर लॉकडाउन की स्थिति के कारण मानसिक दबाव महसूस करने वाले लोगों की दुविधाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए यूनिसेफ व यूपी राष्ट्रीय सेवा योजना ने जिलेवार काउंसलर की लिस्ट जारी की, कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ की ओर से प्रत्येक जिले के 5 राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, काउंसलर के सम्पर्क नंम्बर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किये गये जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो सकें।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौर में व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी खुशहाली के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश, यूनिसेफ इण्डिया और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इण्डिया के ''मुस्कुराएगा इण्डिया'' अभियान के समस्त काउंसलर की ऑनलाइन कार्यशाला हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अवसादग्रसित युवाओं को अवसाद से मुक्त कराना है। राज्य सम्पर्क अधिकारी डॉ0 अंशुमाली शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ एन.एस.एस. संकट के समय में युवाओं के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के काउंसलर्स कोरोना से संक्रमित, क्वारटाइन, लॉकडाउन की स्थिति से उपजे मानसिक दबाव को दूर करने में मदद करेंगें और प्रभावित होने वालों की जिन्दगी में मुस्कुराहट वापस लाने का प्रयास करेंगें। मुस्कुराएगा इण्डिया में आम जनता ही नहीं वरन् कई अधिकारी भी मानसिक दबाव झेल रहे थे, ऐसी स्थिति में एन.एस.एस. के काउंसलर्स ने सभी की समस्याओं का निदान किया। काउसंलरों ने पुलिस विभाग में भी अफसरों की समस्यायें सुनी और उन्हें अवसाद से मुक्त किया। छात्र–छात्राओं की समस्याओं का भी निदान किया। एन.एस.एस. ने इस लॉकडाउन में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई।

इसी कोरोना काल में एन.एस.एस. ने आम नागरिक के मानसिक दबाव को कम करने के उपाय बताए, साथ ही साथ उन्हें विश्वास दिलाया कि किसी भी समस्या का समाधान परेशान होकर नहीं किया जा सकता वरन् उन समस्याओं का सामना करके ही समस्त परेशानियों का निदान किया जा सकता है। उन्हें सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में नही आने देना है। सभी काउंसलरों ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। आज एन.एस.एस. ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भी काउंसलरों के पास अवसादग्रस्त व्यक्तियों के फोन आते हैं और एन.एस.एस. अधिकारी उन्हें उनकी समस्याओं का निदान करके एक नयी सोच के साथ आगे चलने को प्रयासरत कर रहे हैं। अधिकारी व काउंसलर जनता को लाभांवित करके उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।

निष्कर्ष

कोरोना काल में एन.एस.एस. जनता के साथ खड़ी हुई व उनकी सहायता करके अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य यही है 'Not me. But you'। एक स्वयंसेवक और स्वयंसेवी स्वयं से पहले समुदाय को स्थान देता है। एस.एस.एस. स्वयंसेवियों ने कोरोना काल में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें प्रवासी मजदूरों की सहायता, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, मास्क बैंक की स्थापना, मास्क बनाकर जनता को देना, गर्भवती महिलाओं को पोषण की जानकारी देना, बाल पेटिंग द्वारा जनता को जागरूक करना, पौधारोपण करना, योगा कराना और सबसे महत्वपूर्ण अवसादग्रस्त व्यक्तियों की समस्याएं सुनकर उन्हें अवसाद से मुक्त कराना इत्यादि शामिल हैं। अब जब कोरोना काल का दूसरा चक्र फिर से देश में अपने पैर पसारे बैठा है एक बार फिर एन.एस.एस. के अधिकारी, काउंसलर, स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकायें अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और साथ ही साथ जनता को टीकाकरण के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं।

संदर्भ

1. Cohen, Jon; Normile, Dennis (17-01-2020). "New SARS-like virus in China triggers alarm". Science (In English). 367 (6475): 234–235. PMID 31949058. ISSN 0036-8075. D.O.I. :10.1126/science.367.6475.234. (17-01-2020)
2. "Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23-01-2020". www.who.int (In English).
3. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवाणी, विभिन्न तिथियों से सम्बन्धित

Website

- https://www.covid19india.org/
- https://prsindia.org/covid-19/cases
- www.publicationsdivision.nic.in

26

वर्तमान समय में आध्यात्मिकता की महत्ता

डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह

असिस्टैंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

साहू जैन पी0जी0 कालेज, नजीबाबाद, जनपद–बिजनौर (उ0प्र0)

सारांश

स्वस्थ रहने के लिए किए गए चिकित्सकीय प्रयास या अन्य प्रयास अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते तो यहीं पर उजागर होता है ईश्वरीय शक्ति का महत्व। आध्यात्मिक होकर इन कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है, नकारात्मक भावों या विचारों की न्यूनता होती है और सकारात्मक विचारों की प्रधानता। यह सकारात्मकता ही हमें शक्ति देती है, संबल देती है, इम्युनिटी बढ़ाती है क्योंकि जब हम अनुभव करने लगते हैं कि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है तो हम सशक्त हो जाते हैं रचनात्मक हो जाते हैं। साकार या निराकार शक्ति, जैसा भी हम मानते हैं, हमें आत्मिक बल और ऊर्जा प्रदान करती है। एक अदृश्य वायरस जब हमको डरा सकता है तो अदृश्य ईश्वर हमें बचा भी सकता है।

मुख्य शब्द– सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, ईश्वरीय शक्ति, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल

बहुत ही चुनौती से परिपूर्ण है वर्तमान समय। परिवेश में चारों ओर भय और अशांति का वातावरण है। इस वातावरण का निर्माण किया है कोविड–19 नामक महामारी ने। देश का आम जन मानस इससे आक्रान्त है भयभीत है, और निराशा में डूबा हुआ है। निःसंदेह समस्त योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, विचारशील है, परन्तु कई बार संकटासन्न होने से मनोभावों में परिवर्तन आ जाता है और सकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। ये स्थितियॉ मन की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती हैं। एक वायरस ने जन मानस को भयभीत कर दिया है। इस भय के उत्पन्न होने से मनुष्य की इम्युनिटी कम हो जाती है और वह अनुभव करने लगता है कि मेरा कोई नहीं, इस आपदा का कोई निदान नहीं। स्वस्थ रहने के लिए किए गए चिकित्सकीय प्रयास या अन्य प्रयास अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते तो यहीं पर उजागर होता है ईश्वरीय शक्ति का महत्व। आध्यात्मिक होकर इन कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है, नकारात्मक भावों या विचारों की न्यूनता होती है और सकारात्मक विचारों की प्रधानता। यह सकारात्मकता ही हमें शक्ति देती है, संबल देती है, इम्युनिटी बढ़ाती है क्योंकि जब हम अनुभव करने लगते हैं कि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है तो हम सशक्त हो जाते हैं रचनात्मक हो जाते हैं। साकार या निराकार शक्ति, जैसा भी हम मानते हैं, हमें आत्मिक बल और ऊर्जा प्रदान करती है। एक अदृश्य वायरस जब हमको डरा सकता है तो अदृश्य ईश्वर हमें बचा भी सकता है। भक्ति, पूजा, प्रार्थना से आत्मबल को अपार शक्ति प्राप्त होती है। आदिकाल के बाद के समय पर दृष्टिपात करें तो पायेंगें कि तत्कालीन समाज में नैराश्य का वातावरण व्याप्त था, दिशा–बोध का अभाव था। उसी समय भक्तिकाल में संत कवियों ने अलख जगाकर समाज को जागृत करने का पुण्य कार्य किया और नवीन चेतना प्रदान की। वर्तमान परिवेश में इन सन्तों की वाणी की सार्थकता पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होती है। भक्ति से आत्मोन्नयन और आत्मोन्नयन से पूर्णरूपेण सकारात्मक होकर मन, बुद्वि और चित्त से स्वस्थ होकर इस आपदा ने निपटने में किंचित कठिनाई नहीं होगी।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक युग का साहित्य समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उनको प्रभावित करता भी है। भारतीय समाज अनेक जातियों और वर्णों का समन्वित रूप है। पुरातन काल से ही इस देश में अनेक जातियॉ रही हैं। शक, हूण, यवन, कंबोज, पारसी, मंगोल आदि अनेक जातियों के लोग विशाल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अपना –अपना स्थान बनाते चले गए। मध्यकाल में आए मुस्लिमों और हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्थायें साथ–साथ चलीं। इस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में संकीर्णता आयी और अनेक प्रकार के दोष दृष्टिगोचर हुए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रारंभ हुए। छुआछूत के बन्धन शनैः–शनैः कठोर हुए। जातियों–उपजातियों में वृद्वि तथा हिन्दू बहुविवाह और पुनर्विवाह इस परिवेश में दृष्टिगोचर हुए।

मनुष्य के आत्मोन्नयन हेतु सांस्कृतिक समन्वय का महत्वपूर्ण प्रयास विद्वानों और सूफी सन्तों के द्वारा हुआ। सूफियों का दर्शन और सिद्वान्त उदारता से ओत–प्रोत थे। उनका जीवन उच्च और आदर्शमय था। वो धार्मिक संकीर्णता से कोसों दूर थे तथा मानवीय लौकिक प्रेम को ही

आध्यात्मिक प्रेम का सोपान मानते थे। इनकी इस उदारता ने सामाजिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसी श्रृंखला में हिन्दी सन्त कवियों का अवदान अतिमहत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। ये संत कवि पूर्णरूपेण धार्मिक संकीर्णता, रूढ़ीवादिता और पोंगापंथ के घोर विरोधी थे। वाह्य आडंबरों को छोड़कर अन्तर्मन की शुद्वता पर विशेष बल देकर संसार के कण–कण व्याप्त परमेश्वर की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास के स्वर इनके काव्य से मुखरित हुए। इन्होंने जहॉ एक ओर हिन्दुओं की जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेद–भाव की भावना, माला–जप, छापा–तिलक आदि की ओर इंगित किया वहीं मुस्लिम समाज में व्याप्त रूढ़ियों की ओर भी इशारा किया। उनके ये विचार दोनों धर्मों को निकट लाने में बहुत सहायक सिद्व हुए।

मध्यकाल में साहित्य और कला को नवीन आयाम प्राप्त हुआ। यहॉ के निवासी साहित्य के संपर्क में आए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उद्भव का जो अंकुर आदिकाल में प्रस्फुटित हुआ वह क्रमशः विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा। इस युग में भाषा के क्षेत्र में जो अद्भुत क्रान्ति हुई वह सुखद है। अमीर खुसरो जैसे फारसी के विद्वान ने हिंदी में काव्य–रचना की। अलबरूनी भारतीय साहित्य का श्रेष्ठ ज्ञाता था।

निःसंन्देह भक्ति काव्य ने भारतीय जन–जीवन के लौकिक व आध्यात्मिक पक्षों को नवीन दिशा दी। इन पुरोधाओं ने सामाजिक जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोधों को डटकर चुनौती दी। भक्त कवियों ने ढोंग–ढकोसलों, मिथ्या रूढ़ियों, पाखंडों, संकीर्णताओं का पूरी शक्ति से विरोध करके मानवतावाद को पुर्नप्रतिष्ठित किया तो सगुण भक्त कवियों ने प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं के आलोक में सामाजिक जागरण का संदेश प्रदान किया। इन्होने लोकभाषा हिंदी को स्वीकृति प्रदान कर महत्वपूर्ण कार्य किया।

कबीरदास की साधना विलक्षण है। इनके पूर्ववर्ती संतो में जयदेव, नामदेव, संत लल्ला, त्रिलोचन, सधना बेनी, सेन, अग्रदास, नाभादास आदि अनेक नाम हैं। रामानन्द का मानना था कि ईश्वर (राम) के सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं। हिन्दी के भक्ति काव्य के जनक स्वामी रामानन्द ने लोकभाषा हिन्दी व्यवहार में प्रयोग कर स्तुत्य कार्य किया। उन्होंने भक्ति के द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की–"जाति–पॉति पूछै नहिं कोई। हरि को भजै सो हरि को होई।।"

कबीरदास की साधना पद्धति में योग व भक्ति का संतुलित समन्वय है। उनका धर्म सच्चा मानव धर्म है जो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। समस्त धर्मों में निहित सत्यता, मानव–मात्र के आत्मोन्नयन व लोक कल्याणार्थ है। ये पाखंडों और वाह्याडंबरों से मुक्त हैं। भाषा के महापंडित, सच्चे समाज सुधारक कबीरदास सर्वव्यापी, सर्ववंदनीय ब्रहम के लिए कहते हैं –

''गोव्यंदे तू निरंजन तू निरंजन राया।
तेरे रूप नाहीं, रेख नाहीं, मुद्रा नहीं, माया।।''[1]

सब अपनी–अपनी तरह से ब्रह्म की प्राप्ति कर आत्मोन्नयन हेतु संलन्न हैं–

''जोगी माते धरि जोग, ध्यान पंडित माते पढ़ि पुरान।
तपसी माते तय के भेव, सन्यासी माते करि हमेव।।
मौलाना माते पढ़ि मुसाफ, काजी माते दै निसाफ।।''[2]

वैभव, विलास अर्थात् सुखों की पूर्णता के उपरान्त भी अभाव अर्थात् मानव जीवन की असंतुष्टि और अशान्ति ही खोज है शान्ति और संतुष्टि की। वस्तुतः यहीं से साहित्य की उपादेयता प्रारम्भ हो जाती है। जीवन के किसी भी चरण में चाहे धनवान हो या निर्धन, सुन्दर या कुरूप; मनुष्य सोचने को विवश अवश्य हो जाता है कि उसके जीवन का हेतु क्या है ?

यह सर्वमान्य तथ्य है कि साहित्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है क्योंकि आत्मबोध कराने की क्षमता मात्र और मात्र उसी में है। सूर, तुलसी, मीरा, रसखान आदि भक्त कवियों की वाणी में आनन्द और उल्लास का जो स्वर है उसमें जीवन के प्रति असीम अनुराग है, आशा का अनन्त स्रोत है, वाह्य से अन्तर की ओर जाने का मार्ग है। इनके आराध्य संसार से पलायन का उपदेश नहीं देते अपितु संसार में 'कमल' की भॉति रहते हुए सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म–मंथन, आत्मावलोक और आत्मोन्नयन का सन्देश देते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में –"कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को सॅभालने के लिए, लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा प्रबल और विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिन्दू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेमस्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हराकर पीछे कर दिया। वस्तुतः यही सच्चा सौहार्द्र था।''

लोकमंगल की भावना इन कवियों की वाणी का प्रमुख स्वर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि –

"कोऊ कहै सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल–प्रबल कोउ मानै।
तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहचानै।।'' [3]

गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के माध्यम से समाज के सामने अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। "परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।" धर्म और अधर्म की इससे श्रेष्ठ व्याख्या श्रीरामचरित मानस के अतिरिक्त और कहॉ मिलेगी। वस्तुतः

गोस्वामी तुलसीदास का समग्र काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतीय संस्कृति के समस्त कल्याणकारी सूत्र उनकी कृतियों में विद्यमान हैं। आत्मोन्नयन पर विशेष बल गोस्वामी तुलसीदास सहित समस्त सन्त, भक्त कवियों के काव्य में मिलता है।

महाकवि सूरदास के काव्य में भी कृष्णोपासना के साथ–साथ 'सूरसागर' में वन को गमन करते हुए श्रीराम–लक्ष्मण व देवी सीता को देखकर पुरवधुएँ सीता से प्रश्न करती हैं–

"अरी अरी सुन्दर नारि सुहागिनि लागौ तेरे पाऊँ।
किहि धां के तुम वीर बटाऊ, कौन तुम्हारो गाऊँ।।'[4]

लोक जीवन के सामने कोई 'रोल मॉडल' रखकर उसके गुण, शील, संस्कार, नैतिकता जैसे गुणों की प्रतिष्ठा करके भक्ति काव्य में जन सामान्य के वाह्य और आन्तरिक हेतु 'श्रीरामचरित मानस', 'बीजक', 'सूरसागर' जैसे ग्रंथों के माध्यम से सत्प्रयास किए गए जो प्रभावी भी हुए। भक्तिकालीन काव्य में निहित दर्शन ''सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया'' का उद्घोष है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणा का लोकोपयोगी चिंतन है। यह काव्य अतीत में जितना सार्थक था, वर्तमान में उतना प्रासंगिक है और भविष्य में उतना ही उपयोगी और कल्याणकारी रहेगा। इन भक्त कवियों ने "स्वान्तः सुखाय" की भावना से कहीं और ऊपर "परजन हिताय" की भावना को रखा।

सत्यता यह है कि मनुष्य पूरी दुनिया को जान लेना चाहता है, इस प्रक्रिया में वह झूठ, कपट, ईर्ष्या, पाखण्ड, लोभ जैसे विकारों को अनायास ग्रहण कर लेता है। भौतिक उन्नति अर्थात् वाह्य को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है, जो नश्वर है उसके प्रति आसक्त रहता है और इसी उपक्रम में अपना सारा जीवन व्यर्थ गॅवा देता है किन्तु जो वास्तविक वस्तु अर्थात सद्प्रवृतियों को ग्रहण कर सदाचार के पथ पर चलकर अपने अस्तित्व की खोज नहीं करना चाहता है। ज्ञानी, सन्त, भक्त, कवि कहते हैं कि बडे भाग्य से ही यह मनुष्य का जन्म मिला है जो चौरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः इसे व्यर्थ में गॅवाना कहॉ की बुद्विमानी है।

अज्ञान के अधंकार में आकंठ डूबे मानव समाज को इन सन्त कवियों ने अपनी वाणी से नई चेतना प्रदान की और निराशा के कूप से भक्ति रूपी रस्सी के सहारे से निकालकर अपने कर्तव्य और धर्म को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बताया–"भक्ति स्वतंत्र सकल गुन खानी।"

इस दृष्टि से वैसे भी साहित्य के–आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में 'भक्तिकाल' को ही हिन्दी साहित्य का 'स्वर्णकाल' कहा गया। जब आत्मबोध हो जाता है,सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो यही कहना पर्याप्त होता है–

"जो कुछ था सो ही भया अब कछु कहा न जाए" **–कबीरदास**

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सन्त कवियों की वाणी ने मनुष्य के आत्मोन्नयन और समाज के मार्गदर्शन का कार्य किया है। वर्तमान समय में उनकी वाणी कल्याणकारी और प्रासंगिक है। प्रेरकता से परिपूर्ण है, नैराश्य की भावना को समाप्त करने में सक्षम है। संत कवियों से प्राप्त भक्तिपरक संदेश सम्पूर्ण भास्वरता के साथ मनुष्य के आत्मोन्नयन पर विचार करते हैं और बताते हैं कि इस युक्ति का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी आपदा से सकारात्मक होकर निपटा जा सकता है क्योंकि आत्मोन्नयन से आत्म बल प्राप्त होता है जिससे मनुष्य सकारात्मक भाव से बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुनौती मानकर उनका समाधान करने के लिए तत्पर हो जाता है।

संदर्भ

1. कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ 162
2. सबद, कबीर वाड़मय, पृष्ठ 483
3. विनय पत्रिका–तुलसीदास, पृष्ठ 111
4. सूरसागर (प्रथम खण्ड) पर–488, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी (पं0सं0) वि0 2035

27

कोविड-19 : भारतीय संस्कृति की ओर लौटने का संकेत

डॉ0 दीपा
असिस्टैंट प्रोफेसर,
काइट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
(काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन्स,
दिल्ली–एनसीआर)

डॉ0 प्रतीक गुप्ता
एसोसिऐट प्रोफेसर
काइट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
(काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन्स,
दिल्ली–एनसीआर)

डॉ0 शैली रस्तौगी
पीडीएफडब्लू अवार्डी
(यू.जी.सी.), डी. एन. कालेज, मेरठ

सारांश

आज संपूर्ण विश्व के समस्त देश चाहते हैं कि वे पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम करें। इस हेतु वे हर संभव हर सीमा का प्रयास कर रहे हैं और वह विनाशकारी हथियार परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे जो कि मानव जाति के अजातशत्रु हैं ऐसे हथियारों का निर्माण प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर कर रहे हैं। ऐसा करते वक्त हम यह भूल जाते हैं कि इस से मानव जाति और प्रकृति को कितना नुकसान है। सभी अपनी–अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चाहे उसके लिए फिर प्रकृति का गला ही क्यों ना घोटना पड़े? चाहे फिर प्राकृतिक जीवों को कितनी भी हानि क्यों न पहुंचानी पड़े। और जब हमारी प्रकृति ऐसे लोग की स्वार्थपरकता से तंग आती है तब प्रकृति अपने भीतर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जिससे मानव को पुनः अपनी मर्यादा का आभास हो और वह प्रकृति से विमुख होने की बजाय प्रकृति की ओर बढ़े। काफी समय से प्रकृति विभिन्न संकेतों के माध्यम से नैसर्गिक आपदाओं तथा महामारी संकट आने की पूर्व सूचना दे रही थी परंतु हमारे द्वारा उसकी बात ना मानने पर आज एक अति सूक्ष्म वायरस कोविड–19 ने हमारे अहंकार के चिथड़े उड़ा दिए हैं। आज जो हम हर तरफ महामारी का प्रकोप देख रहे हैं यह प्रकोप हमारी ही स्वार्थ सिद्धि का फल है। अनेक समाज–सुधारक, संत–महापुरुष, हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद और शास्त्र सभी सतत स्वार्थ त्याग कर हमें प्रकृति और भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ना चाहते हैं। इस लेख–पत्र में लेखकों द्वारा कोरोना नामक विश्व्यापी महामारी को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है जिसमें इंगित किया गया है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसी महामारी का कारण है।

मुख्य शब्द– प्रकृति, महामारी, भारतीय संस्कृति, कोविड–19

विश्वव्यापी महामारी से तात्पर्य और समाजवाद का विकल्प

सर्वप्रथम तो हम यह समझते हैं कि महामारी से क्या तात्पर्य है? महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो एक ही वक्त पर अलग–अलग देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाती है यानी महामारी का संबंध किसी बीमारी के भीषण रूप लेकर ज्यादा अधिक जगहों पर फैलने से जुड़ा हुआ है। यदि कोई बीमारी दुनिया के एक से अधिक क्षेत्रों में फैल जाती है तो आमतौर पर डब्ल्यूएचओ इसे महामारी घोषित कर देता है। महामारी की बीमारियां भी दो प्रकार की होती है। पहली है एपिडेमिक बीमारी और दूसरी है पैनडेमिक बीमारी। एपिडेमिक बीमारी उस बीमारी को कहा जाता है जो किसी एक ही देश के एक ही समुदाय पर किसी सीमित क्षेत्र तक फैली हो। और जब कोई बीमारी किसी देश या उसकी सीमा तक सीमित नहीं रहती और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसे पैनडेमिक बीमारी कहा जाता है।

कोविड–19 जैसी बेहद उच्च मृत्यु दर वाली महामारी वाला वैश्विक प्रकोप एक बार पहले भी हो चुका है, जिसे 1918 में स्पेनिश फ्लू वायरस के दौरान देखा गया था। उस समय भी यह दुनिया भर में फैल गया था क्योंकि यह महामारी युद्ध के दौरान फूटी थी। हजारों की संख्या में सैनिक टुकड़ियों के रूप में लड़ने के लिए हजारों मील पार लड़ रहे थे और फिर वायरस के वाहक के रूप में अपने–अपने घरों में लेकर लौटे थे। संक्षेप में कहें तो जो युद्ध छिड़ा उसने उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अपवाद को तोड़ डाला और जिसके चलते वैश्विक महामारी फैल गई जो लगभग 5 करोड लोगों की मौत का कारण बनी थी। 2003 में इसी तरह के प्रकोप ने कुल 26 देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था जो लगभग 800 लोगों की मौत का कारण बना था। जबकि वर्तमान महामारी अभी से ही 32 लाख से अधिक जानें ले चुकने का दावा कर चुकी है। हालाँकि अब राष्ट्रीय विशिष्टता की दीवार की टूटन इस व्यवस्था में स्व–निर्मित हो चुकी है, और यही वजह है कि हम जिस तरह के वैश्विक प्रकोप को आज देख रहे हैं, वह पूंजीवाद के मौजूदा चरण में आम परिघटना होने जा रही है और इन्हीं कारणों से वे प्रयास जिसमें इस संकट

को चुनिन्दा जनसंख्या क्षेत्रों के लिए सीमित कर देने और दूसरों को बचाने की जुगत विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। संक्षेप में कहें तो पूँजीवाद अब एक ऐसे चरण में प्रविष्ट कर चुका है जहां इसके विशिष्ट संस्थान इसके खुद के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं से निपटने में असफल हो रहे हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण

''मनुष्य के स्वभाव में छुपा है, आपत्तियों का कारण''

हमारी संस्कृति ही प्रकृति की पूजा करने वाली थी। गौमाता, गंगा नदी, बरगद, पीपल, गंगासागर, कैलाशपर्वत, मानसरोवर इस प्रकार हम वृक्ष से लेकर महासागर तक प्रकृति की पूजा करते थे। हमारी संस्कृति इस भूमि को पवित्र भारत माता मानने वाली, पत्थर में भी भगवान देखकर उसे पूजने वाली थी, परंतु विदेशी शिक्षा पद्धति तथा कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण हमने इसे निम्न दर्जे का मानना प्रारंभ किया। गौमाता को संभालने में हमें लाभ–हानि दिखाई देने लगी। धीरे धीरे हमने पश्चिम की और आकर्षित होकर अपने ऋषि–मुनियों और अपने पुरखों द्वारा संजोई आचरण पद्धति को ठुकरा दिया। विदेश में जो हो रहा है, वह अच्छा और हमारे प्रौढ व्यक्ति जो धर्म का ज्ञान देता है, वह पिछडा–– यह मनोभाव भी हर भारतीय को संकेत दे रहा है, अब तो जाग जाओ।

स्वच्छ पर्यावरण को हमारे देश में प्राचीनकाल से ही वरीयता दी गई। सच तो यह है कि हमारा भारतीय दर्शन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जितना समृद्ध है उतना किसी अन्य देश का नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का भारतीय दर्शन इतना व्यवहारिक है कि यह हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है और यही कारण है किस भी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं के मूल में कहीं न कहीं पर्यावरण सुरक्षा को और आध्यात्म को भी महत्व दिया गया है। भारत में प्राचीनकाल से सूर्य पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, वनस्पतियों, सरिताओं और सरोवर आदि को पूजनीय मानने की परंपरा रही है जिसके मूल में पर्यावरण संरक्षण का भाव निहित है, प्रकृति की और मुखर होने का भाव निहित है। सूर्य–उपासना, ग्रहों की अभ्यर्थना, अग्नि–पूजा एवं वृक्ष–पूजा आदि की परंपराएं विकसित करके हमने सदैव प्रकृति संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीव–जंतुओं को हानि पहुंचाने तथा उनका भक्षण करने की अनुमति नहीं है। प्रकृति के किसी भी जीव को अथवा प्रकृति को भी हमें नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है परंतु केवल कुछ स्वार्थ सिद्धि वर्ग और तथाकथित विकासवादी परंपरा की सोच के कारण आज हम प्रकृति के हनन पर उतर आए हैं। हमारे शास्त्र और ग्रंथों में जीवों की उपयोगिता के अनुरूप उन्हें धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्रदान की गई है और उनके पूजन की परंपरा को शुरू करके संरक्षण का संदेश दिया गया है। गाय भारतीय समाज में आज भी पूजनीय है। राजस्थान का विश्नोई समुदाय आज भी काले हिरणों को शुभ मानकर इनकी पूजा करता है तथा इनकी रक्षा के प्रति सदैव संकल्पबद्ध रहता है। और इतना ही नहीं, आदिवासियों के वस्त्र तक प्रकृति के अनुरूप रंग–बिरंगे होते हैं। इनकी जीवन शैली में प्रकृति का पूरा प्रभाव दिखता है।

हम नाग को नाग देवता कहकर नागपंचमी जैसा त्यौहार अकारण नहीं मनाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व है। सर्प वायुमंडल में विद्यमान जहरीली गैसों को आत्मसात करके वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में पर्यावरण को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में सम्मानित और संरक्षित ही माना गया है। परंतु तथाकथित गलत सोच के आधार पर हम अपने प्राचीन और अति सूक्ष्मविज्ञान से दूर होकर प्रकृति के हनन की ओर तेजी से अग्रसर होते जा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ''ईश्वरीय आत्मा से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की और अग्नि से जल की तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।'' पृथ्वी ने वनस्पति–उपजा दिये और मानव जाति सहित असंख्य जीव–जंतुओं को पैदा किया। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव जंतु अहम भूमिका निभाता है। हमारे देश में पर्यावरण और प्रकृति प्रेम को जीवन के अभिन्न रूप से जोड़कर इसके संरक्षण के संस्कार विकसित किए गए हैं।

शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति का कोप सारे कोपों से बढ़कर होता है। हमने यदि इस सूत्र वाक्य पर ध्यान दिया होता तो शायद आपदाओं के रूप में हमें प्रकृति का यह क्रूर और विनाशकारी चेहरा न देखना पड़ता और यदि हमने संतुलित विकास को तरजीह दी होती तो प्रकृति इस तरह हम पर कभी कुपित नहीं होती। आज हमारे मनोभाव में केवल परिवर्तन ही नहीं हुआ, अपितु वह नीचे गिर गया है। तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली। गोमाता की जगह कुत्तों ने ले ली। हमने हाथ जोडकर नमस्ते, राम–राम कहना छोडकर शेकहैंड करना प्रारंभ कर दिया। जन्मदिन पर आरती उतारना छोडकर, केक काटना और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाना प्रारंभ कर किया। बाहर से घर में आते समय पैर धोना तो दूर की बात, जूते पहन कर हम घर में घूमने लगे। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसका भी हमनें ध्यान रखना छोड दिया। जूठा अथवा प्राणियों द्वारा सूंघा भोजन न खाना, जन्म–मृत्यु के समय सूतक रखना, आदि सभी हमारे आचार धर्म की बातें हमने पिछडेपन के नाम पर ठुकरा दीं। मंदिर जाने में हमें आलस्य आने लगा। खेद है कि अज्ञानवश जिन बातों को हमने छोडा, उसको आज विदेशी लोग अपना रहे हैं। 'स्वाइन फ्ल्यू' और अब 'कोरोना' के बाद पूरा विश्व नमस्ते कर रहा है। डिस्कवरी चैनल यह शोध बता रहा है कि बच्चा जब जन्मदिन पर केक पर रखी मोमबत्ती बुझाता है, तो उसके मुंह के जीवाणु जाकर केक पर गिरते हैं। ऐसा केक खाना सेहत के लिए गलत है।

कोरोना के बाद अब बाहर से आने पर लोग स्नान कर रहे हैं, बार–बार हाथ–पैर धो रहे हैं। परंतु हम क्यों भूल गए हमारे यहां संध्या होती थी। हमारे यहां बाहर से आने पर जूते निकालकर, हाथ–मुंह धोकर ही घर में प्रवेश होता। घर में होते, तो भी संध्या के समय हाथ–मुंह धोना एक नित्य आचार था। हमारे धर्माचरण को स्वच्छता तक ही सीमित नहीं रखा गया था, स्वच्छता के साथ पवित्रता भी कैसे रहेगी, इतना गहरा

चिंतन हमारा था। पर हमने सब छोड दिया और अब उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। केवल भोजन की बात करें। हमारे यहां बाह्य सफाई का तो पूरा ध्यान तो था ही। पर भोजन बनाते समय मन में पवित्रता आए, इसलिए भगवान को भोग लगाने की व्यवस्था थी। भोजन को यज्ञ का स्थान देकर उससे पहले प्रार्थना होती थी। भोजन बनाना, परोसना, खाना आदि सभी के विषय में कुछ नियम थे। भोजन का एक अंश गोमाता और कुत्ते के लिए निकाला जाता था। इतना विलक्षण आचरण छोडकर, आज हमने अपनी क्या स्थिति बना ली है ? आज तो घर का ताजा भोजन छोडकर होटल, स्वीगी, जुमैटो से आ रहा खाना हमें पसंद है। विवाह और पार्टियों में हमें खडे हो कर खाने में प्रतिष्ठा लगती है। फिर रोग तो होंगें ही न? मानसिक बीमारियां भी आएंगीं हीं। अभी भी समय है, हमें हमारे धर्म, संस्कृति की ओर लौटना होगा और पूरे विश्व को राह दिखानी होगी कि प्रकृति को संतुलित होना है, तो पूरब की ओर लौट चलें।

आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में कोविड–19 महामारी से उत्पन्न रोग और मृत्यु दर के कारण हमारे समाज में उत्पन्न भय, तनाव और आशंका से निपटने के लिए हमें पुनः प्रकृति की ओर मुखर होकर धैर्य और एक सधी हुई प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक तनाव कम करने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक ''योग'' इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा इसकी जटिलताओं को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आज संपूर्ण विश्व इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि इस घातक स्थिति से हम कब उभरेंगे? इस स्थिति से हम कब बाहर आएंगे, साथ ही आज संपूर्ण विश्व अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्ध होकर उनकी स्वास्थ्य की देखभाल में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें आज के समय में 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां तक भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो भारत को अभी तक स्वास्थ्य का अधिकार एक भी मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यह अधिकार शिक्षा के अधिकार के रूप की तरह नागरिकों का वैधानिक अधिकार भी नहीं है। माना कि पिछले दशक में लाखों भारतीय तीव्र आर्थिक विकास के कारण अत्यधिक निर्धनता से बाहर आने में सफल भी रहे हैं और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हमारे देश ने की है। परंतु स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और जनसंख्या स्तर पर इसके परिणामों में भी अभी महत्वपूर्ण सुधार एवं कानून बनाने की आवश्यकता है। हालांकि इसकी सुधार की गति में थोड़ा बहुत बदलाव और तेजी आई है परंतु स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के प्रभावी समाधान जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में समान आर्थिक विकास के स्तर के अन्य देशों के मानक की तुलना में भारी सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन और परिणामों में भारी अंतर है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र को वह राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व और लाभ नहीं मिल पाया है, जो उसे अभी तक मिलना चाहिए था।

आज आवश्यकता है हमें पुनः हमारी योग पद्धति की ओर लौटने की। योग आधारित जीवन शैली में भारतीय प्राचीन धर्मग्रंथों से सही जीवनयापन की अवधारणाओं पर आधारित जीवन शैली में सुधार शामिल है। योग सिद्धांतों के अनुसार जीवन शैली के चार घटक है– आहार, शारीरिक गतिविधि, आदतें और भावनात्मक कल्याण। जीवन शैली के इन कारकों में अनियमितता को एक प्रमुख कारण माना जाता है जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली की पूर्णता को प्रभावित करता है और संक्रमण का जोखिम बढ़ाता है। उचित जीवन शैली के पालन के अभाव (जंकफूड का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता, अनियमित दिनचर्या, व्यसन) का मस्तिष्क के एक विशेष प्रकार से सोचने की गति से पता लगाया जा सकता है, अतः इसलिए योग आधारित जीवन शैली की संपूर्ण अवधारणा मस्तिष्क की गति को कम करना है (शारीरिक मुद्राओं के अभ्यास के साथ–साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझना, श्वसन नियंत्रण, कार्य और विश्राम की तकनीक) और इस प्रकार इसे कुशलता से प्रतिबंधित किया जाए ताकि व्यक्ति उचित जीवन शैली का पालन करने में सक्षम हो। मन को शांत करने से होमोस्टेसिस और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली प्रणाली को गहरा आराम मिलता है और उसका कायाकल्प होता है। आवश्यक है कि हम हमारी प्रकृति की ओर लौटे, हमारी प्राचीन सभ्यता की ओर लौटे तथा प्रकृति के संरक्षण हेतु पुनः संकल्पबद्ध हों। हमारी प्राचीन संस्कृति में पहले क्या होता था उसके कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में दिनचर्या का शुभारंभ हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि से होता था। तपस्वी और ऋषि–मुनियों से लेकर सद् गृहस्थों, वटुक–ब्रह्मचारियों तक नित्यप्रति यज्ञ किया करते थे। प्रातः और सायं यज्ञ करके संसार के विविध रोगों का निवारण करते थे। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की किताब 'यज्ञचिकित्सा' में बताया गया है कि यज्ञों का वैज्ञानिक आधार है। यज्ञों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उठाया जा सकता है और विभिन्न रोगों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। इतना ही नहीं संपूर्ण वैज्ञानिक एवं वैदिक विधि से किए गए यज्ञ से वृक्ष–वनस्पतियों की अभिवृद्धि भी की जा सकती है। यज्ञ अनुसंधान वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की एक शोध शाखा है।

शारीरिक रोगों के साथ ही मानसिक रोगों, मनोविकृतियों से उत्पन्न विपन्नता से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ चिकित्सा से बढ़कर अन्य कोई उपयुक्त उपाय–उपचार नहीं है। विविध अध्ययन, अनुसंधानों एवं प्रयोग परीक्षणों द्वारा ऋषि प्रणीत यह तथ्य अब सुनिश्चित होता जा रहा है। यह एक समग्र चिकित्सा की विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, जो एलोपैथी, होम्योपैथी आदि की तरह सफल सिद्ध हुई है। ब्रह्मवर्चस ने लिखा है, 'भिन्न भिन्न रोगों के लिए विशेष प्रकार की हवन सामग्री प्रयुक्त करने पर उनके जो परिणाम सामने आए हैं, वे बहुत ही उत्साहजनक हैं।' यज्ञोपैथी में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि आयुर्वेद में जिस रोग की जो औषधि बताई गई है, उसे खाने के साथ ही उन वनौषधियों को पलाश, उदुम्बर, आम, पीपल आदि की समिधाओं के साथ नियमित रूप से हवन किया जाता रहे, तो कम समय में अधिक लाभ मिलता है। आरोग्य वृद्धि एव रोग निवारण के लिए किए गए यज्ञों को 'भैषज्ञयज्ञ' कहते हैं। इसके तहत रोगी के शरीर में कौन सी व्याधि बढ़ी हुई है और कौन से तत्व घट या बढ़ गए हैं? उनकी पूर्ति करके शरीर की धातुओं का संतुलन ठीक करने के लिए किन औषधियों की आवश्यकता है? ऐसा निर्णय करके वनौषधियों की हवन सामग्री बनाकर उसी प्रकृति के वेद मंत्रों से आहुतियां दिलाकर हवन कराया जाता है। यज्ञ के धुएं में रहने और उसी वायु से सुवासित जल, वायु एवं आहार का सेवन करने से रोगी को बड़ा आराम मिलता है। अन्य विधियों से ज्यादा असरकारक यज्ञ चिकित्सा

के जानकार कहते हैं कि इसके सूक्ष्म परमाणु सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं और पाचन शक्ति पर बोझ नहीं पड़ता जबकि मुख द्वारा ज्यादा पौष्टिक पदार्थ पाचन प्रणाली को लड़खड़ा सकते हैं। मुख द्वारा दी गई औषधि का कुछ अंश रक्त में जाकर शेष मल–मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है, इस प्रकार कुछ ही मांग इच्छित अवयवों तक पहुंचता है। इंजेक्शन द्वारा दी गई औषधि ज्यादा असर करती है लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। कई दवाएं इन्हेलेशन थेरेपी से दी जाती हैं, ये जल्दी असर करती है। इसी तरह यज्ञोपैथी में फ्यूमीगेशन द्वारा धुएं में मौजूद दवाइयां श्वास मार्ग से एवं रोमकूपों से सीधे शरीर में प्रविष्ट करती हैं। रोगों के आधार पर वनौषधियों, जड़ियों, हवन सामग्री एवं हवन कुण्ड के आकार आदि का निर्णय लिया जाता है।

निष्कर्ष

अतः संपूर्ण लेख का निष्कर्ष यही है कि हम पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटे, पुनः हम अपने गांवों की ओर प्रस्थान करें, और गांव के विकास पर ध्यान दें क्योंकि गांव भारत की आत्मा कहा जाता है और यदि गांव का विकास नहीं होगा तो ना शहर का विकास संभव है और जब शहर का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। अतः यदि हमें भारत देश का सचमुच विकास करना है तो हमें पुनः अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा तभी हम इस देश को विश्वगुरु पुनः बना पाएंगें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Journal:

- Vaillant GE. Psychiatry, religion, positive emotions and spirituality. Asian J Psychiatr. 2013;6(6):590–4. doi: 10.1016/j.ajp.2013.08.073.[PubMed: 24309879]
- Albers, G., Echteld, M. A., de Vet, H. C., Onwuteaka-Philipsen, B. D., van der Linden, M. H., & Deliens, L. (2010). Content and spiritual items of quality of life instruments appropriate for use in palliative care: A review. Journal of Pain and Symptom Management, 40, 290–300.
- Mishra, S. K., Togneri, E., Tripathi, B., & Trikamii, B. (2017). Spirituality and religiosity and its role in helath and disease. Journal of Religion and Health, 56, 1282–1301.
- Puchalski, C. M., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., Baird, P., Bull, J., et al. (2009). Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: The report of the consensus conference. Journal of Palliative Medicine, 12, 885–904.
- Burnet F, Clark E Influenza: a survey of the last 50 years in the light of modern work on the virus of epidemic influenza. Melbourne: MacMillan; 1942 [Google Scholar]
- Gopalkrishna Barkur, Vibha, Giridhar B. Kamath, "Sentiment analysis of nationwide lockdown due to COVID 19 Outbreak: Evidence from India", Asian Journal of Psychiatry, Vol. 51, 2020.https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102089
- Chandrasekhar, D, Zhang, Y, Xiao, Y. Nontraditional participation in disaster recovery planning: cases from China, India, and the United States. J Am Plan Assoc. 2014;80(4):373–384. doi:10.1080/01944363.2014.989399
- COVID 19: Impact on mental health of graduating and post graduating students, Pratibha Kumari , Prateek Gupta , Atul Kant Piyoosh , Babita Tyagi & Parvin Kumar, Journal of Statistics and Management Systems (taru Publication, Taylor & Francis Group, ISSN 0972-0510 (Print), ISSN 2169-0014 (Online) DOI : https://doi.org/10.1080/09720510.2020.1833449, Dec9, 2020 PP: 1-13

Books:

- Taittiriya Upanishad, Vedanta Press, CA, ISBN: 9788175050242
- Pandemic 1918 : the story of the deadliest influenza in history by Arnold, Catharine, ISBN: 9781782438090

Online Articles:

- https://www.merriam-webster.com/dictionary/epidemic
- https://intermountainhealthcare.org/blogs/topics/live-well/2020/04/whats-the-difference-between-a-pandemic-an-epidemic-endemic-and-an-outbreak/
- Coronavirus: Greatest test since World War Two, says UN chief, 1 April 2020, https://www.bbc.com/news/world-52114829
- COVID-19 Is World's Biggest Challenge Since World War II, Says UN Secretary General, 01/04/2020 • Gauri Saxena & Grace Ren and Elaine Ruth Fletcher, https://healthpolicy-watch.news/covid-19-is-worlds-biggest-challenge-since-world-war-ii-says-un-secretary-general/
- https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19 vaccines?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVjLK2viMFS4japYD3mC9NsEyXXXN76ChIF68CW7PnOC_FkMX1wd2bgaAvBvEALw_wcB

28

बदलते परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज

डॉ0 अंजू बंसल
असिस्टैंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
वर्धमान कॉलेज, बिजनौर

सारांश

साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज का वह परिधान है, जो जनता के जीवन के सुख–दुख, हर्ष विषाद, आकर्षण–विकर्षण के ताने बाने से बुना जाता है जिसमें मानव जाति की आत्मा स्पन्दित होती है। साहित्य प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक काल, प्रत्येक विषमता का खुला दस्तावेज है। हिन्दी साहित्य में आदिकालीन साहित्य वीरगाथात्मक रचनाओं का साहित्य है, उस समय राजा महाराजा वीरता प्रदर्शन को ही अपना सर्वोत्तम गुण समझते थे; भक्तिकाल में सूरदास, कबीर, तुलसी आदि ने भक्ति की गंगा बहायी क्योंकि प्रभु का सहारा दिखाना ही उनका उद्देश्य था, परन्तु परिवर्तन सृष्टि का नियम है। लगातार भगवान का नाम लेते–लेते जनता ऊब रही थी, फिर श्रृंगार काल का उदय हुआ तथा नर और नारी की प्रेमपूर्ण रचनाओं में कवि डूब गया। इस प्रकार प्रत्येक काल की परिस्थिति को साहित्य बयाँ करता है। वर्तमान काल में भ्रष्टाचार, बलात्कार, साम्प्रदायिकता अपना मुँह खोलकर मानवता को निगल रही है, ऐसे में कोरोना वायरस के पदार्पण ने मानव जाति को झकझोर दिया है। स्वयं को बुलंदियों पर समझने वाला व नित नई ऊँचाईयों को प्राप्त करने वाला मानव आज घर की चार दिवारी में घुस गया है, एक अदृश्य वायरस ने दृश्य धन व रिश्ते सब कुछ समाप्त कर दिया है। इस वायरस दौर से भी साहित्यकार अनजान नहीं है। नित नयी नयी कवितायें मानव जाति को झकझोर रही हैं। इस प्रकार साहित्य प्रत्येक बदलती तस्वीर को जीवंत बयाँ करता है।

मुख्य शब्द– कोरोना वायरस, विडम्बनायें, साहित्यिक विजय, नैतिक मूल्यों का हनन, प्रकृति का विनाश, विजयी प्रकृति।

सर्वप्रथम साहित्य का क्या अर्थ है? साहित्य का शाब्दिक अर्थ है साथ–साथ हित अथवा कल्याण, जो हित सहित हो वही साहित्य है, जिसमें कल्याण का भाव हो वही साहित्य है। अब बात आती है समाज की, तो समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों सम् एवं अज से बना है। सम् का अर्थ है इकट्ठा व एक साथ तथा अज का अर्थ है साथ रहना अर्थात समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। वास्तव में साहित्य समाज की चेतना में साँस लेता है। यह समाज का वह परिधान है जो जनता के जीवन के सुख–दुख, हर्ष–विषाद, आकर्षण–विकर्षण के ताने–बाने से बुना जाता है। उसमें विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पन्दन ध्वनित होता है, इसलिए विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। भृर्तहरि ने तो यहाँ तक कहा है– ''साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाण हीनः''। साहित्य संगीत और कला से हीन पुरुष साक्षात पशु ही है जिसके पूँछ और सींग नहीं हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समाज के निर्माण में साहित्य का क्या योगदान है, वास्तव में बदलते परिप्रेक्ष्य में साहित्य समाज का दर्पण है भी या नहीं! तो इस तथ्य के संदर्भ में मुझे वशीर बद्र की गज़ल याद आ रही है–

''घरों का नाम थे नामों के साथ ओहदे थे
बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला।''

वास्तव में वर्तमान परिस्थिति को साहित्य ही बयां करता है क्योंकि आज निरन्तर इंसानियत मरती जा रही है। मानव–मानव के लिए नहीं अपितु पैसे के लिए जी रहा है, दया रोती हुई नजर आ रही है, हैवानियत पनप रही है, अन्याय की अदालत में न्याय को शर्म आती है। खून सस्ता और पानी महंगा है, आप यकीन मानिए ऐसे में अगर कोई सच्चा है तो वह साहित्य ही है। साहित्य समाज का चक्षु है, वह समाज को दिव्य दृष्टि प्रदान करके कंटकाकीर्ण पथ पर भी हंसते–हंसते अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता समाज के लिए बोल रही है–

''जो अगणित लघु दीप हमारे। तूफानों में एक किनारे।

जल जला कर बुझ गये किसी दिन।

माँगा नहीं स्नेह मुँह खोल।

कलम आज उनकी जय बोल।''

अब हम सब स्वयं ही विचार लें कि साहित्य प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका अदा करता है, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका नेत्र है, यदि समाज बादल है तो साहित्य जल है, यदि समाज उत्तुंग हिमालय है तो साहित्य उससे निःसृत सूरसरि है, यदि समाज पुष्पोद्यान है तो साहित्य उसकी सुरभि है यदि समाज बसंत है तो साहित्य बासन्तिक छटा है और यदि समाज बिम्ब है तो साहित्य उसका प्रतिबिम्ब है। साहित्य में हम समाज के प्रत्येक बदलते बिंदु के दर्शन कर सकते हैं। एक जगह शेरजंग गर्ग कहते है–

''पहले, हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश।

एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश।।''

कवि कभी हुँकार लगाता है, कभी प्रेरित करता है कभी जगाता है तो कभी प्रताड़ित भी करता है, जिस प्रकार एक पौधे को पल्लवित और पुष्पित होने के लिए कभी खाद, कभी पानी कभी धूप, कभी छाया और कभी कभी खुरपियों की मार सहनी पड़ती है, उसी प्रकार समाज के पल्लवित और पुष्पित होने में जब जब जिस तरह की आवश्यकता पड़ी तब तब हमारा कवि और साहित्यकार अपनी कलम लेकर खड़ा हो गया क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।

द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी एक जगह कहते हैं–

''उठो धरा के अमर सपूतों

पुनः नया निर्माण करो।

जन–जन के जीवन में फिर से

नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो।''

अब यदि मैं आपसे वर्तमान संदर्भ में बात करूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कवितायें मानव जीवन में जुनून पैदा कर रहीं हैं–

''मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं,

लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं।''

इनकी कवितायें रह रह कर मानव के हृदय में गुंजार कर रही हैं, एक जगह वे कहते हैं–

''क्या हार में क्या जीत में

किंचित नहीं भयभीत में।

कर्तव्य पथ पर जो भी मिला

यह भी सही वो भी सही

वरदान नहीं मागूँगा।

हो कुछ, पर हार नहीं मानूँगा।''

ये पंक्तियाँ हर मानव के अंदर एक जुनून, एक आग पैदा कर रही हैं और ये पंक्तियाँ आने वाले कल में भी अपनी प्रासंगिकता बनायें रखेंगीं क्योंकि साहित्य कभी मरता नहीं। रामचरित मानस आज भी न जाने कितने हताश और भीरू हृदयों को सांत्वना देकर कर्मक्षेत्र में अवतरित होने का संदेश दे रही है।

सुंदरकाण्ड की एक चौपाई प्रस्तुत है–

''अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ।

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहि। उर अपराध न एकउ धरिही।''

तुलसीदास जी कह रहें हैं कि प्रभु का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, वे आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं धरेंगें। ऐसी वाणी आज तक जन मानस को सींच रही है।

अतः साहित्यिक विजय शाश्वत होती हैं और शस्त्रों की क्षणिक। साहित्य में ही किसी समाज की चेतना विद्यमान रहती है, उसके प्राण विद्यमान रहते हैं। किसी भी समाज को समझने के लिए वहाँ का साहित्य समझना होगा। वह समाज को उचित एवं अनुचित पथ का ज्ञान, कराता हुआ 'राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं' का सदुपदेश देता है। साहित्य समाज का शिक्षक है, वह समाज के सम्पूर्ण अज्ञान को दूर करके मंगलमय वृद्धि का प्रयास करता है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास का वीरगाथा काल इस बात का साक्षी है कि चारणों एवं भाटों की वीररसात्मक कविताओं को सुन–सुनकर किस तरह तत्कालीन वीर योद्धा युद्ध के मैदान में शौर्य एवं पराक्रम दिखाया करते थे। ऐसे ही भक्ति कालीन साहित्य इस बात का साक्षी है कि शासकों से त्रस्त जनता किस प्रकार उस अगोचर सत्ता के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने लगी। किस प्रकार गुरू की महत्ता बताकर जनता को सही राह पर लाने का प्रयास किया गया। कबीर ने कहा है–

''सतगुरू की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार
लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार।''

उस अनंत के उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन सतगुरू के माध्यम से ही हो सकते हैं। इसी प्रकार रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान रचनाओं को पढ़कर एवं सुनकर भारतीय जन–जीवन विलासिता की ओर उन्मुख हो गया था।

बिहारी कहते हैं–

''कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात,
भरै भौन में करत है नैनन ही सो बात।''

नायिका अपने प्रियतम से नेत्रों–नेत्रों से ही बातें कर रही है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जब आधुनिक युग में पदार्पण करते हैं तो साहित्य ने भी करवट बदली और राष्ट्र प्रेम और स्वदेश भक्ति साहित्य में गूंज उठी। भोग विलास की मादक निद्रा का परित्याग कर समाज स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए मचल उठा। यह है साहित्य का प्रभाव, जो रूसो और वॉल्टेयर के लेखों द्वारा जनक्रान्ति का आह्वान कर सकता है, जो मार्क्स और लेनिन के विचारों द्वारा रूस में खूनी क्रान्ति को बढ़ावा दे सकता है। जो मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर आदि की कविताओं के द्वारा समाज में तूफान खड़ा कर सकता है तथा जो लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित कर सकता है।

अंत में मैं युग पुरुष अटल जी के संदर्भ में एक कवि की कविता जो आपको यह प्रदर्शित करेगी कि किस प्रकार साहित्य वर्तमान को बोलता है, वाणी देता है, प्रस्तुत है –

''वह अटल अजातशत्रु वह राजनीति का
वैभव जा रहा है
हवाओं रास्ता दो
मेरा भारत रत्न मेरा जननायक जा रहा है।
वो जब बोलता था तब लोग मंत्र मुगध होकर सुनते थे।
साथ उसके वाणी का सम्मोहक जा रहा है।
पोखरण में जिसकी धमक को दुनिया ने देखा
वो जिसने खींची राष्ट्र में स्वर्णिम चतुर्भुज की रेखा
हवाओं रास्ता दो।
मेरा राष्ट्र रत्न मेरा देश नायक जा रहा है
मेरा राष्ट्र भक्त मेरा राष्ट्र नायक जा रहा है
कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ राजनीति, कृतज्ञ जनमानस
निःशब्द खड़े देखते हैं
हम इंसानों के बीच से वह देवतुल्य महामानव जा रहा है।
हवाओं रास्ता दो
मेरा विश्वरत्न मेरा गणनायक जा रहा है।''

वास्तव में ऐसे साहित्य को शत–शत नमन जो जीवन के प्रत्येक बिम्ब को प्रतिबिंबित कर रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में वायरस के पदार्पण के सापेक्ष साहित्य–

समाज के प्रत्येक पटल पर विषमतायें और विड़म्बनायें दृष्टिगत हो रही हैं। समाज में विकृतियों की अंतहीन श्रृंखला निर्मित होती जा रही है, शोषण का रूप विश्वव्यापी हो गया है, देश की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बदल गयी है तथा अधिकार प्राप्त व्यक्ति मनमाने ढंग से अपने अधिकार का दुरूपयोग करने लगा है। इस विड़म्बना पर श्री नेमिचन्द्र जैन की लेखनी कहती है –

''जीवन के सब दृश्य आज नहीं रहे,
बदल गये संस्कृति के, समाज के मानदण्ड,
पड़ गये पुराने निस्सार, वे विचार,
हो गये खोखले वे सारे आदर्श
वे सारी मर्यादाएँ सीमाएँ
बन गयी जन–जन–जन की बेड़ियाँ,
धर्म और नीति के वे संस्कार,
आज बने दासता के रावण के अस्त्र
पराजय की लंका के प्रहरी।''

समाज में व्याप्त शोषण का सर्वाधिक प्रभाव निम्न वर्ग व निम्न मध्य वर्ग पर पड़ता है। आजाद भारत ने उपहार में साम्प्रदायिकता, सामाजिक, धार्मिक आदि विषमताओं को प्राप्त किया है। वर्तमान परिस्थितियों की झलक कवि की वाणी में प्रस्तुत है –

''देस रे देस तेरे सिर पर कोल्हू
इसका भार तू कैसे ढोयेगा
जिसे पेरेंगे जाट, बाम्हन, बनिया, तेली, खत्री
मोलवी, कायस्थ, मसीही, जाटव, सरदार, भूमिहर, अहीर,
तू किस–किस को रोयेगा,
कब बनेगा तू राष्ट्र
कब तू अपनी नियति को पकड़ पा कर
तकिया लगा कर सोयेगा।''

कवि और लेखक वर्तमान परिदृश्य को अपनी कविता या लेख में वाणी देता है अन्यथा कविता काल के गर्त में समा जाती है। समाज के विषय ही उसके ह्रदय की वेदना बनते हैं।

अब अगर आज के पहलू पर विचार करें तो हम तकनीकी और विज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। आप कहीं पर भी बैठकर विदेशों में बात कर सकते हैं। मनुष्य सब कुछ अपनी मुटठी में करता जा रहा था, निरन्तर प्रकृति का विनाश कर ऊँची–ऊँची इमारतें और नित नई फैक्ट्रियों का श्रीगणेश हो रहा था तभी एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस कोविड–19 ने किस प्रकार से सम्पूर्ण दुनिया को डरा कर अपने–अपने घरों में कैद कर दिया। आदमी–आदमी से ही नहीं स्वयं से भी डरा–डरा रहने लगा। वह मनुष्य जो स्वयं को ईश्वर तुल्य समझने लगा था आज चींटी के समान दुबक जाना चाहता है। तो विचारणीय प्रश्न यह है कि मनुष्य जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करना चाहता था एक वायरस के आगे वह झुक गया, मजबूर हो गया अपने आप में सिमट गया। मनुष्य को उसकी औकात दिखाने के लिए यह वायरस जो इन आँखों से दिखता नहीं, काफी है। गजलकार दुष्यन्त कुमार कहते हैं –

''हो गई है परी पर्वत सी, पिघलनी चाहिये,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।''

मनुष्य ने गंगा को नालियों के समान गंदा किया, प्रकृति का बेहिसाब विनाश किया। केवल स्वसुख को ही वह सब कुछ समझने लगा ऐसे में प्रकृति चीत्कार उठी, गंगा विवश हुई और उसने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य को ही कैद कर दिया। अब वह तड़प रहा है, अपनी गलती मान रहा है परन्तु कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब आज के दौर में चीन से फैले कोरोना वायरस ने धीरे–धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है।

अब इस समय की दर्दनाक कविता प्रस्तुत है –

''कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के
घुटने टूटे सुपरशक्ति की तानाशाही के
कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के
फँसी हुई दुनिया कैसे अपने ही पांसों में
एक वायरस टहल रहा है आदमी की सांसों में
अवरोधक लग गए पांव में आवाजाही के

कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के
कहाँ गया ईश्वर बहुव्यापी, जग का विषपायी
एक वायरस ने दुनिया को, किया धराशाही
कुछ दिन में और लोग मिलेंगे, नहीं गवाही के
कितने खौफनाक मंजर है, यहाँ तबाही के।''

बस अब प्रकृति मनुष्य को क्षमा कर दे, ईश्वर मनुष्य को क्षमा कर दे तभी विश्व में शान्ति व्याप्त होगी। ऐसी भीषण परिस्थिति में कवि रूप में प्रत्येक मानव ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने हृदय में यह विश्वास कर रहा है कि वास्तव में एक दिन वह इस जंग में भी जीत जायेगा क्योंकि आज वह इंसान से दूर होकर ईश्वर के करीब है।

इस पर एक कविता और प्रस्तुत है –

''अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर पहुंच आसमां जीता,
अब अपने आप में झांक इंसान यह जीत लेंगे
आदमी ने मीलों का फासला तय कर संसार जीता
अब घर की चार दीवारी में रह वर्तमान जीत लेंगे
मौत पर जीत नहीं है मुमकिन, बहुत मुश्किल
लेकिन एक अमृत की खोज इसको जीत लेंगे।''

निश्चित रूप से साहित्य की ऐसी प्रेरणास्पद कवितायें मानव को जीत दिलाती हैं और भविष्य को सुखमय बनाती हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आत्मिक उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल है। हम समाज में कितनी भी ऊँचाइयों पर पहुँच जायें, स्वयं के लिए आवश्यकता से अधिक धन उपार्जित कर लें, परन्तु प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, ममता के गुणों से भरपूर मानव नहीं बन पायें तो निश्चित ही हम आनन्द से कोसों दूर रहेंगें। वर्तमान में मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह प्रसन्न नहीं, आनन्दित नहीं। वास्तव में साहित्य प्रत्येक पटल पर मनुष्य को आगे बढ़ने का उपदेश दे रहा है, गलत कार्यों के लिए रोक रहा है, मानवता के गुणों से सींच रहा है, विडम्बनाओं की खुली आवाज बन रहा है। साहित्य ही मानव को इंसान बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर प्रकृति का मानव निरन्तर विध्वंस करता चला गया और औद्योगिक उन्नति करता गया; वर्तमान कोरोना वायरस उसी की देन है। अब मानव ऑक्सीजन के सिलेण्डर के पीछे भाग रहा है। कैसी दुदर्शा कर ली मानव ने अपनी, अब उसे शर्म आनी चाहिए। ऐसी भीषण परिस्थिति में कवि रूप में प्रत्येक मानव ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपने हृदय में यह विश्वास कर रहा है कि वास्तव में एक दिन वह इस जंग में भी जीत जायेगा क्योंकि आज वह इंसान से दूर होकर ईश्वर के करीब है। बस अब प्रकृति मनुष्य को क्षमा कर दे, ईश्वर मनुष्य को क्षमा कर दे तभी विश्व में शान्ति व्याप्त होगी।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, पत्रकारिता एवं निबन्ध, लेखक डा. रामस्वरूप आर्य।
2. साहित्यिक निबंध, राजनाथ शर्मा।
3. राजपाल हिन्दी शब्दकोश, डॉ. हरदेव बाहरी।
4. हिन्दी साहित्यः युग और प्रवत्तियाँ, शिव कुमार शर्मा।
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा. नगेन्द्र।
6. एकान्त, कविता संग्रह, नेमिचन्द्र जैन।
7. कागज के फूल, भारत भूषण अग्रवाल।
8. तारसप्तक के कवियों की काव्य कृतियों में व्यंग्य विधान, डॉ. अंजू बंसल (शोध ग्रन्थ)।
9. पत्र–पत्रिकायें।
10. अन्य उपजीव्य व उपस्कारक ग्रन्थ।

29

वाल्मीकिरामायणम् का उद्देश्य

डॉ0 रंजना अग्रवाल
एसोसिऐट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
एन. के. बी. एम. जी. कॉलेज, चन्दौसी (जिला–सम्भल)

सारांश

किसी भी ग्रन्थ, लेख या वक्तव्य का उद्देश्य उसके उपक्रम में ही निहित रहता है। ग्रन्थकार, लेखक अथवा वक्ता अपनी कृति के आरम्भ में ही उसके उद्देश्य का उल्लेख करता है। इस दृष्टि से यदि हम श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् के उपक्रम को देखें तो हम सहज ही उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। महर्षि नारद कहते हैं–यह रामकथा वेदों के समान अत्यन्त पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय है। जो यह रामचरित्र पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। देखिए–

''इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्।
यः पठेद् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते।।'' वा.रा.१/१/९८. ' १

रामायण का पाठ करने वाले मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है, मनुष्य केवल इहलोक में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात् पुत्र पौत्रादि सहित स्वर्ग में प्रतिष्ठित होगा ।

''एतदाख्यानमायुष्यंपठन् रामायणं नरः।
सपुत्रपौत्रः सगणःप्रेत्य स्वर्गे महीयते।।'' वा. रामा. १/१/९९ '२

देवर्षि नारद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथन कहते हैं। वह इस प्रकार है–

''पठन्द्विजो वागृषभत्वमीयात्
स्यात्क्षत्रियोभूमिपतित्वमीयात्।
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्
जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्।।'' वा.रा.१/१/१०० '३

यदि इसको ब्राह्मण पढ़े तो वह विद्वान हो सकता है। यदि क्षत्रिय पढ़े तो भूमिपति राजा हो सकता है। यदि वैश्य पढ़े तो वह व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकता है। और यदि शूद्र पढ़े तो वह महत्त्व अथवा प्रतिष्ठा पा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए परम उपकारी यह कथा है।

महर्षि वाल्मीकि ने सात काण्डों, पाँच सौ सर्गों और चौबीस हजार श्लोकों का यह अद्भुत रामायण महाकाव्य रचा। जिसने संसार के लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने हेतु न केवल आकृष्ट किया अपितु उनका मार्गदर्शन भी किया। हिन्दू–दर्शन में इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक् रूप से अर्जित कर लेने को जीवन की सफलता माना जाता है। चारों वर्णों के सभी लोगों को सम्पूर्ण जीवन की सफलता (पुरुषार्थ–चतुष्टय) प्राप्त करने के लिए यह महाकाव्य है। यही इस रामायण का उद्देश्य है।

वाल्मीकीय रामायण संस्कृत साहित्य का एक आरम्भिक महाकाव्य है, जो संस्कृत भाषा में अनुष्टुप छन्दों में रचित है। इसमें श्रीराम के चरित्र का उत्तम एवं वृहद् विवरण काव्य रूप में उपस्थापित हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होने के कारण इसे 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण' कहा जाता है। वर्तमान में राम के चरित्र पर आधारित जितने भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन सभी का मूल महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ही है। 'रामायण' के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि को 'आदिकवि' माना जाता है और इसीलिए यह महाकाव्य 'आदिकाव्य' माना गया है। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण आयामों को प्रतिबिंबित करने वाला होने से साहित्य रूप में अक्षय निधि है।

वृहद्धर्म पुराण में इस महाकाव्य की प्रशंसा 'काव्यबीजं सनातनम्' कहकर की गयी है। (वृहदृधर्म पुराण १/३०/४७)' ४

अग्निपुराण, गरुड़पुराण, हरिवंश पुराण (विष्णु पर्व), स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड), मत्स्यपुराण, महाकवि कालिदास रचित रघुवंश, भवभूति रचित उत्तररामचरित, वृहद्धर्म पुराण जैसे अनेक प्राचीन ग्रन्थों में महर्षि वाल्मीकि एवं उनके महाकाव्य रामायणम् का उल्लेख मिलता है।

काव्यगुणों की दृष्टि से वाल्मीकीय रामायण अद्वितीय महाकाव्य है। विद्वानों का मत है कि यह महाकाव्य संस्कृत काव्यों की परिभाषा का आधार है। अन्य रचनाकारों के समक्ष उनकी रचनाशैली के लिये अनेक प्रेरक तथा पथ–प्रदर्शक ग्रन्थ रहे हैं, किन्तु महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख ऐसी कोई रचना नहीं थी, जो उनका पथ–प्रदर्शन कर सके। अतः यह महाकाव्य पूर्णतः उनकी मौलिक कृति है। अपने इस महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने अद्वितीय शैली में प्रकृति–चित्रण, संवाद–संयोजन तथा विषय प्रतिपादन किया है।

त्रेतायुग में महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से साक्षात् वेदों का ही श्रीमद्रामायण रूप में प्राकट्य हुआ, ऐसी आस्तिक जगत की मान्यता है। अतः श्रीमद्रामायण को वेदतुल्य प्रतिष्ठा प्राप्त है। धराधाम का आदिकाव्य होने से इस में भगवान के लोकपावन चरित्र की सर्वप्रथम वाङ्मयी परिक्रमा है। इसके एक–एक श्लोक में भगवान के दिव्य गुण, सत्य, सौहार्द्र, दया, क्षमा, मृदुता, धीरता, गम्भीरता, ज्ञान, पराक्रम, प्रज्ञा–रंजकता, गुरुभक्ति, मैत्री, करुणा, शरणागत–वत्सलता जैसे अनन्त पुष्पों की दिव्य सुगन्ध है।

रामायण के प्रारम्भ में ही महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद की भेंट होने का वर्णन है। इसी भेंट में वे देवर्षि नारद से वह जिज्ञासा करते हैं जो उनके मन मस्तिष्क में चल रही थी। वे किसी ऐसे पुरुष के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते हैं जिसमें वे सोलह गुण विद्यमान हों , जिसकी कल्पना उनके (वाल्मीकि जी) मन में उमड़ रही थी । स्पष्ट है कि वे किसी ऐसे धीरोदात्त पुरुष के सम्बन्ध में लिखना चाहते थे। देखिए –

''ऊँ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्।

नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्।।'' वा. रामा. श्लोक १/१/१ '५

तपस्वी वाल्मीकि ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए, विद्वानों में श्रेष्ठ और मुनियों (मननशील व्यक्तियों) में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि जी ने तभी पूछा होगा जब नारद के उत्तर का कुछ उपयोग करने की कोई योजना उनके मन में रही होगी।

वे पूछते हैं –

''को न्वस्मिन् साम्प्रते लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः।।'' वा.रा.१/१/२ '६

अभी वर्तमान समय में कौन व्यक्ति गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ (किए हुए उपकार को मानने वाला), सत्यवक्ता और दृढ़व्रती है ?

उनकी जिज्ञासा भूतकाल में हुए किसी महापुरुष के सम्बन्ध में नहीं थी। वे केवल वर्तमान में उपस्थित पुरुष की बात कर रहे थे। मृत्यु के पश्चात् तो लोग सभी को महान् बता दिया करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि भूतकाल में कौन कितना महान हो गया; यह वर्तमान को महान् बना देने के लिए निश्चित निर्धारण बिन्दु तो नहीं है ?

''चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः।

विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।।'' वा.रा.१/१/३ '७

कौन व्यक्ति चारित्र्य से युक्त है और सम्पूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है। कौन विद्वान् और समर्थ है। कौन प्रियदर्शन (देखने में प्रिय और सबको प्रिय देखने वाला) है।

''आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः।

कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे।।'' वा.रा.१/१/४ '८

जिसका मन वश में हो, क्रोध को जीत लिया हो, तेजस्वी और परनिन्दा न करनेवाला कौन है। रणभूमि में कुपित होने पर किससे देवता (भी) भय खाते हैं।

ये ही वे सोलह गुण हैं जिन गुणों से युक्त पुरुष के सम्बन्ध में महर्षि वाल्मीकि जानना चाहते हैं कि किस पुरुष में ये गुण विद्यमान है ?

वे देवर्षि नारद को यह ज्ञान रखने के सर्वथा योग्य मानते हैं। वे आगे कहते हैं–

''एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे।

महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्।।'' वा.रा.१/१/५ '९

महर्षि! मैं यह जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप ऐसे मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। अर्थात् अवश्य जानते होंगे।

रामायण में भी नारद जी को 'त्रिलोकी का ज्ञान रखने वाला' कहा गया है ।

''श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदोवचः।'' वा.रा.१/१/६ '१०

इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि नारद जी से भेंट से पूर्व ही सोलह गुणों से युक्त पुरुष के सम्बन्ध में जानने का कौतूहल वाल्मीकि जी के मन में विद्यमान था और नारद जी से भेंट का अवसर प्राप्त करते ही उन्होंने अपने कौतूहल को प्रकट कर दिया।

ऐसा सुनकर नारद बोले कि इतने सभी गुण एक व्यक्ति में होना दुर्लभ हैं। तो भी मैं विचार करके बताता हूँ। सुनो–

''इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः।'' वा.रा.१/१/८ '११

इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न राम एक ऐसे पुरुष हैं जिनकी ख्याति जन–जन में फैली है।

ऐसा कहकर वे श्रीराम के कुछ गुणों का वर्णन करने लगते हैं। इस वर्णन में वे संक्षेप में श्रीराम का पूरा चरित्र वर्णित कर देते हैं।

अन्त में वह यह भी कहते हैं कि यह रामकथा वेदों के समान अत्यंत पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय है, जो यह रामचरित्र पढ़ेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जायेगा। देखिए –

''इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्।

यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते।।'' वा.रामा.१/१/९८ '१२

तत्पश्चात् देवर्षि नारद एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं । देखिए–

''पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात्।

स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्।

वणिग्जनःपण्यफलत्वमीया–

ज्जनश्चशूद्रोपिमहत्त्वमीयात्।।'' वा.रा.१/१/१०० '१३

अर्थात् यदि इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान् हो सकता है, यदि क्षत्रिय पढ़े तो भूमिपति हो सकता है, यदि वैश्य पढ़े तो व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकता है और यदि शूद्र पढ़े तो वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। अर्थात् समाज के प्रत्येक वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के लिए यह कथा लाभकारी और उपकारी हो सकती है।

यह प्रसंग हमने इसलिए लिखा कि पाठकों के मन में यह स्पष्ट हो जाए कि रामायण की रचना के पूर्व महर्षि वाल्मीकि के मन में क्या कुछ चल रहा था और नारद से मिलने पर उन्हे क्या मार्गदर्शन मिला; यही रामायण के वास्तविक उद्देश्य के निर्धारण का सूत्र है।

यह प्रसंग यह भी बताता है कि वाल्मीकि जी के, नारद जी से मिलने के पूर्व ही कविता के बीज उनके हृदय में आरोपित थे, उनका शास्त्रों का अध्ययन था और वे कुछ महत्त्वपूर्ण लिखने के लिए व्यग्र हो रहे थे।

वाल्मीकि और नारद की इस भेंट के पश्चात् एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसने वाल्मीकि को प्रभावित कर दिया। वह घटना इस प्रकार थी।

नारद जी से भेंट करने के उपरान्त महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर पहुँचे जो गंगा नदी के निकट ही था। वहाँ एक घाट को कीचड़ रहित देखकर महर्षि ने अपने बुद्धिमान शिष्य भरद्वाज से कहा कि यहाँ का जल वैसा ही निर्मल है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। वे बोले –

''न्यस्तां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम।

इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्।।'' वा.रा.१/२/६ '१४

तात भरद्वाज! यहीं पर कलश रख दो और मेरे वल्कल मुझे दो। मैं तमसा के इस उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा।

भरद्वाज ने वैसा ही किया। वे जितेन्द्रिय महर्षि वल्कल हाथ में लेकर विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरण करने लगे।

उस समय उन्होंने क्रौञ्च पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे और मधुर बोली बोल रहे थे।

''तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्।

ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्च्योश्चारुनिःस्वनम्।।'' वा.रा.१/२/९ '१५

उसी समय एक व्याध ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते ही देखते बाण से मार डाला।

''तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः।

जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः।।'' वा.रा.१/२/ १० '१६

''तं शोणितपरीतांगं चेष्टमानं महीतले।

भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्।।'' वा.रा.१/२/११ '१७

रक्त से लथपथ वह पक्षी धरती पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। उसकी भार्या अपने पति की हत्या हुई देखकर करुण वाणी में रोने लगी।

ऐसा देखकर स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि करुणा से भर उठे। उन्होंने इसे अधर्म माना। यहां निम्न श्लोक से यह स्पष्ट है कि महर्षि के अंतस् में करुणा स्वभावतः विद्यमान थी। रोती हुई क्रौञ्ची को देखकर महर्षि ने निषाद को श्राप दे दिया।

''ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः।

निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्।।'' वा.रा.१/२/१४ '१८

महर्षि क्रौञ्ची के करुण विलाप से द्रवित हो उठे। उन्होंने निषाद के कृत्य को अधर्म माना।

धर्म और अधर्म के मध्य सूक्ष्म भेद और उसके निर्धारण का यह विलक्षण और विश्व का एकमात्र उदाहरण ही होगा। रामायण का यह प्रसंग उन लोगों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है जो धर्म के नाम पर क्रूर होकर धर्म के साथ परिहास कर रहे हैं। धर्म और अधर्म की सम्यक् व्याख्या के निर्धारण के लिए यह श्लोक विश्व में सदैव उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता रहेगा।

रामायण की रचना के मूल में महर्षि के हृदय में करुणा–स्त्रोत (जो उनके अन्तस् में स्वभावतः ही विद्यमान थी) फूटने पर निःसृत यह जगप्रसिद्ध श्लोक है, जिसने रामायण लिखे जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह जगत्प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है –

''मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।'' वा.रा.१/२/१५ '१६

अरे निषाद! तुम कभी भी शाश्वत शान्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे; क्योंकि तुमने काममोहित क्रौञ्च के जोड़े में से एक को, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के मार डाला है।

यही वह श्लोक है जिससे महर्षि के हृदय में काव्यधारा बहने लगी। इस प्रकार महर्षि की करुणा ने श्लोकरूप ले लिया था। वे उस हत्यारे व्याध के लिए अमंगलमय शाप देकर पुनः स्वयं सोचने लगे।

उनके मन में यह चिन्ता हुई कि इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला !

''तस्येत्थंब्रुबतश्चिंताबभूव हृदि वीक्षतः ।

शोकार्तेनास्य शकुनेःकिमिदं व्याहृतं मया।।'' वा.रा.१/२/१६ '२०

इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि–

१. महर्षि के हृदय में सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव सदा विद्यमान रहता था। इस स्थल पर वह तत्काल प्रकट हो गया। पशु पक्षियों के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम और करुणा भरी हुई थी।

२. करुणा से उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा। उसके कारण दो बातें घटीं। एक तो उनके कण्ठ से मधुर श्लोक निकला, दूसरे उन्हें तत्क्षण व्याध पर क्रोध आ गया और उन्होंने उसे शाप दे दिया। शाप देने के पश्चात् उन्हें पश्चाताप भी होने लगा।

३. इस घटना के पश्चात् वे जब भी कुछ सोचते विचारते तो उनके सामने वह क्रौञ्च पक्षी का दृश्य और अपने शाप का स्मरण हो आता।

उनकी इस मनःस्थिति में ही एक दिन ब्रह्मा जी महर्षि से मिलने आ पहुँचे। उनके सहसा आ जाने से महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। उनका अर्घ्य, पान, आसन से सत्कार करके वे हाथ जोड़कर खड़े रह गये। कुछ भी बोल न सके। उस समय भी उनके मन में वह क्रौञ्च वाली घटना छायी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनकी ऐसी मनःस्थिति को देखकर पूछा तो वाल्मीकि जी ने अपने साथ घटी घटना को विस्तार से सुना दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे मुख से उस समय यह श्लोक (१/२/१५) निकला था।

पूरी घटना सुनकर ब्रह्मा जी बोले –

''श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा।

मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती।।'' वा.रा.१/२/३१ '२१

तुम्हारे मुख से निकला यह छन्दबद्ध श्लोक ही है। इसमें अब कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार प्रवृत्त हुई है।

''रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम।

धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः।।'' वा.रा.१/२/३२ '२२

ऋषिवर! तुम श्रीराम का सम्पूर्ण चरित्र लिखो; क्योंकि श्रीराम संसार में बुद्धिमान, शुभलक्षण और धर्मात्मा हैं।

आगे उन्होंने यह भी कहा कि जैसा तुम्हें नारद ने रामचरित्र सुनाया है वैसा ही लिखो। मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हें राम के चरित्र की सभी घटनाएँ प्रत्यक्ष हो जाएँगीं।

''वृत्तं कथय धीरस्ययथा ते नारदाच्छ्रुतम्।

रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं तस्य धीमतः।।'' वा.रा.१/२/३३ '२३

तब महर्षि वाल्मीकि ने सात काण्डों, पाँच सौ सर्गों और चौबीस हजार श्लोकों का यह अद्भुत रामायण महाकाव्य रचा। जिसने संसार के लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने हेतु न केवल आकृष्ट किया अपितु उनका मार्गदर्शन भी किया। हिन्दू दर्शन में इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक् रूप से अर्जित कर लेने को जीवन की सफलता माना जाता है। चारों वर्णों के सभी लोगों को सम्पूर्ण जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए यह महाकाव्य है। यही इस रामायण का उद्देश्य है।

इसका प्रधान रस करुण रस है और इसका सन्देश संसार का ऐहिक और पारलौकिक कल्याण है। यह सन्देश अहिंसा, सत्य, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे गुणों के माध्यम से दिया गया है।

निष्कर्ष

कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महर्षि को क्रौञ्च पक्षी की घटना के पहले काव्यकला का ज्ञान न था। वह काव्यकला तो वह परम कारुणिक दृश्य देखकर अकस्मात् उनके हृदय से फूट पड़ी थी। हम इस निष्कर्ष को उचित नहीं मानते। हम ऊपर वर्णन कर आए हैं कि महर्षि वाल्मीकि इस घटना के पहले ही काव्यकला सहित सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। उनके मन में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य अथवा लिखने का विचार इस घटना के पहले से ही विद्यमान था।

श्रीस्कंदपुराण के उत्तरखण्ड में नारद–सनत्कुमार संवाद के अन्तर्गत रामायणमाहात्म्यविषयक कल्पानुकीर्तनं नामक प्रथम अध्याय में रामायण का माहात्म्य इस प्रकार वर्णित है। सूतजी कहते हैं– हे मुनिवरो! यह रामायण नामक महाकाव्य समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। यह सम्पूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। यह महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान् फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है, आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसका श्रवण करें। देखिए–

''रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम्।
सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणम्।।'' स्कन्दपुराण, उत्तर खण्ड – १/१६ '२४
''धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्।
अपूर्वं पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिताः ।।'' स्कन्दपुराण , उत्तरखण्ड – १/२१ '२५

इति।

संदर्भ सूची–

१, २, ३ –वा.रामा. १/१/६८, ६६, १००
४– वृहद्धर्म पुराण –१/३०/४७
५, ६, ७, ८, ६, १०, ११–(वा.रामा.–१/१/१, २, ३, ४, ५, ६, ८)
१२–वा.रामा.– १/१/६८
१३–वा.रामा.–१/१/१००
१४–वा.रामा. –१/२/६
१५,१६,१७– वा.रामा.–१/२/६, १०, ११
१८, १६,२०– (वा.रामा. –१/२/१४, १५,१६)
२१,२२,२३– (वा.रामा.– १/२/३१,३२, ३३)
२४– स्कंद पुराण ,उत्तरखण्ड – १/१६
२५– स्कंद पुराण, उत्तर खण्ड–१/२१

30

जनपद प्रतापगढ़ के संयुक्त एवं एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

डॉ0 योगेश कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (बी0एड0 विभाग)
रा0 ह0 सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, प्रतापगढ़

डॉ0 शैलेष कुमार पाण्डेय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (बी0एड0 विभाग)
एम. डी. पी. जी. कालेज, प्रतापगढ़

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन संयुक्त एवं एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से सम्बन्धित है जिसमें प्रतापगढ़ जिले के कुल 200 बच्चों का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्श प्रणाली द्वारा किया गया है। इसके लिए स्वनिर्मित सामाजिक गुण, प्रश्नावली मापनी तथा अध्ययन आदत के लिए डॉ0 एम0एन0 पल्सानी एवं साधना शर्मा द्वारा निर्मित अध्ययन आदत अनुसूची मापनी से आँकड़े संग्रहित किये गये और आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन व 'टी' टेस्ट की गणना की गई और निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों में सार्थक अन्तर होता है, जिसका प्रभाव उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ता है।

मुख्य शब्द– सामाजिक गुण, अध्ययन आदत, सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्श प्रणाली, सामाजिक प्राणी

प्रस्तावना

मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म परिवार में होता है जो उसके प्राथमिक समाज का रूप ले लेता है। इसके बाद जैसे–जैसे वह बड़ा हो जाता है उसके सम्पर्क में दूसरे व्यक्ति आते–जाते हैं और उसके समाज का दायरा विस्तृत होता जाता है। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता लगभग शून्य होती है। जैसे–जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है वैसे–वैसे उसका समाजीकरण भी होने लगता है। समाजीकरण का प्रारम्भ परिवार से ही होता है। वह अपने माता–पिता परिवार के सभी सदस्यों, संगी–साथियों तथा अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तथा जगत में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है।

परिवार एक छोटी सामाजिक संस्था है जिसमें रहते हुए बालक माता–पिता के अतिरिक्त भाई–बहन तथा अन्य संबंधियों के सम्पर्क में आता है। बालक परिवार में प्रत्येक सदस्य से प्रत्येक क्षण प्रभावित होता रहता है। इस प्रभाव से वह समाज के तौर–तरीके सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रथम 6 वर्षों तक बालक इस सामाजिक वातावरण में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता तथा माता–पिता, भाई–बहनों तथा अन्य सदस्यों के दैनिक जीवन में होने वाले सभी कार्यों का अनुकरण करने लगता है। प्रत्येक परिवार का व्यक्तित्व अलग–अलग होता है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बच्चों के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। बच्चों के सामाजिक गुणों के कारण उनमें अनुकरण, प्रतिद्वन्दिता, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं का विकास होता है।

प्रायः यह देखा जाता है कि संयुक्त परिवार के बच्चों का सामाजिक विकास संतुलित रूप से होता है जबकि एकल परिवार में सामाजिक गुणों के विकास में कम विविधता पाई जाती है। संयुक्त परिवार में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, एकल परिवार में बच्चे निर्देशित होकर सीखते हैं।

संयुक्त परिवार में बच्चों का सामाजिक गुण ठीक प्रकार से विकसित होता है जिससे बालक समूह में रहना पसन्द करता है तथा उसके अन्दर सहयोग की भावना होती है। वह किसी कार्य को सबके साथ मिलजुल कर करना पसन्द करता है। वहीं एकल परिवार का बालक एकान्त में रहना ज्यादा पसन्द करता है। उनकी चिन्तन शक्ति अधिक होती है। माता–पिता के अत्यधिक नजदीक होने के कारण उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है।

बच्चों की अध्ययन आदतों पर सामाजिक गुण का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। संयुक्त परिवार का बालक समूह में कार्य करता है तथा किसी समस्या को आपस में तर्क–वितर्क करके आसानी से समाधान प्राप्त कर लेता है। वहीं, एकल परिवार में बालक एकान्त में अध्ययन करके किसी समस्या का समाधान चिन्तन की उच्चतम सीमा के द्वारा प्राप्त कर लेता है। संयुक्त परिवार के बालकों की सामाजिक क्रिया–कलापों में भागीदारी अधिक होती है। जबकि एकल परिवार बच्चों की अकेले करने की भावना अधिक होती है। ''संयुक्त परिवार के बालकों का सामाजिक गुण अधिक विकसित है या एकल परिवार के बालकों का तथा इन सामाजिक गुणों का उनकी अध्ययन आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है?''– इसी दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का शीर्षक 'संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन' का चयन किया गया है।

शोध समस्या के प्रमुख शब्दों का स्पष्टीकरण–

संयुक्त परिवार– संयुक्त परिवार में माता–पिता, भाई–बहन के अतिरिक्त चाचा, ताऊ की विवाहित सन्तान, उनके विवाहित पुत्र, पौत्र आदि भी हो सकते हैं।

एकल परिवार– एकल परिवार वे परिवार हैं, जिनमें माता–पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं।

सामाजिक गुण– सामाजिक गुण से तात्पर्य है अनुकरण प्रतिद्वंदिता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना का होना।

अध्ययन आदत– जो निरन्तर लगातार हो रही हो, वह आदत है। किसी बच्चे की अध्ययन प्रक्रिया से सम्बन्धित आदत को ही अध्ययन आदत कहते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य–

- संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का अध्ययन करना।
- बच्चों का उनकी अध्ययन आदतों से सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

- संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि/प्रकार– प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

समष्टि – प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि में प्रतापगढ़ जिले के समस्त संयुक्त और एकल परिवार के समस्त बच्चों को लिया गया है।

न्यादर्श/न्यादर्शन तकनीक– प्रस्तुत अध्ययन में कुल 200 बच्चों को सोद्देश्यपूर्ण तरीके से न्यादर्श के रूप में लिया जायेगा जो संयुक्त एवं एकल परिवार से आधे–आधे होंगें।

प्रयुक्त मापनी– प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक गुण हेतु स्वनिर्मित सामाजिक गुण मापनी तथा अध्ययन आदत के लिए डॉ0 एम0एन0 पल्सानी एवं साधना शर्मा द्वारा निर्मित अध्ययन आदत अनुसूची मापनी का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या– प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है; का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना के निर्माण हेतु प्रदत्तों के विश्लेषणोपरान्त निम्नलिखित तालिका निर्मित की गयी–

तालिका–01

सामाजिक गुण

क्र. सं.	चर	संख्या "N"	मध्यमान "M"	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि	C.R. Value	सार्थकता स्तर (d.f.)
1.	संयुक्त परिवार	100	42.7	4.48	0.72	10.96	0.05
2.	एकल परिवार	100	35	5.8			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के बच्चों का सामाजिक गुण के संदर्भ में मध्यमान 42.7 जबकि एकल परिवार के बच्चों का मध्यमान 35 है। दोनों समूहों का मानक विचलन क्रमशः 4.48 तथा 5.8 है। दोनों मध्यमान की मानक त्रुटि 0.72 है जिसका सी0आर0 अनुपात 10.96 आया जो सार्थकता स्तर 0.05 पर तथा मुक्तांश 198 पर 'टी' सारणी के मान 1.97 से अधिक है।

अतः इस शोध की परिकल्पना–1 अस्वीकृत हो जाती है कि संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। यहाँ संयुक्त परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों का मध्यमान एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों के मध्यमान से अधिक है। अतः संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों के सामाजिक गुणों में सार्थक अंतर है।

प्रस्तुत अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदतों से सम्बन्ध का अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदतों मे कोई सार्थक अन्तर नहीं है; का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना के निर्माण हेतु प्रदत्तों के विश्लेषणोपरान्त निम्नलिखित तालिका निर्मित की गयी–

तालिका–02

अध्ययन आदत

क्र. सं.	चर	संख्या "N"	मध्यमान "M"	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि	C.R. Value	सार्थकता स्तर (d.f.)
1.	संयुक्त परिवार	100	77	7.92	1.12	2.41	0.05
2.	एकल परिवार	100	79.7	8.02			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के बच्चों का अध्ययन आदत के संदर्भ में मध्यमान 77 जबकि एकल परिवार के बच्चों का मध्यमान 79.7 है। दोनों समूहों का मानक विचलन क्रमशः 7.92 तथा 8.02 है। दोनों मध्यमान की मानक त्रुटि 1.12 है जिसका सी0आर0 अनुपात 2.41 आया जो सार्थकता स्तर 0.05 पर तथा मुक्तांश 198 पर 'टी' सारणी के मान 1.97 से अधिक है।

अतः इस शोध की परिकल्पना–2 अस्वीकृत हो जाती है कि संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। यहाँ संयुक्त परिवार के बच्चों की अध्ययन आदत का मध्यमान एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदत गुणों के मध्यमान से कम है। अतः संयुक्त और एकल परिवार के बच्चों की अध्ययन आदतों में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक निहितार्थ निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार बालक की अध्ययन प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए गुणों का विकास करने में ध्यान देना चाहिए। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। बच्चों का विकास माता–पिता, परिवार तथा शिक्षक पर निर्भर करता है। माता–पिता को अपने बच्चों के गुणों का विकास भली–भाँति करना चाहिये, उन्हें कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहियें। उन्हें दण्ड नहीं देना चाहिए बल्कि पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरित करना चाहिये। बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए। परिवार का वातावरण अगर सामाजिक और मानसिक रूप से ठीक है तो बच्चे को अपने वातावरण में समायोजन करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- गुप्ता एस0पी0, 2003, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गुप्ता एस0पी0, 2007, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- चौहान एस0एस0 2006, एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी, न्यू देलही विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लि0।
- गुप्ता एस0पी0, 2012, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गौरिट एच0आई0, 1993, शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना।
- पाण्डेय कामता प्रसाद, 2008, शैक्षिक अनुसंसधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- बुच एम0वी0, 1988, फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली।
- बुलाक, 1952, सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, गुप्ता एस0पी0, 2007, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गूगल सर्च
- विकिपीडया

डॉ0 अभय कुमार मीतल, प्राचार्य, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश सन् 1984 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने वाणिज्य विषय की अनेकों पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, लेख और शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों की संपादित पुस्तकों में 40 से अधिक अध्यायों का भी योगदान दिया है। उन्होंने 125 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वेबिनार, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्हें दो राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के सफलतापूर्वक आयोजन का श्रेय भी है। उनके निर्देशन में 6 उम्मीदवारों को डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है। 140 से अधिक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने उनके निर्देशन में लघु शोध प्रबंध कार्य पूरा किया है। व्यावसायिक सन्नियम, अंकेक्षण, प्रबंधकीय लेखांकन और कराधान इत्यादि उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।

डॉ0 संजय कुमार बंसल सन् 2001 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्तमान में, वह एन.आर.ई. सी. कॉलेज, खुर्जा (जिला बुलंदशहर), उत्तर प्रदेश में एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं और संपादित पुस्तकों के लिए 25 से अधिक लेखों एवं शोध पत्रों का योगदान किया है। उन्होंने 'व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन' नामक एक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने आयकर, वित्तीय प्रबंधन, ई–कॉमर्स, प्रतिभूति विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन पर संपादित पुस्तकों में विभिन्न अध्याय भी लिखे हैं। उन्होंने 45 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वेबिनार और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके निर्देशन में 6 शोधार्थी अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु शोध कार्य कर रहे हैं। वित्त और कराधान इत्यादि उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।

डॉ0 मनीष कुमार गुप्ता सन् 2003 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, वह साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (जिला बिजनौर), उत्तर प्रदेश में एसोसिऐट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं और संपादित पुस्तकों के लिए 35 से अधिक लेखों एवं शोध पत्रों का योगदान किया है। उन्होंने 80 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वेबिनार, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उनके निर्देशन में 6 शोधार्थी अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु शोध कार्य कर रहे हैं। 24 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने उनके निर्देशन में अपना लघु शोध प्रबंध कार्य पूरा किया है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र, लागत लेखांकन, व्यवसायिक सांख्यिकी और वित्तीय प्रबंधन इत्यादि उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।

Published By :

ANU BOOKS

New Delhi • Meerut • Glasgow (UK)
E-mail : anubooks123@gmail.com
Website : www.anubooks.com
Phone : 0121-2657362, Mob. : 99978 47837 (India)
+44 758 651 3591 (UK)

₹ 750/-